बेटियों के लिए सुरक्षा कवच

केंद्र सरकार सर्वाइकल कैंसर (गर्भाशय ग्रीवा कैंसर) के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रही है. नब्बे दिनों का यह विशेष टीकाकरण अभियान 14 वर्ष की किशोरियों के लिए चलाया जायेगा, ताकि देश पर ग्रभाशय ग्रीवा कैंसर का बढ़ता बोझ कम हो सके. यह अभियान विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों के अनुरूप है, जिसमें 20 वर्ष तक की लड़कियों के लिए टीके की एक खुराक और 21 वर्ष से अधिक उम्र के लिए छह महीने के अंतराल पर टीके की दो खुराक लेने की बात कही गयी है. इस अभियान के तहत सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण किया जायेगा. इस 90 दिनों के अभियान के बाद टीका लेने के योग्य किशोरियों को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के वैक्सीन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म 'यू-विन' के जरिये एक स्लॉट बुक करना होगा. ठीक वैसे ही जैसे कोविड महामारी के समय लोग को-विन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते थे. चौदह वर्ष की आयु पूरी कर चुकी किशोरियां सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर टीका लगवा सकेंगी. यह कार्यक्रम पूरी तरह निःशुल्क और स्वैच्छिक है. ऐसा करने का उद्देश्य सभी किशोरियों तक टीके की एक समान पहुंच सुनिश्चित करना है. इस कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ, भारत उन 160 से अधिक देशों में शामिल हो जायेगा, जहां एचपीवी टीकाकरण शुरू हो चुका है. एचपीवी एक आम यौन संचारित संक्रमण (सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन) है और लगभग 14 प्रकार के एचपीवी, कैंसर का कारण बन सकते हैं. यह अभियान 90 दिनों के बाद भी समाप्त नहीं होगा, बल्कि टीकाकरण के नियमित कार्यक्रम के साथ स्वास्थ्य व कल्याण केंद्रों पर जारी रहेगा. यह अभियान इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि सभी प्रकार के गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लगभग 90 प्रतिशत का कारण लगातार बने रहने वाला एचपीवी संक्रमण है. इसलिए भी क्योंकि वैश्विक स्तर पर गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के मामले में भारत पांचवें स्थान पर है और देश में महिलाओं में यह दूसरा सबसे आम कैंसर है. देश में प्रतिवर्ष 1.25 लाख महिलाएं गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से प्रभावित होती हैं और इस कारण सालाना 75,000 महिलाओं की जान चली जाती है. हालांकि, भारत के पास स्वदेशी एचपीवी टीका (सर्वावैक) है, पर इस अभियान के लिए एमएसडी फार्मास्युटिकल्स के 'गार्डासिल' टीके का उपयोग होगा, जो प्रमाणित है. 'सर्वावैक' को विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी मिलनी बाकी है और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) इसकी एकल खुराक की प्रभावशीलता का अध्ययन कर रही है.

केंद्र सरकार गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के विरुद्ध निःशुल्क व स्वैच्छिक राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रही है. इसका उद्देश्य देश पर ग्रभाशय ग्रीवा कैंसर के बढ़ते बोझ को कम करना है.

मिलन युद्धाभ्यास: भारत की नौसेना शक्ति का प्रदर्शन

अरुणेन्द्र नाथ वर्मा
विंग कमांडर (सेवानिवृत्त)
arungraphicsverma@gmail.com

सुरक्षित, मुक्त और संतुलित समुद्री क्षेत्र को वैश्विक शांति और समृद्धि की कुंजी मानकर भारत विभिन्न देशों के साथ समय-समय पर सैन्य अभ्यास आयोजित करता आया है और ऐसे आयोजनों में भाग लेता आया है. ऐसे युद्धाभ्यासों की शृंखला में जुड़ने वाला अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास है विशाखापट्टनम में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास 'मिलन.' यह अभ्यास केवल भारत की नौसैन्य क्षमता और शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच आपसी विश्वास, सहयोग और समन्वय बढ़ाना है.

मध्य युग से आज तक सैन्य और आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए समुद्र की लहरों पर एकाधिपत्य जमाने का प्रयत्न करते आये हैं. हालांकि, साम्राज्यवाद का अब अंत हो चुका है, पर आज भी वैश्विक अर्थव्यवस्था सुदूर देशों के बीच फैले महासागरों में निरापद वाणिज्य पर टिकी हुई है. सुदूर दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला से भारत में खनिज, तेल का आयात या वियतनाम से अमेरिकी नागरिकों के लिए वस्त्र-परिधान का निर्यात, आज की अर्थव्यवस्था के ये दो छोटे-से नमूने सिद्ध करते हैं कि विश्व के सागर-महासागर दुनिया के समस्त देशों के साझा संसाधन और साझा पूंजी के रूप में देखे जाने चाहिए. भारत मानता है कि इक्कीसवीं सदी की चुनौतियों का समाधान एकाकी नहीं, सामूहिक प्रयासों में निहित है. सुरक्षित, मुक्त और संतुलित समुद्री क्षेत्र को वैश्विक शांति और समृद्धि की कुंजी मानकर भारत विभिन्न देशों के साथ समय-समय पर सैन्य अभ्यास आयोजित करता आया है और ऐसे आयोजनों में भाग लेता आया है.

हाल के वर्षों में मित्र देशों के साथ किये गये उल्लेखनीय युद्धाभ्यासों में प्रमुख था, मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास. वर्ष 1992 में अमेरिका और भारत के संयुक्त प्रयास से आरंभ होने वाले इस अभ्यास में जापान और ऑस्ट्रेलिया भी जुड़कर अब क्वाड नाम से जाने जाते हैं. इसके अतिरिक्त, वरुण और गरुड़-25 (भारत-फ्रांस की नौसेनाओं का), इंद्र (रूस-भारत की तीनों सेनाओं का) और समुद्र शक्ति (भारत-इंडोनेशिया का) कुछ अन्य उदाहरण हैं. ऐसे युद्धाभ्यासों की शृंखला में जुड़ने वाला अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास है 15 फरवरी से 25 फरवरी तक विशाखापट्टनम में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास 'मिलन.' इस विशाल अभ्यास में शामिल 74 देशों की नौसेनाओं के 84 युद्धपोतों में भारतीय विमानवाहक पोत विक्रांत और पनडुब्बियों को मिलाकर 19 भारतीय नौसैनिक पोत थे. इन पोतों के कार्यकलाप में कठिन समुद्री युद्धाभ्यास, पनडुब्बी रोधी और हवाई रोधी अभ्यास शामिल हैं. 'मिलन' अभ्यास केवल भारत की नौसैन्य क्षमता और शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि इस सम्मिलित युद्धाभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच आपसी विश्वास, सहयोग और समन्वय बढ़ाना है. एक तरफ इसका तत्काल प्रभाव उन्नत युद्ध कौशल और बेहतर सामरिक क्षमता के रूप में दिखेगा, तो दूसरी तरफ इसका दीर्घकालीन उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा, नियम आधारित व्यवस्था और परस्पर विश्वास बढ़ाना है.

भारत आज अमेरिका, चीन और रूस के बाद विश्व की चौथी बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में जाना जाता है. उसके साथ अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ईरान जैसे देशों की नौसेनाओं का यह संयुक्त अभ्यास हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्र ही नहीं, पूरे विश्व के समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति की जीवनरेखा बनकर उभरेगा. समुद्री मार्गों की सुरक्षा, सभी देशों की साझा चिंता है. इसी पृष्ठभूमि में यह अभ्यास स्पष्ट करता है कि समुद्री डकैती, तस्करी, आतंकवाद और आपदाओं जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय सहयोग अनिवार्य है. वर्ष 2024 में सोमालिया के जिन समुद्री लुटेरों ने ईरानी वाणिज्य पोतों पर कब्जा कर 19 पाकिस्तानी क्रू को बंदी बना लिया था, उन्हें भारतीय नौसेना पोत 'सुमित्रा' ने समर्पण करने के लिए मजबूर किया था. इसी तरह, भारतीय नौसेना पोत 'कोलकाता' भी सोमालिया के समुद्री लुटेरों पर भारी पड़ा था. इस तरह भारत, सागर में अंतरराष्ट्रीय सहयोग का वर्षों से प्रशंसनीय प्रदर्शन करता आया है. यह युद्धाभ्यास भारत की बढ़ती समुद्री भूमिका को भी रेखांकित करता है. एक ओर भारत एक विश्वसनीय सुरक्षा भागीदार के रूप में उभर रहा है, जहां उसकी नौसेना न केवल संचालन क्षमता दिखाती है, बल्कि समन्वय, प्रशिक्षण और मानवीय सहायता के क्षेत्रों में भी नेतृत्व प्रस्तुत करती है. दूसरी ओर है चीन का विस्तारवादी रुझान. दक्षिण चीन सागर में चीन के समुद्री दावों, कृत्रिम द्वीपों और सैन्य उपस्थिति से झांकती आक्रामकता पूरे हिंद-प्रशांत में चिंता का विषय बनी हुई है. एक अरसे से ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेने की चीन की अभिलाषा अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण पूरी नहीं हो सकी है. किंतु समय-समय पर चीनी नौसेना और वायुसेना द्वारा ताइवान के इर्द-गिर्द पैदा किये गये आतंक के माहौल ने जापान को भी आशंकित कर रखा है. अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार, फिलीपींस से 200 मील दूर तक उसके एक्सटेंडेड इकोनॉमिक जोन में आने वाले क्षेत्र में चीनी नौसेना और तटरक्षक युद्धपोतों ने हाल में ही फिलीपींस की एक जहाज को टक्कर मार क्षतिग्रस्त कर दिया. चीन की इस आक्रामक हरकत के कारण फिलीपींस को अमेरिका के साथ एक सुरक्षा संधि का सहारा लेना पड़ा.

हिंद और प्रशांत महासागर में भी चीन आर्थिक कूटनीति के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है. पड़ोसी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाहों और संपर्क परियोजनाओं के जरिये चीन की रणनीतिक उपस्थिति प्रतिस्पर्धा को जन्म दे रही है. चीन के एक्सिम बैंक ने श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह बनाने के लिए भारी कर्ज देकर श्रीलंका को इस बंदरगाह को 99 वर्षों के लिए चीन को लीज पर देने के लिए मजबूर कर दिया. श्रीलंका के आग्रह के बावजूद, कि वह हंबनटोटा को चीनी सैन्य शक्ति के उपयोग में नहीं आने देगा, चीन के मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री शोध करने वाले जहाजों की उपस्थिति से आज यह बंदरगाह हिंद महासागर में चीन की सैन्य शक्ति जमाने वाला पहला सशक्त चरण बन चुका है. चीन ने होर्मुज जलडमरूमध्य में भी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की है. तेल आपूर्ति के इस संकरे लेकिन प्रमुख मार्ग से भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है. फारस की खाड़ी में अरब सागर और ईरान के तटीय क्षेत्र के निकट ग्वादर बंदरगाह के निर्माण और विकास के पीछे चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और नौसेना के उपयोग के लिए समुचित प्रबंध करने की मंशा ही है. ऊर्जा और व्यापार के प्रमुख मार्गों पर किसी एक देश का बढ़ता नियंत्रण क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित करता है. ऐसे में बहुराष्ट्रीय अभ्यास यह संदेश देते हैं कि समुद्र किसी एक शक्ति का क्षेत्र नहीं, साझा धरोहर हैं, जहां नियम आधारित व्यवस्था का सम्मान आवश्यक है. भारत अन्य देशों के साथ समावेशी और पारदर्शी विकास मॉडल अपनाकर और सहयोग कर चीनी प्रतिस्पर्धा पर भारी पड़ सकता है. विशाखापट्टनम में नौसैनिक शक्तियों के बीच सहयोग द्वारा संतुलन स्थापित करने के इस प्रशंसनीय प्रयोग को शक्ति प्रदर्शन की आक्रामक अभिव्यक्ति समझना गलत होगा. यह 74 देशों की नौसेनाओं के बीच मैत्रीपूर्ण साझेदारी और सहयोग का प्रशंसनीय प्रयत्न है. **(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

लुटियंस दिल्ली में एक स्मारक अनाम मजदूरों का हो

विवेक शुक्ला
वरिष्ठ पत्रकार
vivekshukladelhi@gmail.com

राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की मूर्ति हटाकर राजगोपालाचारी की मूर्ति लगायी गयी है. यह कदम औपनिवेशिक सोच से बाहर निकलकर भारतीय विरासत को सम्मान देने की दिशा में एक संकेत माना जा रहा है. यहां प्रश्न उठता है कि क्या हम उन अज्ञात मजदूरों, संगतराशों और ठेकेदारों की याद में एक स्मारक नहीं बना सकते, जो इन लाखों हाथों को समर्पित हो, जिन्होंने नयी दिल्ली को खड़ा किया.

राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की मूर्ति हटाकर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की मूर्ति लगायी गयी है. यह कदम औपनिवेशिक सोच से बाहर निकलकर भारतीय विरासत को सम्मान देने की दिशा में एक संकेत माना जा रहा है. पर केवल प्रतीक बदल देने से बात पूरी नहीं हो जाती. हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए, जिन्होंने इन ऐतिहासिक भवनों को अपने हाथों से बनाया. नयी दिल्ली का निर्माण 1911 से 1931 के बीच हुआ, जब अंग्रेजों ने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने का निर्णय किया. उस समय लुटियंस मुख्य वास्तुकार थे और उनके साथ हर्बर्ट बेकर भी काम कर रहे थे. पर इन भव्य इमारतों को खड़ा करने का असली काम तो हजारों भारतीय मजदूरों ने किया था. निर्माण के दौरान करीब 30,000 श्रमिक दिन-रात मेहनत कर रहे थे, जिनमें सैकड़ों कुशल संगतराश भी शामिल थे.

ये मजदूर ज्यादातर राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा जैसे क्षेत्रों से आये थे. वे अपने परिवारों के साथ गांव छोड़कर दिल्ली पहुंचे और वहां अस्थायी बस्तियों में रहने लगे. उनकी मजदूरी बहुत कम थी- पुरुषों को एक रुपया रोज और महिलाओं को आधा रुपया, यानी अठन्नी. कम मेहनताना होने के बावजूद उन्होंने पूरी लगन से काम किया और भव्य इमारतों को आकार दिया. पत्थरों पर बारीक नक्काशी करने वाले कई संगतराश आगरा, मिर्जापुर और भरतपुर से आये थे. उनके पूर्वज ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसे ऐतिहासिक स्मारकों के निर्माण में योगदान दे चुके थे. नयी दिल्ली की शान केवल मानचित्रों से नहीं, बल्कि इन मेहनतकश हाथों की मेहनत से बनी है. कम मजदूरी के बावजूद इन सीधे-सादे लोगों ने दिन-रात अथक मेहनत की. यहां काम कर रहे संगतराश पत्थरों पर नक्काशी, जालियां और बारीक काम में निपुण थे. राष्ट्रपति भवन के भव्य स्तंभ, संसद भवन की गोलाकार संरचना, नॉर्थ-साउथ ब्लॉक की शानदार नक्काशी- सबमें इन कारीगरों की कला और कौशल साफ दिखाई देता है. इन कारीगरों ने लाखों ईंटों और बड़ी मात्रा में पत्थरों से शानदार इमारतें खड़ी की थीं.

इन भवनों के निर्माण में भारतीय ठेकेदारों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी. संसद भवन (तब काउंसिल हाउस या लेजिस्लेटिव चैंबर्स) के मुख्य ठेकेदार लक्ष्मण दास सिंध के थे. खुशवंत सिंह ने उन्हें 'सच्चाई और नेकनीयती की मिसाल' बताया है. लक्ष्मण दास ने कभी घटिया सामग्री इस्तेमाल नहीं की, मजदूरों को समय पर वेतन दिया और टैक्स में कभी कोई चोरी नहीं की. खुशवंत सिंह ने जितनी प्रशंसा लक्ष्मण दास की की है, उतनी प्रशंसा अपने पिता सर शोभा सिंह या अन्य ठेकेदारों की नहीं की, जबकि शोभा सिंह ने भी नयी दिल्ली की कई इमारतों का निर्माण किया था. लक्ष्मण दास मजदूरों के साथ घुल-मिलकर रहते थे, उनकी परेशानियां समझते थे. संसद भवन के उद्घाटन के समय लक्ष्मण दास मौजूद थे. उनका मिशन पूरा हो चुका था, इसका उन्हें संतोष था. पर उन्होंने नयी दिल्ली में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लिया. वह सिंध भी नहीं लौटे, हरिद्वार जाकर साधु बन गये, वहीं उनका निधन हुआ. यह उनकी सादगी, मानवीयता और निःस्वार्थ सेवा का जीता-जागता प्रमाण है. समय बदल गया है. आज राजस्थान से दिल्ली में मजदूर कम आते हैं. जो तब आये थे, वे दिल्ली का अभिन्न अंग बन गये. उनके वंशज अब विभिन्न क्षेत्रों में सफल हैं- कई सामाजिक-आर्थिक रूप से मजबूत हैं, यहां तक कि मंत्री पद तक पहुंचे. जैसे, मदन लाल खुराना सरकार में सुरेंद्र रातावाल मंत्री थे, जिनके दादा और रिश्तेदारों ने संसद भवन बनाया था. रातावाल को इस विरासत पर गर्व है. आने वाली पीढ़ियां भी नयी ऊंचाइयां छू रही हैं और छुएंगी. राजधानी में आजकल सेंट्रल विस्टा और अन्य परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हजारों मजदूर आये हुए हैं. ये एक प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद अगले प्रोजेक्ट से जुड़ जाते हैं. ये ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ से हैं. दिल्ली के पुराने लोगों को याद होगा कि यहां पर 1982 के एशियाई खेलों के समय बहुत बड़ी तादाद में मजदूर आये थे. तब बिहार से काफी तादाद में मजदूर आये थे. अब बिहार से आने वाले मजदूरों की संख्या निश्चित रूप से बहुत कम हुई है.

अब आते हैं मूल प्रश्न पर. क्या हम उन अज्ञात मजदूरों, संगतराशों और ठेकेदारों, जैसे लक्ष्मण दास, की याद में एक स्मारक नहीं बना सकते? राष्ट्रपति भवन या संसद भवन के आसपास, या किसी सार्वजनिक स्थान पर, जो इन लाखों हाथों को समर्पित हो. यह सिर्फ पत्थर नहीं होगा, बल्कि उन मेहनतकशों का प्रतीक होगा जिन्होंने नयी दिल्ली को खड़ा किया. लुटियंस की मूर्ति हटाना औपनिवेशिक प्रतीकों से मुक्ति है, पर असली मुक्ति तब होगी जब हम उन भारतीयों को याद करेंगे, जिन्होंने असल में यह शहर बनाया. ऐसा स्मारक बनाने से इतिहास के उन पन्नों को सम्मान मिलेगा, जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं. आने वाली पीढ़ियां जानेंगी कि राजधानी की भव्यता सिर्फ डिजाइन से नहीं, उन मजदूरों के पसीने, बलिदान और कौशल से बनी है. सरकार, समाज और इतिहासकार मिलकर इस दिशा में कदम उठायें. यह हमारा नैतिक दायित्व है, क्योंकि सच्ची आजादी तब पूरी होती है, जब हम अपने असली नायकों को श्रद्धांजलि देते हैं. **(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

देश दुनिया

ट्रंप के ईरान पर हमले की धमकी से पूरे मध्य-पूर्व में तनाव व्याप्त

ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दबाव वाली रणनीति की आलोचना की है. गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में अपने सबसे लंबे स्टेट ऑफ यूनियन भाषण में ईरान का जिक्र करते हुए कहा कि 'ईरान ऐसी मिसाइल विकसित कर चुका है, जो यूरोप और हमारे विदेशी अड्डों को खतरे में डाल सकती है और वह ऐसी मिसाइल बनाने पर भी काम कर रहा है, जो जल्द ही अमेरिका तक पहुंच सकती है.' अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि ईरान को चेतावनी दी जा चुकी है कि वह भविष्य में अपने हथियार कार्यक्रम को बहाल न करे और खास तौर पर परमाणु कार्यक्रम को, पर इसके बावजूद ईरान ऐसा करना जारी रखे हुए है. ट्रंप की मानें, तो ईरान के हालिया प्रदर्शनों में कम से कम 32,000 लोग मारे गये हैं. वहीं अमेरिका स्थित एक मानवाधिकार संगठन ने इस संख्या को 7,000 से अधिक बताया है. जबकि तेहरान का कहना है कि 21 जनवरी तक हिंसा में 3,117 लोग मारे जा चुके हैं. ट्रंप के बयान के एक दिन बाद ही तेहरान ने ट्रंप के इस दावे को बड़ा झूठ करार दिया. जिनेवा में अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत कर रहे ईरान ने यह भी कहा कि समझौता सम्मानजनक कूटनीति से ही निकलेगा. दरअसल, तेहरान पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने इस वक्त मध्य-पूर्व में बड़े पैमाने पर अमेरिकी सेना तैनात कर रखी है. कई दशकों बाद यह पहला अवसर है, जब अमेरिका ने दो विमानवाहक युद्धपोतों के साथ इतने बड़े स्तर पर वहां सैन्य तैनाती की है. इसके साथ ही, ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरान के साथ बातचीत नाकाम रही, तो वह उस पर हमला कर सकते हैं. इन धमकियों से ईरान ही नहीं, बल्कि पूरे मध्य-पूर्व में तनाव व्याप्त है. उधर ईरान का कहना है कि वह अमेरिकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा और मध्य-पूर्व में अमेरिकी सेना के ठिकानों को निशाना बनायेगा. **-ओंकार सिंह जनौटी व आदर्श शर्मा**

Deutsche Welle

बोधि वृक्ष

अपूर्णता सच बताती है

परिपूर्ण बनने की चाह बहुत से लोगों को गुस्सैल बना देती है. इससे ऐसे लोगों की सामाजिक और मानसिक स्थिति दयनीय हो जाती है. अगर आप भी परिपूर्णता की चाह में भटक रहे हैं, या भटकेंगे, तो एक समय बाद आप भी गुस्सैल लोगों की श्रेणी में शामिल हो जायेंगे. अज्ञानता की स्थिति में अधूरापन या अपूर्णता ही प्राकृतिक है, जबकि परिपूर्णता के लिए काफी मेहनत करने की आवश्यकता होती है. बुद्धिमानी या ज्ञानोदय की स्थिति में अपूर्णता आपकी मेहनत का परिणाम है, जबकि परिपूर्णता एक अनिवार्यता है, जिसे आप नकार नहीं सकते. वैराग्य की स्थिति में आप गैर जरूरी चीजों की भी परिपूर्णता या उत्कृष्टता के साथ देखभाल कर सकते हैं. जब हम दिल से प्रसन्न होते हैं, तब हम कभी भी परिपूर्णता के ऊपर ध्यान नहीं देते. परंतु यदि आप परिपूर्णता की तलाश में हैं, तो आप आनंद के स्रोतों को नहीं ढूंढ़ रहे हैं. आनंद क्या है? आनंद इस बात का अहसास है कि बुद्धिमानी से दूर नहीं जाया जा सकता. यह दुनिया ऊपरी तौर पर भले ही अधूरी या अपूर्ण नजर आती हो, परंतु गहराई में जाने पर यह पूर्ण नजर आती है. यानी, यदि आप इसकी गहराई में जायेंगे, तो यह आपको पूर्ण लगेगी. सच तो यह है कि पूर्णता छिपाती है और अपूर्णता वास्तविक बात सामने रखती है. कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति केवल ऊपरी हालात को नहीं देखता, बल्कि गहराई में जाकर चीजों को समझता है. चीजें धुंधली नहीं होतीं, धुंधला आपका दृष्टिकोण होता है. इस बात को समझिए और स्वाभाविक रहने की कोशिश कीजिए. इस दुनिया में कुछ भी, कोई भी ऐसा नहीं है, जो हर समय परिपूर्ण हो. यहां तक कि बहुत सोच-समझकर, अच्छी नीयत के साथ किया गया कार्य भी परिपूर्ण नहीं हो सकता. उसमें भी कोई न कोई त्रुटि होती ही है. हमारे मस्तिष्क की यह प्रवृत्ति ही है कि वह अपूर्णता, कमियों और त्रुटियों को आसानी से पकड़ लेती है और अंत में इस प्रक्रिया के तहत हम अपने मन-मस्तिष्क को त्रुटिपूर्ण कर बैठते हैं. ऐसी स्थिति में यह अनिवार्य हो जाता है कि हम इस प्रक्रिया से बाहर निकलकर भीतरी तौर पर मजबूत और साहसी बनें. **-श्री श्री रवि शंकर**

कुछ अलग

'बूंग' भारतीय फिल्म है, ये अपने ही लोग हैं

प्रीति सिंह परिहार
कॉपी राइटर, प्रभात खबर
preetisingh.parihar@prabhatkhabar.in

फरवरी के इन आखिरी दिनों में पूर्वोत्तर भारत दो अहम कारणों से चर्चा में है. एक में भारत को वैश्विक पटल पर गर्व और खुशी का क्षण दिलाने का जिक्र है, तो दूसरे में देश की राजधानी में पूर्वोत्तर भारत के लोगों के साथ घटित शर्मसार करनेवाला व्यवहार है. पूर्वोत्तर के लोगों के साथ उत्तर भारत में बरते गये नस्लवादी रवैये का यह कोई पहला मामला नहीं, यह बस पुनरावृत्ति है, उस पूर्वाग्रह की, जो अपने ही देश के एक हिस्से के लोगों के प्रति अपने ही देश के एक और हिस्से के रहवासियों ने बना रखा है. यह दरअसल, भारत की बहुलतावादी संस्कृति का खुद भारतीयों द्वारा किया गया अपमान भी है.

जिस पूर्वोत्तर के लोगों पर चिंकी, चाइनीज, मोमो जैसी टिप्पणियां की जाती हैं और अक्सर यह सवाल पूछा जाता है, 'क्या तुम भारत से हो?' और उनकी भाषा का मजाक बनाया जाता है, क्या आपने कभी सोचा है कि वह पूर्वोत्तर कैसा है? नहीं सोचा, नहीं जानते हैं, तो कृपया गूगल कर लीजिए. गूगल पर पूर्वोत्तर भारत लिखेंगे, तो इतनी खूबसूरत तस्वीरें खुलेंगी कि यकीन करना मुश्किल हो जायेगा, क्या यह भारत ही है! इस पूर्वोत्तर भारत में सात बहनें (राज्य) अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा और एक भाई सिक्किम शामिल है. यह भारत का बेहद सुंदर, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा है और 200 से अधिक जनजातियों एवं बोलियों का घर है. पूर्वोत्तर भारत दुनिया के प्रमुख 'बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स' में से एक है. सिक्किम से दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा साफ देखी जा सकती हैं. यहां ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदी है और दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान 'मासिनराम' भी. असम का काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है और मेघालय के चेरापूंजी और मावलिननॉन्ग में पाये जाने वाले 'लिविंग रूट ब्रिजेस' दुनिया के लिए इंजीनियरिंग का एक अजूबा हैं.

फिलहाल पूर्वोत्तर भारत ने पूरे भारत को खुशी और गर्व की जो वजह दी है, उस पर आते हैं. पूर्वोत्तर भारत की एक फिल्म ने भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर पहुंचाया है. मणिपुरी भाषा की फिल्म 'बूंग' ने सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म की श्रेणी में 'बाफ्टा' पुरस्कार जीता है. लंदन में आयोजित 79वें बाफ्टा पुरस्कार में इस श्रेणी में यह सम्मान हासिल करने वाली यह पहली भारतीय फिल्म बन गयी है. इसकी फिल्मकार लक्ष्मीप्रिया देवी मूल रूप से मणिपुर की हैं और यह उनकी पहली फीचर फिल्म है. फिल्म 'बूंग' एक छोटे बच्चे के माध्यम से पारिवारिक प्रेम और मणिपुर की सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों को बयां करती है. जी हां वही मणिपुर, जो आधिकारिक तौर पर भारत का एक राज्य है.

आपके पत्र

भारत टैक्सी से यात्रियों को फायदा

सरकार ने देश की पहली सरकार समर्थित भारत टैक्सी सेवा शुरू की गयी है. इसका उद्देश्य टैक्सी चालकों को सशक्त बनाना और यात्रियों को किफायती सेवा देना है. यह डिजिटल प्लेटफॉर्म मोबाइल एप के माध्यम से यात्रियों को निजी ड्राइवरों-अब 'सारथी'-से जोड़ता है. नामकरण का अर्थ है, जैसे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन के सारथी थे, वैसे ही ड्राइवरों को समाज में सम्मान और गरिमा मिल सके. अमूल, इफ्को, नेफेड और कृभको जैसी सहकारी संस्थाओं के समर्थन से संचालित यह सेवा जनता की सुविधा पर केंद्रित है.

युगल किशोर राही, छपरा

शहरी आवास योजना में गड़बड़ी

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का मकसद गरीबों को पक्का मकान प्रदान करना था, लेकिन रामनगर नगर परिषद के 27 वार्डों में इस योजना में खुलेआम धांधली सामने आयी है. गरीब परिवार लगातार कार्यालय का चक्कर काटते रह जाते हैं, जबकि अमीर इस योजना का लाभ ले रहे हैं. पहले से बने मकानों पर भी राशि का आवंटन कर दिया गया, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं. यदि जिला प्रशासन 2016 से अब तक की जांच कराये, तो इस घोटाले की पोल खुल सकती है.

लव राज, पश्चिम चंपारण

सिटी बाइट्स

टूरिस्ट बस ने ट्रक में मारी टक्कर, एक की मौत

डेहरी (रोहतास). डेहरी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एनएच 17 पर जवाहर लाल नेहरू कॉलेज के पास गुरुवार की अहले सुबह तमिलनाडु के यात्रियों को वाराणसी से गया जी के लिए निकली ट्रैवलर बस ने पीछे से ट्रक में टक्कर मार दी. इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गयी. वहीं, ट्रेवलर में सवार 19 यात्री जख्मी हो गये. इस संबंध में थानाध्यक्ष नितेश कुमार ने बताया कि हादसे में तमिलनाडु राज्य के काजीपुरम 24 अब्राहम स्ट्रीट आदमबाकम निवासी 83 वर्षीय रामो स्वामी की मौत घटनास्थल पर ही हो गयी थी.

लोन दिलाने के नाम पर महिलाओं से ठगी

लखीसराय. लोन दिलाने के नाम पर दर्जनों महिलाओं से पांच-पांच हजार रुपये की ठगी कर ली. ठग ने तीन दिन में डेढ़ लाख ऋण दिलाने के नाम प्रति महिलाओं से पांच-पांच हजार रुपये की ठगी कर ली. महिलाओं को नन बैंकिंग कर्मी बताकर पांच हजार प्रत्येक महिलाओं से ले लिया गया व मोबाइल को बंद कर पैसा लेकर फरार हो गया.

सड़क हादसे में दो चचेरे भाइयों की गयी जान

बगहा. नदी घाटी थाना क्षेत्र के नौनहा ढाला के समीप तेज रफ़्तार वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार दो चचेरे भाइयों की मौत हो गयी. मृतकों की पहचान दौनाहा निवासी शंभू यादव के 32 वर्षीय पुत्र ब्यास यादव तथा भिखु यादव 24 वर्षीय पुत्र श्याम यादव के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि दोनों बहन के यहां शादी समारोह में शामिल होने गये थे.

वीआइपी के प्रखंड अध्यक्ष समेत तीन गिरफ्तार

चिरैया (पूर्वी चंपारण). हत्या के प्रयास मामले में वीआइपी प्रखंड अध्यक्ष सहित तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. गिरफ्तार किये गये संतोष सहनी वीआइपी के चिरैया प्रखंड इकाई का अध्यक्ष बताया गया है. वही पन्नालाल राय और सोनेलाल राय किसान हैं. थानाध्यक्ष गोपाल कुमार ने बताया कि भूमि विवाद को लेकर गोढ़ीया गांव निवासी संतोष सहनी और मनीष सहनी के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शिकारगंज पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है.

पटाखे से लगी आग जिंदा जला पशुपालक

नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण). प्रखंड के चमुआ गांव में बुधवार की देर रात बारात की आतिशबाजी से लगी आग से पांच घर जलकर राख हो गये, जबकि तीन मवेशी झुलसकर मर गये. वहीं, पशुपालक धुरंदर यादव की जिंदा जलकर मौत हो गयी. घुरंघर आगलगी के दौरान मवेशियों को बचाने का प्रयास कर रहे थे. इसी दौरान वह आग में घिर गये और बुरी तरह से झुलस गये.

पुलिस ने चिता से बरामद की अधजली लाश

बहेड़ी (दरभंगा). शिवराम निवासी 38 वर्षीय युवक बबलू लाल देव की हत्या कर शव को चुपके से जलाने का मामला सामने आया है. सूचना मिलने पर पुलिस शमशान पहुंच गयी और अधजली लाश को कब्जे में ले लिया. युवक के बहनोई राजेश लाल देव ने थाने में शिकायत की थी. थानाध्यक्ष ने बताया कि एक आरोपित अशोक लाल देव को गिरफ्तार कर लिया गया है.

सीएम से मिलकर भेंट किया सोमनाथ का प्रसाद

पटना. बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव छोटू सिंह ने सपरिवार गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर भगवान महादेव की विशेष पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तम स्वास्थ्य और बिहार की निरंतर प्रगति एवं समृद्धि के लिए मंगलकामना की.पटना वापसी के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर नीतीश कुमार से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें सोमनाथ धाम का प्रसाद भेंट किया.

मखाना, डेयरी से बढ़ेगी किसानों की आय : मधुरेंदु

पटना.जदयू मीडिया पैनलिस्ट डॉ मधुरेंदु पांडेय ने सोशल मीडिया संवाद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की कृषि नीति अब केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रही. बल्कि, किसानों की आय में निरंतर वृद्धि, कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार, आधुनिक तकनीक के उपयोग, जैविक खेती और मूल्य संवर्धन पर केंद्रित है.

बिहार प्रशासनिक सेवा के तीन अफसरों की तैनाती

पटना. राज्य सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के तीन पदाधिकारियों की नयी तैनाती की है. यह तीनों पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे. पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहीं रश्मि सिन्हा को सिविल नगर विमानन विभाग में उपसचिव, अविनाश कुमार को उद्योग विभाग मे उपसचिव और शिशिर कुमार मिश्र को उच्च शिक्षा विभाग में उपसचिव बनाया गया है.

कैमूर. एक आरोपित के बेल पर छूटने की खुशी में चल रही थी पार्टी

डांस व शराब पार्टी रोकने पहुंची पुलिस पर फायरिंग, ग्रामीण को लगी गोली

- डीएसपी-एसडीओ के समझाने पर छह घंटे बाद हटा जाम, 50 अज्ञात समेत 78 लोगों पर केस दर्ज

प्रतिनिधि, मोहनिया (कैमूर)

मामले की जांच करने पहुचे एसडीओ और डीएसपी.

स्थानीय नगर पंचायत के वार्ड संख्या आठ (कझार घाट टोला) में बुधवार की आधी शराब व हेरोइन तस्करी के आरोपित गोरख मल्लाह को जेल से मिली बेल की खुशी में चल रही शराब और डांस पार्टी चल रही थी. सूचना पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गयी. पुलिस टीम पर ईंट-पत्थरों से हमला और फायरिंग की गयी. हालात बेकाबू होने पर पुलिस को भी बचाव में जवाबी फायरिंग करनी पड़ी. इस घटना में कमलेश नामक एक ग्रामीण को गोली लगी है, जिसे गंभीर हालत में वाराणसी रेफर किया गया है. वहीं, रोड़ेबाजी में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज कुदरा पीएचसी में कराया गया. रात की घटना के विरोध में गुरुवार सुबह करीब छह बजे से सैकड़ों ग्रामीणों ने बांस-बल्ली लगाकर कुदरा-भभुआ मुख्य मार्ग को जाम कर दिया. प्रदर्शन में महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे. करीब छह घंटे तक चले इस जाम के कारण सैकड़ों मालवाहक और यात्री वाहन सड़क पर फंसे रहे. बाद में मौके पर पहुंचे एसडीओ और डीएसपी के आश्वासन के बाद जाम खत्म हुआ. ग्रामीणों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाये हैं. फिलहाल, पुलिस पर पथराव और फायरिंग के आरोप में 28 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इलाके में तनाव को देखते हुए चौकसी बरती जा रही है.

इधर, एसपी हरिमोहन शुक्ला ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट का आरोपित गोरख मल्लाह जेल से छूटा है. उसके आने के खुशी में गांव में नाच की व्यवस्था है. थानाध्यक्ष गश्ती टीम के साथ गांव पहुंचे. वहां काफी भीड़ थी. थानाध्यक्ष लौटने लगे तो लोग ईंट-पत्थर चलाने लगे. पुलिस और पब्लिक के वाहन क्षतिग्रस्त कर दिये गये. पुलिस की तरफ से चार राउंड फायरिंग की गयी. ग्रामीण की ओर से भी फायरिंग हुई. इसमें एक व्यक्ति को गोली लगी. उसने पुलिस को बताया कि गोली किसकी तरफ से लगी है, नहीं देख पाये थे.

बांका : पेट्रोल डाल 50 वर्षीया नेत्रहीन मां को जिंदा जलाया

पुलिस ने आरोपित बेटे को किया गिरफ्तार

मृत महिला का फाइल फोटो.

बौंसी (बांका). बौंसी थाना क्षेत्र के पोरायं गांव में बुधवार की शाम बेटे ने 50 वर्षीया नेत्रहीन मां पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. इससे वह गंभीर रूप से झुलसी गयी, जिसकी मौत मायागंज अस्पताल भागलपुर में मौत हुई. मृतका प्रमोद मंडल की पत्नी उर्मिला देवी थी. सूचना मिलने पर बौंसी पुलिस बुधवार को मौके पर पहुंची थी. आक्रोशित ग्रामीण आरोपित पुत्र की पिटाई करने ही वाले थे कि पुलिस ने हस्तक्षेप कर उसे बचाया और हिरासत में ले लिया. ग्रामीण के अनुसार, मृतका के बड़े पुत्र गोपी मंडल ने पहले मां के शरीर पर प्लास्टिक के बोरे लपेटा और फिर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया. घर में पानी की बोतल में पेट्रोल रखा हुआ था. ग्रामीणों ने शोर मचाया, लेकिन आग की तेज लपटों के कारण कोई भी महिला को बचाने की हिम्मत नहीं जुटा सका.

नालंदा : बारात में डांस करते समय महिला को टच करने पर दुकानदार को पीटकर मार डाला

बिहारशरीफ (नालंदा). दीपनगर थाने के नदिऔना गांव में बुधवार की शाम बरात में महिला को गलती से टच करने पर बदमाशों ने दुकानदार की पीट-पीटकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान उपेंद्र मांझी के रूप में की गयी है. उपेंद्र मांझी के पुत्र गुलशन कुमार ने बताया कि गांव में ही धाम से लौटकर अशोक मांझी के बेटे की बारात आयी थी, जिसमें गाना बज रहा था. उसके पिता बारात से आए और घर में बाइक लगाकर नाचने चले गये, जहां डीजे की धुन पर नाचने के दौरान गांव के ही हरिमुनि मांझी की बहू को गलती से टच कर दिया. इसके बाद हरिमुनि मांझी व उसके साथियों ने घर से खींच कर पिटाई कर दी.

राजकीय सम्मान के साथ पूर्व मंत्री का हुआ अंतिम संस्कार

बगहा (पश्चिम चंपारण). बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व बगहा के कद्दावर नेता पूर्णमासी राम को गुरुवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गयी. उनका पार्थिव शरीर बगहा स्थित नरईपुर पहुंचने के बाद गंडक नदी के तट पर अवस्थित नारायणपुर घाट पर लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम किया गया. इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों,पुलिस पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व आम जनता की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. गौरतलब है कि बुधवार की शाम पटना में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया शोक

पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि पूर्णमासी राम एक कुशल राजनेता एवं समाजसेवी थे. वे 1990 से लगातार पांच बार तक बगहा के विधायक रह चुके थे. वे गोपालगंज लोकसभा सीट से सांसद भी रहे थे. वे मृदुभाषी एवं सरल स्वभाव के व्यक्ति थे. पूर्णमासी राम के निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है.

10 हजार घूस लेते पटना के धनरूआ का रहनेवाला पंचायत सचिव गिरफ्तार

करगहर (रोहतास). निगरानी की टीम ने गुरुवार को करगहर प्रखंड के पंचायत सचिव ऋतु रंजन पांडेय को 10 हजार रुपये घूस लेते गिरफ्तार कर लिया. आरोपित पंचायत सचिव मूल रूप से पटना जिले के धनरूआ (थाना नदवां, प्रखंड नयी हवेली) निवासी जगदीश पांडेय का पुत्र है. आरोपित ऋतु रंजन पांडेय के पास प्रखंड की दो पंचायतों, ठोरसन और रीवां का प्रभार था. वह ठोरसन पंचायत के वार्ड 12 में नल जल योजना के अनुरक्षक धर्मेंद्र पटेल से मानदेय भुगतान करने के एवज में 12 हजार रुपये रिश्वत मांगी. उसने इसकी शिकायत निगरानी विभाग में की.

दुल्हन को गोली मारनेवाला दीनबंधू पिस्टल के साथ धराया

गिरफ्तार आरोपित युवक.

चौसा (बक्सर). मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चौसा बाजार में मंगलवार की जयमाला के समय दुल्हन को सिरफिरे युवक ने गोली मार दी थी. पुलिस ने आरोपित युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, घायल युवती वाराणसी ट्रामा सेंटर में जीवन और मौत से जूझ रही है. बुधवार को एसपी शुभम आर्य ने बताया कि दीनबंधु चौधरी को समाहरणालय बक्सर के पास से गिरफ्तार किया गया है. आरोपित ने स्वीकार किया कि प्रेम प्रसंग को लेकर उसने युवती को गोली मारी है इसके पास से देसी पिस्टल और एक खोखा बरामद किया गया है. गौरतलब है कि मंगलवार की रात दीनबन्धु ने वरमाला के दौरान स्टेज के पास से दुल्हन आरती कुमारी को गोली मार दी थी. उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है.

पत्रकार हत्याकांड में दो दोषियों को उम्रकैद

अररिया. जिला व अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत लगभग ढाई वर्ष पुराने त पत्रकार विमल कुमार हत्याकांड में रानीगंज थाना क्षेत्र के कोसकापुर उत्तर के र माधव कुमार यादव उर्फ लाट साहब व मनुलालाहपट्टी वार्ड संख्या दो स्थित भरना निवासी विपिन यादव को उम्रकैद की सजा सुनायी है. दोनों पर 50- 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं, शैशव कुमार, उमेश यादव, क्रांति कुमार यादव, संतोष कुमार भारती उर्फ संतोष राम, रूपेश यादव, आशीष कुमार यादव व अर्जुन कुमार को साक्ष्य के आभाव में रिहा कर दिया गया है.

हाइकोर्ट में रिटायर्ड कर्मियों को किया गया सम्मानित

संवाददाता,पटना

हाइकोर्ट में बुधवार को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सम्मान में एक गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में लंबे समय तक न्यायपालिका की सेवा देने वाले कर्मचारियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया.
समारोह में मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू , न्यायाधीश जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद सहित अन्य न्यायाधीश उपस्थित रहे. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र, शॉल, स्मृति-चिह्न एवं पौधे भेंट कर सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में रजिस्ट्री के सदस्य, विभिन्न वकील संघों के पदाधिकारी तथा हाइकोर्ट के कर्मचारी भी मौजूद थे.

राजस्व प्रशासन में दलाल मुंशी प्रथा पर लगेगी रोक

पटना .राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व प्रशासन की इकाइयों में दलालों एवं मुंशियों के हस्तक्षेप पर रोक लगाने और भू-माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये हैं. विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी समाहर्ताओं को पत्र लिखा है. इसमें क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान दलाल या मुंशी की पहचान होने पर उनके विरुद्ध धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसी धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है.

फुटपाथों पर से हटेगा अतिक्रमण

पटना. सड़क पर पैदल चलने वाले नागरिकों के सम्मान एवं सुविधा के लिए फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया गया है. इस संबंध में विकास आयुक्त ने सड़क सुरक्षा पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग को निर्देश दिया है.

नये स्वीकृत सेंट्रल स्कूल को मिलेगी जमीन

संवाददाता,पटना

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि राज्य में अब कुल 72 केंद्रीय विद्यालय हो गये हैं. उन्होंने बताया कि इनमें से 14 विद्यालयों की स्वीकृति विधानसभा चुनाव के पहले मिली है. राज्य में जितने भी स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें से अभी तक 71 को जमीन उपलब्ध करा दी गयी है. शेष विद्यालयों को जमीन उपलब्ध करायी जा रही है. जमीन को लेकर कुछ समस्याएं आ रही हैं जिसे 15 दिनों में दूर करा लिया जायेगा.
उन्होंने बताया कि अभी गोपालगंज-औरंगाबाद सहित अन्य जिलों के केंद्रीय विद्यालयों को जमीन उपलब्ध कराना है. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार विधानसभा में राजू कुमार सिंह, मंजीत सिंह सहित अन्य सदस्यों द्वारा पूछे गये ध्यानाकर्षण सूचना का जवाब दे रहे थे.
राजू कुमार सिंह ने कहा था कि मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है. वह मुजफ्फरपुर से 60-70 किलोमीटर दूर है. वहां पर केंद्रीय विद्यालय स्थापित होने से उस क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्राप्त हो सकेगी.

उद्योग विभाग ने 429 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को दी हरी झंडी

पटना. उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 112वीं बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में 25 निवेश प्रस्तावों प्रथम क्लियरेंस दिया गया है. इसमें 429.6 करोड़ के निवेश होने की संभावना है. इसके अलावा 14.2 करोड़ के निवेश वाली परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृति भी दी गयी है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुख्य निवेश प्रस्तावों में सर्वाधिक अहम प्रस्ताव हल्दीराम स्नेक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड , हाइकेन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड , नोस्टिनो फूड प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य प्रस्ताव शामिल हैं.

अधिवक्ता कल्याण निधि में अब ₹50 जमा होंगे

पटना. अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि 25 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दी गयी है. इस प्रकार अब अधिवक्ता कल्याण निधि में 25 की जगह 50 रुपये जमा होंगे. गुरुवार को विधानसभा में इस संबंध में बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक पर सहमति प्रदान की गयी.

समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

भिक्षावृत्ति में संलिप्त व्यक्तियों के सभी 38 जिलों में सर्वेक्षण का शुभारंभ

27 फरवरी 2026

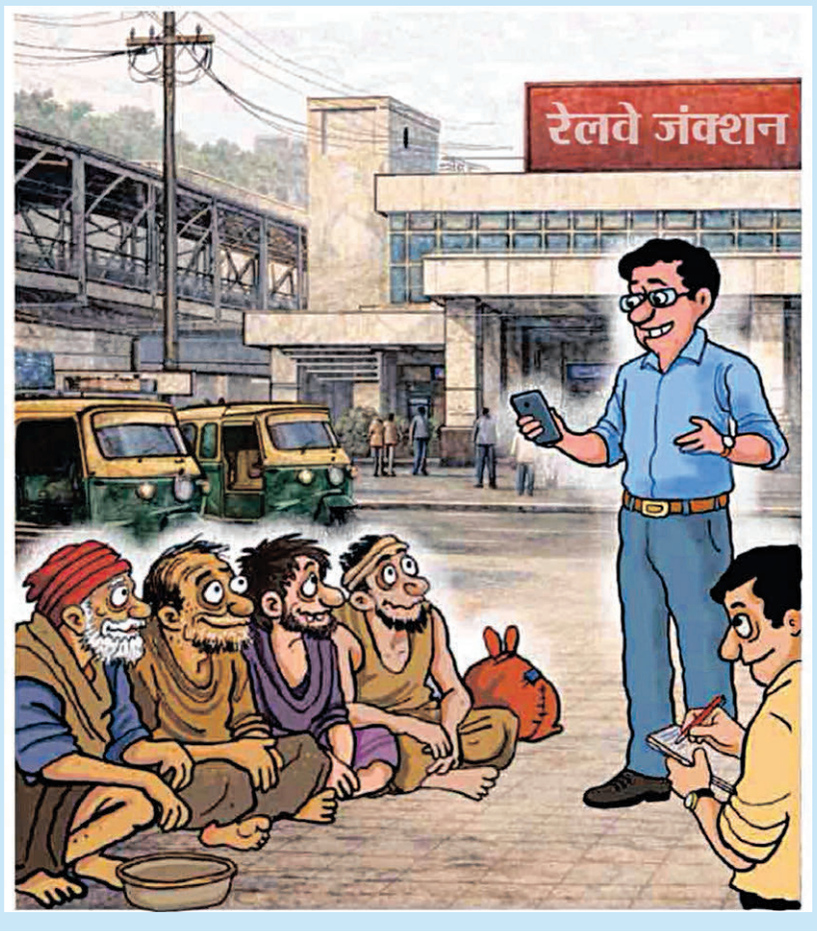

सर्वे का कार्य मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा!

उद्देश्य:
- भिक्षाटन कर जीवनयापन कर रहे महिला, पुरुष, बच्चे एवं ट्रांसजेंडर भिक्षुकों की पहचान करना।
- भिक्षावृत्ति में संलिप्त व्यक्तियों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से आच्छादित कर उनका देखभाल एवं पुनर्वास करना ताकि उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

सर्वेक्षण अवधि: 27 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक

भिक्षावृत्ति में संलिप्त व्यक्तियों की सूचना प्राप्त करने हेतु
टॉल फ्री नं0 1800-345-6262 पर डायल करें!

सक्षम समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी!

PR No.- 025299 (SWD)D. 2025-26

22 हजार ट्रेनी सिपाही सीखेंगे हथियारों से लक्ष्य को भेदना

संवाददाता, पटना

बिहार पुलिस में हाल में नियुक्त करीब 22 हजार सिपाहियों को अप्रैल तक छोटे और बड़े सभी हथियारों से लक्ष्य भेदन का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा. यह निर्देश एडीजी (प्रशिक्षण) संजय सिंह ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में दिया. जिला पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की विभिन्न वाहिनियों में 21 जुलाई से बुनियादी प्रशिक्षण जारी है. समीक्षा में प्रशिक्षण का स्तर संतोषजनक पाया गया, हालांकि गुणवत्ता को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया.बिहार पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक में प्रशिक्षण की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम क्रियान्वयन और संसाधनों की उपलब्धता की विस्तृत समीक्षा की गई. बैठक में डीआइजी (प्रशिक्षण), एआइजी (प्रशिक्षण), डीएसपी प्रशिक्षण, पुलिस निरीक्षक (प्रशिक्षण), विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों के उपप्राचार्य और अन्य अधिकारी शामिल हुए. एडीजी (प्रशिक्षण) ने निर्देश दिया कि अप्रैल तक सभी प्रशिक्षुओं का लक्ष्याभ्यास पूरा कराया जाए. उन्होंने प्रशिक्षुओं को नैतिक रूप से सुदृढ़ बनाने, अनुशासन सुनिश्चित करने और तकनीकी दक्षता बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने को कहा.

मधुबनी-बेनीपट्टी व पुपरी नयी रेल लाइन की केंद्र से सिफारिश

संवाददाता, पटना

राज्य सरकार मधुबनी-बेनीपट्टी-पुपरी नयी रेल लाइन की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी गयी है. विप में प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने सदन को धनश्शम ठाकुर के एक गैर सरकारी संकल्प के जवाब में बताया कि मधुबनी-बेनीपट्टी-पुपरी नयी रेल लाइन निर्माण परियोजना को बढ़ाया जायेगा. इसके लिए रेल मंत्रालय को हाल ही में सिफारिश की गयी है. इसका पूरे सदन ने स्वागत किया. विधान परिषद में गुरुवार को 24 से अधिक गैर सरकारी संकल्प लाये गये. उनमें से एक संकल्प को मतदान के बाद अमान्य कर दिया गया. बाकी संकल्पों के प्रस्ताव सरकार के कहने पर वापस ले लिये गये. वंशीधर ब्रजवासी की तरफ से लाये संकल्प प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया राइट टू एजुकेशन के तहत कमजोर एवं अलाभकारी वर्ग के 86 हजार विद्यार्थियों के नामांकन कराये गये हैं.

संपादकीय

एनसीईआरटीची लक्तरे

संस्कारक्षम वयातील मुलांना समाजाच्या विविध अंगांचे, विशेषत: लोकशाही आणि त्यातील न्यायव्यवस्थेचे ज्ञान देण्याच्या नावाखाली चक्क कुजबुज वाटावी अशी माहिती पाठ्यपुस्तकात समाविष्ट करण्याचे प्रकरण राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद म्हणजे एनसीईआरटीच्या प्रचंड अंगलट आले आहे. देशभरातील सीबीएसई शाळा, केंद्रीय विद्यालये, जवाहर नवोदय विद्यालयांमधील इयत्ता आठवीच्या समाजशास्त्राच्या 'एक्सप्लोरिंग सोसायटी : इंडिया ॲण्ड बियॉण्ड' पुस्तकाच्या भाग २ मध्ये परिषदेच्या विद्वानांनी हा न्यायव्यवस्थेशी संबंधित मजकूर टाकला आणि एनसीईआरटी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तडाख्यात सापडली. सुधारित पाठ्यपुस्तक नुकतेच बाजारात आले. एका वृत्तपत्राने वादग्रस्त मजकुराची बातमी प्रकाशित केली. ती वाचून सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी पुस्तक मागवले. बुधवारी सकाळी सर्व न्यायाधीशांची त्यावर चर्चा झाली. न्यायालयाचे कामकाज सुरू होताच कपिल सिब्बल व अभिषेक मनू सिंघवी या ज्येष्ठ विधिज्ञांनी हा मुद्दा उचलला आणि एनसीईआरटीच्या आगाऊपणाची स्वत: दखल घेत सरन्यायाधीशांनी तिची अक्षरश: चंपी केली. त्यावर हा मजकूर लगेच मागे घेण्याची उपरती केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने दाखवली. तरीही हे प्रकरण संपले नाही. गुरुवारी सरन्यायाधीशांनी पुन्हा नवा आदेश देताना, या पाठ्यपुस्तकावर पूर्णत: बंदी, विकल्या गेलेल्या प्रती जप्त करणे, डिजिटल बुक काढून टाकायला सांगितले. शिवाय केंद्रीय शिक्षण सचिव तसेच एनसीईआरटीचे संचालक दिनेश प्रसाद सकलानी यांना न्यायव्यवस्थेची अवमानना केल्याबद्दल नोटीस जारी करण्यात आली आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची भूमिका मांडताना दोन अधिकारी या अपराधासाठी जबाबदार असल्याचे सांगून त्यांना भविष्यात एनसीईआरटी किंवा यूजीसीमध्ये कोणतीही जबाबदारी दिली जाणार नाही, असे सांगितले खरे, पण सरन्यायाधीश त्यावर समाधानी नाहीत. हे सगळे प्रकरण बहुतेक एनसीईआरटीचे संचालक दिनेश प्रसाद सकलानी यांच्यावर चांगलेच शेकणार अशी चिन्हे आहेत. तसेच व्हायला हवे. कारण, राजकीय आशीर्वादामुळे गेली चार वर्षे या पदावर बसलेले सकलानी याआधीही चर्चेत राहिले आहेत. विशेषत: दोन वर्षांपूर्वी इतिहासाच्या पुस्तकात सुधारणा करताना एनसीईआरटीने बाबरी मशिदीचे पतन, गुजरातच्या दंगली असा बराच संवेदनशील भाग वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर सकलानी यांचा युक्तिवाद होता की, अशा घटनांचा विद्यार्थ्यांच्या मनावर विपरीत परिणाम होऊ नये, सकारात्मक नागरिक घडावेत, यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत. ही सकारात्मक नागरिक घडविण्याची भूमिका आता न्यायव्यवस्थेतील कथित भ्रष्टाचार किंवा खटल्यांविषयीचा मजकूर पाठ्यपुस्तकात घुसडण्याच्या प्रकरणात कुठे गेली, असा प्रश्न सहज उपस्थित केला जाऊ शकतो. या प्रकरणावर अत्यंत कठोर भूमिका घेताना न्यायालयाने दोन दिवस कामकाजावेळी केलेली विधाने अत्यंत गंभीर, देशाचे समग्र शैक्षणिक धोरण ठरविण्याची जबाबदारी असलेल्या संस्थेबद्दल चिंता निर्माण करणारी आहेत. काहीही गरज, औचित्य नसताना न्यायव्यवस्थेतील कथित भ्रष्टाचाराचे धडे विद्यार्थ्यांना देण्याची एनसीईआरटीची ही कृती अनावधानाने झालेली चूक नाही. त्यामागे सुनियोजित षडयंत्र आहे, असे न्यायालयाचे निरीक्षण आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणालेत की, 'न्यायव्यवस्थेवर असे शिंतोडे उडविण्याची परवानगी कुणालाही नाही. एनसीईआरटीची ही चूक साधी समजून दुर्लक्ष केले तर जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडेल आणि या व्यवस्थेचा प्रमुख म्हणून आपण हे होऊ देणार नाही.' खरेतर देशाचे नवे शैक्षणिक धोरण, अभ्यासक्रमांमधील बदल, नव्या स्वरूपाची पाठ्यपुस्तके आदींबद्दल देशातील एका मोठ्या वर्गाकडून अधूनमधून आक्षेप घेतले जातात. काही प्रकरणे उच्च न्यायालयांमध्ये गेली. एखाददुसरे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही गेले. बहुतेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी अभ्यासक्रम किंवा शिक्षणाची दिशा ठरविणे हा एनसीईआरटीचा अधिकार असल्याचे सांगून बंदी किंवा बदलाची मागणी फेटाळून लावली. हे न्यायव्यवस्थेवरील मजकुराचे प्रकरण मात्र साधे नाही. ते थेट न्यायालयाशी संबंधित आहेच, शिवाय मजकुराला काहीही आधार नाही. म्हणूनच सरन्यायाधीश तसेच इतर न्यायाधीशांच्या संतापाचा कडेलोट झाला आहे. एनसीईआरटी व दिनेश प्रसाद सकलानी यांच्या कारभाराचे वाभाडे निघाले आहेत. परिषदेच्या मनमानीची लक्तरे न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च ठिकाणी टांगली गेली आहेत. विद्यार्थ्यांना अनुचित धडा शिकविण्याचे प्रकरण अंगलट आल्यानंतर सकलानी व एनसीईआरटी यातून काहीतरी धडा शिकेल, अशी आशा बाळगूया.

...आधी उपमुख्यमंत्री, आता राष्ट्रीय अध्यक्ष, पुढे?

सुनेत्राताईंच्या धीरोदात्तपणाचे, शांतपणाचे कौतुक झाले; पण आता त्यांना 'बोलावे' लागेल. त्यांची आणि पार्थ या दोघांचीही आता खरी परीक्षा असेल!

यदु जोशी
राजकीय संपादक, लोकमत

अजितदादांच्या अपघाती निधनाला उद्या एक महिना पूर्ण होईल. दु:खातून सावरत सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री झाल्या, आता त्या त्यांच्या पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षही झाल्या आहेत. काळ थांबतो थोडाच? सुनेत्राताईंच्या धीरोदात्तपणाचे, शांतपणाचे कौतुक झाले, पण आता आहेत त्याच मूड आणि मोडमध्ये त्या राहिल्या तर कौतुकाची जागा टीका घेईल. धीरोदत्तपणा हा आजचा गुण उद्याचा अवगुण ठरेल. संयमाचीही 'एक्सपायरी डेट' असते. धीरगंभीरता एका वळणापर्यंत ठीक असते. आता विधिमंडळात काय किंवा बाहेरही काय; त्यांना बोलावे लागेल. वारसा हा आधार आहे पण भविष्य हे कृतीतूनच लिहिले जाईल.

वयाच्या पासष्टाव्या वर्षी राजकीय कारकिर्दीची नवी उंची गाठण्यासाठी अजित पवार यांनी स्वत:मध्ये प्रचंड बदल करवून घेतले होते, आता ती वेळ नियतीने सुनेत्रा पवार यांच्यावर वयाच्या बासष्टाव्या वर्षी आणली आहे. त्यांना वा पार्थ पवारांना मागे सारून पटेल, तटकरे पक्षाचा कब्जा घेतील, अशी आवई काही जणांनी उठवली होती, तेव्हा याच ठिकाणी असे लिहिले होते की ते शक्य नाही. ही राष्ट्रवादी असो की ती... पवार या नावाशिवाय चालू शकत नाही. आज ते खरे ठरले आहे. पटेल, तटकरे हे अष्टप्रधान मंडळात राहतील, पण प्रमुख होणार नाहीत.

सल्लागार मात्र कायम

अजितदादांच्या जागी सुनेत्राताई आल्या, पण अजितदादांची जागा सर्वदृष्टीने त्या किती लवकर घेतात ते त्यांच्या नेतृत्वाच्या आणि पक्षाच्या दृष्टीनेही खूपच महत्त्वाचे ठरणार आहे. पार्थ पवार उद्या राज्यसभेत जाणारच आहेत, आईबरोबर त्यांचीही कसोटी आहे; चिडचिड न करता परिपक्वता आणणे हाच त्यांच्यासाठी योग्य मार्ग असेल. कारण आईच्या कारभारात त्यांच्या म्हणण्याला फारच महत्त्व असते, असे म्हणतात. अजितदादांची उणीव सुनेत्राताई कितपत भरून काढू शकतील, याचा अंदाज त्यांच्या पक्षातील नेते सध्या बांधत आहेत. पक्षाध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री म्हणून पुढचे एक वर्ष सुनेत्राताईंसाठी अतिशय महत्त्वाचे असेल. कारण, त्यांच्या एकूणच क्षमतेचे मूल्यमापन आतले आणि बाहेरचेदेखील करत राहतील. 'लाडावलेला मुलगा' या प्रतिमेतून बाहेर येत पार्थ पवार त्यांना किती परिपक्वपणे साथ देतात हेही महत्त्वाचे असेल.

माहिती अशी आहे की, महिन्याकाठी बक्कळ

पैसा घेणाऱ्या एका सल्लागाराला घरी पाठवण्याचा निर्णय अजितदादांनी घेतला होता. त्याच्यासोबतचे कॉन्ट्रॅक्ट संपल्याची नोटीस २९ जानेवारीला देण्याचे ठरले होते. पण अजितदादा गेले अन् सल्लागार अजूनही कायम आहेत. गेल्या महिनाभरात आपले कोण आणि परके कोण, याची एक यादी सुनेत्राताईंनी तयार केली असेलच. अजितदादांचे जे अगदी खूपच निष्ठावंत होते ते सुनेत्राताईंजवळ इच्छा असूनही मन मोकळे करू शकत नाहीत आणि राजकीय मजबुरी म्हणून जे अजितदादांना नेते मानायचे ते आता चमकोगिरी करत आहेत, असे म्हणतात.

विरोधी पक्षनेता नाही अन् विरोधकही नाहीत

विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत विरोधी पक्षनेता नसताना होणारे हे पहिलेच अधिवेशन आहे. विरोधी पक्षनेता तर नाहीच, पण विरोधही दिसत नाही. संख्येने दुबळे असलेले विरोधक सरकारवर हल्ला चढवण्याबाबतही खूपच कमकुवत दिसतात. सरकारची कोंडी होण्याऐवजी विरोधकांचीच झालेली दिसत आहे. तीन पक्षांमधील समन्वय बेपत्ता झाला आहे. सरकारशी भांडायचे सोडून राज्यसभेच्या एका जागेसाठी एकमेकांशीच भांडत आहेत. नाना पटोले यांच्याकडे गोव्यात लग्न होते, त्यामुळे ते पहिल्या आठवड्यात अधिवेशनात नव्हते. सोमवारपासून ते येतील तेव्हा विरोधकांची कामगिरी एकदम उंचावेल, अशी अपेक्षा करावी काय?

जाता जाता

सार्वजनिक बांधकाम विभागात २९३ कनिष्ठ अभियंत्यांना नियुक्ती देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. चर्चा अशी आहे की, 'धर्मा'च्या नावाखाली अधर्म केला जात आहे. सोबत कोणी दिनेशही आहे म्हणे! सरकारी नोकरीची सुरुवात करणाऱ्या तरुणांकडून 'मागणी' केली जात असल्याची जोरदार चर्चा आहे. अशा तरुणांचे सरकारबद्दल आणि एकूणच सरकारी नोकरीबद्दल काय मत होईल? - हेच की इथे पैसे द्यावे लागतात आणि खावेही लागतात. या परस्पर झालेल्या अधर्मामुळे प्रचंड अस्वस्थ झालेल्या राज्यमंत्र्यांनी धर्मासह तिघांना खूप झापले म्हणे, पण उपयोग काय? घ्यायचे ते घेऊन झाले आहे, आता कनिष्ठ अभियंत्यांना ते परत थोडेच दिले जाणार? मोठी इनिंग खेळण्याची संधी असलेल्या नेत्यांनी अपप्रवृत्तींना दूर केलेच पाहिजे. 'सावज टप्प्यात आल्याशिवाय मी शिकार करत नसतो' असे सुधाकरराव नाईक म्हणायचे. त्यांचा वारसा सांगणाऱ्यांनी टप्प्यात आलेल्या अपप्रवृत्तींना टिपले पाहिजे.

yadu.joshi@lokmat.com

अन्वयार्थ

सावध असा, मुंग्यांच्या वारुळावर आपला पाय पडतो आहे!

नॉर्वेतील प्रमुख वर्तमानपत्र 'दैगसाविजेन'चे पत्रकार केटील स्टेल्सेन यांचा दिल्लीत एआय-समीटमध्ये सहभाग होता. मायदेशी परतल्यावर त्यांनी लिहिलेला हा लेख..

केटील स्टेल्सेन
प्रतिनिधी, 'दैगसाविजेन', नॉर्वे

एका कामासाठी मी नवी दिल्लीत होतो. नेहमीप्रमाणे शहराच्या एका भागातून दुसऱ्या भागाकडे जायचे होते. या गरम देशात आपल्यापुरते थंड वाटायला हवे असेल, तर एअरकंडिशण्ड टॅक्सी लागते. ती बुक करावी का? या विचारात असताना जाणवले, रस्त्यावर नेहमीपेक्षा जास्त गर्दी आहे; कारण एआय-समीट सुरू झाले होते. पोलिसांनी रस्त्यावरची वाहने कमी करण्यासाठी काही रस्ते बंद केले. मग म्हटले, पायी जाणे इष्ट. नवी दिल्लीत सकाळच्या गर्दीत चालणे हा रोचक अनुभव आहे. कित्येक प्रकारचे गंध, कित्येक आवाज. नॉर्वेच्या छोट्या शांत गावातून आलेल्या माणसासाठी हे सारेच वेगळे.

नवी दिल्लीतले संमेलन कृत्रिम बुद्धिमत्तेविषयी होते. हा विषय आला की, भविष्याची चर्चा सुरू होते; परंतु दिल्लीच्या रस्त्यांवर भविष्य आधीच अवतीर्ण झालेले दिसले. हा देश आधीच बदलला आहे. २२ वर्षांआधी भारत एक अगदी वेगळा देश होता. सर्व दिशांना गर्दी ठासून भरलेली आहे. वाहनांची संख्या वाढते आहे. प्रत्येक गोष्टीला तिचा तिचा वेग आहे. हवेची गुणवत्ता घसरली आहे. संस्कृती बदलली आहे.

२२ वर्षांपूर्वी मी भारताच्या इंग्रजी वृत्तपत्रात 'पीडीए'विषयी वाचले होते. मला वाटले की, 'पर्सनल डिजिटल असिस्टंट' असेल; परंतु भारतात याचा अर्थ 'पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन' असा होता. तरुण-तरुणी हातात हात घालून चालतील, गळामिठी करतील, चुंबन घेतील, अशा चर्चा नव्या भारतात दिसत नाहीत. कारण आता येथे या गोष्टी अंगवळणी पडल्या आहेत. तरुण स्वतंत्र आहेत. त्यांच्या हातात स्मार्ट फोन आहे. पूर्वी तरुणी पारंपरिक पोशाख करत. अंग पूर्णपणे झाकून घेत. कानात मोठे, चमकणारे सोन्याचे झुमके, सर्वांग कपड्यांनी झाकलेले. एकेकाळी हा प्रघात होता. सुपारी किंवा तंबाखू चघळणे सामान्य होते. आता ते दिसत नाही. संस्कृतीत बदल सोपा नाही; परंतु भारतात तो झाला आहे.

माहिती तंत्रज्ञान तथा आयटी उद्योगामुळे या देशाची अर्थ-रचना वेगाने बदलली. हजारो लोकांना त्यांची पहिली कायमस्वरूपी नोकरी याच उद्योगात मिळाली. खिशात पैसे खुळखुळणारा मोठा वर्ग विकसित झाला. बाजारपेठ बहरली. आता भारतातले लोक स्मार्ट फोनने पैसे देतात. या देशात जुन्या परंपरांना आव्हान दिले जात आहे. विशाल महत्त्वाकांक्षा बाळगल्या जात आहेत.

भारत प्रगती करत आहे, हे तर स्पष्टच आहे. आता केवळ माहिती तंत्रज्ञान सेवा नव्हेत तर प्रगत तांत्रिक सेवाही येथे उपलब्ध आहेत. भारतात कृत्रिम बुद्धिमत्ताही पोहोचली आहे. प्रगतिशील विचारांना दिशा मिळाली आहे. मी ज्या लोकांना भेटलो त्यांच्यापैकी हजारोंच्या नोकऱ्या बदलल्या आहेत. रस्त्यावर खूपच गर्दी आहे. बसेस, वाहतूक व्यवस्था, मोटारी, मोटरसायकली, सायकली, रिक्षा वेगवेगळे सामान वाहून नेताना दिसतात. ही इतकी सारी माणसे करतात त्यातल्या अनेक गोष्टी नव्या तंत्रज्ञानाने खरोखरच करायला सुरुवात केली तर या लोकांचे काय होईल? तशी शक्यता तर आता व्यक्त होतेच आहे. आज हजारो भारतीय चालक त्यांच्या तीनचाकी रिक्षाने प्रवासी नेतात. या रिक्षावाल्यांना वातानुकूलित, चालकरहित मोटारींशी भाड्यावरून स्पर्धा करावी लागली तर? मोटारसायकल किंवा सायकलवर पोचवले जाणारे सामान ड्रोनने पोचवले गेले तर? दुकानांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या जागी या कर्मचाऱ्यांपेक्षा अधिक कार्यक्षम आणि स्वस्त यंत्रमानव काम करू लागले तर?

- कष्टाच्या बाजारात नेमके काय होणार आहे याचा विचार जगभरातील लोक करत आहेत. नवे तंत्रज्ञान बदल घेऊन येईल हे सर्वांना माहीत आहे. भारतासारख्या एखाद्या देशाला अचानक मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारीचा सामना करावा लागला तर तो स्थिर राहणार नाही. विरोध होईल. लोक हिंसक होतील. रस्त्यावर उतरतील.

आपण जन्मभर शिकत राहिले पाहिजे असे आपण म्हणतो. ते बरोबरच आहे; परंतु प्रत्येकजण काही आयटीमधील तज्ज्ञ होऊ शकत नाही. ज्यांना हे जमणार नाही, त्यांचे काय होईल?

- अगदी आजच कुणी आपल्यापासून नोकरीच्या संधी हिसकावत नाही, आपण उद्याही कामावर जाऊ; परंतु सगळ्या शक्यतांवर विचार करणे गरजेचे आहे. औद्योगिक क्रांतीच्या वेळी अनेक लोक मागे राहून गेले. अर्थात त्यावेळी नव्या नोकऱ्याही उपलब्ध झाल्या. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्रांतीमधून एकाधिकारासारख्या प्रवृत्ती निर्माण होऊ शकतात. कदाचित मूठभर लोकांना त्याचा फायदा होईल; पण बाकीच्यांचे काय?

- सांभाळून चालावे लागेल. एक जरी चूक झाली तरी आपले पाऊल मुंग्यांच्या वारुळावर पडेल, हे नक्की!

जगभर

आता अनुभवा उडत्या कारचा वेगवान थरार !

विमानप्रवास आजही सर्वांत सुरक्षित आणि सर्वांत वेगवान मानला जातो. ती वस्तुस्थितीही आहे, तरीही प्रत्यक्ष विमानप्रवासापेक्षा विमानतळावर खूप आधी पोहोचावं लागणं, काहीवेळा ढगाळ, खराब हवामानामुळे विमानांना विलंब होणं, यामुळे बऱ्याचदा एकूण प्रवासास विलंब होतो. अलीकडच्या काळात विमानं आणि हेलिकॉप्टर्सच्या अपघातांमुळेही हे प्रवास चर्चेत आहेत. हेलिकॉप्टर आणि चार्टर विमानांच्या प्रवासासाठी तुलनेनं खर्चही खूप मोठ्या प्रमाणात असतो. त्यामुळेच या प्रवासाला तसेच वेगवान पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न गेल्या काही काळापासून जगभरात सुरू आहेत.

त्याचाच एक प्रकार म्हणजे उडणाऱ्या कार! आपली स्वत:ची कारच जर विमान किंवा हेलिकॉप्टरसारखी उडवता आली तर त्या प्रवासावर आपलं पूर्णपणे नियंत्रण असेल आणि त्याचा खर्चही बऱ्याच प्रमाणात आटोक्यात आणता येईल या उद्देशानं उडत्या कारसंदर्भात जगभरात संशोधनं सुरू आहेत. त्याचे काही यशस्वी प्रयोगही झाले आहेत. पण या प्रयोगात सध्या सगळ्यांत आघाडी घेतली आहे ती चीननं. उडत्या कारच्या प्रयोगात त्यांनी बरंच संशोधन केलं असून, विविध खासगी कंपन्याही आता कार उडवण्याच्या स्पर्धेत आहेत.

चीनच्या ऑटोफ्लाइट कंपनीनं आपल्या V5000 मॅट्रिक्स या उडत्या कारची नुकतीच यशस्वी चाचणी घेतली आहे. ही जगातील पहिली ५ टन श्रेणीतील eVTOL (इलेक्ट्रिक व्हर्टिकल टेक-ऑफ ॲण्ड लॅण्डिंग) कार असून, यात १० जण बसू शकतात. एका उड्डाणात ही कार १५०० किलोमीटरचं अंतर पार करू शकते. या कारची कमाल टेकऑफ क्षमता ५७०० किलोग्रॅम आहे. सामान्य हेलिकॉप्टरच्या तुलनेत या कारचा खर्च तब्बल १० पटींनी कमी आहे.

नवीन मॅट्रिक्स ही ५ टन श्रेणीपर्यंत पोहोचणारी पहिली eVTOL कार आहे. तिचा विंगस्पॅन २० मीटर आहे. लांबी १७.१ मीटर, तर उंची ३.३ मीटर आहे. केबिनची लांबी ५.२५ मीटर आणि रुंदी १.८ मीटर असून, आतल्या मार्गिकेची उंची १.८५ मीटर आहे.

उद्योग क्षेत्रातील अंदाजानुसार, चीनचा eVTOL कारचा बाजार २०२६ पर्यंत ९.५ अब्ज युआन म्हणजेच सुमारे १.३७ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकतो. चीनच्या उद्योग आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयांतर्गत असलेल्या cnni.com.cn या न्यूज पोर्टलच्या रिपोर्टमध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे.

या कारच्या अत्यंत काटेकोर आणि वेगानं तपासण्या सुरू आहेत. त्यात काही त्रुटी तर नाहीत ना, त्यांना काही धोका तर नाही ना, यासंदर्भात सातत्यानं चाचण्या घेतल्या जात आहेत.

सर्व चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतर चीनची ऑटोफ्लाइट कंपनी या उडणाऱ्या कार्स लवकरच बाजारात आणणार आहेत. ग्लोबल टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार, पूर्व चीनमधील जियांगसू प्रांतातील कुनशान येथे या कारनं यशस्वी उड्डाण केलं. या उडत्या कार लवकरच बाजारात येतील. असं कंपनीचंही म्हणणं आहे.

पहिल्यांदा चीनमधील शहरांमध्ये या उडत्या कार पाहायला मिळतील. त्यानंतर संपूर्ण जगभरातच त्या दिसू लागतील. या उडत्या कार पहिल्यांदा जो कोणी लॉन्च करेल, त्यांना ग्राहकांचा लाभ जास्त मिळेल आणि त्यांच्या नावावर हे संशोधन जाईल म्हणून लवकरात लवकर त्या बाजारात आणण्याचा कंपन्यांचा प्रयत्न आहे.

जनमन

उच्च शिक्षणाची परिस्थिती चिंताजनक

आजच्या वेगवान व स्पर्धात्मक युगात शिक्षण हे केवळ पदवी मिळविण्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही; ते व्यक्तिमत्त्व घडविण्याचे, चिकित्सक विचार विकसित करण्याचे आणि समाजाला सक्षम दिशा देण्याचे प्रभावी साधन आहे.

मात्र, भारतातील उच्च शिक्षणाची सध्याची परिस्थिती अनेक अंगांनी चिंताजनक आहे. संख्यात्मक विस्तार झाला असला, तरी गुणवत्तेच्या पातळीवर गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत. गुणवत्तेचा असमतोल हा यातील प्रमुख मुद्दा आहे. काही मोजक्या नामांकित संस्थांमध्ये जागतिक दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध असताना, बहुसंख्य महाविद्यालयांमध्ये पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित प्राध्यापक, संशोधनपर वातावरण आणि अद्ययावत अभ्यासक्रमांचा अभाव प्रकर्षाने जाणवतो. परिणामी, विद्यार्थ्यांचा संकल्पनात्मक समज विकसित न होता, परीक्षाकेंद्रित शिक्षणावरच भर राहतो. उच्च शिक्षणातील आणखी एक गंभीर समस्या म्हणजे खासगी संस्थांमधील प्राध्यापक नियुक्तीची निकृष्ट पद्धत. अनेक ठिकाणी गुणवत्ता हा प्रमुख निकष न राहता, अल्प मानधन, तात्पुरत्या नियुक्त्या आणि अपारदर्शक निवडप्रक्रिया आढळतात. याचा थेट परिणाम अध्यापनाच्या दर्जावर आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक घडणीत दिसून येतो. संशोधन, नवोन्मेष आणि उद्योग-शिक्षण समन्वय यांनाही त्यामुळे मर्यादा येतात. यासाठी गुणवत्ताधिष्ठित नियोजन, शिक्षक सक्षमीकरण, अभ्यासक्रमांचे अद्ययावतीकरण, संशोधनाभिमुख संस्कृती आणि उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासन या दिशांनी ठोस प्रयत्न करण्याची गरज आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणव्यवस्था उभारणे ही काळाची गरज आहे.

- प्रा. डॉ. प्रदीप हिरापुरे

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : **janman@lokmat.com**

पर्पजफुल

काही लोकांकडे मखमली गादी आणि अनेकांकडे चटईही नाही?

आजची जागतिक परिस्थिती मोजक्या लोकांनाच समृद्धीच्या संधी व त्यात वाटा देते. ही असमानता केवळ उत्पन्न वा संपत्तीपुरती मर्यादित राहत नाही !

अमृत बंग
सहसंचालक, 'सर्च' 'निर्माण' या युवा उपक्रमाचे प्रमुख

वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट २०२६ नुकताच काही काळापूर्वी जाहीर झाला. दोनशे नामवंत अभ्यासकांनी अत्यंत तपशीलवारपणे तयार केलेल्या या 'जागतिक असमानता अहवाला'तील मुख्य निष्कर्ष काय?

जग अत्यंत असमान आहे : जगातील सर्वात गरीब अर्धे लोक एकूण जागतिक उत्पन्नाच्या केवळ ८ टक्के एवढेच कमावतात, तर वरच्या १० टक्के लोकांचे उत्पन्न (इन्कम) उर्वरित ९० टक्के लोकांपेक्षा जास्त आहे.

संपत्ती (वेल्थ) आणखीनच केंद्रित आहे. वरच्या १० टक्के लोकांकडे जागतिक संपत्तीचा ७५ टक्के, तर खालच्या अर्ध्या लोकांकडे फक्त २ टक्के भाग आहे. सर्वात वरच्या १ टक्के लोकांची संपत्ती ही खालच्या ९० टक्के लोकांपेक्षा दीडपट अधिक आहे. वरच्या ०.००१ टक्के (सुमारे ५६,०००) लोकांकडे जगातील अर्ध्या लोकसंख्येपेक्षा ३ पट जास्त संपत्ती आहे.

हे आर्थिक केंद्रीकरण वेगाने वाढते आहे. जगात एका मोजक्या 'अल्पसंख्याक' गटाकडे अभूतपूर्व आर्थिक शक्ती आहे, तर अब्जावधी लोक मूलभूत आर्थिक स्थिरतेपासूनही वंचित आहेत. वशिष्ठ अनुप त्यांच्या 'इसलिये' या कवितेत म्हणतात त्याप्रमाणे..

'हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा,
और किसी के लिए एक चटाई ना हो'
अशी ही विचित्र परिस्थिती आहे.

मुळातच कमी सरासरी उत्पन्न असलेला भारत हा जगात सर्वाधिक आर्थिक असमानता असलेल्या देशांपैकी एक आहे. सर्वात श्रीमंत १० टक्के लोकांकडे एकूण संपत्तीच्या ६५ टक्के आणि त्यातही वरच्या १ टक्के लोकांकडे ४० टक्के संपत्ती आहे, तर खालच्या ५० टक्के लोकांचा हिस्सा फक्त ६.४ टक्के आहे. सार्वजनिक व्यवस्था अत्यंत कमकुवत असलेल्या

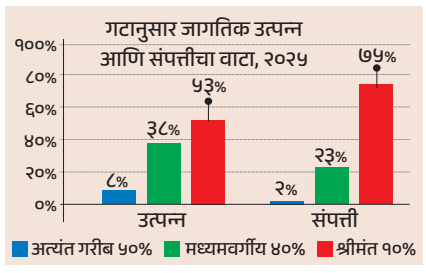

आपल्यासारख्या विविध देशांमध्ये, जिथे जीवनावश्यक गरजांसाठी, प्रगतीच्या संधींसाठी आणि कठीण समयी सुरक्षितता म्हणून पैसा अधिकाधिक महत्त्वाचा ठरतो, तिथे कमालीची आर्थिक असमानता ही विशेष धोकादायक आहे.

हवामान बदलातील योगदानाचे वितरण देखील असमान आहे. जगातील सर्वात गरीब अर्ध्या लोकसंख्येचा कार्बन उत्सर्जनाचा वाटा फक्त ३ टक्के आहे, तर वरच्या श्रीमंत १० टक्के लोकसंख्येचा वाटा ७७ टक्के आहे. त्यातही टॉप १ टक्के लोक ४१ टक्के उत्सर्जनासाठी जबाबदार आहेत. जे कमी उत्सर्जन करतात ते हवामानाच्या धक्क्यांना सर्वाधिक बळी पडतात. दरम्यान, जे सर्वात जास्त उत्सर्जन करतात त्यांच्याकडे हवामान बदलाच्या परिणामांशी जुळवून घेण्यासाठी किंवा टाळण्यासाठी भरपूर संसाधने असतात. म्हणूनच, कार्बन उत्सर्जनातील जबाबदारीची ही प्रचंड तफावत जगण्याच्या जोखमीचे देखील असमान वितरण आहे.

अमेरिकेच्या 'डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडन्स'मधील 'ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल' ही ओळ प्रसिद्ध आहे. आजची जागतिक परिस्थिती मात्र त्यातील मोजक्यांनाच आर्थिक समृद्धीच्या संधी व त्यात वाटा देते आणि ही असमानता केवळ उत्पन्न वा संपत्तीपुरती मर्यादित राहत नाही, तर जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रावर परिणाम करते. प्रश्न हा की आता याचे काय करायचे ?

तुमची एकूण संपत्ती (सर्व असेट्स, शेती, घर, गुंतवणूक मिळून) ६० लाख रुपये असल्यास तुम्ही जगातील सर्वाधिक श्रीमंत १० टक्क्यांमध्ये आहात आणि ६.५ लाख रुपये तुम्हाला मधल्या ४० टक्क्यांचा भाग बनवतात. याचाच अर्थ जगातील अर्ध्या लोकसंख्येकडे साडेसहा लाख रुपये इतकीदेखील संपत्ती नाही. असे जग न्याय्य व सर्वांसाठी राहायला योग्य आहे का?

amrutabang@gmail.com

तिरकस आणि चौकस

गजानन घोंगडे

हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८१८ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७०५ येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२ ४६०४१७८४
● **मुंबई कार्यालय :** लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. १०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००१८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२- ४६०३५९३०, ०२२- ४७५०७९४६ ● **ठाणे कार्यालय :** वेस्टर्न व्ह्यू, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे, फोन : २५४४१९०५, २५३८१७७४ ● **नवी मुंबई कार्यालय :** पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४००७०५. फोन : ०२२ ४६०४१७८४ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड : **डॉ. विजय दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर**
● संपादक : **अतुल कुलकर्णी*** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.) 'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत ® हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे. व्यापारचिन्ह आहे.

राज्यात सक्तीची फक्त मराठी, हिंदी सक्तीचा निर्णय ठाकरेंचाच

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत ठणकावले, मंजूर केलेले इतिवृत्तही दाखवले

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : आमच्या राज्यात सक्तीची फक्त मराठी असणार आहे, अशा शब्दात मराठी भाषेवरून राजकारण करणाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावले.

राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांचा चांगलाच समाचार घेतला. हिंदी सक्तीचा निर्णय उद्धव ठाकरेंनीच घेतल्याचा पुनरुच्चार करत सगळे करायचे तुम्ही आणि ठोकायचे आम्हाला, करून सवरून भागले आणि देवपूजेला लागले, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

इंग्रजी आणि हिंदी ही दुसरी भाषा पहिल्या वर्गापासून बारावीपर्यंत सक्तीची करण्यात यावी, आवश्यकता भासत असेल तर पदवी अभ्यासक्रमातही इंग्रजी आणि हिंदी सक्तीची करावी, असा अहवाल २० जाने. २०२२ रोजी ठाकरे मंत्रिमंडळासमोर आला. त्याचे इतिवृत्त मी घेऊन आलो आहे. जेव्हा मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्री असतात तेव्हा मुख्यमंत्री सर्वेसर्वा असतात, या बैठकीत अहवाल स्वीकारला गेला. त्यानंतर इतिवृत्त मंजूर करण्यात आले, त्यावर ठाकरेंची स्वाक्षरी आहे. तेव्हा राज्याने काय स्वीकारले हे लक्षात घ्या, अशा शब्दात फडणवीस यांनी उत्तर दिले.

ठाकरे बंधू एकत्र आल्याचे क्रेडिट माझेच बरं का...

आमचे राज ठाकरेही त्यांच्याबरोबर गेले, फडणवीस यांच्यामुळे दोन भाऊ एकत्र आले याचे क्रेडिट मला घ्यायचे आहे, असेही मुख्यमंत्री मिश्किलपणे म्हणाले.

वीर सावरकरांचा आत्मसमर्पणाचा दिवस आहे, ते नेहमी असे म्हणायचे की, तयारीत शांतता आणि अंमलबजावणीत धाडस दाखवले पाहिजे, त्यांना अभिवादन करताना याच विचाराने आपला महाराष्ट्र काम करतो आहे, असे सांगत

खुदसे जितने की जिद है मेरी,
मुझे खुद को ही हराना है ||
मैं भीड नही हू दुनिया की,
मेरे अंदर भी एक जमाना है ||

या ओळींनी त्यांनी भाषणाचा शेवट केला.

छत्रपती शिवरायांची टिपू सुलतानशी तुलना करण्यावर आक्षेप

टिपू सुलतान चांगले की वाईट यावर आमचा आक्षेप नाही. टिपू सुलतान शिवाजी महाराजांएवढे मोठे राजे होते, अशी तुलना ज्यावेळी केली जाते त्याला आमचा आक्षेप आहे. इतिहासात आम्हाला टिपू सुलतान महान राजे होते हे शिकवले. पण ते ४५ हजार हिंदूंची आणि ३३ हजार नायरांची कत्तल करणारे होते, हे सांगितले नाही. ते इंग्रजांशी स्वतःचे राज्य वाचवण्यासाठी लढले. आता खरा इतिहास सापडतो आहे. वर्षानुवर्षे सरकारने एनसीईआरटीच्या पुस्तकात मुघल इतिहासाला १७ पाने दिली आणि छत्रपतींच्या इतिहासाला एक पान दिले, आता मोदी सरकारने छत्रपतींच्या मराठा इतिहासाला २० पाने दिली आहेत. योग्य वेळी जर आपण नीट इतिहास शिकवला असता तर या देशातील एकाही मुसलमानाने औरंगजेबाला आपला हिरो म्हटले नसते, पण आपण खरा इतिहास कधीच शिकवला नाही, अशी टीका फडणवीस यांनी केली.

कर्जमाफीचे आश्वासन उचित वेळी पूर्ण करणार

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी कधी करणार, असा सवाल या चर्चेत विरोधी पक्षातील अनेक आमदारांनी उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकरी कर्जमाफीबाबत समिती तयार केली आहे. त्याचा अहवाल येईलच. कर्जमाफीबाबत जे आश्वासन दिले आहे ते उचित वेळी पूर्ण करणार आहोत.

कर्जमाफी करताना मागील वेळी लक्षात आलेल्या चुका दुरुस्त करणार आहोत. चुकीचे खाते क्रमांक देऊन कर्जमाफीचे पैसे घेतले जातात, त्यासाठी आपण ॲग्रीस्टॅकच्या माध्यमातून शेतीचा डिजिटल रेकॉर्ड तयार केला आहे, कर्जाचे खाते आधारशी लिंक आहे, त्या आधारे खऱ्या गरजूंना कर्जमाफी मिळाली पाहिजे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

कुजबुज

लक्षवेधी हो लक्षवेधी

विधानसभेत लक्षवेधींची संख्या प्रचंड वाढल्याने अनेकांनी टीका केली होती. भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी तर 'विधानभवना'चे नाव बदलून 'लक्षवेधी भवन' करावे, अशी उद्विग्न मागणी मागील अधिवेशनात केली होती. अधिवेशनापूर्वी पार पडलेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत लक्षवेधींची संख्या कमी करण्याबाबत चर्चा झाली. त्यानुसार प्रत्येक दिवशी केवळ ३ लक्षवेधी लावण्याचा निर्णय झाला. यापूर्वी ३० ते ३५ लक्षवेधी दिवसाला लागत होत्या. आता लक्षवेधींची संख्या कमी केल्याने आमदारांच्या लक्षवेधी लागत नसल्याने त्यांच्यात अस्वस्थता आहे. यालाच गुरुवारी विधानसभेत भाजप आ. देवयानी फरांदे यांनी वाचा फोडली. लक्षवेधीमार्फत मतदारसंघातील प्रश्न मार्गी लागतात, त्यामुळे लक्षवेधींची संख्या वाढवावी. सगळ्या आमदारांच्या लक्षवेधी लावून आमदारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. विधानसभा अध्यक्ष चांगले काम करत आहेत, असे कौतुक करत, जास्तीत - जास्त लक्षवेधी स्वीकृत कराव्यात, असे त्या म्हणाल्या. काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला.

देश मंगळावर गेला तरी तुम्ही चड्डी-बनियनमध्ये!

विधान परिषदेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उत्तर देत होते. त्याचवेळी काँग्रेसचे भाई जगताप सभागृहाबाहेर जात होते. जगताप यांनी याच चर्चेत सहभागी होताना सरकारवर टीका केली होती. त्याचा संदर्भ यांनी दिला. पूर्वी तुमचे भाषण चांगले होत होते. मात्र आता काय झाले? असा सवाल त्यांनी केला. दिल्लीतील भारत मंडपम येथे आंतरराष्ट्रीय परिषद झाली. जगभरातील नेते भारताची प्रगती पाहण्यासाठी आले. एआय समिटमध्ये देशाची ताकद दाखवली गेली. भारताचे साम्राज्य दाखविण्यात आले. मात्र, काँग्रेस तिथे वेगळ्याच भूमिकेत दिसली. एआय समिटमध्ये काँग्रेसवाले चड्डी-बनियान गँगमध्ये घुसले. जनतेसाठी समर्पित काम करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अभिमान असला पाहिजे. पण, जगासमोर आपली अब्रू वेशीवर टांगली गेली. काँग्रेसच्या काळात इतके घोटाळे झाले, पण मोदींच्या काळात एकही घोटाळा झाला नाही. देशाच्या प्रतिमेचा अभिमान बाळगायला हवा, असे शिंदे म्हणाले. भारताचे यान चंद्रावर-मंगळावर पोहोचले. देशाने तंत्रज्ञानात मोठी झेप घेतली. पण, काँग्रेसची मानसिकता अजूनही 'चड्डी-बनियन'पुरतीच मर्यादित आहे. शिंदे यांच्या या 'जबरी टोल्या'ने विरोधकांचे चेहरे पाहण्यासारखे झाले.

'सारथी शिष्यवृत्ती; एकही विद्यार्थी वंचित नाही राहणार'

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : सारथी संस्थेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या डॉ. पंजाबराव देशमुख देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांना लाभ देणारच, असे राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले.

मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण पूर्ण करता यावे, यासाठी देण्यात येणाऱ्या डॉ. पंजाबराव देशमुख देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेतील सन २०२५-२६साठी शिष्यवृत्तीबाबत सदस्य जयंत पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्न विचारला होता.

जयस्वाल म्हणाले की, सारथी संस्थेद्वारे डॉ. पंजाबराव देशमुख देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजना सन २०२१-२२ मध्ये सुरू करण्यात आली असून, ही योजना सन २०२१-२२ ते २०२४-२५ या कालावधीत यशस्वीपणे राबविण्यात आल्याने मराठा समाजातील असंख्य विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक आधार मिळाला आहे.

योजनेंतर्गत २०२५-२६मध्ये ३८८ लाभार्थ्यांना ७.२४ कोटी इतकी शिष्यवृत्तीची रक्कम वितरीत करण्यात आली असून, ३७९ लाभार्थ्यांना ५.९६ कोटी इतकी शिष्यवृत्ती रक्कम वितरीत करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. संस्थेला वेगवेगळ्या योजना राबविण्यासाठी ३०० कोटींचा अर्थसंकल्पीय निधी मंजूर करण्यात आला असून, आणखी १०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या निधीचे नियोजन करुन २०२५-२६ मध्येही योजना राबविण्यात येत आहेत.

चर्चेत राजेश पवार, अर्जुन खोतकर, अभिजीत पाटील यांनी सहभाग घेतला.

महायुतीच्या कामांमुळेच विकासाचे चित्र; मारेकरी नव्हे, विकासाचे वारकरी व्हा!

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा विरोधकांना टोला

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्यात गेल्या चार वर्षांपासून स्थगितीचे राजकारण संपवून प्रगतीच्या दिशेने घोडदौड सुरू झाली आहे. मुंबई व राज्यातील प्रलंबित प्रकल्पांना गती देण्याचे काम सुरू आहे. महायुती सरकारने झपाट्याने काम केले नसते तर राज्यात दिसणारे विकासाचे चित्र निर्माण झाले नसते. विकास हाच आमचा अजेंडा असून, आम्ही विकासाचे राजकारण करतो. त्यामुळे विरोधकांनी विकासाचे मारेकरी न होता वारकरी व्हावे, असा टोला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत विरोधकांना लगावला.

राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेत सहभागी होताना विरोधकांनी सरकारवर टीका केली होती. त्याला उत्तर देताना शिंदे म्हणाले, की २०२४-२५ वर्षात देशाच्या एकूण गुंतवणुकीच्या तब्बल ३९ टक्के परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्राला मिळाली.

या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत ९१,३३७ कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली. यामधून क्वांटम कम्प्युटिंग, एआय, सेमीकंडक्टर्स आणि ग्रीन एनर्जी अशा क्षेत्रांत मोठी कामे होणार आहेत.

लाडक्या बहिणींना योग्य वेळी २१०० रुपयांची मदत

'लाडकी बहीण' योजनेचे लाभार्थी हे समाजाचाच भाग असल्याने समाजकल्याण विभागाचा निधी वळविला. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच लाभार्थ्यांच्या खात्यात दोन महिन्यांचे पैसे जमा केले. २,१०० रुपयांच्या आर्थिक मदतीबाबत योग्य वेळी निर्णय घेऊ, असे शिंदे म्हणाले.

अधिवेशनामध्ये विकासाच्या मुद्द्यावर सकारात्मक चर्चा व्हावी. अजित पवार यांनी नेहमी विकासाचे राजकारण केले.

आज ते आपल्यासोबत नसले तरी त्यांचे विचार आणि विकासाचे व्हिजन आपल्यासोबत आहे, त्यांच्या दृष्टिकोनातून काम करणे हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल, असे शिंदे म्हणाले.

गिरणी कामगारांच्या थकीत वेतनाची जबाबदारी केंद्राची

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मुंबईतील बंद पडलेल्या चार गिरण्यांतील कामगारांची थकीत वेतन व देणीबाबत कामगार विभागामार्फत कोणतीही कार्यवाही केली जाणार नाही, असे राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरातून स्पष्ट केले आहे. याबाबत आ. भाई जगताप, सुनील शिंदे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.

कोरोना काळात मुंबईतील एनटीसीच्या चार गिरण्या बंद पडल्या. त्या अद्यापही सुरू झालेल्या नाहीत. त्यामुळे त्या गिरण्यांचे कामगार, त्यांच्या कुटुंबीयांवर आर्थिक संकट ओढावले आहे. मागील नऊ महिन्यांचे थकीत वेतन आणि अन्य देणी तत्काळ देण्यात यावीत तसेच गिरण्या पुन्हा सुरू कराव्यात, अशी मागणी कामगारांकडून होत आहे.

झेडपी, पंचायत समित्यांत स्वीकृत सदस्य

राज्य मंत्रिमंडळाने केले शिक्कामोर्तब : साधारण पाच सदस्य स्वीकृत होतील

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्येही स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

१२ जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गतच्या १२५ पंचायत समित्यांचे अनुक्रमे अध्यक्ष आणि सभापती निवडण्यासाठीची कार्यवाही २० मार्चच्या आधी पूर्ण करण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने नुकतेच दिले आहेत. या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांच्या आधी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देऊन जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये महापालिका व नगरपालिकांप्रमाणे स्वीकृत सदस्य नियुक्त करावेत, अशी मागणी केली होती.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत असेही ठरविण्यात आले, की स्वीकृत सदस्यांचे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये प्रमाण काय असावे, याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाशी चर्चा करून अंतिम केला जाईल. मात्र, साधारणत: ६० ते ६५ सदस्य असलेल्या जिल्हा परिषदांमध्ये पाच स्वीकृत सदस्य असतील. त्यापेक्षा अधिक जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या असलेल्या ठिकाणी सदस्य संख्येच्या अनुपातानुसार स्वीकृत सदस्यांचे प्रमाण वाढविले जाणार आहे. सुरुवातीला १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्या आणि सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर अन्य जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्येही स्वीकृत सदस्याचा निर्णय लागू होईल.

मोठ्या पंचायत समित्यांमध्ये दोन तर लहान पंचायत समित्यांमध्ये एक स्वीकृत सदस्य असतील. राज्यातील ७० पंचायत समित्या अशा आहेत जिथे प्रत्येकी ४-५ निर्वाचित सदस्य आहेत. अशा ठिकाणी एक सदस्य असावा, अशी सूचना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केली. नगरपालिकांमध्ये निर्वाचित सदस्यांच्या अनुपातात स्वीकृत सदस्य नेमण्याचे जे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे जवळपास तसेच प्रमाण जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी असावे, असाही विचार करण्यात आला आहे.

संमिश्र

निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेसाठी सुप्रीम कोर्टाची केंद्र सरकारला नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांकडून निवडणुकांमध्ये केल्या जाणाऱ्या भरमसाट खर्चावर मर्यादा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली. यासंदर्भात २७ एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र व आयोगाला दिले आहेत. स्वयंसेवी संस्थांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोटीस पाठवली.

कॉमन कॉज स्वयंसेवी संस्था व सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जयमाल्या बागची व न्या. एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने केंद्र व निवडणूक आयोगाला उत्तर मागितले आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ च्या कलम ७७(१) अंतर्गत निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांना कठोर मर्यादा आहेत. मात्र, राजकीय पक्षांना खर्चाची कोणतीही मर्यादा नसल्याने निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैशांची उधळपट्टी केली जाते. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता बाधित होण्यासोबतच संविधानाच्या कलम १४ अंतर्गत समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा संबंधित याचिकेत केला आहे.

निरोगी समाजासाठी डॉक्टरांनी जनजागृती करावी : राज्यपाल देवव्रत

नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याची गरज; 'लोकमत टाइम्स एक्सलन्स इन हेल्थ केअर अवॉर्ड'चे दिमाखदार सोहळ्यात वितरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : दया, करुणा आणि सहिष्णू भावाने कार्य करत रुग्णांना जीवदान देणाऱ्या डॉक्टरांचे समाजावर मोठे उपकार आहेत. निरोगी समाजासाठी शुद्ध हवा, पाणी व मातीची गरज आहे. त्यासाठी नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्व समाजघटकांनी पुढे येण्याची आवश्यकता आहे. निसर्गाच्या जवळ जाणे हे निरोगी समाजाचे लक्षण असून निसर्गापासून लांब जाणे हे रोगी समाजाचे लक्षण आहे. समाजात वेगाने वाढत असलेल्या रोगांच्या पार्श्वभूमीवर निरोगी समाज घडविण्यासाठी डॉक्टरांनी जनजागृती करावी, असे आवाहन राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी केले.

आरोग्य क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या डॉक्टर्सना राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या हस्ते 'लोकमत टाइम्स एक्सलन्स इन हेल्थ केअर अवॉर्ड' देऊन सन्मानित करण्यात आले. नागपुरातील सेंटर पॉइंट हॉटेल येथे गुरुवारी आयोजित या सोहळ्याला राज्यपालांच्या सुविद्य पत्नी दर्शनादेवी, आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री प्रकाश आबिटकर, नागपूरच्या महापौर नीता ठाकरे, लोकमत एडिटोरियल बोर्डचे चेअरमन व माजी खासदार डॉ. विजय दर्डा, 'नीरी'चे संचालक डॉ. एस. व्यंकटमोहन, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, ज्यूरी बोर्डाचे अध्यक्ष डॉ. जय देशमुख, सचिव डॉ. राजू खंडेलवाल, पद्मश्री डॉ. विकास महात्मे, पद्मश्री डॉ. चंद्रशेखर मेश्राम, 'एम्स'चे कार्यकारी संचालक डॉ. प्रशांत जोशी, 'लोकमत'चे संचालक अशोक जैन, 'लोकमत टाइम्स'चे संपादक एन. के. नायक आदी मान्यवर उपस्थित होते.

'लोकमत टाइम्स एक्सलन्स इन हेल्थकेअर अवॉर्ड्स'चा दिमाखदार सोहळा गुरुवारी हॉटेल सेंटर पॉइंट, येथे थाटात पार पडला. याप्रसंगी वैद्यकीय क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या डॉक्टरांना पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. या प्रतिष्ठित सोहळ्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून मार्गदर्शन करताना महाराष्ट्र व गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत. मंचावर महाराष्ट्राचे आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, महापौर नीता ठाकरे, लोकमत एडिटोरियल बोर्डचे चेअरमन आणि माजी खासदार डॉ. विजय दर्डा यांच्यासह (डावीकडून) लोकमतचे संचालक अशोक जैन, पद्मश्री डॉ. चंद्रशेखर मेश्राम, ज्युरी बोर्डचे सचिव डॉ. राजू खंडेलवाल, ज्युरी बोर्डचे अध्यक्ष डॉ. जय देशमुख, पद्मश्री डॉ. विकास महात्मे, राष्ट्रीय पर्यावरण संशोधन अभियांत्रिकी संस्थेचे (नीरी) संचालक डॉ. एस. व्यंकट मोहन, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे व लोकमत टाइम्सचे संपादक एन. के. नायक.

रुग्णांची संख्या वाढू नये यासाठी डॉक्टरांचे प्रयत्न हवेत : प्रकाश आबिटकर

गरजेपेक्षा जास्त वाढणारे रुग्ण ही काळजीची बाब आहे. डॉक्टरांनी रुग्णांची संख्या वाढू नये यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, असे आवाहन राज्याचे आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले. आज वैद्यकीय क्षेत्रातील स्पर्धेसोबतच अर्थकारणदेखील वाढले असून, त्यामुळे सामान्य व्यक्ती अस्वस्थ होत आहेत. वैद्यकीय क्षेत्रातील सेवा की व्यवसाय ही तफावत कमी झाली पाहिजे. व्यवसाय करायलाच हवा, मात्र डॉक्टरांनी सेवाभावाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची गरज आबिटकर यांनी व्यक्त केली. लोकांना बिल किती येईल याची भीती वाटते. सामान्य माणसाला परवडणाऱ्या अशा उत्कृष्ट वैद्यकीय सेवा डॉक्टरांनी दिल्या पाहिजेत. राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू करण्यात आली आहे. यात महात्मा फुले आरोग्यदायी योजना व आयुष्मान भारत योजना एकत्रित करून २ हजार ३९९ आजारांवर मोफत उपचार होतील. ९ ते १४ वयोगटांतील मुलींसाठी लसीकरण मोहीम राबविण्यात येणार आहे. तसेच ३० हून अधिक वयोगटातील लोकांची कर्करोगाबाबतीची तपासणीदेखील सुरू करण्यात येणार आहे. रुग्णालयांनाही अडचणी येतात. त्यासाठी सरकार म्हणून आम्ही भूमिका घेतली पाहिजे. बॉम्बे नर्सिंग ॲक्टमध्ये वन विंडो प्रणाली करून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. फायर सेफ्टी, पर्यावरणाशी संबंधित परवानगीची किचकट प्रक्रिया दूर करून ती सुटसुटीत करण्यावर भर राहणार असल्याचे ते म्हणाले.

चुकीच्या खानपान सवयींवर डॉक्टरांनी मार्गदर्शन करावे

भारतीय संस्कृतीचा आधार असणाऱ्या वेदांमध्ये दुसऱ्यांप्रती सहवेदना भाव व्यक्त करणाऱ्या मानवतेला प्राधान्य दिले आहे. हाच मानवतेचा भाव वैद्यकीय क्षेत्रात दिसून येतो. पौष्टिक अन्न सर्वांना मिळाले पाहिजे. मात्र चुकीच्या खानपान सवयींमुळे रोगांचे प्रमाण वाढत आहे. डॉक्टरांनी यावरही सर्वांना मार्गदर्शन करण्याचे आवाहन राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी केले. पौष्टिक व कसदार अन्नधान्य निर्मितीसाठी नैसर्गिक शेती काळाची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.

'लोकमत'च्या वाटचालीचा गौरव

स्वातंत्र्यलढा सुरू असताना १९१८ मध्ये 'लोकमत' वृत्तपत्र सुरू झाले. राज्यातील सर्वाधिक लोकप्रिय वृत्तपत्र ठरलेल्या 'लोकमत'चे लोकशाहीच्या स्थापनेत मोठे योगदान आहे. 'लोकमत' हे निष्पक्ष पत्रकारितेचे एक मोठे माध्यम बनले आहे. आपत्ती निवारण, शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या विविध क्षेत्रांत 'लोकमत' जनकल्याणासाठी काम करीत आहे, अशा शब्दांत राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी 'लोकमत'च्या वाटचालीचा गौरव केला.

वैद्यकीय क्षेत्रातील मान्यतांसाठी सिंगल विंडो प्रणाली हवी, वैद्यकीय तज्ज्ञांचा बराचसा वेळ वाचेल : डॉ. विजय दर्डा

❶ वैद्यकीय तज्ज्ञाला एखादे रुग्णालय उघडायचे असेल तर मोठी पायपीट करावी लागते. विविध ना-हरकत प्रमाणपत्रे घ्यावी लागतात. पर्यावरण मान्यता, अग्निशमन मान्यता यांसारख्या विविध परवानग्यांची आवश्यकता असते. त्यात वैद्यकीय तज्ज्ञांचा बराचसा वेळ जातो. या प्रक्रियेला गती देण्याची गरज आहे. त्यामुळे उद्योगक्षेत्राप्रमाणे वैद्यकीय क्षेत्रासाठी विविध मान्यतांसाठीही सिंगल विंडो प्रणालीची आवश्यकता आहे, असे मत 'लोकमत'च्या एडिटोरियल बोर्डचे चेअरमन आणि माजी खासदार डॉ. विजय दर्डा यांनी व्यक्त केले.

❷ **लहान मुलांकडे शाळेत स्मार्टफोन असतात. त्यातून अनेक वाईट गोष्टी त्यांच्यापर्यंत पोहोचतात. अनेक मुले त्यामुळे भरकटतात आणि वाईट मार्गालादेखील लागण्याचा धोका असतो. यासंबंधातील नियामक प्राधिकरणांनी शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या मोबाइल वापरावर बंदी आणायला हवी. ऑस्ट्रेलियात याबाबतीत पाऊल उचलण्यात आले आहे, असे प्रतिपादन डॉ. दर्डा यांनी केले.**

आदित्य नारायण चोपड़ा

adityachopra@punjabkesari.com

भारत-इजराइल रणनीतिक रिश्ते

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद इजराइल और भारत के संबंधों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इजराइल के मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारतीय विदेश नीति की पुरानी परम्पराओं को तोड़ने वाले साबित हुए। एक तरफ भारत की इजराइल से नजदीकियां बढ़ीं तो दूसरी तरफ भारत के खाड़ी देशों से संबंधों में भी गर्मजोशी आई। भारत की अपनी सुरक्षा चिंताएं हैं और इजराइल एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में उभरा है। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल का दौरा किया था तो ये आशंकाएं व्यक्त की गई थीं कि इससे भारत के करोड़ों मुसलमान अलग-थलग पड़ सकते हैं लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा नीत एनडीए घरेलू राजनीतिक प्रभावों से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। भारत ने जहां फिलिस्तीन के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखा तो दूसरी तरफ इजराइल से भी अपने रिश्तों का विस्तार किया।

आतंकवाद को लेकर दोनों देशों की साझा चिंताओं ने दोनों देशों के बीच खुफिया सहयोग को बढ़ावा दिया। हाईटेक हथियारों की भारत की मांग और उन्हें बेचने की इजराइल की उदारता ने मजबूत रक्षा व्यापार संबंधों को जन्म दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इजराइली संसद नेसेट को सम्बोधित करते हुए इजराइल पर 7 अक्तूबर 2023 को हुए हमास के हमले की स्पष्ट शब्दों में निन्दा की और कहा कि नागरिकों की हत्या को किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही उन्होंने गाजा में शांति स्थापना की पहल को दृढ़ समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि हम शांति के पेरोकार हैं। क्षेत्र के सभी लोगों के लिए न्यायपूर्ण और स्थायी शांति बहुत जरूरी है। जिसमें फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान शामिल है। इस तरह प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत के स्टैंड को नहीं छोड़ा साथ ही आतंकवाद पर चोट भी की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मैडल से नवाजा भी गया। यह पदक प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत नेतृत्व के माध्यम से भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक संबंध मज़बूत करने में उनके असाधारण योगदान को मान्यता प्रदान करता है। अब यह तथ्य पूरी तरह से सार्वजनिक हो चुका है कि इजराइल ने 1962 में चीन से, 1965, 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान भारत की गुपचुप ढंग से सैन्य मदद की थी और कारगिल युद्ध में इजराइली मदद से ही हमने पाकिस्तान के घुसपैठियों को खदेड़ने में सफलता प्राप्त की थी तब इजराइल ने भारत को लेजर गाइडेड बम किट और मिसाइलें दी थीं। उस के बाद से ही दोनों देशों के रक्षा संबंधों की शुरुआत हुई।

> **इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की हेक्सागन समूह की स्थापना करने की घोषणा वर्ल्ड आर्डर में नया आयाम स्थापित कर सकती है। हेक्सागन का अर्थ ऐसा षटकोण जिसमें इजराइल, भारत, अमेरिका, खाड़ी देश और अफ्रीकी देश शामिल होंगे। अगर पहल सिरे चढ़ती है तो यह पाकिस्तान और चीन को बड़ा झटका होगा। दोनों देशों में रक्षा, एआई, साइबर सुरक्षा, क्वांटम, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, दुर्लभ खनिज, कृषि, डिजिटल भुगतान समेत अन्य महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शीघ्र ही दोनों देश मुक्त व्यापार समझौता को मूर्त रूप देंगे।**

लोकतान्त्रिक देश भारत की विदेश नीति 90 के दशक तक इजराइल के प्रति भेदभाव की रही और हमने फिलिस्तीन के मुक्ति संग्राम का खुलकर समर्थन किया मगर इसमें भी कोई दोष नहीं था क्योंकि स्व. यासर अराफात के नेतृत्व में फिलिस्तीन के लोग भी अपने जायज हकों के लिए लड़ रहे थे और वह स्वतन्त्र देश का दर्जा चाहते थे। भारत ने इस संघर्ष में कूटनीतिक स्तर पर उनका साथ दिया। फिलिस्तीन के अस्तित्व में आने के बाद विश्व परिस्थितियों में अन्तर आया है और इजराइल ने अरब देशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय निगरानी में कई बार शान्ति प्रयास किये हैं जिनमें 'कैम्प डेविड' समझौता सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। बदलती दुनिया में इजराइल की स्थिति में परिवर्तन आना लाजिमी था और इस माहौल में भारत के राष्ट्रहितों में परिवर्तन आना भी लाजिमी था। अत: 90 के दशक में तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. पी.वी. नरसिम्हा राव के शासनकाल में हमने इजराइल के साथ कूटनीतिक सम्बन्धों की शुरूआत की। आज इजराइल दुनिया का सामरिक उद्योग क्षेत्र का महारथी माना जाता है और आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध लड़ने का माहिर भी माना जाता है। कृषि व विज्ञान के क्षेत्र में इस छोटे से देश ने जबर्दस्त तरक्की तब की है जब यह चारों तरफ से अरब देशों जैसे सीरिया, जोर्डन, मिस्र, लेबनान और फिलिस्तीन से घिरा हुआ है।

90 के दशक से लेकर अब तक भारत की तरफ से राजनयिक स्तर की यात्राएं तो होती रही हैं मगर उच्चस्थ स्तर पर राजनयिक यात्राएं नहीं हुईं। पहली बार भारत के राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को मोदी सरकार ने इजराइल यात्रा पर भेजा था। याद कीजिए जब केन्द्र में 1977 में पहली गैर कांग्रेस जनता पार्टी की मोरारजी देसाई सरकार बनीं थी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे तो इजराइल के तत्कालीन रक्षा मंत्री 'मोशे दायां' दिल्ली के हवाई अड्डे पर आकर ही वापस स्वदेश चले गए थे।

इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की हेक्सागन समूह की स्थापना करने की घोषणा वर्ल्ड आर्डर में नया आयाम स्थापित कर सकती है। हेक्सागन का अर्थ ऐसा षटकोण जिसमें इजराइल, भारत, अमेरिका, खाड़ी देश और अफ्रीकी देश शामिल होंगे। अगर पहल सिरे चढ़ती है तो यह पाकिस्तान और चीन को बड़ा झटका होगा। दोनों देशों में रक्षा, एआई, साइबर सुरक्षा, क्वांटम, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, दुर्लभ खनिज, कृषि, डिजिटल भुगतान समेत अन्य महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शीघ्र ही दोनों देश मुक्त व्यापार समझौता को मूर्त रूप देंगे।

अटूट विश्वास

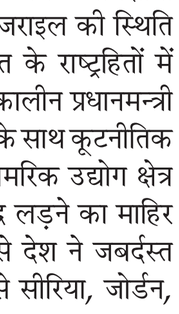

गीता पाढा

भारत-इजराइल दोनों देशों का एक-दूसरे पर अटूट विश्वास है,
आतंक से जूझकर आगे बढ़ने का रहा
दोनों मुल्कों का एक समान इतिहास है,
माननीय प्रधानमंत्री जी के इजरायली दौरे से
रणनीतिक संबंधों की नई आस है,
कूटनीति की इस नई दिशा से विश्व मंच पर सुदृढ़ होता विश्वास है...।"

फिर भड़की आग

कलम-दवात

कुमकुम चड्ढा

जब केंद्र सरकार ने मणिपुर में दो उपमुख्यमंत्रियों के साथ एक मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की, तो उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि विरोध भड़क उठेगा और वह भी उसी समुदाय की ओर से जिसे शांत करने की कोशिश की गई थी: कुकी-ज़ो।

मई 2023 में मणिपुर हिंसा की चपेट में था। बहुसंख्यक समुदाय मैतेई और कुकी-ज़ो जनजातियों के बीच संघर्ष छिड़ गया था। यह टकराव उस न्यायालय आदेश के बाद हुआ जिसमें मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की सिफारिश की गई थी। कुकी-ज़ो समुदाय ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इससे पहले से प्रभावशाली मैतेई और मजबूत होंगे, सरकार पर उनकी पकड़ बढ़ेगी और उनकी जमीनें भी छीनी जा सकती हैं। मुख्यत: मैतेई और कुकी समुदायों के बीच भड़की यह हिंसा धार्मिक नहीं, बल्कि जातीय आधार पर थी। यौन हिंसा, विस्थापन, हत्याएं और बदले की कार्रवाई आम हो गईं।

बेशक अल्पकालिक उपायों के तौर पर मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफ़े के बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, लेकिन इन्हें स्थायी शांति से पहले के अंतरिम कदम ही माना गया, यदि स्थायी शांति संभव हो भी सके। 2023 से मणिपुर अभूतपूर्व हिंसा का गवाह रहा है, जहां दोनों समुदाय एक-दूसरे के खिलाफ़ संघर्षरत हैं। तीन वर्षों से अधिक समय से राज्य में विस्थापन, हत्याएं, दुष्कर्म और जातीय हिंसा का सिलसिला जारी है।

इस वर्ष फरवरी में केंद्र ने नया शासन स्थापित करने की पहल की। 4 फरवरी को राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद युमनाम खेमचंद सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन इससे हिंसा थमी नहीं; उलटे हालात फिर भड़क उठे। नई सरकार के शपथ लेते ही कुछ घंटों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, सड़कें जाम कर दी गईं और बाजार व दफ्तर बंद कर दिए गए। मार्शल आर्ट ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के दौरान ही उनके एक उपमुख्यमंत्री पर हमले की खबर सामने आई। भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता रहे सिंह विधानसभा अध्यक्ष और राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। वे बहुसंख्यक मैतेई समुदाय से आते हैं, जिसका कुकी-ज़ो अल्पसंख्यकों से तीखा टकराव रहा है।

अतीत में सरकार पर घटनाक्रम को अनदेखा करने और लोगों को मरने के लिए छोड़ देने जैसे आरोप लगते रहे हैं। इसी महीने जब सरकार ने सिंह को संकटग्रस्त राज्य की कमान सौंपी, तो इसे कई लोगों ने महज़ दिखावा बताया, आम धारणा यही रही कि "दिखने में अच्छा, पर भीतर से खोखला।"

संतुलन साधने की कोशिश में सरकार ने सिंह के साथ दो उपमुख्यमंत्री नियुक्त किए, एक नागा और एक कुकी-ज़ो समुदाय से। परिस्थितियों में इसे "सकारात्मक कदम" माना गया और उम्मीद जताई गई कि कम से कम शांति की झलक लौटेगी, लेकिन यह संभावना दूर होती दिख रही है। कुकी-ज़ो समुदाय के कुछ वर्गों ने अपने ही विधायकों के सरकार में शामिल होने की निंदा की है। उनका आरोप है कि "अपने ही लोग दुश्मन यानी मैतेई पक्ष में चले गए," जिसे वे विश्वासघात मानते हैं।

इसी व्यापक आक्रोश के बीच उपमुख्यमंत्री नेमचा किपगेन निशाने पर हैं। राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री किपगेन को सुरक्षा कारणों से दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शपथ लेनी पड़ी।

कुकी-ज़ो समुदाय अपने लंबे समय से लंबित अलग प्रशासन की मांग पूरी होने तक विरोध जारी रखने के संकेत दे चुका है। साथ ही, वे उन विधायकों के बहिष्कार पर भी अड़े हैं जिन्होंने सरकार का हिस्सा बनने का फैसला किया है। इसी बीच उपमुख्यमंत्री नेमचा किपगेन ने "संवाद, उपचार और समावेशी शासन" का आह्वान करते हुए खाई पाटने की अपील की, लेकिन यह गुहार कम से कम कुकी समुदाय के एक हिस्से तक तो बेअसर ही रही। कुकी-ज़ो समुदाय के प्रमुख नेता और मुख्य प्रवक्ता गिंज़ा वुआलजोंग ने कहा, "जिन्होंने हमें धोखा दिया, उन पर हम कैसे भरोसा करें?" स्थिति को "शांति से बहुत दूर" बताते हुए उन्होंने कहा कि जब तक कुकी और मैतेई समुदायों के बीच कोई समझौता नहीं होता, हालात सामान्य नहीं हो सकते। उनके अनुसार, "सरकार हमें नई सरकार स्वीकार करने के लिए मजबूर करती दिख रही है, चाहे हमें पसंद हो या नहीं।" वुआलजोंग और कई अन्य नेताओं ने माना कि शांति बंदूक की नोक पर नहीं, बल्कि बातचीत से संभव है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ वार्ता जारी है, पर "मेज" मैतेई नेतृत्व वाली राज्य सरकार के साथ नहीं हो सकती। उनका तर्क है कि अतीत में ऐसे प्रयास विफल रहे हैं, इसलिए अब उनसे बातचीत नहीं की जाएगी।

कुकी-ज़ो समुदाय अपने विधायकों के सरकार में शामिल होने को जनता की इच्छा के विरुद्ध कदम बताते हुए खुद को "ठगा हुआ" महसूस कर रहा है। आरोप है कि कुकी-ज़ो परिषद और विधायकों के बीच बैठकों में यह तय हुआ था कि जब तक राज्य या केंद्र उनकी मांगें नहीं मानते, वे सरकार से दूर रहेंगे। ऐसे में जो विधायक सरकार में शामिल हुए, उन्हें "बहुमत की भावना के खिलाफ़" व्यक्तिगत निर्णय लेने वाला माना जा रहा है।

इस भावना के साथ मैतेई नेतृत्व वाली सरकार के प्रति अविश्वास जुड़ जाए तो टकराव और गहरा जाता है। समुदाय के लोग याद दिलाते हैं कि एन. बीरेन सिंह के शासनकाल में कुकी-ज़ो लोगों की जानें गईं, वे घरों से बेदखल हुए और उनकी संपत्तियाँ नष्ट हुईं। ऐसे में उसी सत्ता तंत्र से उम्मीद रखना उन्हें निरर्थक लगता है।

वे नई व्यवस्था को "पुरानी बोतल में नई शराब" करार देते हुए कहते हैं कि मुख्यमंत्री बदलने से कुछ नहीं बदला, क्योंकि जिनसे उनका संघर्ष है, मैतेई समुदाय, वे वही हैं। उनके अनुसार विवाद किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि पूरे समुदाय से है।

यह भी स्वीकार करना होगा कि केंद्र सरकार ने सकारात्मक कदम उठाने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री के साथ एक नागा और एक कुकी नेता को उपमुख्यमंत्री बनाकर उसने सभी पक्षों तक पहुंचने और घाव भरने का प्रयास किया है। ऐसे में कुकी समुदाय द्वारा तीखी आपत्ति जताना न तो पूरी तरह उचित कहा जा सकता है और न ही न्यायसंगत। दरअसल यह केवल शुरुआत है और प्रक्रिया अभी प्रारंभिक चरण में है। इसलिए इस समय धैर्य और संयम की आवश्यकता है, न कि "मेरी मर्जी या कुछ नहीं" जैसा रुख, जो फिलहाल कुछ वर्ग अपनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा रवैया न केवल मणिपुर राज्य के हितों और संभावित शांति पहलों को नुकसान पहुँचा सकता है, बल्कि उन रचनात्मक प्रयासों को भी पटरी से उतार सकता है जो हालात को शांत करने और जख्मों पर मरहम लगाने के लिए किए जा रहे हैं।

इसके साथ ही यह आशंका भी नकारा नहीं जा सकती कि अशांति को भड़काने और वित्तपोषित करने में बाहरी तत्वों की भूमिका हो।

अल्फ्रेड पार्क में अंतिम गोली से निभाया 'आजाद' रहने का प्रण

चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर विशेष

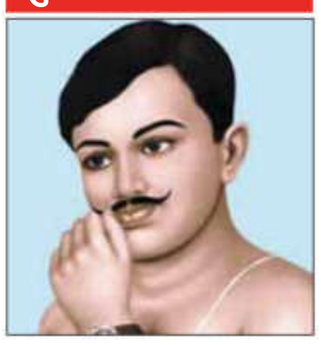

दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे।यह चंद्रशेखर आजाद के शब्द मात्र नहीं थे, बल्कि यह भारत भूमि के लिए मर मिटने का प्रण था। फौलाद सा शरीर, मूंछों पर ताव और चेहरे पर तेज वाले चंद्रशेखर आजाद की आंखों में आजादी का सपना था। वे ऐसे वीर सपूत थे, जिन्होंने अपनी बहादुरी और साहस की कहानी खुद लिखी।

27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि है। 1920 से 1930 के दशक में जब अंग्रेजी हुकूमत का दमन चरम पर था, उस वक्त चंद्रशेखर आजाद जैसे मतवालों ने आजादी की वो अलख जगाई, जिसने गोरी हुकूमत की जड़ों को हिलाकर रख दिया।

23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाबरा में जन्मे चंद्रशेखर के सीने में बचपन से ऐसी मशाल जल रही थी कि उन्होंने पुलिस की बर्बरता का विरोध प्रकट करते हुए एक अंग्रेज अफसर के सिर पर पत्थर दे मारा था।

महज 14 साल की उम्र में महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने अपना नाम 'आजाद', पिता का नाम 'आजादी' और पता 'जेल खाना' बताया। उम्र कम थी। ऐसे में अंग्रेज मजिस्ट्रेट चाहकर भी उन्हें चारदीवारी के अंदर की खौफनाक सजा नहीं सुना सकता था। इसलिए खीजकर 15 कोड़े की सजा सुनाई। हर कोड़े की मार पर दर्द नहीं था, बल्कि जुबान से 'भारत माता की जय' नारा निकला। यह एक ऐसी घटना भी थी, जिससे बालक चंद्रशेखर तिवारी का नाम 'चंद्रशेखर आजाद' पड़ा। इतिहासकार कपिल कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा, चौरी-चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी की तरफ से अपने आंदोलन को वापस लेने के निर्णय ने चंद्रशेखर आजाद को क्रांतिकारी बनाया, क्योंकि वे समझ गए थे कि अहिंसावादी तरीके से अंग्रेजों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है।

उनका मानना था कि अगर आपके लहू में रोष नहीं है, तो ये पानी है जो आपकी रगों में बह रहा है। ऐसी जवानी का क्या मतलब अगर वह मातृभूमि के काम न आए?

जब असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाने लगा और अंग्रेजों की बर्बरता हद से बाहर होने लगी, तो वे सशस्त्र क्रांति की सोच को लेकर चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़े। वे बहुत जल्द युवाओं के आदर्श बन चुके थे। अपनी बुद्धिमता से अंग्रेजों को चकमा देते रहे और नई-नई योजना बनाकर युवाओं को एकजुट करते रहे। उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' का गठन किया। इसके साथ-साथ आजाद ने अन्य क्रांतिकारी सदस्यों के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारत से भगाने का हरसंभव प्रयास किया। इतिहासकार कपिल कुमार ने इस बारे में कहा, पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी तरीकों से देश के अंदर गणतंत्र की स्थापना करना था, जिसका नाम 'हिंदुस्तान रिपब्लिकन' रखना था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का मतलब था कि यह क्रांतिकारी उसकी सेना है।

वे कहते थे, चिंगारी आजादी की सुलगी मेरे जश्न में है, इंकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में हैं। मौत जहां जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है।

वे स्वाधीनता संग्राम को एक नए आयाम तक पहुंचा चुके थे। आजाद 'काकोरी' की धरपकड़ और मुकदमे के दौरान पुलिस की बहुत कोशिशों के बाद भी हाथ नहीं आए। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया था।

उनका प्रण था कि 'आखिरी सांस' तक उन्हें कोई जिंदा पकड़ न सके। वे कभी अंग्रेजों के आगे आत्मसमर्पण नहीं कर सकते थे। 27 फरवरी 1931 को मुखबिर की सूचना पर ब्रिटिश पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया था। उन्होंने बहादुरी से पुलिस का मुकाबला किया। इतिहासकार कपिल कुमार कहते हैं, अंग्रेजों ने इस देश में कोई भी युद्ध बिना गद्दारों के नहीं जीता। क्रांतिकारियों के साथ यही हाल हुआ था। किसी न किसी ने क्रांतिकारियों की मुखबिरी की।

उनके अनुसार, जब चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद में थे, वे किसी के घर से आ रहे थे। यहां लोगों को मालूम था कि ये चंद्रशेखर आजाद हैं। सुखदेव से उनकी मुलाकात होनी थी। ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया था और दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। इस संघर्ष पर जब आजाद को पता लग चुका था कि बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने अपने प्रण को पूरा करने की ठान ली।

बीजापुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो माओवादी ढेर

बीजापुर, (पंजाब केसरी): छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के इंद्रावती नदी क्षेत्र में सुरक्षाकर्मियों के साथ हुई मुठभेड़ में गुरुवार को दो माओवादी मारे गए और भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया। अधिकारियों ने बताया कि बीजापुर के इंद्रावती नदी क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति के बारे में विशिष्ट खुफिया जानकारी मिलने के बाद यह अभियान शुरू किया गया था। सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने क्षेत्र में माओवादी विरोधी तलाशी अभियान शुरू किया। अभियान के दौरान गुरुवार सुबह इंद्रावती नदी क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच गोलीबारी हुई। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुठभेड़ के बाद इलाके की तलाशी में वर्दीधारी माओवादियों के दो शव बरामद हुए। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से एसएलआर राइफल, आईएनएसए राइफल और 12 बोर राइफल सहित कई हथियार जब्त किए गए। साथ ही विस्फोटक और माओवादी गतिविधियों से संबंधित अन्य सामग्री भी बरामद की गई है।

फैशन जगत में सांवली युवती की धूम

आकाश चोपड़ा

भारत में गोरा रंग एक गहरा सामाजिक मुद्दा है, जिसे अक्सर सुंदरता, सफलता और उच्च सामाजिक स्थिति से जोड़ा जाता है। औपनिवेशिक विरासत और ऐतिहासिक पूर्वग्रहों के कारण भारतीय समाज में गोरी त्वचा को पसंद किया जाता है जबकि काले रंग को अक्सर नकारात्मक रूप से देखा जाता है। यह पसंद सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक व्यापक सांस्कृतिक रूढ़िवादी सोच का हिस्सा है। रंग सुंदरता का प्रतीक है। विवाहों में गोरी त्वचा को अत्यधिक प्राथमिकता दी जाती है और इसके लिए कई उत्पाद और प्रथाएं मौजूद हैं। हर कोई गोरी दुल्हन चाहता है। इतना ही नहीं शादीशुदा जोड़ें बच्चों का रंग भी गोरा ही चाहते हैं। औपनिवेशिक शासन (ब्रिटिश काल) से भी पहले से मौजूद है, जो आर्यों और द्रविड़ों के समय से चली आ रही है, जहां गोरे रंग को कुलीन माना जाता था। विस्तृत श्रृंखला है लेकिन पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसे उत्तर-पश्चिमी राज्यों में गोरी त्वचा के लोग अधिक आम हैं। भारतीय मीडिया, फिल्मों और गानों में अक्सर गोरी त्वचा को "दीवाना" या आकर्षक बताया जाता है। जो इस सोच को और मजबूत करता है। हालांकि, अब युवा पीढ़ी में इस सोच को बदलने की कोशिश हो रही है। लोग रंग के बजाय व्यक्तित्व और गुणों को महत्व दे रहे हैं लेकिन 'गोरापन' का आकर्षण अभी भी बना हुआ है। मानसिकता के खिलाफ जागरूकता बढ़ रही है। कई लोग और विज्ञापन अब "रंगभेद" के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और गोरी त्वचा को ही एकमात्र सुंदरता का पैमाना मानने से इन्कार कर रहे हैं। दुनियाभर में सांवले रंग के लोग भी शीर्ष ऊंचाइयों को छू रहे हैं। चमड़ी के रंग का टैलेंट से कोई संबंध नहीं है। अगर आप में प्रतिभा है तो आप दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। आज समाज का कोई भी क्षेत्र हो चाहे उद्योगजगत हो, व्यापार हो, स्टार्टअप हो, शिक्षा का क्षेत्र हो सांवले रंग के लोग अपनी प्रतिभा का सिक्का जमा रहे हैं। यह खुशी की बात है कि फैशन की दुनिया में भी मानसिकता काफी हद तक बदल चुकी है। भविता मांडवा भारत की दूसरी ऐसी महिला हैं जिन्हें ब्रिटिश वोग मैगजीन में जगह मिली है। भविता मांडवा की यह उपलब्धि इतिहास रचने की भांति हैं। इसकी वजह यह है कि भविता मांडवा दूसरी ऐसी भारतीय हैं, जिन्होंने भारतीय सौंदर्य यानी डस्की स्किन टोन के साथ यह अवसर प्राप्त किया है। ये वो लड़की है जिसने फैशन इंडस्ट्री में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को फिर से डिफाइन करने का काम किया है। उनसे पहले प्रियंका चोपड़ा ने यह इतिहास बनाया था और प्रियंका चोपड़ा भी भारत के डस्की टोन की मल्लिका हैं। भविता मांडवा एक तेलुगू परिवार में जन्मी युवती हैं। 25 साल की 5 फुट 9 इंच लंबी इस मॉडल का बचपन हैदराबाद में गुजरा है। उन्होंने हैदराबाद के जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद उन्होंने न्यूयार्क में आगे की पढ़ाई की है। उसी दौरान भविता की पहचान डिजाइनर मैथ्यू ब्लेजी से हुई और भविता को 2025 के स्प्रिंग/समर शो में विशेष मॉडल के रूप में रैंप वॉक करने का मौका मिला। इसके बाद भविता मंडावा मेटियर्स डीआर्ट 2026 शनेल फैशन शो को ओपन करने वाली मॉडल बनीं।

भविता ने अपने इंटरव्यू में यह कहा है कि शैनेल फैशन शो की ओपनिंग मेरे लिए बहुत ही खास थी। पश्चिम के देशों में मेरी इस उपलब्धि ने इस आइडिया को जन्म दिया कि क्या भारतीय महिलाओं को ट्रेडिशनल रूप में सुंदर माना जा सकता है? भारत में रंगभेद हावी है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता और सुंदरता का पहला मापदंड ही यही है कि लड़की को गोरी होना चाहिए। वैसी दुनिया में भविता मांडवा की एचीवमेंट बहुत ही मायने रखती है। वोग की पत्रिका पर भविता मांडवा से पहले भी कई डस्की स्किन वाली लड़कियों ने जगह बनाई है लेकिन उनकी संख्या बहुत सीमित है, जिनमें प्रियंका चोपड़ा भी एक हैं। उन्होंने कहा, "सांवली लड़कियां खुद को देखा हुआ महसूस करती हैं," यह जोर देते हुए कि उनकी सफलता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक है। अपनी भारतीय पहचान और प्राकृतिक विशेषताओं को अपनाकर, वह एक ऐसे उद्योग में समावेशिता की दिशा में एक व्यापक बदलाव का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसने अक्सर विविध आवाजों को हाशिए पर रखा है। जहां चोपड़ा ने बॉलीवुड और हॉलीवुड की चकाचौंध को कवर पर पेश किया, वहीं मंडावा एक नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं जो शैक्षणिक उपलब्धि, डिजाइन में नवाचार और रैंप पर प्रभुत्व का संगम है। अपनी बुद्धिमत्ता, कलात्मकता और रैंप पर दमदार उपस्थिति के अनूठे मेल के साथ वह अंतर्राष्ट्रीय फैशन जगत में एक अहम नाम बनने के लिए तैयार हैं। उद्योग जगत के जानकार उन्हें मैथ्यू ब्लेज़ी जैसे डिज़ाइनरों के लिए प्रेरणास्रोत मानते हैं और कई क्षेत्रों में एक साथ काम करने की उनकी क्षमता उन्हें अपने साथियों से अलग करती है। भू-राजनीतिक तनाव के कारण, ब्रांड्स अब केवल लागत कम करने के बजाय लचीली और अनुकूलन आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं, ताकि वैश्विक झटकों का सामना किया जा सके। वैश्विक फैशन में अब केवल पश्चिमी मानकों का अनुकरण नहीं किया जा रहा है, बल्कि भारतीय जैसे घरेलू परिधान और औपचारिक उपदेश तंत्र को महत्व मिल रहा है।

भविता मांडवा भारतीय मॉडल युवतियों के लिए आदर्श बन सकती है। भारत में भी गोरी त्वचा के प्रति यह जुनून धीरे-धीरे बदल रहा है लेकिन अभी भी यह समाज में एक मजबूत धारणा के रूप में मौजूद है।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83

पंजाब केसरी

दिल्ली कार्यालय :

फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री ने विधानसभा में कहा- राज्य में पर्यटन के विकास के लिए कई योजनाएं तैयार

पटना से डोभी तक बनेगा ग्रीन कॉरिडोर : प्रमोद कुमार

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

पटना. बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रमोद कुमार ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश को पर्यटन का हब बनाने के क्रम में सरकार 'पायलट प्रोजेक्ट' के रूप में पटना से गया के रास्ते डोभी तक 'ग्रीन कॉरिडोर' का विकास करेगी।

मंत्री कुमार ने विधायक नीतीश मिश्रा, मंजीत सिंह और अन्य विधायकों के ध्यानाकर्षण का जवाब देते हुए कहा कि विभिन्न प्रकार के नियमों और रेगुलेशन से स्वीकृति मिलने में देरी के चलते पर्यटन से जुड़ी कुछ योजनाओं की प्रगति धीमी है, लेकिन सरकार उसके शीघ्र समाधान की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि 'ग्रीन कॉरिडोर' में प्रत्येक 10 किलोमीटर पर 'दादा का दालान' बनाया जाएगा, जहां बिहार टूरिस्ट से संबंधित जानकारियों के साथ 'सेल्फी पॉइंट' बनाया जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर के रास्ते में ग्राम पंचायतों के सौजन्य से सड़क के किनारे खेतों में आम, जामुन, आंवला और विभिन्न प्रकार के रसीले फलों के पेड़ लगाए जाएंगे। इस प्रयास से खूबसूरत रास्तों के साथ किसानों की आमदनी बढ़ेगी और सड़क के किनारे होने के कारण फलों को मंडियों तक पहुंचना भी आसान होगा।

गयाजी विष्णुपद मंदिर मार्ग को हरियाली से सजाया जाएगा

इसी तरह से गयाजी में विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर से हवाई अड्डे के रास्ते को पेड़ों से सजा कर खूबसूरत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन के विकास में जो भी नियामक बाधाएं हैं, उन्हें केंद्र, राज्य सरकार, पर्यटन विभाग, वन और पर्यावरण विभाग से जरूरी अनुमति लेकर दूर कर दिया जाएगा।

बक्सर और रोहतास में पर्यटन स्थलों का विकास

मंत्री ने कहा कि बक्सर में महर्षि विश्वामित्र पार्क का निर्माण होना है और इसके लिए 24 करोड़ 42 लाख की राशि स्वीकृत है। गुप्ता धाम तुतला भवानी, रोहतास के लिए 14 करोड़ 9 लाख तथा 11 करोड़ 08 लाख की राशि स्वीकृत है और वन तथा पर्यावरण एवं वाइल्ड लाइफ नियमों के तहत स्वीकृति का इंतजार है। करमचंद, 'इको टूरिज्म' रोहतास के विकास के लिए 49 करोड़ 73 लाख स्वीकृत किए गए हैं।

गोपालगंज थावे भवानी मंदिर में पर्यटन विस्तार

कुमार ने कहा कि गोपालगंज जिले में 4.1 एकड़ जमीन में मां थावे भवानी के मंदिर का पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जा रहा है। 9 करोड़ 92 लाख को स्वीकृति दे दी गई है। वन विभाग से स्वीकृति, जमीन अतिक्रमण हटाने और उच्च न्यायालय में लंबित एक मामले के निपटारे के बाद यहां काम शुरू होगा। उन्होने मां मुंडेश्वरी मंदिर, कैमूर के विकास के लिए 6 करोड़ 28 लाख तथा एक करोड़ 11 लाख एवं गयाजी में बराबर की गुफा के लिए 49 करोड़ 98 लाख के आबंटन की बात कही।

जापान दौरे पर मुख्यमंत्री योगी ने औद्योगिक साझेदारी को दी नई दिशा

'रिएक्टिव' नहीं, बल्कि 'प्रोएक्टिव' नीति से मजबूत हुई अर्थव्यवस्था'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को यामानाशी में उत्तर प्रदेश और जापान के यामानाशी प्रांत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में नई ऊर्जा भरने के लिए उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट रोड शो के दौरान भाषण दिया।

ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज पर एमओयू साइन

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

लखनऊ/जापान. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान दौरे के दूसरे दिन राज्य की औद्योगिक प्रगति और निवेश-अनुकूल नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश ने 'रिएक्टिव' नहीं बल्कि 'प्रोएक्टिव' नीति दृष्टिकोण अपनाया है। इसके परिणामस्वरूप राज्य की प्रति व्यक्ति आय और अर्थव्यवस्था तीन गुना बढ़ी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश-यामानाशी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान इंडस्ट्री, पर्यटन और वोकेशनल एजुकेशन में सहयोग बढ़ाने के लिए एक एमओयू साइन किया गया। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज पर विशेष ध्यान दिया गया।

योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए आइआइटी कानपुर को ग्रीन हाइड्रोजन में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित कर रहा है। उन्होंने अगस्त में 200 सीईओ के डेलीगेशन के उत्तर प्रदेश दौरे के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि इससे औद्योगिक साझेदारी और निवेश की गति और तेज होगी।

निवेश रोड शो में आमंत्रण

मुख्यमंत्री ने यामानाशी में आयोजित 'उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट रोड शो' में भाग लिया और जापान के उद्योगपतियों एवं बिजनेस लीडर्स को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने ग्रीन एनर्जी, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और अवसंरचना क्षेत्रों में साझेदारी का आह्वान किया। योगी ने कहा कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्ट यूपी का जापान डेस्क और यीडा में प्रस्तावित जापान इंडस्ट्रियल टाउनशिप निवेशकों को स्केल, स्किल और स्पीड के साथ बेहतर सुविधा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर और सभी स्टेकहोल्डर्स का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह सहयोग साझा आर्थिक दृष्टि और सांस्कृतिक जुड़ाव पर आधारित है।

जमुई : पार्टी के बहाने बुलाकर व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या

जमुई@पत्रिका. बिहार में जमुई जिले के चंद्रमंडी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि बुधवाडीह गांव में बुधवार की शाम द्वारिका प्रसाद यादव (52) की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई।

मृतक द्वारिका प्रसाद यादव के पुत्र कुंदन यादव ने बताया कि बुधवार की देर शाम बगल के गांव बर्नपुर निवासी पिंटू यादव ने उनके पिता को चिकन पार्टी के बहाने बुलाया। पिंटू का घर उनके घर से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर है। कुंदन ने बताया कि उनके पिता द्वारिका प्रसाद यादव और मंझले चाचा लालकिशोर यादव बाइक से जा रहे थे। रास्ते में बांस की बाड़ी में पहले से घात लगाए बैठे संजय यादव सहित पांच से छह लोगों ने बाइक रोककर लाठी-डंडा, रॉड और कुदाल से हमला कर दिया। मंझले चाचा किसी तरह जान बचाकर भाग निकले, लेकिन उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके दोनों हाथ-पैर और सिर में गंभीर चोटें आईं। उन्हें इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

चंद्रमंडी थानाध्यक्ष गजेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ गुरुवार सुबह देवघर अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक द्वारिका प्रसाद यादव के बेटे के फर्द बयान पर पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

झारखंड : जमशेदपुर में भव्य भूमिपूजन समारोह संपन्न

मुर्मु ने जगन्नाथ सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी

100 करोड़ की लागत से बनेगा सांस्कृतिक केंद्र

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रांची . झारखंड के मरीन ड्राइव (कदमा) जमशेदपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण के लिए आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच धार्मिक पुरोहितों द्वारा पूरे विधि-विधान के साथ भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न कराया गया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शिलापट्ट का अनावरण कर श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी। इस अवसर पर सांसद बिद्युत बरन महतो, विधायक सरयू राय, विधायक पूर्णिमा साहू सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र का संचालन श्री जगन्नाथ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल चैरिटेबल सेंटर ट्रस्ट द्वारा की जाएगी। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस केंद्र की रूपरेखा ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर होगी।

सोरेन ने कहा कि हम सभी लोग यहां श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण के लिए आयोजित भूमि पूजन समारोह का साक्षी बन रहे हैं। उन्होंने श्री जगन्नाथ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल चैरिटेबल सेंटर ट्रस्ट की सोच एवं उद्देश्य की सराहना की। उन्होंने विश्वास जताया कि ट्रस्ट के माध्यम से आने वाले समय में यहां एक अभूतपूर्व और भव्य केंद्र मूर्त रूप लेगी। मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सीईओ एवं एमडी टाटा स्टील टीवी नरेंद्रन, मैनेजिंग ट्रस्टी श्री जगन्नाथ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल चैरिटेबल सेंटर एसके बेहरा, ट्रस्टी मनोरंजन दास एवं श्रीधर प्रधान सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे।

भूमि पूजन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान।

मुख्यमंत्री ने जय जगन्नाथ का उद्घोष किया

सोरेन ने जय जगन्नाथ का उद्घोष करते हुए अपने संबोधन में कहा कि निश्चित रूप से देश और दुनिया में ऐसी कई संस्थाएं हैं जहां अलग-अलग उद्देश्य और अलग-अलग विचारों के साथ कुछ चीजें स्थापित की जाती है। इन संस्थाओं के माध्यम से हम स्वयं के साथ साथ-साथ मानव जीवन को भी तराशते हैं। इसी कड़ी में सामाजिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक समन्वय के भव्य जीवंत केंद्र के स्थापना की नींव रही जा रही है।

पूसा के मखाना अनुसंधान केंद्र से बेहतर होगा उत्पादन: रामनाथ ठाकुर

समस्तीपुर@पत्रिका. केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि मखाना उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए पूसा में मखाना अनुसंधान केंद्र खोला गया है।

ठाकुर ने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कृषि मंत्रालय बिहार समेत देश मे काम कर रहा है। इस अवसर पर भारत सरकार के बागवानी आयुक्त डॉ. प्रभात कुमार ने कहा कि वर्तमान में 35 से 38 हजार हेक्टेयर में मखाना की खेती की जा रही है, जिसे बढ़ाकर 55 से 60 हजार हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। मखाना के उत्पादकता को दोगुना करने के लिए यह केंद्र प्रसंस्करण, विपणन और गुणवत्तापूर्ण मखाना के उत्पादन में काम करेगा।

किसानों के आर्थिक विकास के प्रति कृत संकल्पित केंद्र सरकार: केन्द्रीय मंत्री ठाकुर ने गुरुवार को समस्तीपुर जिले के पूसा स्थित डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में मखाना अनुसंधान विकास केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के आर्थिक विकास के प्रति कृत संकल्पित है। बिहार में मखाना की खेती एवं गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने समस्तीपुर जिले के पूसा स्थित इस विश्वविद्यालय में मखाना अनुसंधान विकास केंद्र की स्थापना की है।

कार में जलकर महिला कांस्टेबल और मासूम की मौत

रामपुर @ पत्रिका. उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के गंज क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में महिला कांस्टेबल लता (27) और उनके ढाई वर्षीय पुत्र अभियांश की कार में जलकर मौत हो गई। हादसे में लता के पति दान सिंह और रिश्तेदार रवि को मामूली चोटें आई।

पुलिस के अनुसार, लता अपने परिवार के साथ नैनीताल से लौट रही थीं। देर रात ग्राम काशीपुर के पास उनकी कार की अज्ञात डंपर से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई, जिससे लता और उनके पुत्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है और मृतकों के शव मोर्चरी में रखवाए गए हैं। थाना गंज पुलिस ने अज्ञात डंपर चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया।

'एपस्टीन फाइल्स' से ध्यान भटकाने की साजिश : अविमुक्तेश्वरानंद

पुलिस जांच रिपोर्ट साझा करने पर उठाए सवाल

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

वाराणसी. ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि उनके खिलाफ झूठा मामला उछालकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित 'एपस्टीन फाइल्स' से ध्यान भटकाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य को बदनाम करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा जा रहा है और जनता को विवादों में उलझाकर असली मुद्दों से ध्यान हटाने का प्रयास किया जा रहा है। शंकराचार्य ने आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस जांच रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने पर आपत्ति जताई।

मठ परिसर और राजनीतिक आरोपों पर प्रतिक्रिया: मठ परिसर में 'शीशमहल' होने के आरोपों पर शंकराचार्य ने कहा कि यदि परिसर में शीशे लगे हैं तो इससे पारदर्शिता ही बढ़ती है और कोई भी अंदर की स्थिति देख सकता है। उन्होंने कहा कि मठ में कुछ भी छिपा नहीं है और यदि सरकार के अधिकारी देखना चाहें तो कभी भी आ सकते हैं। प्रयागराज माघ मेले से जुड़े विवाद और एक उपमुख्यमंत्री पर धरने के लिए उकसाने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले उन्हें कभी समाजवादी पार्टी तो कभी बहुजन समाज पार्टी से जोड़ते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लेते। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में भाजपा के भीतर दो तरह की प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं और उन पर आरोप लगाने वाले लोग 'बुलडोजर भाजपा' की सोच का हिस्सा हैं।

सारण : गोली लगने से किशोर घायल

छपरा @ पत्रिका. बिहार में सारण जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गुरुवार को अपराधियों ने एक किशोर को गोली मार कर घायल कर दिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि हरनारायण छपरा गांव निवासी शिवम कुमार को अपराधियों ने गोली मार कर घायल कर दिया। परिजन शिवम को इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक चिकित्सा के बाद शिवम को बेहतर इलाज के लिए पटना भेज दिया। सूत्रों ने बताया कि पुलिस घायल किशोर का बयान लेने के लिए पटना गई हुई है। किशोर के बयान के आधार पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जांच करेगी।

घरेलू विवाद : साले ने बहनोई की हत्या की

जमुई @ पत्रिका. बिहार में जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद में एक व्यक्ति ने अपने बहनोई की हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि बुधवार की देर शाम मोगल चपरी गांव निवासी कालीचरण भुइयां का अपनी पत्नी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। वहां मौजूद कालीचरण का साला तोता मांझी बीच-बचाव करने पहुंचा। झगड़ा बढ़ने पर आवेश में आकर तोता मांझी ने तवा उठाकर कालीचरण भुइयां पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से कालीचरण की मौके पर ही मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया।

सीएम ने पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम के निधन पर संवेदना व्यक्त की

पटना @ पत्रिका. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि पूर्णमासी राम एक कुशल राजनेता एवं समाजसेवी थे। वे 1990 से लगातार पांच बार तक बगहा के विधायक रह चुके थे। वे गोपालगंज लोकसभा सीट से सासंद भी रहे थे। वे मृदुभाषी एवं सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता ने मधुबनी सदर अस्पताल में किया निरीक्षण

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

मधुबनी . राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने बिहार में मधुबनी सदर अस्पताल का दौरा कर अस्पताल में महिला मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तृत निरीक्षण किया।

इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य अस्पताल में महिलाओं और प्रसूति सेवाओं की गुणवत्ता की जांच करना था। ममता कुमारी के नेतृत्व में आई टीम ने मॉडल अस्पताल, प्रसव कक्ष (लेबर रूम), प्रसूति वार्ड और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विभाग का गहनता से जायजा लिया। विशेष रूप से प्रसव कक्ष में प्रदर्शित सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्रियों की टीम ने सराहना की, जो मरीजों को जागरूक करने के लिए लगाई गई हैं। ममता कुमारी ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर सुधार आवश्यक है, जिससे दूर-दराज से आने वाली महिलाओं को सुलभ और सम्मानजनक इलाज मिल सके।

संतोष व्यक्त किया: निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया। टीम ने दवाओं के स्टॉक,रखरखाव और वितरण प्रणाली की जांच की। वार्डों में भर्ती महिला मरीजों से खान-पान की गुणवत्ता और स्वास्थ्यकर्मियों के व्यवहार के बारे में सीधा संवाद किया गया। प्रसव के बाद दी जाने वाली देखभाल और शिशुओं के लिए उपलब्ध चिकित्सा व्यवस्था का अवलोकन किया। टीम ने अस्पताल की स्वच्छता और वहां उपलब्ध बुनियादी ढांचे को देख संतोष व्यक्त किया।

मुंगेर में 'राजस्व प्रशासन आपके द्वार' कार्यक्रम कल

पटना@पत्रिका. बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मुंगेर जिले में 28 फरवरी को ''राजस्व प्रशासन आपके द्वार'' कार्यक्रम का आयोजन करेगा। अपर सचिव आजीव वत्सराज ने समाहर्ता, मुंगेर को पत्र जारी कर आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह कार्यक्रम 28 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रेक्षा गृह सभागार, मुंगेर में आयोजित होगा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल करेंगे। इस अवसर पर मुंगेर जिले के बन्दोबस्त पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर), जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी तथा राजस्व कर्मचारी/अमीन के साथ राजस्व से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर समीक्षात्मक बैठक होगी।

बैठक के लिए विस्तृत एजेंडा निर्धारित किया : बैठक के लिए विस्तृत एजेंडा निर्धारित किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से परिमार्जन प्लस की प्रगति, दाखिल-खारिज/नामांतरण वादों की स्थिति, भूमि विवादों का निष्पादन, सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, डीसीएलआर न्यायालयों में लंबित वाद, भूमि मापी की प्रगति, राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली की स्थिति और राज्य में चल रहे भूमि सर्वेक्षण की अद्यतन स्थिति पर फोकस होगा।

पटना : जनसंख्या के अनुपात में चिड़ियाखानों को बनाने के निर्देश

पटना @ पत्रिका. बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने गुरुवार को सदन में निर्देश दिया कि अन्य प्रदेशों का अध्ययन करते हुए बिहार सरकार प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में चिड़ियाखानों का निर्माण एवं विकास करे। भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा के बिहार में चिड़ियाखानों की कम संख्या विषय पर ध्यानाकर्षण पर वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रमोद कुमार के जवाब के बाद अध्यक्ष कुमार ने सरकार को निर्देश दिये कि अन्य प्रदेशों का अध्ययन कर बिहार में भी जनसंख्या के हिसाब से चिड़ियाखानों को निर्मित और विकसित किया जाए।

टहलने के दौरान छत से गिरे सहायक अवर निरीक्षक, मौत

गोड्डा @ पत्रिका. झारखंड के गोड्डा जिले के टाऊन थाना क्षेत्र में सहायक अवर निरीक्षक की छत से गिरने से मौत गई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को अशोक यादव अपने आवास के छत पर चहलकदमी कर रहे थे। अचानक पैर फिसल गया और छत के नीचे गिर गए। गंभीर हालत में उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टर ने भागलपुर रेफर कर दिया गया था। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। गोड्डा टाउन थाना में कार्यरत सहायक अवर निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे।

शिवराज ने वाराणसी में कृषि वैज्ञानिकों के साथ की समीक्षा बैठक

सब्जी उत्पादन में गुणवत्ता और निर्यात पर बल

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

वाराणसी. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान परिसर में रक्त-चंदन का पौधरोपण किया और वैज्ञानिकों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि सब्जी उत्पादन की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के बीच निरंतर समन्वय आवश्यक है।

नवाचारों का लाभ किसानों तक पहुंचे: प्रक्षेत्र भ्रमण के दौरान मंत्री ने किसानों से बीजों की उपलब्धता, उत्पादन लागत कम करने के उपायों और आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर संवाद किया। वैज्ञानिकों ने ग्राफ्टेड बैंगन-टमाटर (ब्रिमेटो) और आलू-टमाटर (पोमेटो) जैसी तकनीकों पर प्रस्तुति दी। मंत्री ने इन नवाचारों की सराहना करते हुए निर्देश दिया कि इनका लाभ शीघ्र किसानों तक पहुंचे। उन्होंने 'हाई-टेक नर्सरी' की उपयोगिता पर बल देते हुए एफपीओ के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण पौध एवं बीज उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताई।

मंत्री ने टमाटर सहित अन्य सब्जियों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने, प्रसंस्करण योग्य किस्मों के विकास, निर्यातोन्मुखी उत्पादन तथा जैविक खेती को प्रोत्साहन देने पर बल दिया। उन्होंने संस्थान द्वारा विकसित सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक, बायो-स्टिमुलेंट और बायोपेस्टिसाइड उत्पादों का अवलोकन किया।

शिवराज ने लगाई विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी

वाराणसी @ पत्रिका. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर विधि-विधान से दर्शन-पूजन किया। उन्होंने बाबा विश्वनाथ से देशवासियों के सुख, स्वास्थ्य और कल्याण की कामना की। मंदिर में दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में चौहान ने कहा, ''सौभाग्य से बाबा विश्वनाथ के दर्शन प्राप्त हुए हैं। मेरी यही कामना है कि बाबा सभी पर अपनी कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें। देश की जनता सुखी व निरोग रहे और सभी का कल्याण हो।

स्थापना दिवस पर नेताजी की अनदेखी

सपा का विश्वविद्यालय प्रशासन पर हमला

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

इटावा. उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई के स्थापना दिवस समारोह में समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के परिवार की कथित अनदेखी को लेकर सपा ने तीखा विरोध दर्ज कराया है। सपा नेताओं का आरोप है कि कार्यक्रम में नेताजी का नाम तक नहीं लिया गया और उनके परिवार के प्रमुख नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया।

आरोप है कि प्रोफाइल फिल्म में भी नेताजी की तस्वीर शामिल नहीं की गई। सपा नेताओं ने कहा कि

नेताजी का नाम नहीं लिया गया

सपा जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य और प्रदेश सचिव गोपाल यादव ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने अपने संबोधन में मुलायम सिंह यादव का उल्लेख नहीं किया, जबकि विश्वविद्यालय की स्थापना उनके कार्यकाल में हुई थी।

क्षेत्रीय विधायक शिवपाल सिंह यादव और सांसद डिंपल यादव को आमंत्रित न करना अपमानजनक है। उन्होंने इसे भाजपा की ''छोटी सोच'' बताते हुए चेतावनी दी कि पार्टी कार्यकर्ता जनजागरण अभियान चलाकर मामले को व्यापक स्तर पर उठाएंगे।

मानव सम्पदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण का अंतिम मौका

लखनऊ@ पत्रिका. उत्तर प्रदेश सरकार ने मानव सम्पदा पोर्टल पर संपत्ति का विवरण न देने वाले 47 हजार 816 कर्मचारियों को राहत देते हुए अंतिम अवसर प्रदान किया है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने गुरुवार को सभी एसीएस, प्रमुख सचिवों, विभागाध्यक्षों और मंडलायुक्तों को आदेश जारी कर 10 मार्च तक विवरण अपलोड कराने के निर्देश दिए।

आदेश के अनुसार कर्मचारियों को 31 जनवरी तक संपत्ति का विवरण दर्ज करना था। निर्धारित अवधि तक विवरण न देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

राजस्व वसूली पर बिहार परिवहन विभाग सख्त

लक्ष्य से कम राजस्व वसूली पर 40 अधिकारियों को शो-कॉज नोटिस

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

पटना. बिहार परिवहन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्धारित राजस्व लक्ष्य से कम राजस्व वसूली पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य के विभिन्न जिलों के 10 जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ), 10 अपर जिला परिवहन पदाधिकारी (एडीटीओ), कई मोटर यान निरीक्षक (एमवीआइ) और प्रवर्तन अवर निरीक्षक (ईएसआइ) सहित कुल 40 पदाधिकारियों को शो-कॉज नोटिस जारी किया है। इन अधिकारियों से तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है, अन्यथा विभागीय कार्रवाई होगी।

गौरतलब है परिवहन मंत्री के निर्देशानुसार विभागीय पदाधिकारियों द्वारा गत कुछ महीनों में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन निबंधन सहित अन्य लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। परिणामस्वरूप लंबित मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। राजस्व संग्रहण में वृद्धि के उद्देश्य से आगामी 15 दिनों के भीतर संबंधित पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी, जिससे कार्यप्रणाली में और सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

मंत्री कुमार ने बताया कि निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करना सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया गया: परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने पिछले दिनों में विभागीय समीक्षा बैठक की, जहां डीटीओ, एमवीआइ, ईएसआइ आदि के कार्य को असंतोषजनक बताते हुए सुधार के लिए दो महीने का समय दिया था। लेकिन निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बावजूद इन पदाधिकारियों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया गया।

प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन उनके कार्य-प्रदर्शन के आधार पर: मंत्री कुमार ने स्पष्ट किया कि आगे चलकर पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति /पदस्थापन उनके कार्य-प्रदर्शन के आधार पर ही सुनिश्चित की जाएगी। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, कई जिलों में राजस्व वसूली लक्ष्य का महज 8 से 14 प्रतिशत ही हुई है।

रोहतास : पर्यटकों से भरी बस ने ट्रक में मारी टक्कर, एक की मौत

डेहरी आन सोन @ पत्रिका. बिहार में रोहतास जिले के डेहरी मुफस्सिल थाना क्षेत्रमें गुरुवार की सुबह तमिलनाडु के पर्यटकों से भरी बस ने एक ट्रक में टक्कर मार दी, जिससे एक व्यकि की मौत हो गई तथा 19 अन्य घायल हो गए।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि सुअरा गांव के समीप गुरुवार सुबह तमिलनाडु के कांचीपुरम के पर्यटकों से भरी बस ने एक ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा 19 लोग घायल हो गए। बस पर 24 लोग सवार थे।

घायलों को नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों ने बताया कि मृतक की पहचान तमिलनाडु के कांचीपुरम अब्राहम स्ट्रीट निवासी राजू एम (72) के रूप में की गई है।

विरोध प्रदर्शन

लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद लाल बारादरी को बंद करने के विरोध में स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन और सोशल एक्टिविस्ट ने गुरुवार को हजरतगंज के परिवर्तन चौक पर विरोध प्रदर्शन किया।

मेरा अनुभव बताता है कि एआइ के इस्तेमाल से स्मार्ट-मेहनती लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। युवाओं को इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ इस टेक्नोलॉजी को जानने-सीखने की जरूरत है।

एन. आर. नारायणमूर्ति को-फाउंडर, इंफोसिस

पत्रिका फाइनेंस

@ बिजनेस & वेल्थ

शेयर बाजार		सोना	चांदी	डॉलर
सेंसेक्स 82,248 (-24.76)	निफ्टी 25,496 (+14.05)	स्टैंडर्ड (24K) ₹1,63,500 (प्रति 10 ग्राम) (-750)	चांदी (999) ₹2,73,000 (प्रति किग्रा) (-3000)	₹90.91 (प्रति 1 डॉलर) (+0.00)

सीएलएसए रिपोर्ट स्मॉलकैप से उम्मीदें ज्यादा पर नतीजे कर रहे निराश, अर्निंग डाउनग्रेड ज्यादा देखने को मिली

मुनाफे की पिच पर सरपट भाग रहीं मिडकैप कंपनियां

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

मुंबई. कमाई के मामले में दिसंबर तिमाही में बड़ी और छोटी कंपनियों के मुकाबले मझोली (मिडकैप) लगातार छठी तिमाही आगे रहीं। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए के मुताबिक, अर्निंग ग्रोथ में मिडकैप-लार्जकैप कंपनियां जहां मजबूत दिख रही हैं, स्मॉलकैप फर्म्स पर अर्निंग कटौती का दबाव बढ़ रहा है। सीएलएसए रिपोर्ट बताती है कि स्मॉलकैप को लेकर बाजार में उम्मीदें ऊंची हैं, लेकिन जमीन पर प्रदर्शन उतना मजबूत नहीं है। स्मॉलकैप कंपनियों के वर्ष 2026-27 और 2027-28 अर्निंग अनुमान में क्रमशः 3.9% व 3.1% की कटौती की गई है। दिलचस्प बात यह है कि इसके बावजूद अगले 2 साल में सबसे तेज कमाई का अनुमान अब भी स्मॉलकैप के लिए लगाया जा रहा है।

2026-27 और 2027-28 के अर्निंग अनुमान में क्रमशः ***3.9% और 3.1% की कटौती की गई है स्मॉलकैप कंपनियों के लिए***

इतनी रही कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ

(दिसंबर तिमाही में कंपनियों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स)

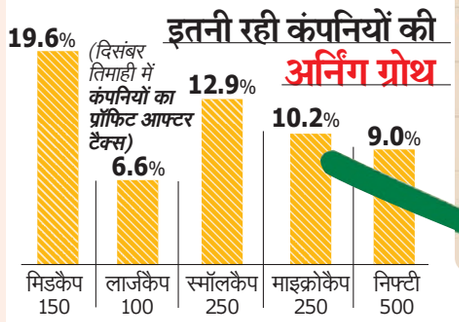

लिस्टेड कंपनियों का स्कोर कार्ड

विवरण	राशि	इजाफा
कुल बिक्री	39,50,483	13.7%
ऑपरेटिंग प्रॉफिट	5,73,312	10.0%
नेट प्रॉफिट	2,88,058	11.2%

(2986 लिस्टेड फर्म्स का दिसंबर तिमाही स्कोर, बैंक-फाइनेंस शामिल नहीं)

28.4% सीएजीआर ***अर्निंग ग्रोथ का अनुमान*** स्मॉलकैप के लिए अगले दो साल में

(अमरीका से ट्रेड डील-दिसंबर तिमाही के ***बेहतर नतीजों का दिखा असर)***

इतना मिला रिटर्न

श्रेणी	पिछले एक माह में
लार्जकैप 100	2.57%
मिडकैप 150	5.13%
स्मॉलकैप 250	4.79%
माइक्रोकैप 250	4.88%
निफ्टी 500	2.76%

डाउनग्रेड का जोखिम

स्मॉलकैप कंपनियों के लिए अगले दो साल में 28.4% सीएजीआर अर्निंग ग्रोथ का अनुमान है। मिडकैप के लिए यह 22% और लार्जकैप के लिए 13.4% है। इसके उलट, लार्जकैप कंपनियों के 2026-27 और 20207-28 के अनुमान में क्रमशः 0.6% और 0.9% की बढ़ोतरी हुई। मिडकैप में 2026-27 के लिए हल्की कटौती हुई, लेकिन 2027-28 के लिए अनुमान बढ़ाया गया है। ब्रोकरेज का मानना है कि हालिया प्रदर्शन और भविष्य की उम्मीदों के बीच का यह अंतर स्मॉलकैप कंपनियों के लिए आगे और डाउनग्रेड का जोखिम बढ़ा सकता है। ब्रोकरेज ने साफ कहा है कि वह लार्जकैप को प्राथमिकता देता है और स्मॉलकैप में ज्यादा जोखिम देखता है। जब उम्मीदें ऊंची हों और वैल्यूएशन भी महंगा हो, तब निराशा की गुंजाइश बढ़ जाती है।

बदला ट्रेंड सस्ते मोबाइल की कम बिक्री, प्रीमियम फोन की मांग बढ़ी

चाइनीज मोबाइल से भारतीयों का हो रहा मोहभंग, पहली बार घट गई बिक्री

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. देश में सस्ते स्मार्टफोन की बिक्री घटने और एपल-सैमसंग के प्रीमियम फोन की मांग बढ़ने से पहली बार वर्ष 2025 में भारत में चीन की स्मार्टफोन कंपनियों की बिक्री में गिरावट आई है। भारत में 9 प्रमुख चीनी कंपनियों का कुल रेवेन्यू 2024-25 में 4.5% घटा। 2023-24 में इनके रेवेन्यू में 42% की तेजी आई थी। काउंटरपॉइंट रिसर्च के मुताबिक, देश में 20,000 रुपए से कम कीमत के स्मार्टफोनों की वैल्यू साल 2023 के 38% से घटकर 2025 में 29% रह गई है। इससे चीनी कंपनियों की बिक्री घटी है। हालांकि हालांकि, वॉल्यूम के लिहाज से इनकी बाजार हिस्सेदारी अब भी 73% है।

चीनी कंपनियों की बज गई 'घंटी'

कंपनी	बिक्री घटी-बढ़ी
ओप्पो	-38%
वनप्लस	-13%
रियलमी	-8.4%
शाओमी	-07%
वीवो	10.91%
लेनोवो	24%

इतने रुपए के चीनी स्मार्टफोन खरीदे

वर्ष	राशि
2022-23	1.30
2023-24	1.72
2024-25	1.65

(राशि लाख करोड़ रुपए में)

₹45,000 से अधिक के फोन की हिस्सेदारी 47%, जो 2023 में 36%

₹20,000 से कम कम स्मार्टफोन की कुल बिक्री में हिस्सेदारी घटकर वर्ष 2025 में 29% हो गई, ***जो 2023 में 38% थी***

कीमतें बढ़ने की आशंका एक्सपर्ट का कहना है कि मेमोरी चिप्स सहित कंपोनेंट्स की कीमतों में तेज बढ़ोतरी और रुपए की कमजोरी के कारण स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ रही हैं। इसका सबसे ज्यादा असर लोअर और मिड-प्राइस सेगमेंट पर पड़ेगा, जहां उपभोक्ताओं की खरीद क्षमता पहले ही सीमित है।

रिपोर्ट जयपुर-भोपाल-रायपुर शामिल

वेयरहाउसिंग बूम... देश के 30 शहर भविष्य के हॉटस्पॉट

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. भारत के औद्योगिक और वेयरहाउसिंग बाजार में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। यह परिवर्तन नीति प्रोत्साहन, इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार, उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव, आपूर्ति श्रृंखला का पुनर्गठन और टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाने के कारण हो रहा है। रियल एस्टेट रिसर्च फर्म कॉलियर्स की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 30 शहरों को औद्योगिक और वेयरहाउसिंग हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया है। जिनमें प्रमुख, उभरते और नए हब शामिल हैं। ये हॉटस्पॉट भविष्य में उद्योग और वेयरहाउसिंग की बढ़ती मांग को पूरा करेंगे, जिससे निवेशकों और डेवलपर्स को नए अवसर मिलेंगे।

ये शहर बनेंगे हब

जो शहर वेयरहाउसिंग के भविष्य के हॉटस्पॉटबन सकते हैं, उनमें प्रमुख हब में अहमदाबाद, बेंगलूरु, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे शामिल हैं। उभरते हुए हब में भोपाल, इंदौर, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, जयपुर, कोच्चि, लखनऊ, नासिक, पटना, सूरत, विशाखापट्टनम शामिल हैं, जबकि नवजात यानी अभी नए बन रहे हब में अमरावती, गुवाहाटी, होसूर, जम्मू, जमशेदपुर, कानपुर, नागपुर, प्रयागराज, रायपुर और विजयवाड़ा को शामिल किया गया है।

इन मापदंडों पर की गई पहचान

देश में औद्योगिक और वेयरहाउसिंग क्षेत्र के लिए 30 उच्च पोटेंशियल शहरों की पहचान पांच प्रमुख मापदंडों पर आधारित है। जिनमें औद्योगिक और माल परिवहन गलियारों के माध्यम से उन्नत कनेक्टिविटी, आगामी औद्योगिक स्मार्ट शहर, प्रस्तावित मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क, समुद्र और हवाई अड्डे लिंक का विस्तार, बड़े एकीकृत टेक्सटाइल हब का विकास शामिल हैं। इन हब का विकास न केवल डेवलपर्स के लिए, बल्कि राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण होगा।

2030 तक वार्षिक मांग 5 करोड़ वर्ग फुट

भारत का औद्योगिक और वेयरहाउसिंग क्षेत्र तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है, जिसे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनियों और विभिन्न क्षेत्रों जैसे ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, एफएमसीजी, ई-कॉमर्स आदि में मजबूत मांग से समर्थन मिल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2030 तक शीर्ष 8 शहरों (प्रमुख हब) में ग्रेड ए वेयरहाउसिंग स्पेस की वार्षिक मांग 5 करोड़ वर्ग फुट से अधिक होने का अनुमान है।

सेबी एसेट एलोकेशन का गणित बदला, बच्चों और रिटायरमेंट वाली 44 स्कीमें बंद

इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीमों को मिली गोल्ड-सिल्वर में निवेश की मंजूरी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

मुंबई. बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सेबी ने 26 फरवरी को एक सर्कुलर जारी कर म्यूचुअल फंड स्कीमों के कैटेगराइजेशन के पुराने स्ट्रक्चर को पूरी तरह बदल दिया है। इस फैसले का असर निवेशकों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटजी पर पड़ेगा। सेबी ने सॉल्यूशन ओरिएंटेड कैटेगरी को पूरी तरह खत्म कर दिया। वहीं लक्ष्य आधारित निवेश के लिए नया लाइफ साइकिल फंड शुरू किया गया है। साथ ही इक्विटी और हाइब्रिड स्कीमों के लिए निवेश की सीमाएं भी नए सिरे से तय कर दी गई हैं।

एक्टिव इक्विटी स्कीम्स को सोना और चांदी में निवेश की अनुमति दे दी है। सोना और चांदी में निवेश का विकल्प मिलने से फंड मैनेजरों को बाजार की अस्थिरता से निपटने में ज्यादा लचीलापन मिलेगा। अब तक इक्विटी स्कीम्स को अपने कुल निवेश का 20-35% तक हिस्सा नॉन-इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जैसे डेट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (रीट्स) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) में लगाने की अनुमति थी। अब इस मिक्स में सोना और चांदी को भी शामिल किया जा सकेगा। सेबी ने अपने सर्कुलर में यह भी साफ किया है कि म्यूचुअल फंड स्कीमों के नाम उनके काम के आधार पर ही होंगे। फंड कंपनियां ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी जो केवल रिटर्न का लालच देते हों। सेबी ने एक्टिव इक्विटी और हाइब्रिड कैटेगरीज की संख्या 11 से बढ़ाकर 12 कर दी है। अब फंड हाउस को वैल्यू व कॉन्ट्रा और बैलेंस्ड व एग्रेसिव हाइब्रिड फंड दोनों तरह की योजनाएं पेश करने की अनुमति मिल गई है। नए नियमों का पालन करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है।

लक्ष्य आधारित निवेश के लिए 'लाइफ साइकिल फंड' की शुरुआत, **'सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम' बंद**

एसेट एलोकेशन बदला

1. सबसे बड़ा बदलाव मल्टी कैप फंड्स में देखने को मिला है। अब इन फंड्स के लिए ***एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) का कम से कम 75% हिस्सा इक्विटी में निवेश करना अनिवार्य हो गया है।***
2. फंड मैनेजर को लॉर्ज कैप, मिड कैप और ***स्मॉल कैप में कम से कम 25-25% निवेश करना जरूरी होगा।***
3. इसी तरह, लार्ज कैप फंड के लिए नियम और सख्त कर दिए गए हैं। अब इन स्कीमों को ***अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 80% हिस्सा लार्ज-कैप कंपनियों के शेयरों में रखना होगा।***
4. वहीं, लार्ज और मिड कैप कैटेगरी की स्कीमों के लिए दोनों कैटेगरीज में ***कम से कम 35-35% का एलोकेशन जरूरी कर दिया गया है।***

'सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम' बंद

सेबी ने 'सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम' कैटेगरी को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इस कैटेगरी में वे म्यूचुअल फंड स्कीम्स आती हैं, जिन्हें खास तौर पर बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट जैसे लक्ष्यों के लिए बनाया गया था। सेबी के इस फैसले का मतलब यह है कि अब इस श्रेणी की कोई नई योजना नहीं आएगी और जो योजनाएं पहले से चल रही हैं, वे अब नए निवेश स्वीकार नहीं करेंगी। धीरे-धीरे इन योजनाओं को अन्य समान प्रकृति वाली म्यूचुअल फंड योजनाओं में मिलाया जाएगा।

लक्ष्य आधारित निवेश को लाइफ साइकिल फंड शुरू

सेबी ने निवेशकों को लक्ष्य आधारित निवेश का नया विकल्प देने के लिए 'लाइफ साइकिल फंड' नाम से नई श्रेणी भी शुरू की है। ये फंड लंबी अवधि के निवेश के लिए बनाए जाएंगे और समय के साथ-साथ अपने आप जोखिम कम करते जाएंगे। उदाहरण के तौर पर, शुरुआत में इनमें इक्विटी का हिस्सा ज्यादा होगा, लेकिन जैसे-जैसे लक्ष्य की तारीख नजदीक आएगी, निवेश धीरे-धीरे सुरक्षित विकल्पों में शिफ्ट हो जाएगा।

निवेश अवधि: इन फंड्स की अवधि कम से कम 5 साल और अधिकतम 30 साल तक हो सकती है। इससे निवेशकों को अपने वित्तीय लक्ष्यों, जैसे बच्चों की शिक्षा या रिटायरमेंट के लिए बेहतर और व्यवस्थित तरीके से निवेश करने में मदद मिलेगी। हालांकि ये योजनाएं पूरे इन्वेस्टमेंट पीरियड में रिडेम्पशन के लिए खुली रहेंगी, लेकिन वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए इन पर ज्यादा एग्जिट लोड (पहले साल में 3%) लागू होगा।

फंड हाउस की विभिन्न स्कीम्स में ओवरलैप पर सख्ती

अब अगर कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड दोनों चलाती है, तो उनके पोर्टफोलियो में 50% से ज्यादा समानता (ओवरलैप) नहीं होनी चाहिए। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि हर योजना वास्तव में अलग रणनीति के साथ काम करे। नए फ्रेमवर्क के तहत सेक्टोरल-थीमैटिक और अन्य इक्विटी स्कीम्स (लार्जकैप फंड्स को छोड़कर) के बीच पोर्टफोलियो ओवरलैप 50% से ज्यादा न हो। अगर तीन साल के भीतर यह ओवरलैप तय सीमा से नीचे नहीं लाया गया, तो ऐसी योजना को दूसरी योजना में मिलाना अनिवार्य होगा। अब फंड हाउस को हर महीने अपनी वेबसाइट पर पोर्टफोलियो ओवरलैप की जानकारी देनी होगी, जिससे निवेशकों को पूरी पारदर्शिता मिल सके।

तैयारी 1 अप्रेल से विदेशी बेंचमार्क अलविदा

गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ की वैल्यू घरेलू भाव से तय होगी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

मुंबई. सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के पास रखे फिजिकल सोने और चांदी के मूल्यांकन ढांचे में संशोधन किया है। सेबी के निर्देश के मुताबिक, 1 अप्रेल 2026 से गोल्ड और सिल्वक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में रखे गए भौतिक सोने और चांदी का मूल्यांकन विदेशी कीमतों की बजाय देश की हाजिर बाजार की कीमतों के आधार पर किया जाएगा। सेबी ने गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि म्यूचुअल फंड्स को सोने और चांदी का मूल्यांकन उन पोल्ड स्पॉट कीमतों (औसत हाजिर भाव) के आधार पर करना होगा, जिन्हें मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज प्रकाशित करते हैं और जिनका उपयोग भौतिक डिलीवरी वाले गोल्ड और सिल्वर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स के निपटान के लिए किया जाता है। पिछले एक साल में गोल्ड ईटीएफ मे निवेशकों को 82% तक तो सिल्वर ईटीएफ ने 172% तक रिटर्न दिया है।

अभी ऐसे होती है तय

अभी तक सोना और चांदी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की कीमत तय करने की प्रक्रिया लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (एलबीएमए) की सुबह तय होने वाली कीमतों पर आधारित थी। इसके बाद उन कीमतों में मुद्रा विनिमय दर, परिवहन खर्च, सीमा शुल्क, टैक्स और अन्य शुल्क जोड़कर देश में लागू कीमत निकाली जाती थी। सेबी का कहना है कि देश की हाजिर कीमतों के इस्तेमाल से मूल्यांकन अधिक पारदर्शी होगा और यह भारतीय बाजार की वास्तविक स्थिति को बेहतर तरीके से दर्शाएगा। इससे पूरे उद्योग में एक समान व्यवस्था लागू होगी। हाजिर कीमत तय करने की प्रक्रिया सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए। एम्फी सेबी के साथ मिलकर इसे लागू करने के लिए नीति तैयार करेगा।

तैयारी बचेंगे 6 लाख करोड़ रुपए

पेट्रोल-डीजल विदेश से लाने को भारत खरीदेगा खुद के जहाज!

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. भारत कच्चे तेल और ईंधन की ढुलाई के लिए विदेशी जहाजों पर निर्भर रहता है। इस पर सालाना करीब 6 लाख करोड़ रुपए का भारी खर्च होता है। अब प्रमुख तेल कंपनियां इस खर्च को कम करने की तैयारी में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक खास जॉइंट वेंचर बनाने का बड़ा फैसला किया है। इस प्रस्तावित नई कंपनी में तीनों सरकारी तेल कंपनियों की कुल 35% हिस्सेदारी होगी। वहीं, शिपिंग कॉर्पोरेशन इस नई कंपनी में 50% के साथ प्रमुख भागीदार की भूमिका निभाएगा। बची 15% हिस्सेदारी मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड (एमडीएफ) के पास रहेगी।

₹15,000 करोड़ का निवेश, 59 नए जहाज

एमडीएफ सरकार की एक विशेष पहल है, जिसे समुद्री क्षेत्र में वित्तीय मदद देने के लिए 25,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी जहाजों पर निर्भरता को खत्म करना और मूल्यवान विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखना है। शिपिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बीके त्यागी ने कहा, इस ज्वाइंट वेंचर की तकनीकी शर्तों पर तेजी से काम चल रहा है। इस महायोजना के तहत 59 जहाज खरीदे जाएंगे। इनमें बड़े क्रूड कैरियर, गैस कैरियर और ऑफशोर जहाज शामिल होंगे। इस पूरी खरीद प्रक्रिया में लगभग 15,000 से 17,000 करोड़ रुपए निवेश होने का अनुमान है।

योजना इन राज्यों में हुई शुरुआत

ई-रुपए से मिलेगा राशन, डिजिटल वॉलेट में सब्सिडी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रही है, जिसमें लोगों को डिजिटल रुपए से राशन मिलेगा और सब्सिडी की राशि उनके डिजिटल वॉलेट में आएगी। सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाइ) के तहत खाद्य सब्सिडी को ई-रुपए के माध्यम से देने जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत गुजरात के चार जिलों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुई है, जिसे देशभर में लागू करने की योजना है। अब तक खाद्य सब्सिडी का लाभ या तो वस्तु के रूप में या पारंपरिक डीबीटी के जरिए मिलता था। नई व्यवस्था में पात्र लाभार्थियों के लिए एक विशेष डिजिटल वालेट बनाया जाएगा। सरकार तय सब्सिडी राशि इसी वालेट में ई-रुपये के रूप में भेजेगी, जिसे केवल राशन खरीदने के उद्देश्य से ही इस्तेमाल किया जा सकेगा।

सीधे दुकानदार के खाते में जाएगी राशि

इससे सब्सिडी के दुरुपयोग या राशि के अन्य मदों में खर्च होने की आशंका कम होगी। प्रयोग सफल रहा तो यह खाद्य सुरक्षा, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और डिजिटल मुद्रा के एकीकरण का राष्ट्रीय माडल बन सकता है। पात्र लाभार्थी उचित मूल्य की दुकानों पर भुगतान क्यूआर कोड या कूपन कोड के माध्यम से कर सकेंगे। लेनदेन की प्रक्रिया पूरी होते ही राशि सीधे दुकानदार के खाते में पहुंच जाएगी और उसका डिजिटल रिकार्ड तुरंत दर्ज हो जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, भुगतान में देरी घटेगी और लाभार्थी तथा दुकानदार दोनों को सुविधा मिलेगी। 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' और राशन कार्ड के डिजिटलीकरण के बाद यह तीसरी बड़ी पहल है।

एपल पे

पेमेंट सेवा शुरू करने की तैयारी में एपल

नई दिल्ली@ पत्रिका. आइफोन बनाने वाली कंपनी एपल भारत में जल्द अपनी पेमेंट सेवा एपल पे शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी देश के बड़े बैंकों और अंतरराष्ट्रीय कार्ड नेटवर्क के साथ बातचीत कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, एपल आइसीआइसीआइ, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक से बातचीत कर रही है। कंपनी का लक्ष्य 2026 के मध्य तक भारत में एपल पे लॉन्च करना है। हालांकि लॉन्च की समयसीमा अभी तय नहीं है, लेकिन बातचीत से संकेत मिलते हैं कि तैयारी आगे बढ़ रही है। कंपनी मास्टरकार्ड और वीजा जैसे कार्ड नेटवर्क के साथ भी चर्चा कर रही है। एपल पे को यूपीआइ से भी सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।

डब्ल्यूटीओ सब्सिडी पर सवाल, मेक इन इंडिया के सामने नई परीक्षा

'मेक इन इंडिया' पहल को पीछे धकेलने की कोशिश में जुटे चीन और अमरीका

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. भारत की महत्वाकांक्षी विनिर्माण मुहिम 'मेक इन इंडिया' को अब वैश्विक स्तर पर नए दबाव का सामना करना पड़ रहा है। अब अमरीका और चीन जैसे प्रमुख देशों ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाली पीएलआइ योजना सहित कुछ नीतियों पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि भारत की ओर से दी जा रही प्रोत्साहन योजनाएं अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के खिलाफ हैं। अमरीका ने आरोप लगाया है कि भारतीय कंपनियों को सरकारी मदद मिलने से प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो रही है। इसी आधार पर भारतीय सोलर उत्पादों पर 126% टैरिफ लगाया है। वहीं चीन ने डब्ल्यूटीओ में शिकायत दर्ज कराई है।

पीएलआइ योजना के बाद ऐसे बढ़ा सोलर उत्पादन

डब्ल्यूटीओ ने जांच पैनल गठित किया है, जो यह देखेगा कि भारत की नीतियां सही हैं या नहीं। जांच में भारत की योजनाएं नियमों के खिलाफ पाई जाती हैं, तो देश पर दबाव बढ़ सकता है।

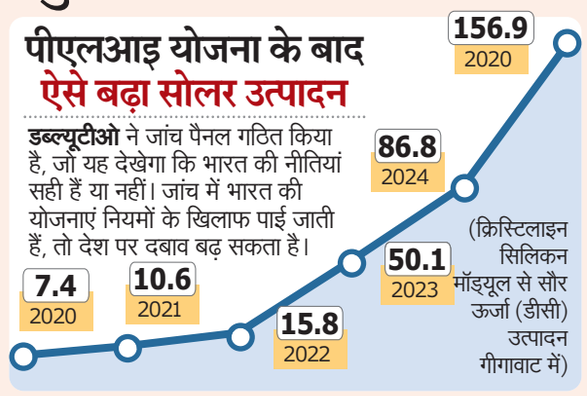

चिंता: घर की सफाई में हो रहे थे इस्तेमाल

एक चूक और 7 हजार रोबोट इंजीनियर के कंट्रोल में आ गए

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

न्यूयॉर्क. सफाई करने वाला रोबोट और स्मार्ट होम गैजेट्स आपके घर की जासूसी कर सकते हैं। हाल ही अमरीका के इंजीनियर ने 24 देशों के हजारों गैजेट्स पर कंट्रोल पाने का दावा किया है। सैमी अजदोफल ने बताया कि एक तकनीकी चूक के कारण उन्हें करीबन 7 हजार घरों के रोबोट्स और वैक्यूम क्लीनर्स का एक्सेस मिल गया। वे हजारों रोबोट, कैमरा और माइक को कंट्रोल पा रहे थे। घरों के अंदर के नजारे, लाइव कैमरा फीड और लोगों की निजी बातें भी सुन पा रहे थे। विशेषज्ञ चिंता जाहिर कर रहे हैं कि इससे प्राइवेसी को बड़ा खतरा हो सकता है।

एक्सेस मिलने के बाद क्या किया?

सैमी ने रोबोट को रिमोट से चलाने के लिए कोडिंग करते वक्त गलती से मास्टर एक्सेस पा लिया। कंपनी के सर्वर ने उन्हें आम यूजर की जगह मास्टर ओनर समझ लिया। सैमी ने तुरंत कंपनी को जानकारी दी। गैजेट्स बनाने वाली डीजेआई कंपनी ने कहा कि सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है।

एपस्टीन फाइल्स: जांच के बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सीईओ का इस्तीफा

जिनेवा @ पत्रिका. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष और सीईओ बोर्ज ब्रेंडे ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अमरीका के यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से उनके संबंधों की जांच पूरी होने के बाद यह इस्तीफा हुआ। एपस्टीन फाइल्स में खुलासा हुआ था कि ब्रेंडे ने एपस्टीन के साथ तीन बिजनेस डिनर में हिस्सा लिया था। ईमेल और मैसेज के जरिए उससे संपर्क भी किया था।

पेज एक का शेष

इजरायल में...

मोदी ने कहा कि दोनों देश डिफेंस में जॉइंट डेवलपमेंट, प्रोडक्शन व टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर पर भी काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत व इजरायल के रिश्ते गहरे भरोसे, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूत नींव पर बने हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं।

हमने इस पार्टनरशिप को विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने का ऐतिहासिक फैसला किया है। दो नों नेताओं ने क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भारत मध्यपूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा (आइ-मेक) और भारत-इजरायल-संयुक्त अरब अमीरात-अमरीका (आइ-टू-यू-टू) पर भी बातचीत की। मोदी ने यरूशलम में इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्गोज से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और उन्हें भारत आने का न्योता दिया।

5 साल में 50000 भारतीय श्रमिकों का कोटा: दोनों देशों में इस पर समझौता हुआ कि आने वाले पांच साल में इजरायल में 50,000 भारतीय श्रमिकों को अवसर मिलेगा। इससे रोजगार के अवसर खुलेंगे। अभी वहां 10,000 भारतीय श्रमिक कार्यरत हैं।

आतंकवाद के खिलाफ, गाजा में शांति का समर्थन: मोदी ने कहा कि भारत और इजरायल की स्पष्ट सोच है कि दुनिया में किसी भी रूप में आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है और दोनों देश कंधे-से-कंधा मिलाकर आतंक और उनके समर्थकों का विरोध करते रहेंगे। उन्होंने गाजा शांति योजना का समर्थन करते हुए भारत की साफ सोच बताई कि मानवता कभी भी युद्ध और संघर्ष की शिकार नहीं बननी चाहिए।

यात्रा अत्यधिक सफल: भारत— मोदी के इजरायल दौरे को भारत ने अत्यधिक सफल बताया है। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने दौरे को 'रिच और प्रोडक्टिव' बताते हुए कहा कि इसमें 16 एमओयू हुए व अन्य घोषणाएं हुईं। यह दौरा प्रधानमंत्री की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वे पश्चिम एशिया के देशों के साथ भारत के रिश्तों को सक्रिय रूप से मजबूत कर रहे हैं। मिसरी ने कहा कि इजरायल में 'स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल' सम्मान पाने वाले पीएम मोदी दुनिया के पहले शख्स हैं।

चैप्टर से...

कोर्ट में एनसीआरटी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, सबसे पहले, हम बिना शर्त माफी मांगते हैं। स्कूल एजुकेशन के सेक्रेटरी यहां हैं। उन्होंने कहा कि जो बुक बाजार में छपकर गई थी वो वापस ले ली गई है। इस मामले में जिम्मेदार रहे लोगों को काम में नहीं लाया जाएगा। 32 किताबें बाजार में आईं, उन्हें वापस लिया जा रहा है। एक टीम पूरे चैप्टर को फिर से देखेगी। इस पर सीजेआइ ने कहा कि आपने तो बहुत हल्के में छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि किताब बाजार में मौजूद है। मुझे भी सोर्स से एक कॉपी मिली है। उन्होंने कहा कि हम बिना शर्त माफी अभी स्वीकार नहीं करेंगे, वरना भविष्य में कोई भी ऐसा करेगा। हम इस संस्थान की गरिमा को नुकसान नहीं पहुंचने दे सकते।

मंशा नहीं न्यायपालिका का अपमान: प्रधान– एनसीईआरटी की किताब को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जो कुछ हुआ उससे गहरा दुख है। सरकार या शिक्षा मंत्रालय की ओर से न्यायपालिका का अपमान करने की कोई मंशा नहीं थी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा और जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई भी होगी।

चाबहार के लिए भारत से फंड न मिलना नुकसानदेह: ईरान

तेहरान@ पत्रिका. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए भारत के बजट में इस साल फंड आवंटित नहीं किए जाने पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि यह फैसला सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के लिए भी नुकसानदेह है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी इस पोर्ट को सुनहरा द्वार कहा था। अगर चाबहार बंदरगाह का पूरी तरह विकास हो जाए, तो यह भारत को ईरान के रास्ते मध्य एशिया, काकेशस और यूरोप तक जोड़ने में बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। मुझे लगता है कि यह सबसे बेहतरीन ट्रांजिट रूट हो सकता है।

प्रेरणा

उन लोगों को खुशी जरूर मिलती है, जो दूसरों की मदद करते हैं। - **वॉल्ट डिज्नी**

संपादकीय

देश के लिए आत्मनिर्भरता पहली शर्त होनी चाहिए

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रम्प के टैरिफ-संबंधी आदेश को गैरकानूनी करार देने से तिलमिलाए ट्रम्प अब दुनिया के देशों को धमकाने लगे हैं। भारत के सौर उत्पादों पर 126% टैरिफ लगा दिया है। ट्रम्प नीति से परेशान तमाम देशों ने कुछ हद तक तो बर्दाश्त किया, लेकिन अब नए ट्रेडिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं। इकोनॉमिक फोरम में कनाडा के पीएम ने अनायास ही दुनिया से उठ खड़े होने की अपील नहीं की थी। यूएन के कई संगठन, ईयू और नाटो भी अपने पैरों पर खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं। तमाम देशों के नागरिकों के लिए आत्मनिर्भरता इस समय पहली शर्त होनी चाहिए। संभव है कि पाकिस्तान जैसे कुछ देश चाटुकारिता करके कुछ समय के लिए अपना स्वार्थ सिद्ध कर लें, लेकिन वे भूल रहे हैं कि आत्मसम्मान खोकर कोई राष्ट्र ज्यादा दिन नहीं टिकता। भारत ने अकारण ही नहीं युद्ध में मध्यस्थता के ट्रम्प के अनवरत दावों को शालीन तरीके से नकारा है। ट्रम्प ने जब भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा तो भारतीय नेतृत्व ने धैर्य और संकल्प के साथ तमाम ट्रेड समझौते किए। इनमें सबसे अहम थे, ईयू से डील और ताजा एआई इम्पैक्ट समिट। ईयू डील तो ट्रम्प की दबंगई पर दुनिया के एक-चौथाई लोगों का जवाब था। वहीं एआई समिट में दुनिया के तमाम देशों का आना और भारत-नीत घोषणापत्र पर दस्तखत करना यह संदेश है कि दुनिया भी बदल रही है।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

बच्चों की मित्र मंडली के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए

जैसे कुछ साइट्स पर जाने से रोकने के लिए गेट वॉल्व होते हैं, वैसे ही हम अपने बच्चों को सिखाएं कि कुसंग के लिए गेट वॉल्व बनाएं। पहले माना जाता था कि बच्चे जब युवा उम्र में जाएं तो उनकी मित्रता कुसंग में न बदल जाए, इसकी सावधानी रखी जाए। लेकिन ये खतरा अब बालपन से भी शुरू हो गया है। टेढ़े बच्चों से सीधे बच्चों को बचाया जाए। माता-पिता बच्चों के मित्रों का पारिवारिक बैकग्राउंड पता करें। इसका एक अच्छा प्रयोग भगवान शंकर ने किया था। टेढ़े चंद्रमा को उन्होंने मस्तक पर लगाया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि चंद्रमा को श्रीराम और श्रीकृष्ण ने अपने नाम के साथ जोड़ा। इसीलिए मैंने मस्तक पर लगाकर सम्मान दिया। किसी के बैकग्राउंड को जानकर उसका सदुपयोग करना शिव जी सिखा रहे हैं। हमारे बच्चों के साथ जो उनकी मित्र मंडली जुड़ी हुई है, उनके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। यदि हम अपने बच्चों के भविष्य को संवारना चाहते हैं तो उनके मित्रों के वर्तमान और अतीत की पूरी जानकारी रखिएगा। •Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

टु द पीपुल • गत दशक की घटनाएं क्या बताती हैं?

हम कई तरह के संवैधानिक मानकों से दूर भटक आए हैं

सौहार्द

डेरेक ओ ब्रायन
राज्यसभा में टीएमसी के नेता
office@derek.in

कुछ दिन पहले जैसे ही चांद दिखा, हमारी मोबाइल स्क्रीन पर रमजान मुबारक के संदेश उभर आए। लेकिन शुभकामनाओं के बीच दो क्लिप ऐसी भी थीं, जिन्हें एल्गोरिदम नीचे नहीं धकेल सका। पहली, असम के मुख्यमंत्री का एक समुदाय को इस हद तक प्रताड़ित करने का आह्वान कि वे न केवल राज्य, बल्कि देश तक छोड़ने को मजबूर हो जाएं। दूसरी, 28 सेकंड का एक वीडियो, जिसमें बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े एक प्रश्न के उत्तर में धार्मिक पृथक्करण का आह्वान करते हैं। सचमुच, हम संवैधानिक नैतिकता से कितने दूर भटक आए हैं!

अब जब पांच राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं तो सियासी बयानबाजी और अधिक विषैली ही होती चली जाएगी। मुस्लिम समुदाय अक्सर साम्प्रदायिक हमलों का टारगेट रहा है। लेकिन आज मैं इस समुदाय के एक उप-सम्प्रदाय- दाऊदी बोहरा शिया इस्माइली मुसलमानों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। भारत में मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है। इनमें से पांच लाख दाऊदी बोहरा हैं। ऐसा समुदाय, जो स्वयं मुस्लिम समुदाय का भी मात्र 0.25% है, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के लिए क्यों मायने रखता है? हमेशा की तरह, असली बात बारीकियों में छिपी है।

'बोहरा' शब्द गुजराती के 'वोहरवु' या 'व्यवहार' से निकला है, जिसका अर्थ है 'व्यापार करना'। बोहरा मुख्यतः व्यापारिक समुदाय है। विश्वभर में उनके सदस्यों की साक्षरता दर लगभग 100 प्रतिशत है। अपनी कम संख्या के बावजूद वे एक प्रगतिशील समुदाय हैं। उनकी प्रति व्यक्ति आय अन्य मुस्लिम समुदायों की तुलना में अधिक है। भारत के बोहराओं में से लगभग आधे गुजरात में रहते हैं। प्रधानमंत्री उनकी भाषा गुजराती बोलते हैं। जब संसद में विवादास्पद वक्फ संशोधन विधेयक पारित हुआ था तो उसके कुछ ही दिनों बाद प्रधानमंत्री ने बोहरा समुदाय के सदस्यों के साथ एक भेंटवार्ता की थी। इसमें बोहरा समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने वक्फ कानून की प्रशंसा की थी। इसके जरिए यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि भारत के मुसलमान इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। जबकि बोहरा 20 करोड़ की मुस्लिम आबादी में से मात्र पांच लाख ही हैं।

यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 मूलतः संघीय ढांचे और अल्पसंख्यकों के हितों के प्रतिकूल है। गैर-एनडीए दलों (जिनमें टीएमसी, कांग्रेस, एआईएमआईएम, सपा, द्रमुक, राजद शामिल हैं) के मुस्लिम और गैर-मुस्लिम सांसदों ने विधेयक को उसके मूल आधार पर चुनौती दी है। यहां रोचक बात यह है कि दाऊदी बोहराओं के प्रतिनिधियों ने 1923 में ही मुसलमान वक्फ अधिनियम से उन्हें बाहर रखे जाने की बात कही थी। उनका तर्क था कि बोहरा समुदाय अल-दाई अल-मुतलक में आस्था रखता है, जो समुदाय की सभी सम्पत्तियों के एकमात्र न्यासी हैं। समुदाय चाहता है कि उसके सदस्यों को अपनी मान्यताओं के अनुरूप सम्पत्तियों की स्थापना और उनके प्रबंधन की अनुमति दी जाए। वक्फ संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित वक्फ बोर्ड इस स्वायत्तता को चुनौती देता है। ऐसे में पूछा जा सकता है कि समुदाय का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलने और उस विधेयक का समर्थन करने के लिए क्यों सहमत हुआ, जिसका वे ऐतिहासिक रूप से विरोध करते रहे हैं?

अल्पसंख्यकों के प्रति खुलेआम प्रदर्शित की जाने वाली कट्टरता, पक्षपात और पूर्वग्रह की तुलना में भाजपा की यह रणनीति अधिक सूक्ष्म कही जा सकती है। पिछले एक दशक की घटनाओं का बारीकी से मुआयना करें तो एक बात समझ में आती है कि भाजपा चुपचाप अल्पसंख्यकों को एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा करना चाहती है। वह इन समूहों के अंदरूनी मामलों में विसंगतियों की पहचान करती है और उनमें अपनी मदद की पेशकश करती है, ताकि व्यापक रूप से विवादास्पद मुद्दों पर उनका समर्थन हासिल किया जा सके।

इंडोनेशिया व पाकिस्तान के बाद भारत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के पास एक भी ऐसा मुस्लिम सांसद नहीं है, जो उसके चुनाव-चिह्न पर निर्वाचित हुआ हो।

भारत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार यह समुदाय देश की कुल आबादी का 15% है। लेकिन भाजपा के पास एक भी ऐसा मुस्लिम सांसद नहीं है, जो उसके चुनाव-चिह्न पर निर्वाचित हुआ हो। गुलाम अली राज्यसभा में 'नामांकित' श्रेणी के अंतर्गत 12 सदस्यों में से एक थे। छह महीने की समय-सीमा के भीतर उन्होंने सभापति को पत्र लिखकर स्वयं को भाजपा सदस्य के रूप में शामिल किए जाने का अनुरोध किया था। यूपी में चार करोड़ मुसलमान हैं, फिर भी 403 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा का एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है। दूसरी तरफ 8% हिंदू आबादी वाले बांग्लादेश को देखें, जिसने हाल ही में हिंदू समुदाय से एक मंत्री का चुनाव किया है! **(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

नजरिया • लुटियन्स दिल्ली का एक पहलू यह भी

गुलामी के प्रतीकों को हटाने का हमें स्वागत करना चाहिए

नया भारत

पवन के. वर्मा
पूर्व राज्यसभा सांसद व राजनयिक
pavankvarma1953@gmail.com

यूं तो मैं नई दिल्ली की सड़कों, प्रतिमाओं और इमारतों में सरकार द्वारा किए गए हर परिवर्तन का समर्थन नहीं करता हूं। मिसाल के तौर पर, मुझे समझ नहीं आता कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ क्यों किया गया। न ही मैं यह समझ पाया हूं कि मुगल गार्डन्स का नाम बदलकर अमृत उद्यान क्यों किया गया, क्योंकि वह उद्यान मुगल शैली में ही निर्मित है। लेकिन इस महीने जब राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन में एडविन लुटियन्स की प्रतिमा के स्थान पर सी. राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया, तो इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। लुटियन्स बेशक एक प्रतिभाशाली आर्किटेक्ट रहे होंगे, लेकिन वे असंदिग्ध नस्लवादी थे। भारतीयों के प्रति उनके मन में गहरी अवमानना की भावना थी, जिसे उन्होंने कभी नहीं छिपाया।

इसका अकाट्य प्रमाण 1985 में प्रकाशित पुस्तक 'द लेटर्स ऑफ एडविन लुटियन्स टु हिज वाइफ लेडी एमिली' में मिलता है। भारत का कुछ भी लुटियन्स को प्रभावित नहीं कर सका था- न वास्तुकला, न दर्शन, न संस्कृति और यहां के लोगों की चमड़ी का रंग तो हरगिज नहीं। इंदौर के डेली कॉलेज में उन्होंने छात्रों को एक नस्लवादी शब्द से सम्बोधित किया था। बनारस में उन्होंने पाया कि यहां 'हर तरह के काले लोग, हर तरह का काम करते' हैं। मद्रास के लोगों के लिए तो उन्होंने और अभद्र टिप्पणी की। एक अन्य प्रसंग में उन्होंने लिखा कि 'भारत के लोगों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती'। भारतीय धर्मों में उन्हें कोई बौद्धिकता नजर नहीं आई। अपने निजी स्टाफ के नामों पर भी वे फब्ती कसने से नहीं चूके। उन्होंने कहा, 'ये लोग वो तमाम हरकतें करते हैं, जो किसी भी गोरे साहब को ऊबा सकती हैं।'

भारतीय वास्तुकला भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाई। बनारस के घाटों के किनारे स्थित मंदिर उन्हें 'बच्चों के खिलौने वाले पेड़ों' जैसे प्रतीत हुए। कुतुब मीनार की गढ़न उनके अनुसार बेपरवाह और बेढंगी थी। मुम्बई में होलकर का महल उन्हें अभद्र और उदयपुर का राजप्रासाद उन्हें आदिम लगा था। ताजमहल को भी उन्होंने खारिज करते हुए कह दिया कि वह यूनानियों और रोमनों की कृतियों के आसपास भी नहीं ठहरता।

उनके साथ काम करने वाले भारतीय शिल्पकारों के बारे में उनकी टिप्पणी थी कि 'इन्हें भद्दे पैटर्न्स और अनगढ़ देवप्रतिमाएं बनाने के सिवा कुछ नहीं आता'। एक निर्माण के अंतिम चरणों में काम का निरीक्षण करते हुए उन्होंने लिखा कि 'लापरवाह भारतीय हमेशा की तरह चीजें बरबाद कर रहे थे और बेतरतीबी फैला रहे थे'। वे अपनी पत्नी के लिए बुद्ध प्रतिमा खरीदना चाहते थे, पर उन्हें कुछ भी मानक के अनुरूप नहीं लगा। उन्होंने लिखा- 'हे भगवान, यहां सबकुछ कितना कुरूप है।' यहां तक कि राष्ट्रपति भवन के भव्य गुम्बद को भी लुटियन्स ने इस प्रकार कल्पित किया था कि वह 'ब्रिटिश सैनिक, अधिकारी, मिशनरी या वायसराय के टोपीधारी सिर की छवि' उत्पन्न करे, जबकि इसे लुटियन्स के समर्थक भारतीय वास्तुकला से प्रेरित बताते हैं।

इन तमाम उद्धरणों से स्पष्ट है कि हम भारतीयों और हमारी महान सभ्यता के प्रति लुटियन्स का रवैया एक कुपढ़, बददिमाग और नस्लवादी व्यक्ति का था। ऐसे में स्वयं राष्ट्रपति भवन में लुटियन्स की प्रतिमा का होना हमारी औपनिवेशिक विस्मृति का दयनीय प्रतीक था। यह पूर्णतः उपयुक्त है कि अब लुटियन्स की प्रतिमा को हटाकर उन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

यह पूर्णतः उपयुक्त है कि अब लुटियन्स की प्रतिमा को हटाकर उन सी. राजगोपालाचारी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम और एकमात्र गवर्नर-जनरल थे। वे एक सच्चे गांधीवादी व स्वतंत्रता सेनानी थे।

की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम और एकमात्र गवर्नर-जनरल थे। राजाजी एक सच्चे गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रीमियर, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में व्यापक राजनीतिक-प्रशासनिक अनुभव प्राप्त था। वे चिंतक और लेखक भी थे। उनका साहित्यिक योगदान- जिसमें रामायण और महाभारत के अनुवादों से लेकर संस्कृति और राजनीति पर चिंतनपरक निबंध तक शामिल हैं- भारतीय बौद्धिक परम्परा को और समृद्ध बनाते हैं।

हम ऐसे गणराज्य हैं, जो अपनी सार्वजनिक स्मृति को अपनी ही मिट्टी में रोपना चाहता है। हमें सरकार को इस निर्णय के लिए बधाई देनी चाहिए, जो औपनिवेशिक इमारतें बनाने वाले के बजाय राष्ट्र की अंतश्चेतना के निर्माण में योगदान देने वाले व्यक्ति की स्मृति को समर्पित है। **(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

ब्रांड से सबक | crocs™ | अमेरिका की मशहूर फुटवियर कंपनी

कभी बदसूरत जूते कहलाए, 2009 में एक डॉलर से नीचे था शेयर, अब 44 हजार करोड़ की कंपनी है क्रॉक्स

सबक क्यों- कंपनी ने जूतों की 'बदसूरती' को अपनी मजबूती के तौर पर पेश किया और दुनिया में अलग पहचान बनाई।

क्या आप जानते हैं? क्रॉक्स के हर जूते में ठीक 13 छेद होते हैं। यानी एक जोड़ी जूते में कुल 26 छेद। इन छेदों में लगाने वाले छोटे-छोटे चार्म्स को 'जिबिट्ज' कहा जाता है। 2005 में एक मां ने बच्चों के क्रॉक्स सजाने के लिए इसे बनाया था। कंपनी को यह आइडिया इतना पसंद आया कि सिर्फ एक साल बाद ही क्रॉक्स ने उस महिला से यह आइडिया करीब एक करोड़ डॉलर में खरीद लिया। आज ये चार्म्स क्रॉक्स की सबसे बड़ी और कस्टमाइज्ड पहचान हैं। 2002 में शुरुआत से केवल 4 साल बाद यानी 2006 में लोगों पर क्रॉक्स का नशा इस कदर छा गया था कि इसका आईपीओ अमेरिका में इतिहास का सबसे बड़ा शू आईपीओ बना। कंपनी इस प्रसिद्धि को हजम नहीं कर पाई। उसने बड़ी संख्या में स्टोर्स खोल दिए, लेकिन 2008 की मंदी के बाद हालात इतने बुरे हो गए कि 2009 में कंपनी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में खुद लिखा कि 'हो सकता है कि हम अब सर्वाइव न कर सकें'। यह कहानी बताती है कि प्रसिद्धि पाने के बाद उसे बनाए रखने के लिए मजबूत और कारगर योजनाओं का होना जरूरी है, अन्यथा अर्श पर पहुंचने वाली बड़ी-बड़ी कंपनियां भी तेजी से धरातल पर आ जाती हैं। ऐसे में ब्रांड से सबक में आज पढ़िए कहानी क्रॉक्स की।

क्रॉक्स के तीनों को-फाउंडर्स।

14 हजार जोड़ी के करीब क्रॉक्स बिकते हैं हर घंटे दुनियाभर में।

30-40% की दर से बढ़ रहा है क्रॉक्स का व्यापार हर साल भारत में।

12.9 करोड़ जोड़ी क्रॉक्स बेचे थे कंपनी ने जनवरी-दिसंबर 2025 में दुनियाभर में।

200 से अधिक पार्टनर स्टोर हैं भारत में क्रॉक्स के। यह एशिया में दूसरा बड़ा बाजार।

ऐसे संकट में फंसी थी क्रॉक्स

❶ **पहचान का संकट-** कंपनी ने हर किसी के लिए कुछ न कुछ बनाना शुरू कर दिया। हाई हील्स, लेदर शूज और कपड़े तक। इससे ब्रांड की आरामदायक फोम शूज की मूल पहचान धुंधली हो गई।

❷ **2008 की मंदी :** मंदी में बिना बिके माल का अंबार लग गया। रिटेलर्स ऑर्डर कैंसिल कर रहे थे। कैश घट गया। कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया।

❸ **जरूरत से अधिक विस्तार :** क्रॉक्स ने बड़ी संख्या में रिटेल स्टोर और कियोस्क खोल दिए। मांग का सही अनुमान लगाए बिना उत्पादन कई गुना बढ़ा दिया। जब 2008 में मांग घटी, तो भारी-भरकम खर्च और खाली पड़े स्टोर्स का किराया बचा।

❹ **फैड फडीग :** 2007-08 तक क्रॉक्स को सिर्फ एक अल्पकालिक फैशन ट्रेंड (फैड) माना जाने लगा। फैशन आलोचकों ने इसे 'दुनिया का सबसे बदसूरत जूता' कहकर इसका मजाक बनाना शुरू कर दिया।

इस तरह की वापसी

❶ **बदसूरती को बनाया कूल-** क्रॉक्स ने 'अग्ली इज कूल'का नैरेटिव सेट किया। हाई-फैशन ब्रांड के साथ मिलकर प्लेटफॉर्म क्रॉक्स बनाए, जिन्होंने फैशन की दुनिया में तहलका मचा दिया।

❷ **घाटे वाले स्टोर बंद किए :** कंपनी ने सैकड़ों घाटे वाले स्टोर बंद किए। 'डायरेक्ट टु कंज्यूमर' और बड़े होलसेलर्स पर फोकस किया। फिक्स्ड कास्ट घटाई।

❸ **मूल पहचान की ओर लौटे-** 2014 में नए प्रबंधन और बाद में सीईओ एंड्रयू रीज ने कमान संभाली। सबसे पहले फालतू प्रोडक्ट्स हील्स, लेदर आदि बंद किए। तय किया कि कंपनी क्लासिक क्लोग ही बेचेगी। कंपनी की 75-80% बिक्री इसी मॉडल से होती है।

❹ **सफल कोलेबरेशन :** क्रॉक्स ने जस्टिन बीबर, केएफसी और यहां तक की 'कार्स' मूवी के साथ लिमिटेड एडिशन निकाले। ये जूते मिनटों में बिक जाते थे। जेन-जी के बीच क्रॉक्स बेहद मशहूर हुए।

क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ के नाम से लिया गया है 'क्रॉक्स' नाम

शुरुआत : तीन दोस्तों ने मिलकर रखी थी कंपनी की नींव

2002 में तीन दोस्त, स्कॉट सीमेंस, लिंडन हैंसन और जॉर्ज बोडेकर जूनियर कैरेबियन द्वीप पर नौकायन कर रहे थे। उन्हें एक ऐसे जूते की जरूरत महसूस हुई जो पानी में फिसलें नहीं, गीला होने पर बदबू न करें। उन्होंने कनाडाई कंपनी 'फोम क्रिएशन्स' की एक विशेष सामग्री क्रॉसलाइट से बने एक क्लोग का डिजाइन बदलकर एक स्ट्रैप जोड़ दिया और इस तरह क्रॉक्स बना।

गंभीर संकट : 2008-09, कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया

क्रॉक्स के लिए सबसे खतरनाक दौर 2008-09 था। यह वो समय था जब कंपनी का शेयर 75 डॉलर से लुढ़ककर 1 डॉलर से भी नीचे चला गया था। कंपनी पर लाखों डॉलर का कर्ज था और गोदामों में दो साल की बिक्री के बराबर जूते जमा थे। स्थिति इतनी गंभीर थी कि ऑडिटर्स ने चेतावनी जारी कर दी थी कि कंपनी शायद अगला साल नहीं देख पाएगी।

ऐसे पड़ा नाम : क्रॉक्स नाम Crocodile से लिया गया है। यह ऐसा जीव है जो पानी और जमीन दोनों जगह रह सकता है।

सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी : कैजुअल फुटवियर में नाइकी और एडिडास मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं। कम्फर्ट सेगमेंट में स्केचर्स और ब्रिकेनस्टॉक हैं।

वर्तमान स्थिति

85 देशों में व्यापार, 2600 मोनो-ब्रांडेड स्टोर

वर्तमान में क्रॉक्स करीब 85 देशों में व्यापार कर रही है। बाजार मूल्य करीब 44 हजार करोड़ रु. है। कंपनी के सीईओ एंड्रयू रीज के अनुसार करीब 2600 मोनो-ब्रांडेड स्टोर्स दुनियाभर में हैं। भारत क्रॉक्स का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। इसके भारत में 200 से अधिक पार्टनर स्टोर हैं। दुनियाभर में हर घंटे 14 हजार जोड़ी क्रॉक्स बिकते हैं। इसने जनवरी से दिसंबर 2025 तक 12.9 करोड़ जोड़ी जूते बेचे थे। देश में क्रॉक्स की बिक्री 30-40% की दर से बढ़ रही है।

पीपुल भास्कर | डारियो अमोदेई | एआई कंपनी एंथ्रोपिक के सीईओ

शीर्ष एआई लैब के सीईओ डारियो नैतिकता के पैरोकार, अपने एआई के लिए रूलबुक भी बनाई है

चर्चा में क्यों- इनकी एआई कंपनी एंथ्रोपिक सबसे सुरक्षित और शक्तिशाली कंपनी कही जाती है। अमेरिका इसे सेना के लिए शामिल करना चाहता है।

वर्ष 2003, अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था। डारियो उस समय ग्रेजुएशन कर रहे थे। कैलिफोर्निया टेक नाम से स्टूडेंट न्यूजपेपर निकलता था। उस न्यूजपेपर में उन्होंने लिखा- 'ज्यादातर लोग सैद्धांतिक रूप से इराक युद्ध के खिलाफ हैं। सब को पता है कि सही क्या, लेकिन कोई भी अपना एक सेकंड देने को तैयार नहीं है। यह चुप्पी क्यों। इसे बिना देर किए बदलना होगा।' उनका यह लेख उस दौरान खूब चर्चा में रहा, जो यह बताता है कि उनकी शख्सियत सिर्फ सोचने वालों में से नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेकर एक्शन लेने वालों में से है।

यह बात उनके करियर के दौरान भी दिखी। 2023 में ओपनएआई के तत्कालीन सीईओ सैम ऑल्टमैन को जब बोर्ड ने बाहर कर दिया था, तब डारियो को ओपनएआई में कंपनी मर्ज करने और नई कंपनी का सीईओ बनने का ऑफर दिया गया था, लेकिन एआई में नैतिकता को लेकर सैद्धांतिक रूप से सहमत न होने के कारण उन्होंने यह ऑफर ठुकरा दिया था। हजारों करोड़ की नेटवर्थ के बावजूद उनका रहन-सहन किसी टेक बॉस से ज्यादा एक आम पीएचडी स्टूडेंट्स जैसा लगता है। वे अक्सर साधारण स्वेटर, जिप-अप फ्लीस जैकेट और प्लेन कैजुअल शर्ट में नजर आते हैं। वे हाई प्रोफाइल पार्टियों, लेट नाइट क्लब और बड़े नेटवर्किंग इवेंट्स से दूर रहते हैं। छुट्टियों के दिनों में वे विज्ञान या साइंस फिक्शन की किताब पढ़ना पसंद करते हैं। उनका फ्रेंड सर्किल भी बेहद सीमित है, जिसमें उनकी बहन और लैब के कुछ साथी शामिल हैं।

बहन डेनिएला अमोदेई के साथ डारियो। डेनिएला उनकी कंपनी एंथ्रोपिक के प्रबंधन में अहम योगदान देती हैं।

डारियो का मानना है कि एआई का विकास इतनी तेजी से हो रहा है कि यह 2030 तक इंसानी बुद्धिमत्ता को आसानी से पीछे छोड़ देगा। इसलिए वे एआई पर कानूनी नियंत्रण और नैतिकता को तरजीह देते हैं।

जन्म : 1983, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका।
शिक्षा : प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से बायोफिजिक्स में पीएचडी।
संपत्ति : 58 हजार करोड़ रु.
(विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार)

परिवार

चमड़े के कारीगर थे पिता, मां मैनेजर थीं

अमोदेई के पिता एक इटैलियन अमेरिकन थे, जो एक चमड़े के कारीगर थे। मां, एलेना एंगेल एक यहूदी-अमेरिकी थीं, जो लाइब्रेरीज रिनोवेशन और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की मैनेजर थीं। डारियो बचपन से ही साइंस किड थे। गणित और फिजिक्स में पूरी तरह डूबे रहते। 3 साल की उम्र में पूरे दिन गिनती करते रहते थे। उनकी छोटी बहन डेनिएला अमोदेई है।

विवाह

शादीशुदा हैं पर कोई संतान नहीं है

डारियो अमोदेई आम तौर पर निजी जिंदगी को मीडिया से दूर रखते हैं। घरेलू जिंदगी पर बात करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन 2024 में उन्होंने खुद अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में छोटी-सी जानकारी दी। 12 अप्रैल 2024 को 'द एजरा क्लाइन शो' में बात करते हुए उन्होंने बताया कि वे शादीशुदा हैं, लेकिन फिलहाल बच्चे नहीं हैं।

करियर

फिजिक्स की फील्ड से एआई के सीईओ तक

2014 में एआई कंपनी बायडू जॉइन की। यहां उन्होंने 'डीप स्पीच 2' नाम से भाषा को पहचानने वाली तकनीक बनाई, जिसकी क्षमता इंसानों से भी बेहतर थी। 2015 में गूगल ब्रेन में सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट बने। 2016 में ओपनएआई जॉइन किया, लेकिन एआई को सुरक्षित बनाने के मुद्दे पर असहमति के बाद के 2021 में एंथ्रोपिक बनाकर सीईओ बने।

रोचक : बायोफिजिक्स में पीएचडी के लिए हर्ट्ज थीसिस प्राइज मिल चुका है

खास : अमेरिकी फिजिक्स ओलिंपियाड का हिस्सा रहे हैं

- वर्ष 2000 में डारियो यूएस फिजिक्स ओलिंपियाड टीम के सदस्य थे।
- बायोफिजिक्स में पीएचडी के लिए उन्हें 2011 में हर्ट्ज थीसिस प्राइज मिल चुका है।
- उन्होंने अपनी कंपनी को 'पब्लिक बेनिफिट कॉर्पोरेशन' बनाया है, जिसका मतलब है कि उनके लिए मुनाफे से ऊपर समाज की भलाई है।

उपलब्धि : दुनिया के सबसे प्रभावशाली एआई फाउंडर्स में

- ओपनएआई में रहते हुए चैट जीपीटी के एआई क्रांति वाले जीपीटी-3 मॉडल को बनाया।
- एआई को इंसानी फीडबैक से सीखने की तकनीक आरएलएचएफ विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है।

नैतिकता व दान : 80% संपत्ति दान करने की घोषणा की है

- ओपेनएआई में शीर्ष पद सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें लगा कि वहां बहुत जल्दबाजी में एआई को मार्केट में लाया जा रहा है।
- 80% संपत्ति दान करने की घोषणा की है।
- अपने एआई मॉडल के लिए रूल बुक बनाई है, जिसमें तय किया है कि रंगभेद, अपमान और भेदभाव वाले काम बिल्कुल नहीं करने।

बिज़नेस भास्कर
Business Standard और TheEconomist की ख़बरों के साथ
नई दिल्ली, शुक्रवार 27 फरवरी, 2026

गेम चेंजरः शेयर बाजार गिरने पर नुकसान कम होगा, बुलियन में 1.2 लाख करोड़ निवेश का रास्ता साफ

सोना-चांदी में भी पैसा लगाएंगे इक्विटी फंड

भास्कर न्यूज | मुंबई

सेबी के अन्य 5 बड़े फैसले, जिनका निवेशकों पर होगा असर... स्कीम के नाम में रिटर्न पर जोर वाले शब्द नहीं होंगे

सॉल्यूशन फंड्स अब बंदः स्कीम मर्ज होंगी
सेबी ने रिटायरमेंट, चिल्ड्रन फंड्स (सॉल्यूशन) में नया निवेश बंद करने के निर्देश दिए हैं। मौजूदा स्कीम्स का विलय होगा। लाइफ साइकल फंड्स इनकी जगह लेंगे।
असरः निवेशकों को अभी के मुकाबले ज्यादा सटीक लक्ष्य आधारित म्यूचुअल फंड स्कीम्स मिलेंगी।

ज्यादा विकल्पः वैल्यू, कॉन्ट्रा दोनों एक साथ
अब एक ही फंड हाउस वैल्यू व कॉन्ट्रा दोनों स्कीम और बैलेंस्ड हाइब्रिड व एग्रेसिव हाइब्रिड फंड लॉन्च कर सकता है। पहले इनमें से एक विकल्प चुनना पड़ता था।
असरः निवेशकों को एक ही फंड हाउस में अलग-अलग निवेश स्टाइल और रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक निवेश के ज्यादा विकल्प मिलेंगे।

थीमैटिक फंड्स में ओवरलैप सीमित
थीमैटिक-सेक्टोरल फंड्स का अन्य फंड से पोर्टफोलियो ओवरलैप 50% से कम रखना अब अनिवार्य है। तीन साल में इस नियम का अनुपालन करना होगा।
असरः डुप्लीकेसी घटेगी। इससे निवेश पोर्टफोलियो में वास्तविक विविधता पक्की होगी।

खास नई कैटेगरीः सेक्टोरल डेट फंड
सेबी ने एक नई कैटेगरी सेक्टोरल डेट फंड बनाई है। इसमें फंड मैनेजर फाइनेंस, एनर्जी, इन्फ्रा, हाउसिंग सेक्टरों में 80% से ज्यादा डेट एलोकेशन करेंगे।
असरः कम रिस्क लेने वाले लोगों के लिए खास सेक्टरों में बॉन्ड निवेश का रास्ता निकला।

स्कीम के भ्रामक नामों पर पाबंदी
बाजार नियामक ने म्यूचुअल फंड स्कीम के नाम में रिटर्न पर जोर देने वाले शब्दों पर पाबंदी लगा दी है। लाइफ साइकल फंड के नाम के साथ मैच्योरिटी वर्ष जोड़ना भी अनिवार्य कर दिया है।
असरः भ्रामक मार्केटिंग पर लगाम लगेगी।

आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड पर अब शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव का कम असर होगा। बाजार नियामक सेबी ने गुरुवार को एक्टिव इक्विटी स्कीम्स को सोना और चांदी में निवेश की अनुमति दे दी। अब तक इक्विटी स्कीम्स शेयरों के अलावा 20-35% निवेश डेट (बॉन्ड), रीट्स और इनविट्स जैसे गैर-इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स कर सकते थे। अब इसमें सोना-चांदी से जुड़े निवेश, मसलन गोल्ड/सिल्वर ईटीएफ भी शामिल हो गए हैं। इसका फायदा ये होगा कि जब शेयर बाजार गिर रहा हो तो सोने-चांदी में संभावित तेजी से एक हद तक उसकी भरपाई हो जाएगी।

सेबी का यह फैसला बुलियन (सोना-चांदी) इंडस्ट्री के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है। भारत में एक्टिव इक्विटी फंड्स का एयूएम करीब 35 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें से 35% तक यानी 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गैर-इक्विटी निवेश की अनुमति है। यदि इस हिस्से में से 10% निवेश भी सोना-चांदी में होता है तो बुलियन मार्केट में 1.2 लाख करोड़ रुपए आएंगे। जाहिर है, इससे सोना-चांदी की मांग और दाम, दोनों बढ़ेंगे। 2026 में अब तक पहले ही सोने की कीमत करीब 20% चांदी की 14% बढ़ चुकी है।

रिटायरमेंट निवेश का नया विकल्प मिलाः लाइफ साइकल फंड्स
सेबी ने लाइफ साइकल फंड्स नाम की एक नई कैटेगरी शुरू की है। यह रिटायरमेंट और चिल्ड्रन स्कीम्स जैसे सॉल्यूशन-ओरिएंटेड फंड्स की जगह लेगी। ये फंड 'ग्लाइड पाथ' रणनीति पर काम करेंगे। इसका मतलब है कि मैच्योरिटी के करीब आते-आते इन फंड्स में इक्विटी निवेश घटता जाएगा।

निवेश अवधि: 5 से 30 साल

कहां पैसे लगाएंगेः शेयर, बॉन्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट्स (इनविट्स), एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स (ईटीसीडी) और गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ।
समय-पूर्व निकासी महंगीः पहले साल एग्जिट लोड 3%, दूसरे साल 2% और तीसरे साल 1% होगा।

भास्कर एनालिसिस | टॉप-500 कंपनियों के नतीजों का निचोड़

लगातार छठी तिमाही मिडकैप कंपनियां विजेता, 19.6 फीसदी बढ़ा इनका मुनाफा

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

शेयर बाजार में मिडकैप कंपनियां लगातार छठी तिमाही विजेता रहीं। लेकिन स्मॉल-कैप शेयर लड़खड़ा रहे हैं। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म सीएलएस ने 'इंडिया स्ट्रैटेजी' रिपोर्ट में आगाह किया है कि स्मॉल-कैप कंपनियां भविष्य में कमाई के मोर्चे पर बड़ी गिरावट का सामना कर सकती हैं।

निफ्टी-500 कंपनियों के विश्लेषण से तैयार रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी कंपनियों की बिक्री 13% बढ़कर 10 तिमाहियों के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। लेकिन मुनाफा बढ़ने की रफ्तार 9% ही रही। हालांकि इस दौरान मिडकैप कंपनियों ने सालाना 19.6% की प्रॉफिट ग्रोथ हासिल की। इसके मुकाबले लार्ज कैप की ग्रोथ 6.6% और स्मॉल-कैप की 13% रही। यह लगातार छठी तिमाही है जब मिड-कैप कंपनियों ने पूरे बाजार का नेतृत्व किया है। सीएलएसए का मानना है कि स्मॉल-कैप में ऊंचे वैल्यूएशन और कमाई घटने की आशंका से बड़े मुनाफे की गुंजाइश कम है।

बीती चार तिमाहियों में सिर्फ 39% छोटी कंपनियों की ग्रोथ 20% से अधिक, 36% का रिटर्न निगेटिव

- सीएलएसए ने वित्त वर्ष 2027 और 2028 के लिए स्मॉल कैप की कमाई के अनुमान क्रमशः 3.9% और 3.1% घटाए हैं। लगातार तीसरी तिमाही स्मॉल-कैप शेयरों के डाउनग्रेड का रिस्क बढ़ा है।
- अनुमान है कि दो साल में स्मॉलकैप कंपनियां 28% की रफ्तार से बढ़ेंगी। लेकिन सीएलएस के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 39% स्मॉल-कैप कंपनियां बीती चार तिमाहियों में 20% से अधिक ग्रोथ दिखा पाईं, जबकि उम्मीद 62% कंपनियों से की जा रही है।
- पिछली चार तिमाहियों के दौरान सिर्फ 26% स्मॉल-कैप कंपनियों ने 30% से ज्यादा ग्रोथ देखेंगी। पर बाजार को उम्मीद है कि दो साल में 35% कंपनियां ऐसा करेंगी।
- सीएलएसए के विश्लेषण के दायरे में आने वाली 36% स्मॉल-कैप कंपनियों ने बीती 4 तिमाही निगेटिव रिटर्न दिया है।
- दिलचस्प है कि ब्रोकरेज फर्म ने टीसीएस को लेकर अपनी 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग दोहराई है।

मुनाफे का 80% हिस्सा तेल, गैस व फाइनेंशियल से
सीएलएसए ने यह भी नोट किया कि बाजार की कमाई की चौड़ाई कम हो गई है। कुल मुनाफे का लगभग 80% हिस्सा केवल ऑयल एंड गैस और फाइनेंशियल सेक्टर से आया है। अगर इन दोनों को हटा दिया जाए, तो बाकी बाजार की प्रॉफिट ग्रोथ मात्र 0.6% ही रह जाती है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए सीएलएसए ने स्पष्ट किया है कि वह लार्ज कैप शेयरों को प्राथमिकता देना जारी रखेगा।

बिजनेस ब्रीफ

एपल पे जून तक भारत में लॉन्च करने की तैयारी
मुंबई | डिजिटल पेमेंट सर्विस एपल पे को भारत में लॉन्च करने की तैयारी है। अमेरिकी कंपनी इसके लिए आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक के साथ-साथ मास्टरकार्ड और वीसा जैसी ग्लोबल कार्ड नेटवर्क्स से भी चर्चा कर रही है। एपल पे यूपीआई और कार्ड-आधारित भुगतान, दोनों को सपोर्ट करेगी। एपल का जून तक भारत में पेमेंट सर्विस लॉन्च करने का लक्ष्य है।

एनएसई का इश्यू साइज 23,000 करोड़ का होगा
मुंबई | नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 23,000 करोड़ रुपए का आईपीओ जल्द दस्तक देगा। ये भारत के सबसे बड़े आईपीओ में से एक होगा। एक्सचेंज ने इंवेस्टमेंट बैंकों से प्रस्ताव मांगे हैं, जो यह आईपीओ मैनेज करने में मदद करेंगे। यह पूरी तरह ऑफर फॉर सेल होगा, जिसमें मौजूदा शेयरधारक 4-4.5% इक्विटी बेचेंगे।

दिवालिया रियल्टी फर्म हर ग्राहक का हिसाब देंगी
नई दिल्ली | इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने दिवाला प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब किसी भी रियल एस्टेट कंपनी के इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में सभी घर खरीदारों का विवरण देना अनिवार्य होगा, चाहे उन्होंने औपचारिक रूप से दावा दाखिल किया हो या नहीं। इसमें कंपनी के बही-खातों या रेरा के रिकॉर्ड में दर्ज हर आवंटी को शामिल करना होगा।

अब पोस्ट में पहचान स्पष्ट करेंगी कंपनियां, एजेंट्स
मुंबई | सेबी ने सभी लिस्टेड कंपनियों, संस्थाओं और उनके एजेंटों के लिए 1 मई से सोशल मीडिया पर शेयर बाजार से जुड़े पोस्ट पर पंजीकृत नाम और सेबी पंजीकरण संख्या दिखाना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वॉट्सएप, एक्स, लिंक्डइन, टेलीग्राम, रेडिट जैसे सभी प्लेटफॉर्म पर लागू होगा।

चुनौती • निजी दान 25% न बढ़ा तो 2030 तक 18 लाख करोड़ की कमी

सोशल सेक्टर पर खर्च 27 लाख करोड़ पहुंचा, जरूरत से 16 लाख करोड़ कम

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

भारत का सामाजिक खर्च जीडीपी से भी तेज गति से बढ़ रहा है। इसके बावजूद यह देश की जरूरतें पूरी करने के लिए काफी नहीं है। बैन एंड कंपनी और रणनीतिक परोपकारी संगठन दसरा की एक रिपोर्ट बताती है कि 2020 से 2025 के बीच सामाजिक क्षेत्र की फंडिंग सालाना 13% बढ़कर करीब 27 लाख करोड़ हो गई है। इसमें 95% योगदान सरकार का है। 2030 तक यह राशि 85% बढ़कर 50 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इसके बावजूद नीति आयोग के मुताबिक, 16 लाख करोड़ के फंड की कमी है। गुरुवार को जारी रिपोर्ट चेताती है कि यदि निजी क्षेत्र के दान की वृद्धि दर 9-11% से बढ़कर 25% नहीं हुई, तो 2030 तक यह कमी बढ़कर 18 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी।

फंडिंग की कमी इन तरीकों से पूरी की जा सकती है...
निजी क्षेत्र का दानः 25% करना होगा जो अभी सिर्फ 11% है।
व्यवस्थित निवेशः धार्मिक, असंगठित दान को पेशेवर संस्थाओं से जोड़ना।
फैमिली ऑफिसः अमीरों को दान को वेल्थ मैनेजमेंट का हिस्सा बनाना।
महिला नेतृत्वः महिलाओं को परोपकार से जुड़े फैसले अपने तरीके से करने की आजादी देनी होगी।

शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ना बड़ी चुनौती
आबादीः विशाल जनसंख्या की बुनियादी जरूरतें बढ़ रही हैं।
बढ़ती लागतः शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च महंगा हुआ है।
वित्तीय बोझः बजट का बड़ा हिस्सा वेतन, पुरानी स्कीम्स में जा रहा है।
निजी क्षेत्रः सामाजिक खर्च में निजी क्षेत्र का योगदान सिर्फ 5%, धार्मिक दान का बड़ा हिस्सा विकास में नहीं।

सुखदः 50 करोड़ से अधिक दान देने वाले 5 साल में दोगुने
- निजी दान में 42% हिस्सा परिवारों का है। इसमें अमीरों और पारिवारिक व्यवसायों का सीएसआर शामिल है।
- 50 करोड़ से अधिक दान देने वाले 5 साल में दोगुने हुए हैं। 60% परिवारों में महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं।
- देश में फैमिली ऑफिस 2018 के 45 से बढ़कर 300 हो गए हैं। ये परोपकार को संपत्ति प्रबंधन का हिस्सा मान रहे हैं।
- 3.4 करोड़ प्रवासी भारतीयों से 2025 में इंडिया गिविंग डे पर करीब 82 करोड़ रुपए जुटे, जो पिछले साल से 60% अधिक है।

जेपीमॉर्गन में ऑटोमेशन, कर्मियों को अब नए काम
एजेंसी | न्यूयॉर्क

दुनिया का सबसे बड़ा बैंक जेपीमॉर्गन चेस में एआई के जरिये बड़े पैमाने पर ऑटोमेशन हो रहा है। सीईओ जेमी डायमन ने निवेशकों की एक बैठक में स्वीकार किया कि एआई ने बैंक के कर्मचारियों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। एआई ने जिन कर्मचारियों की जगह ली है, उन्हें दूसरी नौकरियों में लगाया जा रहा है। बैंक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (सीएफओ) जेरेमी बार्नम ने बताया कि हमारे यहां इस साल एआई का इस्तेमाल लगभग दोगुना हो गया है, खास तौर पर कस्टमर सर्विस और टेक्नोलॉजी के मामले में।

चेतावनीः डायमन ने चेताया कि अगर एआई की रफ्तार को बिना तैयारी के छोड़ा गया तो कई प्रोफेशन खत्म हो सकते हैं। उन्होंने सरकारों और कंपनियों से कहा कि वे अभी से विस्थापित कर्मचारियों के प्रशिक्षण और सहायता की योजनाएं बनाएं।

इक्विटी • विदेशी फंड्स ने शुरू किया निवेश

विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में लगाए 25,044 करोड़

मयंक पटवर्धन | मुंबई

भारतीय शेयर बाजार को लेकर निवेशकों के व्यवहार में बड़ा बदलाव आया है। फरवरी में अब तक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने भारतीय शेयरों में करीब 25,044 करोड़ रुपए लगाए हैं। यह सितंबर 2024 के बाद यानी बीते 17 महीनों में उनकी सबसे बड़ी खरीदारी है। इसके ठीक उलट, पिछले तीन साल से लगातार खरीदारी कर रहे घरेलू म्यूचुअल फंड्स ने इस महीने 972 करोड़ रुपए बाजार से निकाले हैं।

पिछले 13 महीनों में एफपीआई ने भारतीय बाजार से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए निकाले थे। इससे बाजार में तेजी थमी हुई थी। अप्रैल 2023 के बाद यह पहला मौका है जब म्यूचुअल फंड्स ने किसी महीने शुद्ध बिकवाली की है। 2025 से अब तक म्यूचुअल फंड्स बाजार में 5.5 लाख करोड़ रुपए लगा चुके हैं। जानकारों का मानना है कि यह बिकवाली केवल रणनीतिक है। बजट के बाद निचले स्तर से बाजार में तेज उछाल आने और विदेशी भागीदारी बढ़ने के बीच घरेलू फंड मैनेजर मुनाफा बुक कर रहे हैं।

बैंक, FMCG शेयर गिरने से सेंसेक्स 27 अंक टूटा
शेयर बाजार मे गुरुवार को सेंसेक्स 27 अंक फिसलकर 82,249 पर और निफ्टी 14 अंक चढ़कर 25,497 पर बंद हुआ। अमेरिका-ईरान परमाणु वार्ता और शुक्रवार को आने वाले जीडीपी आंकड़ों से पहले निवेशकों ने सतर्कता बरती। मुनाफा वसूली के कारण सेंसेक्स दिन के ऊंचे स्तर से 609 अंक टूटा। बैंकिंग, एफएमसीजी में गिरावट आई।

ओपनएआई का टैलेंट हंट

₹1,800 करोड़ वेतन वाले एआई रिसर्चर ने मेटा छोड़ी
एजेंसी | न्यूयॉर्क

एआई की दुनिया में टैलेंट वॉर तेज हो गई है। चैटजीपीटी डेवलप करने वाली कंपनी ओपनएआई ने मेटा के टॉप एआई रिसर्चर रुओमिंग पैंग को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। खास बात यह है कि मेटा ने पैंग को एपल से 20 करोड़ डॉलर (करीब 1,800 करोड़ रुपए) के पैकेज पर सिर्फ 7 महीने पहले हायर किया था।

पैंग एपल में एआई मॉडल्स के हेड रह चुके हैं। अब तक वह मेटा के सुपरइंटेलिजेंस लैब्स में एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। ओपनएआई उन्हें कंपनी में शामिल करने के लिए कई महीनों से बातचीत कर रही थी। पैंग के जाने के बाद मेटा ने एपल के एआई हेड को अपनी टीम में लेकर ये खाली जगह को भरने की कोशिश की है।

रिजल्ट • डेटा सेंटर का कुल आय में 91% हिस्सा

एनवीडियाः दिसंबर तिमाही में आय 73%, मुनाफा दोगुना बढ़ा

एजेंसी | न्यूयॉर्क

एआई चिप निर्माता एनवीडिया ने दिसंबर तिमाही के अनुमान से बेहतर नतीजे जारी किए हैं। एआई बूम के चलते कंपनी की कुल आय पिछले साल के मुकाबले 73% बढ़कर 68.13 अरब डॉलर (करीब 6.2 लाख करोड़ रुपए) पहुंच गई। पिछले साल इसी तिमाही में यह 39.3 अरब डॉलर थी। कंपनी का मुनाफा भी बीती तिमाही में लगभग दोगुना होकर 43 अरब डॉलर (करीब 3.9 लाख करोड़ रुपए) हो गया। कंपनी की मुख्य ताकत उसका डेटा सेंटर बिजनेस रहा, जिसकी आय 75% की छलांग लगाकर 62.3 अरब डॉलर पर पहुंच गई। एनवीडिया की कुल बिक्री में अब 91% हिस्सेदारी इसी यूनिट की है। कंपनी ने अगली तिमाही के लिए भी 78 अरब डॉलर के रेवेन्यू का मजबूत लक्ष्य रखा है।

रफ्तारः नेटवर्किंग बिजनेस की बिक्री 263% बढ़ी
नेटवर्किंग बिजनेस की बिक्री 263% बढ़कर 10.98 अरब डॉलर हो गई। मेटा जैसी कंपनियों के नए सौदों ने सपोर्ट दिया। यह सेगमेंट ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (जीपीयू) को जोड़ने में काम आता है।

रणनीतिः चीन के बिना भी रिकॉर्ड आय का लक्ष्य
एनवीडिया ने अगली तिमाही के लिए 78 अरब डॉलर की आय का जो लक्ष्य रखा है, उसमें चीन से होने वाली कमाई शामिल नहीं है। अमेरिकी द्वारा एआई चिप्स के निर्यात पर लगाए कड़े प्रतिबंधों से एनवीडिया को चीन के बड़े बाजार में चुनौती मिल रही है। अमेरिका और यूरोप से भारी मांग बनी हुई है।

हर साल सख्त होंगे मानक

टॉप-6 कार कंपनियों ने हासिल किए उत्सर्जन लक्ष्य
बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

देश की टॉप छह कार कंपनियों मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टोयोटा, ह्युंडई और किआ ने 2024-25 के लिए कैफे-2 के तहत तय कार्बन उत्सर्जन (प्रदूषण) के लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) अब आगामी कैफे-3 नियमों को और सख्त करने की तैयारी में है।

आंकड़ों के मुताबिक, टाटा मोटर्स ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी ने लक्ष्य से 20 ग्राम/किमी का बड़ा अंतर रखा। मारुति सुजुकी ने वित्त वर्ष 2025 में 101.389 ग्राम/किमी का उत्सर्जन किया। ह्युंडई और किआ का प्रदर्शन तय सीमा के काफी करीब रहा। वर्तमान में कैफे नीति पांच-पांच साल के ब्लॉक पर चलती है, लेकिन अब इसे सालाना आधार पर बदलने की योजना है।

अबु धाबी की वेलनेस सैंक्चुअरी बक्कारत रेजिडेंसः घर में ही बारिश कराकर थकान मिटा सकेंगे, मिनटों में बुक हो जाएगा प्राइवेट जेट

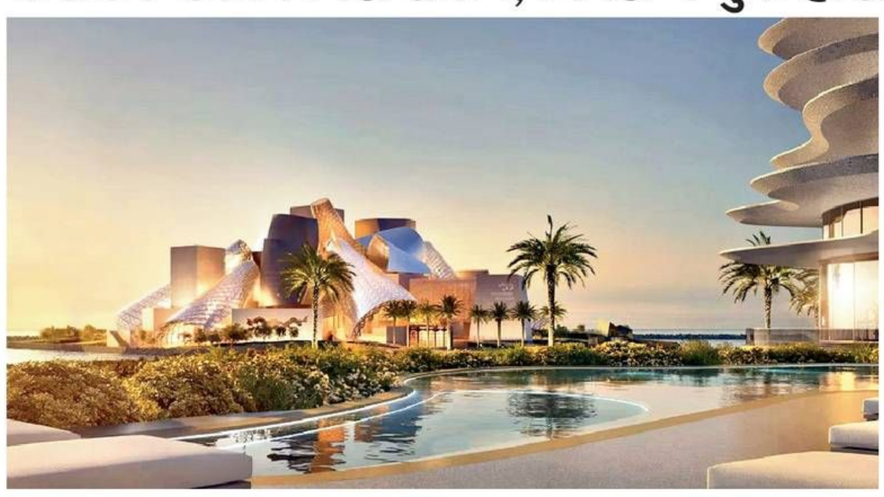

अबु धाबी | अबु धाबी के सादियात द्वीप पर 'बक्कारत रेजिडेंस' आकार ले रहा है। इसे दुनिया के सबसे महंगे और 262 साल पुराने फ्रेंच क्रिस्टल ब्रांड 'बक्कारत' व मशहूर जापानी आर्किटेक्ट सू फुजीमोटो ने डिजाइन किया है। यहां सिर्फ 77 आलीशान घर होंगे। इन घरों के रेन रूम यहां रहने वाले लोगों को अनोखा अनुभव देगा। प्रोजेक्ट 2 साल में पूरा होने की उम्मीद है।

दुनिया में पहली बार ये शाही अनुभव किसी बिल्डिंग में
रेन रूमः घर के भीतर प्रकृति का स्पर्श, जहां मूसलाधार या हल्की बारिश की बूंदें थकान मिटा देंगी। एक ऐसा स्पा और जिम, जहां हर ट्रीटमेंट आपकी रूह को सुकून देने के लिए डिजाइन किया है।
इन्फिनिटी मैजिकः सागर के किनारे बने पूल में डूबते सूरज को देखना, यहां की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होगा।
अल्टीमेट प्राइवेसीः 24 घंटे तैनात आपका निजी कंसीयज, जो आपके लिए प्राइवेट जेट से लेकर दुनिया के बेहतरीन इंटीरियर डिजाइनर्स तक सब कुछ पलक झपकते ही अरेंज कर देगा।

बिजनेस एंकर कॉरपोरेट बर्नआउट का मरहम बना यह गेम, हॉलीवुड सेलिब्रिटी भी इसके दीवाने हैं

गेमिंग कंपनी में नौकरी पाने के लिए बनाया था 'स्टारड्यू वैली' गेम, 10 वर्ष में 5 करोड़ ग्राहक; पोकेमॉन-कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे फ्रैंचाइजी गेम पीछे छूटे

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

कल्पना कीजिए आप अपनी थका देने वाली कॉरपोरेट नौकरी और फाइलों के अंबार को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देते हैं। आपके हाथ में दादाजी की विरासत में मिला छोटा सा घर है। चारों ओर हरी-भरी जमीन, मुट्ठी भर बीज और एक शांत सा कस्बा। यहां आप सिर्फ फसलें नहीं उगाते, बल्कि उन रिश्तों और सुकून को दोबारा सींचते हैं जो आधुनिक भागदौड़ में कहीं खो गए थे। यह 'स्टारड्यू वैली' की जादुई दुनिया है। इस गेम ने बीते 10 साल में सफलता की नई इबारत लिखी है। अब तक लगभग 5 करोड़ गेम बिक चुके हैं, जहां पोकेमॉन और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी अरबों डॉलर की फ्रैंचाइजी वाले गेम फीके नजर आते हैं। इसकी सफलता की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी है। इसे किसी विशाल स्टूडियो या सैकड़ों डेवलपर्स की टीम ने नहीं बनाया। इसे बनाने वाले एरिक बैरोन हैं, जिन्हें गेमिंग जगत 'कंसर्न्डएप' के नाम से जानता है। कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के बाद बिना किसी पेशेवर अनुभव के बैरोन ने 2016 में इसे रिलीज किया। पहला वर्जन जारी करने में 5 साल लगे क्योंकि वे अकेले ही कोडिंग, आर्ट और म्यूजिक पर काम कर रहे थे।
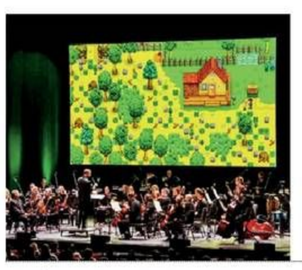
शुरुआत में यह प्रोजेक्ट उनके पोर्टफोलियो के लिए था, ताकि उन्हें गेम इंडस्ट्री में नौकरी मिल सके। लेकिन गेम इतना सफल हुआ कि उन्हें नौकरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। सिएटल के एक छोटे से कार्यालय से काम करने वाले बैरोन कहते हैं, "यह सफलता मेरी कल्पना से परे थी। मैंने सोचा था कि यह एक बहुत ही छोटे बाजार तक ही सीमित रहेगा।" लेकिन पिक्सल के उन छोटे खानों में छिपे सुकून ने दुनिया भर के करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। कैट डेनिंग्स और बॉबी ली जैसे सितारों ने इस गेम के प्रति अपना जुनून साझा किया है। कैट डेनिंग्स का मानना है कि गेम की वजह से उनकी असल जिंदगी में बागवानी की आदत पड़ी।

यह गेम केवल एक 'फार्मिंग सिमुलेटर' नहीं है। 'पेलिकन टाउन' नामक इसके काल्पनिक कस्बे में हर किरदार की अपनी गहराई है। यहां खिलाड़ी को टूटे हुए रिश्तों, अवसाद, युद्ध की मानसिक पीड़ा और शराब की लत जैसे गंभीर मानवीय पहलुओं का सामना करना पड़ता है। खिलाड़ी चाहे तो केवल खेती करे, या कस्बे को 'कॉर्पोरेट पूंजीवाद' की पकड़ से बचाने के मिशन पर निकल पड़े। लाखों खिलाड़ियों के लिए यह गेम 'डिजिटल थेरेपी' बन गया है।

डिजिटल खेतों से 7,000 करोड़ का कारोबार, ऑर्केस्ट्रा टूर भी
स्टारड्यू वैली की अब तक 5 करोड़ कॉपी बिक चुकी है। इसका अनुमानित राजस्व करीब 7276.24 करोड़ हो सकता है। यह किसी एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया शायद अब तक का सबसे लाभदायक बौद्धिक संपदा (आईपी) है। इसकी सफलता केवल गेम तक सीमित नहीं रही; इसने एक कुकबुक, बोर्ड गेम और दो वैश्विक 'ऑर्केस्ट्रा टूर' को भी जन्म दिया है, जहां 35 सदस्यीय बैंड इसके संगीत पर हजारों दर्शकों के सामने प्रस्तुति देता है।

शेयर बाजार से कम कमाई का दिखने लगा असर

देश में 22 करोड़ डीमैट खाते, इनमें से सिर्फ 33% सक्रिय

भास्कर न्यूज | मुंबई

देश में डीमैट खाते भले ही तेजी से बढ़े हैं, लेकिन ज्यादातर निष्क्रिय (डॉर्मेंट) पड़े हैं। 31 जनवरी तक कुल 22 करोड़ डीमैट खातों में से सिर्फ 33% ही सक्रिय थे। यानी करीब दो-तिहाई खातों में कोई ट्रेडिंग या लेन-देन नहीं हो रहा।

बाजार नियामक सेबी के आंकड़ों के विश्लेषण से उभरी यह तस्वीर कोविड महामारी के बाद आई रिटेल निवेश की लहर से उलट है। 2020 के बाद ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोलना आसान होने, मोबाइल ट्रेडिंग और बाजार से जोरदार कमाई के कारण बड़ी संख्या में नए निवेशक सीधे शेयर ट्रेडिंग से जुड़े थे। अब बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ गया है, म्यूचुअल फंड्स की ओर झुकाव ज्यादा है और निवेश के अन्य विकल्प (जैसे सोना) बेहतर रिटर्न दे रहे हैं। इसके चलते सक्रिय ट्रेडिंग घटती नजर आ रही है।

निष्क्रिय खातों पर भी एएमसी जैसे शुल्क
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि निष्क्रिय खातों की बड़ी संख्या बाजार की गहराई पर असर डाल सकती है। साथ ही, डॉर्मेंट अकाउंट पर सालाना मेंटेनेंस चार्जेज (एएमसी) जैसे शुल्क लगते रहते हैं, जो निवेशकों के लिए अतिरिक्त बोझ बन सकते हैं। ये आंकड़े रिटेल निवेशकों की बदलती भागीदारी का ठोस संकेत है।

पैदावार बढ़ाने की कवायद

जीएम सरसों के भविष्य पर फैसला जल्द होगा
बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

देश में जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) खाद्य फसलों की खेती को लेकर केंद्र बड़ा निर्णय लेने की तैयारी में है। मंत्रियों का एक समूह जल्द जीएम सरसों के फील्ड ट्रायल और इसके भविष्य की समीक्षा करेगा। देश की बढ़ती आबादी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव के बीच सरकार कृषि उत्पादकता सुधारना चाहती है। वर्तमान में भारत खाद्य तेलों की कमी से जूझ रहा है। हर साल 1.54 लाख करोड़ रुपए का तेल आयात किया जाता है। जीएम सरसों वैज्ञानिक रूप से तैयार एक ऐसी किस्म है, जिसके जीन में बदलाव करके उसे ज्यादा पैदावार देने और बीमारियों से लड़ने के लायक बनाया गया है।

कल्पमेधा

एक पूंजीवादी समाज की शक्तियों को अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए, तो वे बेलगाम शक्तियां अमीर को और अमीर तथा गरीब को और गरीब बना देती हैं।

– जवाहरलाल नेहरू

सद्भाव का संदेश

भारत में लोकतंत्र की परंपरा बहुत मजबूत रही है और यहां नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार संविधान के तहत मिला हुआ है। मगर इसके साथ ही कुछ जिम्मेदारियां भी अभिन्न हैं, जो आपस में मिल कर ही देश में सद्भाव और सहयोग पर आधारित समाज को जीवन देती हैं। विडंबना यह है कि कई बार अभिव्यक्ति की आजादी पर पूर्वाग्रह और महज धारणा पर आधारित राय हावी दिखती है और इसे किसी व्यक्ति या समुदाय को कठघरे में खड़ा करने का औजार बना लिया जाता है। अपनी प्रभावी संप्रेषण शक्ति और लोगों तक व्यापक पहुंच रखने वाले कला माध्यम के रूप में फिल्मों में अभिव्यक्ति के रचनात्मक पक्ष का इस्तेमाल करते हुए बड़े से बड़े प्रश्नों पर विचार किया जाता रहा है और इसे सभी स्तरों पर स्वीकार्यता भी मिलती रही है। मगर अफसोस की बात यह भी है कि इसी सुविधा का कई बार गलत फायदा भी उठाया जाता है। अभिव्यक्ति के नाम पर किसी फिल्म में परोसी गई कहानी के जरिए किसी समुदाय के बारे में गलत धारणा बनाने की कोशिश की जाती है। इसी तरह, कुछ नेता भी अपनी जिम्मेदारियों और सीमाओं को ताक पर रख कर बेहिचक ऐसे बयान देते हैं, जिससे अलग-अलग समुदायों के बीच द्वेष पैदा होता है। जबकि इसका नतीजा इस रूप में भी सामने आ सकता है कि अलग-अलग समुदायों के बीच सद्भावना आधारित संवाद या संबंध पीछे छूट जाए।

जाहिर है, देश को इसके दूरगामी नुकसान हो सकते हैं। शायद यही वजह है कि हाल ही में अपने शीर्षक की वजह से विवाद के घेरे में आई एक फिल्म पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव के लिए भाईचारा जरूरी है। इस मामले में न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने अपने अलग फैसले में कहा कि सरकारी और गैरसरकारी सहित किसी भी जानी-मानी हस्ती और खासतौर पर ऊंचे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए भाषण, मीम, कार्टून या दृश्य माध्यमों के जरिए किसी भी समुदाय को बदनाम करना, उस पर धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर निशाना साधना संविधान का उल्लंघन है। दरअसल, पिछले कुछ समय से देश भर में अलग-अलग संदर्भ में कुछ नेताओं के बयानों या फिल्मों ने कई बार विवाद की स्थिति खड़ी कर दी। सार्वजनिक रूप से वैसी बातें करने में भी संकोच नहीं किया गया, जिसका कोई मजबूत आधार नहीं था, लेकिन उसने जन मानस के बीच राय बनाने में भूमिका निभाई। वे फिल्मों में चित्रित ब्योरे हों या किसी नेता का बयान, ऐसे अनेक मौके सामने आए, जब उसकी वजह से नाहक विवाद खड़ा हुआ, आपसी सद्भाव को नुकसान पहुंचा और यहां तक कि कोई खास समुदाय अपने आपको कठघरे में खड़ा या असुरक्षित महसूस करने लगा।

सवाल है कि किसी व्यक्ति या समुदाय को लक्ष्य कर बोलने की आजादी के तहत जो भी कहा जाता है, क्या कभी उसके आधार और असर को लेकर भी विचार करने की कोशिश की जाती है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि सद्भावना और आपसी भाईचारा देश के संविधान के बुनियादी उद्देश्यों में से एक है। अनुच्छेद 51ए(ई) के तहत हर नागरिक का यह बुनियादी कर्तव्य है कि वह धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं की सीमा से अलग होकर नागरिकों के बीच सद्भावना और सहयोग को बढ़ावा दे। मगर धर्म, भाषा, जाति या क्षेत्र के आधार पर अगर किसी व्यक्ति या समुदाय को निशाना बनाया जाता है, तो यह संविधान और मानवीय मूल्यों का विरुद्ध है।

बेजा इस्तेमाल

किसी भी देश में सरकारी तंत्र में वित्तीय अनुशासन का अपना महत्त्व है। सरकारी खजाने की राशि सावधानी से और प्राथमिकता के आधार पर ही खर्च की जानी चाहिए। मगर यह राशि जब कल्याणकारी योजनाओं में लगाने या विकास के लिए संसाधन जुटाने के बजाय सरकारी दौरे तथा आतिथ्य प्रबंधन में बर्बाद होने लगे, तो जनता का भरोसा टूटता है। आज एक ओर भारत के दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने के दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर देश के कुछ अधिकारी और नेता फिजूलखर्ची से बाज नहीं आ रहे। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रस्तावित सरकारी दौरे में पद और सार्वजनिक संसाधनों के बेजा इस्तेमाल का मामला सामने आने से एक बार फिर यही जाहिर हुआ है कि पद और रसूख के प्रभाव के पीछे सामंती सोच का ढांचा किस तरह काम करता है। अधिकारी की यात्रा के लिए जिस तरह से पचास अन्य अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपने की खबर आई, वह चौंकाने वाली है। इसमें उनको तौलिया-कंघी और तेल से लेकर अंतःवस्त्र तक जुटाने की हिदायत दी गई थी।

सरकारी यात्रा से जुड़े इन आतिथ्य इंतजामों का ब्योरा चर्चा में आने के बाद संचार मंत्री ने इसे 'बेहद ही बेतुका', 'स्तब्ध कर देने वाला' तथा अस्वीकार्य बताया। इस तरह के आतिथ्य प्रबंधन संबंधी आदेश से बीएसएनएल की तो फजीहत हुई ही, वहीं यह सच्चाई भी सामने आई कि कई सरकारी दौरे में कैसे जम कर फिजूलखर्ची होती है। एक ओर, जनहित की योजनाओं को लागू करने में देरी के सवाल पर धन की कमी को कारण बताया जाता है, वहीं सरकारी तंत्र में पसरी फिजूलखर्ची पर लगाम लगाना जरूरी नहीं समझा जाता। यह छिपा नहीं है कि सरकारी गाड़ियों के दुरुपयोग से लेकर कई तरह के भत्तों पर बेतहाशा खर्च के साथ-साथ अधिकारियों के अनावश्यक दौरों और सरकार के विज्ञापनों पर किस तरह करोड़ों रुपए बहाए जाते हैं। जबकि जनता का यह धन अनेक तरह के करों के जरिए जुटाया गया होता है। इस मामले में बेशक तत्काल कार्रवाई की गई हो, लेकिन सरकारी तंत्र में धन की बर्बादी कैसे हो रही है, यह उसकी यह बानगी भर है। इसे गंभीरता से लेने और इस तरह की प्रवृत्ति पर सख्ती से लगाम लगाने की जरूरत है।

परग्रही जीवन के वजूद पर दावों की सीमा

परग्रही सभ्यता यानी एलियंस को लेकर हमारी जिज्ञासाओं का कोई अंत नहीं है, क्योंकि अभी इसका कोई जवाब नहीं है कि इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी सभ्यता है या नहीं। इसीलिए नए दावों के साथ विशाल सौरमंडल में कहीं और जीवन की संभावनाओं को लेकर अक्सर बहस छिड़ जाती है।

अभिषेक कुमार सिंह

दशकों से दुनिया भर के खगोल विज्ञानी इस पहेली को हल करने के लिए आकाश-पाताल एक करते रहे हैं कि क्या इस ब्रह्मांड में हमसे भी अधिक बुद्धिमान कोई सभ्यता मौजूद है! हाल में, इसकी चर्चा एक बातचीत में शामिल हुए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की एक टिप्पणी से उठी है, जिसमें उन्होंने एलियंस, यानी परग्रही सभ्यता के अस्तित्व को स्वीकार किया। हालांकि बाद के स्पष्टीकरण में उन्होंने साफ किया कि अंतरिक्षीय दूरियों के कारण पृथ्वी पर एलियंस के आने की संभावना कम है, लेकिन ब्रह्मांड की विशालता यह संभावना जगाती है कि पृथ्वी के पार दूसरी कोई दुनिया अवश्य हो सकती है।

सत्ता प्रतिष्ठानों और विज्ञानियों की ओर से पहले भी परग्रही जीवन या एलियंस की संभावनाओं को लेकर काफी कुछ कहा-सुना जाता रहा है। इस संबंध में हमारी जिज्ञासाओं का कोई अंत इसलिए नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी इसका कोई जवाब नहीं है कि इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी सभ्यता है या नहीं। इसीलिए नए दावों, नई खोजों के साथ विशाल सौरमंडल में कहीं और जीवन की संभावनाओं को लेकर अक्सर चर्चा और बहस छिड़ जाती है। करीब तीन वर्ष पहले मैक्सिको की संसद में सुनवाई के दौरान जब दो 'गैर इंसानी जीव' के शवों को दिखाया गया था, तो सोशल मीडिया पर इन्हें लेकर काफी हंगामा मच गया। यह पहला अवसर था, जब परग्रही सभ्यताओं के कथित सबूतों के साथ एक देश की संसद में आधिकारिक रूप से धरती के बाहर जीवन की संभावना का उल्लेख किया गया। सलेटी-भूरे रंग के ममीकृत इन शवों का चेहरा-मोहरा काफी हद तक इंसानों जैसा था। इन शवों के 1800 साल पुराने होने का खुलासा नेशनल आटोनोमस यूनिवर्सिटी आफ मैक्सिको द्वारा किए गए रेडियो कार्बन डेटिंग विश्लेषण से हुआ था। इस विश्वविद्यालय के भौतिकी संस्थान ने बयान जारी कर पुष्टि की थी कि वहां इन शवों की उम्र का पता लगाने के तो परीक्षण किए, लेकिन इसका कोई परीक्षण नहीं हुआ कि इन जीवों की उत्पत्ति कहां हुई। यानी इस बारे में पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये शव एलियंस के ही हैं। शायद यही वजह रही कि बहुत से वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने मैक्सिको में किए गए दावों को सिरे से खारिज कर दिया।

यह आश्चर्य ही है कि आम लोगों से हटकर वैज्ञानिक, अंतरिक्ष इंजीनियर और नासा-इसरो जैसे प्रतिष्ठित संगठनों के शीर्ष अधिकारी और ब्रिटिश भौतिकशास्त्री दिवंगत स्टीफन हाकिंग जैसे विचारक भी परग्रही सभ्यताओं के अस्तित्व को स्वीकारते रहे। मुश्किल यह है कि एलियंस के वजूद से जुड़ी गुत्थियों को ब्रह्मांड के अनंत विस्तार और इसके एक छोर से दूसरे छोर की सदियों लंबी दूरियों को देखते हुए सुलझाना आसान नहीं है। ऐसा कई बार हो चुका है, जब दावे के साथ कहा गया कि एलियंस या उनके यानों को देखा गया, उनके विचरण को रिकार्ड किया गया। फिर भी दावों पर यकीन करना मुश्किल रहा है।

ऐसा क्यों है कि परग्रही सभ्यता और यूएफओ के बारे में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पा रहा है? इसका एक जवाब दस साल पहले वर्ष 2016 में शोध पत्रिका 'एस्ट्रोबायोलाजी' में प्रकाशित हुआ था। इसमें भारतीय मूल के विज्ञानी अंतरिक्ष विज्ञानी आदित्य चोपड़ा और प्रो चार्ली

लाइनवीवर ने यह निष्कर्ष दिया था कि पृथ्वी से परे अन्य ग्रहों पर जीवन के लायक हालात ही नहीं हैं। लिहाजा उन पर एलियंस (समझदार परग्रही प्राणी) तो क्या, कैसा भी जीवन संभव नहीं है। यहां तक कि सौरमंडल के ही ग्रह-मंगल और शुक्र पर 400 करोड़ साल पहले जीवन लायक स्थितियां बनी थीं, पर वहां भी पर्यावरण इतना अनुकूल नहीं रहा कि एलियंस पैदा होकर पनप पाएं। ये नतीजे सामने आने के बाद सवाल यह है कि क्या अब अंतरिक्ष में ऐसी खोजों का कोई महत्त्व रह गया है? खासतौर से इसरो जैसे भारतीय संगठनों को अब क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके चंद्र और मंगल अभियानों को ही खर्चीला बताकर उनकी आलोचना होती रही है!

> **यह आश्चर्य ही है कि आम लोगों से हटकर वैज्ञानिक, अंतरिक्ष इंजीनियर और नासा-इसरो जैसे प्रतिष्ठित संगठनों के शीर्ष अधिकारी और ब्रिटिश भौतिकशास्त्री दिवंगत स्टीफन हाकिंग जैसे विचारक तक परग्रही सभ्यताओं के अस्तित्व को स्वीकारते रहे हैं। मुश्किल यह है कि एलियंस के वजूद से जुड़ी गुत्थियों को ब्रह्मांड के अनंत विस्तार और इसके एक छोर से दूसरे छोर की सदियों लंबी दूरियों को देखते हुए सुलझाना आसान नहीं है। ऐसा कई बार हो चुका है, जब दावे के साथ कहा गया कि एलियंस या उनके यानों को देखा गया, उनके विचरण को रिकार्ड किया गया। फिर भी दावों पर यकीन करना मुश्किल रहा है।**

यह सच है कि बीते कई दशकों में एलियंस की खोज कहीं नहीं पहुंची है, लेकिन कई विशेषज्ञ इस धारणा के धुर समर्थक रहे कि ब्रह्मांड में कहीं न कहीं इंसानों जैसी या उससे भी ज्यादा बुद्धिमान सभ्यता मौजूद है। करीब एक दशक पहले एक टेलीविजन चैनल (डिस्कवरी) पर प्रसारित एक शृंखला में उन्होंने कहा था कि अन्य ग्रहों पर भी बुद्धिमान प्राणी हो सकते हैं और संभव है कि वे संसाधनों की तलाश में पृथ्वी पर हमला करें। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर एलियंस पृथ्वी पर आते हैं तो उसका वैसा ही परिणाम होगा, जैसा कोलबंस के अमेरिका पहुंचने पर वहां के मूल निवासियों का हुआ था। यानी अमेरिका के संसाधनों पर दूसरे इलाके के लोगों का कब्जा हो गया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजंसी- नासा भी हाकिंग की राह पर चलती रही है। उसने इसके लिए पहले 'सेटी' (सर्च फार एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलीजेंस) जैसा व्यापक अभियान चलाया। उससे जब कुछ नहीं मिला तो 2015 से नेक्सस (नेक्सस फार एक्सोप्लैनेट सिस्टम साइंस) नामक अभियान की शुरुआत की थी।

एलियंस के वजूद में भरोसा रखने वालों के नजरिए से देखें, तो कहा जा सकता है कि इस ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं हैं, इसलिए यह सोचना सांख्यिकीय तर्क के हिसाब से सही हो सकता है कि उनमें कहीं न कहीं जीवन हो। मगर पिछले कई दशकों से दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जो जवाब खोजा था, वह यही है कि ब्रह्मांड में इंसान अकेला है। इस उत्तर को मुकम्मल नहीं मानने की एक वजह यही रही कि इस काम में तकनीकी सीमाएं कायम रही हैं। पहले दुनिया के पास न तो बेहद ताकतवर टेलीस्कोप थे और न ही वैसे संकेत पकड़ने वाले यंत्र, जो अंतरिक्ष से आने वाली हर सूक्ष्म आहट को एक अलग प्रकार के जीवन की तरफ से संवाद की कोशिश के रूप में दर्ज कर सकें। दूसरी बड़ी खामी इस मान्यता से जकड़े रहना रहा कि दूसरी दुनिया भी हमारी पृथ्वी जैसी होगी और उस पर इंसान जैसे जीव यानी एलियंस ही बसते होंगे। यह अवधारणा परग्रही जीवन खोजने में बाधक बनी। मगर आधुनिक तकनीक के सहारे भी हमारे ही सौरमंडल में मौजूद दो ग्रहों यानी मंगल और शुक्र पर अभी तक न तो जीवन के कोई संकेत मिले और न ही इसकी कोई संभावना नजर आई है कि इन पर भविष्य में भी जीवन संभव हो सकता है, यानी इंसानों को बसाया जा सकता है। इसका कारण है इन ग्रहों का तापमान, वायुमंडलीय दबाव और सूर्य से इनकी दूरी। कहीं बेहद ऊंचे या अत्यधिक कम दाब व तापमान, तो कहीं जहरीली गैसों की मौजूदगी ने इंसान या जीवाणु आधारित जीवन की संभावनाओं को पलीता लगा रखा है।

चूंकि अब तक का तकनीकी ढांचा पृथ्वी से परे कैसे भी जीवन संकेत को खोज नहीं पाया है, लिहाजा बेहतरी इसी में है कि एलियंस की खोज और संपर्क का काम छोड़ दिया जाए और इसे उन्हीं के यानी एलियंस के हवाले छोड़ा जाए कि बताएं कि उनका कोई वजूद है। कम से कम इसरो जैसे भारतीय संगठनों और हमारे वैज्ञानिकों को इस खोज से परहेज ही करना चाहिए। इनके बजाय स्वदेशी जीपीएस तंत्र को कारगर बनाने और देश के दुर्गम इलाकों को बाढ़ और सूखे से बचाने की जानकारियां दिलाने में कारगर उपग्रहों की तैनाती पर जोर देना चाहिए। ये बुनियादी चीजें ही अंतरिक्ष में हमारी जानकारी के हिसाब से ज्यादा महत्त्व रखती हैं।

मिठास की बोली

रितुप्रिया शर्मा

यह आमतौर पर कहा जाता है कि वाणी ही अमृत है और यह विष भी है। वाणी जितनी सरल और मधुरता लिए होगी, उतनी ही यह गुंजाइश होगी कि हम अपने जीवन में सफल हो पाएं। सही बातों को भी बोलने का अंदाज उसके प्रभाव को सकारात्मक या नकारात्मक बना देता है। अगर कोई उचित राय भी जाहिर करते हुए वाणी को कठोर बना कर बोला जाए, तो इससे न सिर्फ संबंध बिगड़ते हैं, बल्कि यह स्थिति विकट परिस्थितियों को भी जन्म देने में सक्षम है। यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि हमारा विचार किसी अन्य व्यक्ति से मिले या प्रभावित हो और हम उसके अनुकूल ही बात करें। मगर अपनी बात समझाने के लिए हमें अपनी वाणी, यानी संवाद की शैली को सुमधुर बनाना बहुत आवश्यक है। वाणी की मधुरता दूसरे के प्रति सम्मान, धैर्य और समझ का प्रतीक है। उचित, लेकिन संयमित लहजे में प्रतिकार जरूरी है, लेकिन सही संवाद यह सिखाता है कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाए बिना हम कैसे अपनी बात को सामने वाले पक्ष तक पहुंचाएं।

दरअसल, मधुर संवाद हमारा वह साथी है, जो किसी भी तरह के हालात को बदलने में सक्षम है। किसी भी काम की शुरुआत और उसे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए संवाद की शैली ही व्यवहार का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे हम उसकी पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। परिवार में भी देखा जाए, तो माता-पिता से लेकर बच्चों तक के बीच संवाद खुला होना चाहिए। उसमें सौम्यता होनी चाहिए। अगर हम ऐसा करने में सफल होते हैं, तो हम पीढ़ियों के बीच होने वाले वैचारिक मतभेद को कम कर सकते हैं। आजकल पीढ़ियों के बीच सोच-समझ के अंतर पर जोर देकर कई बार परिवार के बीच भी आपसी दूरी की स्थिति को सही ठहराया जाता है। समाज के परिप्रेक्ष्य में भी देखें, तो वही व्यक्ति समाज का सही नेतृत्व कर सकता है, जिसके पास मधुर संवाद और उसका प्रभाव हो। इसकी सीधी वजह यह है कि जिस व्यक्ति की बोली मधुर होगी, उसी की बात लोग सुनेंगे, गुनेंगे और उसी पर विचार करेंगे। कड़वी भाषा में बोली गई बात को आमतौर पर लोग नजरअंदाज करते हैं या फिर उससे असहमत होने के मानस में चले जाते हैं। हालांकि कई बार सच कड़वा होता है, लेकिन उसे बोलने के अंदाज में स्वीकार्यता का ध्यान रखना चाहिए।

बड़े से बड़े विवादों के बीच अगर हम कठोर शब्दों के बजाय मधुर शब्दों का प्रयोग करें, तो विवाद शांति और समझाइश से सुलझाए जा सकते हैं। हमारा संवाद ऐसा होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को दिल से बुरा न लगे। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमें सामने वाले को भी सुनना चाहिए और उसकी परिस्थिति को समझकर उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखना चाहिए। बाद में भ्रम पैदा न हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए, साथ ही संवाद स्पष्ट और सम्मानजनक होना चाहिए। किसी भी प्रकार की असहमति से आहत न होना भी मधुर संवाद की विशेषता है।

तेजी से बदलते दौर में सोशल मीडिया पर लोग आज जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हुए संवाद करते हैं, उससे धीरे-धीरे हमारी संवेदनशीलता और संवाद शैली प्रभावित हो रही है। कई बार हम बिना सोचे-समझे भी किसी के बारे में कुछ कह बैठते हैं और बात फिर बिगड़ती चली जाती है। ऐसे में हमें अपने संवाद और संदेश की मधुरता का ध्यान रखना होगा। हर संदेश को संयम और धैर्य के साथ भेजना ही संवाद शैली की एक विशेषता है। हमें ऐसा लग सकता है कि हम अपने विरोधी से क्यों मधुर स्वर में बात करें, लेकिन अपने विरोधी से भी प्रेम से बात करना केवल शिष्टाचार नहीं है, बल्कि हमारी स्वयं की दूरदर्शिता है। इससे न केवल हम विपक्षी को अपने पक्ष में ला सकते हैं, बल्कि अपने काम में आ रही बाधाओं को भी दूर कर सकते हैं।

मधुर संवाद के लिए हमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस इतना ही करना काफी है कि बोलने से पहले उस बात पर विचार कर लिया जाए। हमेशा सकारात्मक शब्दों का चयन करना चाहिए और कभी-कभी प्रशंसा करने में कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। क्रोध में हमेशा मौन रहने की जरूरत है और किसी के द्वारा की गई आलोचना को नकारात्मक रूप से न लेकर, उसमें अपने प्रति भलाई हो, तो वह ढूंढ़ना चाहिए। वरना उसे छोड़ देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, जो सत्य हो, हितकारी हो और प्रिय भी हो।

प्रकृति ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है और इस श्रेष्ठता के मायने यह है कि मनुष्य के पास संवाद की क्षमता है। यह संवाद केवल क्षमता तक सीमित नहीं है, ये हमारे संवाद के कौशल, यानी उसकी मधुरता और संवेदनशीलता पर भी निर्भर है। मधुर संवाद क्षमता सामने वाले के मन का बोझ दूर करती है। माता-पिता अगर बच्चे से बात करते समय मधुर संवाद का कौशल अपनाएंगे, तो बच्चे पर प्रभाव सकारात्मक होगा। अगर एक अधिकारी अपने अधीनस्थों से मधुर संवाद रखेगा, तो काम में प्रवीणता आएगी और अगर पति-पत्नी के संबंधों के बीच या फिर मित्र और मित्र के बीच में मधुर संवाद होगा, तो आपसी गलतफहमियां स्वतः ही दूर हो जाएंगी।

जरूरी बात यह है कि हमारी बात में दृढ़ता तो हो, लेकिन कटुता नहीं। भाषा की मधुरता जीवन का सच्चा रंग है, जिसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। बड़े से बड़े सफल व्यक्ति ने यही मधुर संवाद शैली अपनाकर अपने जीवन को कामयाब बनाया है और इसके जरिए हम भी अपने जीवन को सफल और सुगम बना सकते हैं।

दुनिया मेरे आगे

> **ते जी से बदलते दौर में सोशल मीडिया पर लोग आज जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हुए संवाद करते हैं, उससे धीरे-धीरे हमारी संवेदनशीलता और संवाद शैली प्रभावित हो रही है। कई बार हम बिना सोचे-समझे भी किसी के बारे में कुछ कह बैठते हैं और बात फिर बिगड़ती चली जाती है।**

रोजगार के आयाम

दिल्ली में हुए एआइ सम्मेलन में भारत ने 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' के अपने मूल मंत्र के साथ कृत्रिम मेधा के मानवीय और समावेशी उपयोग की वकालत की। इस मौके पर वैश्विक शांति एवं रोजगार सृजन के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता का आह्वान किया गया। सम्मेलन में चीन और अमेरिका ने भी सहभागिता कर विकासोन्मुख और जिम्मेदार एआइ के पक्ष में समर्थन जताया। दोनों देशों ने स्वीकार किया कि एआइ का उपयोग स्थानीय बुनियादी जरूरतों को पूरा करने, संसाधनों की लागत घटाने और जनकल्याणकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने में किया जाना चाहिए। आज दुनिया के अनेक देश कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। एआइ के बढ़ते प्रभाव को लेकर यह आशंका व्यक्त की जाती रही है कि इससे पारंपरिक नौकरियों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। मगर सच यह भी है कि जब-जब नई तकनीकें आईं, तमाम आशंकाओं के बावजूद नए रोजगार भी पैदा हुए। हर तकनीकी परिवर्तन ने श्रम के स्वरूप को बदला है, समाप्त नहीं किया। एआइ भी स्वास्थ्य सेवाओं, डेटा विश्लेषण, साइबर सुरक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, शिक्षा तकनीक और नव उद्यम में नए अवसरों के द्वार खोल सकती है।

– अरविंद रावल, झाबुआ, मप्र

जल्दबाजी के जोखिम

हमारे देश में प्रतिदिन कई लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। सड़क दुर्घटनाओं के कई कारण हैं, लेकिन वाहनों की तेज रफ्तार इसका मुख्य कारण है। सुबह सभी को अपने काम के लिए समय पर पहुंचना होता है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वे घर से देरी से निकलते हैं और फिर तेज गति से अपने गंतव्य पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। ऐसा कर वे खुद की और दूसरों की जान को भी जोखिम में डाल देते हैं। इसलिए सभी को समय से पहले घर से निकलना चाहिए। यातायात नियमों का पालन हर किसी को करना चाहिए। कहते भी हैं कि घर कभी न पहुंचने से देर भली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सड़क हादसों में जान गंवाने वाले लोगों के जो आंकड़े देता है, वे चिंता बढ़ाते हैं। यातायात नियम तोड़ने वालों का चालान काटने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं होता, बल्कि उन लोगों को सबक सिखाना होता है, जो सड़कों पर नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं।

– राजेश कुमार चौहान, जलंधर

टूटती कड़ियां

'हिंसा का मानस' (संपादकीय, 25 फरवरी) पढ़ कर यह विचार कौंधना स्वाभाविक है कि आखिर हमारे देश और समाज में ऐसी लोमहर्षक वारदात क्यों बढ़ रही हैं? जहां रक्त का संबंध है, उसमें भी अब मोह नहीं दिखता। माता-पिता और उनकी संतान एक दूसरे के अक्स होते हैं। ऐसे में संतान द्वारा हत्या दुखदायी है। भारत में माता-पिता का सम्मान और उनकी देखभाल को हमेशा से महत्त्व दिया जाता रहा है। फिर यह स्थिति क्यों और कैसे पनप रही है? पति-पत्नी, प्रेमी-प्रेमिका, अनैतिक संबंध और देह व्यापार में ऐसे नतीजे की बहुलता ने इसे इतना आम बना दिया है कि अब यह कौतूहल का विषय नहीं रहा। तो क्या यह माना जाए कि शिक्षा और संस्कार में कमी के कारण जीवन के नैतिक मूल्य खत्म हो रहे हैं? आखिर किस बात का दबाव है हमारी नई पीढ़ी पर? हम व्यवहार में क्यों भौतिकतावादी होते जा रहे हैं अपनी संस्कृति से विरत होकर।

– मुकेश कुमार मनन, पटना

जागरूकता की जरूरत

दुनियाभर में दिनचर्या बदलने के कारण बच्चों-बड़ों सब में मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। इससे निपटने के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। मोटापे को लेकर लोग पहले इतने चिंतित नहीं होते थे। इसे लेकर इतने जागरूक भी नहीं थे। मगर अब जीवनशैली बदलने और खानपान में लापरवाही के कारण बच्चों और बड़ों में मोटापा और उससे पनपने वाली बीमारियां बढ़ रही है। लिहाजा इसके उपचार के लिए हर राज्य में चिकित्सा केंद्र खोले जाने चाहिए। सरकारें उचित कदम उठाएं, जागरूकता अभियान चलाएं, तो लोगों को मोटापे की बीमारी से मुक्ति दिलाई जा सकती है। इसके लिए चिकित्सा विभाग के अधिकारियों और विशेषज्ञों की समिति बना कर ठोस योजना तैयार करनी चाहिए। साथ ही नागरिकों के स्वास्थ्य की दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए।

– शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

केरल में किसान सम्मेलन के दौरान राहुल गांधी ने व्यापार समझौते पर साधा निशाना, कहा

किसानों के हितों को होगा गंभीर नुकसान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 फरवरी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एपस्टीन फाइलों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकाने के लिए किया ताकि वह एक ऐसे व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करें, जिससे भारतीय किसानों के हितों को गंभीर नुकसान होगा।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष केरल के कन्नूर जिले के पेरावूर में एक किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार इस आम सी बात को नहीं समझती कि किसान भारत की बुनियाद हैं। आइटी और अन्य क्षेत्रों के बारे में लंबे-लंबे भाषण दिए जाते हैं लेकिन बुनियाद को मजबूत किए बिना कुछ भी नहीं बनाया जा सकता। अगर आप बुनियाद का सम्मान नहीं करेंगे, तो कुछ भी नहीं बनाया जा सकता। बुनियाद तैयार करने वाले को न तो सम्मान मिलता है और न ही संरक्षण। हम प्रतिदिन भोजन करते हैं लेकिन यह याद नहीं रखते कि उसे हमारी मेज तक कौन पहुंचाता है। राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ जो समझौता किया है, वह (देश की) 'बुनियाद को कमजोर करने जैसा' है।

उन्होंने कहा कि भारतीय किसान छोटे किसान हैं और उनमें मशीनों को लेकर समझ कम है। अमेरिकी किसानों के पास विशाल खेत हैं और उन्हें मशीनों की जानकारी ज्यादा है। अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजारों में प्रवेश देना एक आपराधिक कृत्य है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री ने अमेरिकी किसानों को भारत में सोयाबीन, सब्जियां और फल जैसे उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं दी थी।

उन्होंने कहा कि यह उस बुनियाद को नष्ट कर देगा जिसे हमने बड़ी सावधानी से तैयार किया है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति इसलिए हुई क्योंकि हमारा मानना था कि हमें कृषि में एक मजबूत बुनियाद के निर्माण की जरूरत है। राहुल ने दावा किया कि राष्ट्रपति के भाषण के बाद उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया गया क्योंकि वे दो मुद्दे उठाना चाहते थे। एक मुद्दा एपस्टीन की उन 35 लाख फाइलों से जुड़ा है जो अब तक सामने नहीं आई हैं। ये फाइलें अमेरिकी सरकार द्वारा गुप्त रखी गई हैं और कथित तौर पर इनमें प्रधानमंत्री से संबंधित जानकारियां हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और अनिल अंबानी के बारे में जारी की गई जानकारी भारत के प्रधानमंत्री को निशाना बनाकर की गई है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री के सिर पर तलवार की तरह लटकाया गया दूसरा हथियार अमेरिका में जारी अडाणी मामला है। अडाणी कोई आम कंपनी नहीं है। अडाणी भाजपा और भारत के प्रधानमंत्री का वित्तीय ढांचा है।

वायनाड में भूस्खलन पीड़ितों के लिए 100 घरों की आधारशिला रखी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में 2024 के भूस्खलन के पीड़ितों के लिए पार्टी द्वारा निर्मित किए जाने वाले 100 घरों की आधारशिला रखी। कांग्रेस द्वारा 100 मकानों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल 1,100 वर्ग फुट और भूमि का क्षेत्रफल 8 सेंट होगा। सेंट भूमि मापन की एक इकाई है। उन्होंने प्रभावित परिवारों को आश्वासन दिया कि वह और उनका परिवार इस त्रासदी में सब कुछ खो चुके लोगों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। उन्होंने दो बड़े भूस्खलनों और उन पर लोगों की प्रतिक्रिया को याद किया और कहा कि आपने बहुत कुछ खोया है, लेकिन आपने अपना हौसला नहीं खोया।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को जारी किया नोटिस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 फरवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने झूठी शिकायतों, फर्जी साक्ष्यों और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन पर रोक लगाने संबंधी जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गुरुवार को नोटिस जारी कर दिया। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस याचिका में निर्दोष नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा के लिए प्रशासनिक सुरक्षा उपाय लागू करने की मांग की गई है।

झूठी शिकायतों पर रोक लगाने संबंधी जनहित याचिका दायर।

सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए समाज को दूसरों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा-हमें गैगिंग का आरोप लगाया जाएगा, लेकिन इससे डरना क्यों चाहिए? लोग दुरुपयोग करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। हमें एक जागरूक समाज बनाना होगा, जहां लोग अपने पड़ोसी के मौलिक अधिकारों को भी समझें। बंधुत्व के सिद्धांत को विकसित करना होगा।

अदालत ने यह भी कहा कि कई बार झूठी शिकायतें वास्तविक शिकायतकर्ता की जानकारी के बिना भी दर्ज कर दी जाती हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा-समस्या तब होती है जब झूठी शिकायत दर्ज होती है और वास्तविक शिकायतकर्ता को पता ही नहीं होता। नकली हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं और गरीब व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अदालत में स्वयं उपस्थित होकर वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि फर्जी मुकदमे न्याय प्रणाली पर भारी बोझ हैं। उन्होंने कहा कि अदालतों पर असली मामलों से ज्यादा नकली मामलों का बोझ है। जमीन का विवाद होता है, लेकिन मामला एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज कर दिया जाता है। ईमानदार लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। ग्रामीण समाज का ताना-बाना प्रभावित हो रहा है। सिविल मामला आपराधिक बना दिया जाता है।

'सत्ता खुद को राष्ट्र समझने लगे तो लोकतंत्र मर जाता है'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 फरवरी।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जब सत्ता खुद को राष्ट्र और असहमति को दुश्मन समझने लगे, तब लोकतंत्र मर जाता है। शांतिपूर्ण विरोध अपराध नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। सवाल पूछना लोकतंत्र की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। लोकतंत्र तब मजबूत होता है, जब सरकार आलोचना सुनती है, जवाब देती है और जवाबदेह रहती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, ये उत्तरी कोरिया नहीं, भारत है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 'एक्स' पर लिखा कि आज प्रधानमंत्री (समझौता प्रधानमंत्री) के राज में शांतिपूर्ण विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया है। इस कारण दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को धीरे-धीरे ऐसी दिशा में धकेला जा रहा है, जहां असहमति को देशद्रोह और सवाल पूछने को साजिश बताया जाता है। राहुल गांधी ने सवाल किया कि सोचिए कि मुद्दा कोई भी हो, अगर आप सत्ता के खिलाफ संवैधानिक तरीके से आवाज उठाते हैं, तो लाठी, मुकदमा और जेल यह लगभग तय है। इन मामलों में राहुल गांधी ने पर्चाफोड़ से लेकर किसान आंदोलन जैसे मुद्दों को गिनाया।

उन्होंने कहा कि पर्चाफोड़ से त्रस्त युवाओं ने अपने भविष्य के लिए आवाज उठाई तो उन्हें लाठियां मिलीं। इसी तरह महिला पहलवानों ने भाजपा के प्रभावशाली नेता पर लगे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की तो उनकी पुकार को बदनाम किया गया, आंदोलन को कुचला गया और उन्हें सड़कों से जबरन हटाया गया। एक बलात्कार पीड़िता के समर्थन में इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ। न्याय की मांग को व्यवस्था के लिए असुविधा मानकर हटा दिया गया।

रंगारंग

देहरादून में गुरुवार को उत्तराखंड कांग्रेस कार्यालय में होली मिलन कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुति देते कलाकार।

महाराष्ट्र : राज्यसभा सीट पर महाविकास आघाड़ी में खींचतान

शिवसेना (उद्धव) के बाद कांग्रेस ने भी किया दावा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 फरवरी।

महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी (एमवीए) की जीत वाली एकमात्र राज्यसभा सीट पर गठबंधन के घटक दलों के बीच खींचतान जारी है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होने का हवाला देते हुए गुरुवार को इस सीट पर दावा किया, जबकि कुछ ही दिन पहले शिवसेना (उद्धव) ने इस सीट पर अपना 'पहला अधिकार' जताया था।

कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद गुट) और शिवसेना (उद्धव) के गठबंधन एमवीए के वरिष्ठ नेताओं ने गुरुवार को आगामी राज्यसभा चुनाव और सीट आबंटन पर विचार-विमर्श करने के लिए एक बैठक की। बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने पत्रकारों से कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा है कि राज्यसभा सीट उसे दिया जाए। राकांपा (शरद गुट) अपने पार्टी आला कमान से परामर्श करेगी, जबकि शिवसेना (उद्धव) भी अपना रुख स्पष्ट करेगी। वडेट्टीवार ने भरोसा जताया कि राज्यसभा और महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए सीट बंटवारे का मुद्दा बातचीत के माध्यम से हल हो जाएगा। सभी दल अपने-अपने नेतृत्व के साथ परामर्श करेंगे, जिसके बाद ही अंतिम निर्णय पर पहुंचा जाएगा।

उन्होंने कहा कि वैसे तो शिवसेना (उद्धव) और कांग्रेस दोनों ने इस सीट पर दावा किया है, लेकिन एमवीए एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। तीनों पार्टियों की सहमति से ही उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पांच मार्च तक दाखिल किए जा सकते हैं और गठबंधन सहयोगियों से चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

वडेट्टीवार ने कहा कि अगर गठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़ता है तो एमवीए की जीत निश्चित है। नासिक जिले के मालेगांव कस्बे में नगर निगम कार्यालय के अंदर कथित तौर पर नमाज अदा करने की घटना के बारे में पूछे जाने पर वडेट्टीवार ने कहा कि सड़कों पर इस तरह के कार्य नहीं किए जाने चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि रमजान के दौरान रोजा रखने वालों के लिए समय पर नमाज अदा करना महत्त्वपूर्ण होता है।

महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति ने उठाई मांग

पवार विमान हादसे के तथ्य सरकार सदन में पेश करे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 फरवरी।

महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति राम शिंदे ने गुरुवार को राज्य सरकार को उस विमान दुर्घटना से संबंधित तथ्यों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें प्रदेश के उपमुख्यमंत्री रहे अजित पवार की मृत्यु हो गई थी। सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद गुट) के विधान परिषद सदस्य शशिकांत शिंदे ने 28 जनवरी की दुर्घटना पर चर्चा की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव पेश किया।

उन्होंने कहा कि सांसद अमोल मितकारी और रोहित पवार समेत कई लोगों ने अजित पवार की मौत की परिस्थितियों को लेकर संदेह जताया है। कई लोगों ने सीबीआइ जांच की मांग की है। शशिकांत शिंदे ने कहा कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विमान की उड़ान योग्यता, हवाई सुरक्षा एवं उड़ान संचालन के क्षेत्र में अनुमोदित प्रक्रियाओं का पालन न करने के कारण वीएसआर वेंचर्स के चार विमानों को उड़ान भरने से रोकने का आदेश दिया है।

वीएसआर वेंचर्स उस दुर्भाग्यपूर्ण लियरजेट-45 विमान का संचालन कर रही थी जो 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। शशिकांत शिंदे ने दावा किया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि डीजीसीए के आदेश के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है। इससे संदेह पैदा होता है। कंपनी की ओर से लापरवाही बरती गई है। रोहित पवार और मितकारी वीएसआर वेंचर्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं।

बारामती विमान हादसा : हर पहलू से सीआइडी कर रही है जांच

महाराष्ट्र अपराध जांच विभाग (सीआइडी) ने गुरुवार को कहा कि बारामती विमान दुर्घटना की जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि यह साजिश थी या आपराधिक लापरवाही। इस दुर्घटना में उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र अपराध जांच विभाग के एडीजी सुनील रामानंद ने कहा कि घटना की जांच विस्तृत और पेशेवर तरीके से की जा रही है। सीआइडी जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि विमान दुर्घटना में कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई थी। यह भी जांच की जाएगी कि क्या कोई आपराधिक लापरवाही हुई थी या किसी आपराधिक कृत्य को अंजाम तो नहीं दिया गया।

एनसीईआरटी मामले में जवाबदेही तय करेंगे, कार्रवाई होगी : प्रधान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 फरवरी।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा आठवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक अध्याय शामिल किए जाने को लेकर गुरुवार को नाराजगी जताई। उन्होंने जवाबदेही तय करने और पाठ्यक्रम के विवादास्पद अंश को तैयार करने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया।

प्रधान ने इस बात पर जोर भी दिया कि सरकार न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है और इस संस्था का अनादर करने का उसका कोई इरादा नहीं है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे दिन आई है, जब सुप्रीम कोर्ट ने पाठ्यक्रम के विवादित अंश के संदर्भ में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायिक संस्था को कमजोर करने और न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए एक सुनियोजित प्रयास किया गया है।

प्रधान ने कहा कि जो कुछ हुआ है उससे मैं बहुत दुखी हूं और खेद व्यक्त करता हूं... न्यायपालिका का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। जांच की जाएगी और जवाबदेही तय की जाएगी। अध्याय तैयार करने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही हमें (ऐसी सामग्री होने की) जानकारी मिली, पाठ्यपुस्तकों का वितरण रोक दिया गया। उन्होंने जमशेदपुर में पत्रकारों से कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका सर्वोच्च है और हम उसका पूरा सम्मान करते हैं।

पेज 1 का बाकी

दिल्ली व शिमला पुलिस के बीच 24 घंटे चला टकराव

गिरफ्तारी के दौरान कथित रूप से जमा किया गया। दिल्ली पुलिस ने इस बात पर जोर दिया कि तीनों आरोपियों की हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है और वे अपने किसी सदस्य को नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद वे शोघी की तरफ रवाना हुए। हालांकि, शिमला पुलिस ने तड़के करीब चार बजे शोघी सीमा पर दिल्ली पुलिस की टीम को फिर रोक लिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस के पास मौजूद डिजिटल साक्ष्यों को लेकर गतिरोध की स्थिति बनी रही।

दिल्ली पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त राहुल विक्रम ने बाद में मीडिया से कहा कि शिमला पुलिस कानूनी तौर पर डिजिटल सबूत या उनकी गाड़ी जब्त नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि अगर शिमला पुलिस को सबूत चाहिए तो उन्हें लिखकर अनुरोध करना होगा। इसके बाद दिल्ली की टीम वहां से निकल गई। दिल्ली पुलिस अब आरोपियों को राष्ट्रीय राजधानी में स्थानीय मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर सकती है और उनकी रिमांड मांग सकती है।

दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 20 फरवरी को कमीज उतार कर किए गए विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने पहले भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत दंगा करने और वैमनस्य फैलाने सहित विभिन्न आरोप लगाए थे। अधिकारियों ने बताया कि विशेष प्रकोष्ठ ने विशिष्ट जानकारी और तकनीकी निगरानी के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों का पता लगाया। मामले में मंगलवार को भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब और पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता भूदेव शर्मा को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि दोनों को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

एनसीईआरटी की कक्षा आठवीं की किताब पर प्रतिबंध लगाया

क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए। एनसीईआरटी के बुधवार के पत्र का जिक्र करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यह (पत्र) अपने आप में गहरी साजिश को दर्शाता है, एक सुनियोजित साजिश। पीठ ने कड़े शब्दों में कहा कि ऐसा लगता है कि न्यायपालिका को कमजोर करने और उसकी गरिमा कोठेस पहुंचाने की 'सोची-समझी साजिश' रची जा रही है।

पीठ ने चेतावनी दी कि अगर उसके निर्देशों का किसी भी तरह से उल्लंघन किया गया तो गंभीर कार्रवाई की जाएगी। पुस्तक की सामग्री का हवाला देते हुए पीठ ने टिप्पणी की कि इस प्रकार के व्यवहार का न्यायपालिका पर गहरा असर पड़ेगा। इस तरह का आचरण आपराधिक अवमानना की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर इसे रोका नहीं गया तो इससे न्यायपालिका में लोगों का विश्वास कम होगा। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि संस्था के प्रमुख के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं इसके लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाऊं। हम गहन जांच करना चाहेंगे। पीठ ने इसके बाद निर्देश दिया कि केंद्र और राज्यों के शिक्षा विभागों के समन्वय से एनसीईआरटी यह सुनिश्चित करे कि पुस्तक की सभी प्रतियां, चाहे वह 'हार्ड कापी' हो या 'साफ्ट कापी', उन्हें सार्वजनिक पहुंच से हटा दिया जाए। अत्यधिक सावधानी बरतते हुए आगे पुस्तक के किसी भी तरह से प्रकाशन, पुनर्मुद्रण या डिजिटल प्रसार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता है।न्यायालय ने कहा कि पुस्तक को भौतिक या डिजिटल रूप से वितरित करने का कोई भी प्रयास अदालत के आदेश की जानबूझकर अवहेलना माना जाएगा।

नई पाठ्यपुस्तक में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' शीर्षक वाले खंड में कहा गया है कि भ्रष्टाचार, लंबित मुकदमों का भारी बोझ और न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या की कमी न्यायिक प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों में से हैं। पाठ्यपुस्तक की सामग्री में यह भी कहा गया है कि न्यायाधीश एक आचार संहिता से बंधे होते हैं जो न केवल अदालत में उनके व्यवहार को नियंत्रित करती है, बल्कि अदालत के बाहर उनके आचरण को भी नियंत्रित करती है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि कार्यवाही का उद्देश्य किसी भी वैध आलोचना को दबाना या न्यायपालिका की समीक्षा के अधिकार के प्रयोग को रोकना नहीं है। सुनवाई शुरू होने पर महाधिवक्ता तुषार मेहता ने शिक्षा मंत्रालय की ओर से बिना शर्त माफी मांगी। प्रधान न्यायाधीश हालांकि इससे संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी के पत्र में माफी का एक भी शब्द नहीं है, बल्कि इसमें अध्याय को सही ठहराने की कोशिश की गई है। पुस्तक में शब्दों और अभिव्यक्तियों का चयन असावधानी के कारण या अनजाने में हुई गलती नहीं कहा जा सकता। इस उम्र में छात्रों को 'पक्षपातपूर्ण विमर्श' से अवगत कराना सरासर अनुचित है, क्योंकि इससे मूलभूत गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। पीठ ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 11 मार्च की तारीख तय की।प्रधान न्यायाधीश ने बुधवार को कहा कि दुनिया में किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने और उसकी ईमानदारी को धूमिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी द्वारा इस मामले का जिक्र किए जाने के बाद प्रधान न्यायाधीश स्पष्ट रूप से नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कानून अपना काम करेगा। मुझे इससे निपटना आता है। स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए जिम्मेदार एनसीईआरटी ने बुधवार को अपनी वेबसाइट से पुस्तक हटाने के कुछ घंटों बाद ही पाठ्यपुस्तक का वितरण रोक दिया। उधर, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को को पत्र लिखकर उनसे एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक का डिजिटल मंचों व इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए प्रसार रोकने को कहा।

भारत और इजराइल संबंध विशेष रणनीतिक साझेदारी स्तर तक बढ़े

ने कहा, 'भारत का रुख स्पष्ट है: मानवता को कभी भी संघर्ष का शिकार नहीं बनना चाहिए। गाजा शांति योजना के माध्यम से शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। भारत ने इन प्रयासों का पूर्ण समर्थन किया है।' उन्होंने कहा, 'भविष्य में भी हम सभी देशों के साथ संवाद और सहयोग जारी रखेंगे।'

प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को दो दिवसीय दौरे पर इजराइल पहुंचे। नौ वर्षों में यह उनका इजराइल का दूसरा दौरा है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इजराइल का यह एक साझा मत है कि दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है और दोनों पक्ष आतंकवाद तथा उसके समर्थकों का मुकाबला करने में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन्होंने कहा, 'हमारा रिश्ता गहरे विश्वास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय संवेदनशीलता की मजबूत नींव पर टिका है। हमारा बंधन समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है।' उन्होंने कहा, 'आज हमने अपनी समय की कसौटी पर खरी साझेदारी को विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।'

प्रधानमंत्री ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तकनीक और महत्त्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्रों में सहयोग को नई गति प्रदान करने के लिए भारत-इजराइल महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों की साझेदारी की स्थापना की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, 'मुझे खुशी है कि इजराइल में यूपीआइ के उपयोग के लिए एक समझौता हो गया है।' प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खतरे का जिक्र करते हुए कहा कि भारत और इजराइल इस खतरे का एकजुट होकर सामना करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, 'भारत और इजराइल इस बात को लेकर पूरी तरह स्पष्ट हैं कि दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में, आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।'

उन्होंने आगे कहा, हम आतंकवाद और उसके समर्थकों का विरोध करने में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं, और हम ऐसा करना जारी रखेंगे। भारत और इजराइल के बीच भारत-पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे (आइएमईसी) के कार्यान्वयन और आइ2यू2 (भारत-इजराइल-यूएई-अमेरिका) के ढांचे के तहत सहयोग पर भी चर्चा हुई। विदेश सचिव विक्रम मिसरी के अनुसार, वार्ता में अमेरिका-ईरान गतिरोध और क्षेत्रीय अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद के महत्व में भारत के दृढ़ विश्वास का उल्लेख किया और यदि आवश्यक हो तो शांतिपूर्ण समाधान हासिल करने के लिए समर्थन देने की दिल्ली की तत्परता दोहराई।

बिहार : हजारों करोड़ रुपए के बकाए पर सवाल

कर के रूप में 248.58 करोड़ रुपए बकाया है, जबकि वाहनों पर कर के रूप में 183.39 करोड़ रुपए की वसूली लंबित है। विभाग ने पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित बकायों का स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं कराया। खनन एवं धातुकर्म उद्योग पर 1,505.16 करोड़ रुपए का बकाया दर्शाया गया है। खान एवं भूतत्व विभाग ने भी लंबे समय से लंबित राशि का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया। भू-राजस्व मद में 302.47 करोड़ रुपए, मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस में 215.61 करोड़ रुपए तथा राज्य उत्पाद में 54.30 करोड़ रुपए बकाया पाए गए।

वस्तु एवं सेवा कर में 3.25 करोड़ रुपए तथा विद्युत कर एवं शुल्क मद में भी बकाया राशि का उल्लेख किया गया है। परिवहन विभाग में वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया में भी गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार स्वचालित परीक्षण केंद्रों में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और सभी मानकों की जांच किए बिना ही प्रमाण-पत्र जारी कर दिए गए। जांच में पाया गया कि 47,223 वाहनों में से 42,672 वाहनों (90 फीसद से अधिक) को नियमों के उल्लंघन के बावजूद फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी कर दिए गए, जिससे सरकार को 2.27 करोड़ रुपए की राजस्व हानि हुई। इसके अलावा, 66,345 वाहनों की जांच में 35,921 वाहन फिटनेस परीक्षण में अनुत्तीर्ण पाए गए, जो सड़क सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर चिंता का विषय है।

कई मामलों में 'आनलाइन अपाइंटमेंट' प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम से जुड़े प्रकरण में ठेकेदारों को 94.25 लाख रुपए का अनुचित लाभ पहुंचाने का उल्लेख भी रपट में किया गया है। रपट के सदन में प्रस्तुत होते ही राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और विभिन्न विभागों की जवाबदेही को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को भेजा नोटिस

नई दिल्ली, 26 फरवरी (ब्यूरो)।

सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में संलिप्त नाबालिग के पिता द्वारा दायर जमानत याचिका पर गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा।

पोर्श कार हादसा मामले में मुख्य आरोपी के पिता ने मांगी जमानत।

पुणे के कल्याणी नगर इलाके में 19 मई 2024 को कथित तौर पर शराब के नशे में गाड़ी चला रहे एक किशोर ने पोर्श कार से दो आइटी पेशेवरों को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने विशाल अग्रवाल की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। अग्रवाल ने बंबई हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की है।

गलत पाठ न पढ़ाएं

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) से सर्वोच्च न्यायालय की नाराजगी बिल्कुल जायज है और इस नाराजगी का यथोचित पटाक्षेप होना चाहिए। एनसीईआरटी द्वारा जारी कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य-पुस्तक के एक अध्याय में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की ओर संकेत किया गया था और यह पुस्तक उपयोग में थी। अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर न केवल इस पुस्तक पर पूरी तरह से रोक लग गई है, इसकी तमाम वितरित प्रतियों को भी वापस लेने का आदेश हुआ है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने बिल्कुल सही सवाल किया है- क्या आप सिखाना चाहते हैं कि न्यायपालिका भ्रष्ट है? वाकई स्कूली बच्चों को यह बताना या पढ़ाना किसी भी दृष्टि से अनुचित है। एनसीईआरटी की इस पुस्तक ने न्यायालय को बहुत निराश किया है। न्यायाधीशों की भाषा में कहें, तो न्यायपालिका का खून बहाया गया है। अतः यह न्यायपालिका के साथ खड़े होने का समय है।

सोचकर देखिए, स्कूली बच्चों को अगर यह पढ़ाया जाए कि हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधायिका बुरी है, तो इससे क्या संदेश जाएगा? यह पढ़कर बच्चे देश के बारे में क्या धारणा बनाएंगे?

स्कूली बच्चों को यदि पढ़ाया जाएगा कि हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधायिका बुरी है, तो क्या संदेश जाएगा? यह पढ़कर बच्चे देश के बारे में क्या सोचेंगे?

यह बहुत अफसोस की बात है कि एनसीईआरटी को देश की एक जिम्मेदार संस्था माना जाता है और अनेक चरणों से गुजरकर वहां किताबें तैयार होती हैं। इस बड़ी गलती को एनसीईआरटी अनजाने में हुई गलती मान रहा है। हालांकि, उसकी यह दलील पर्याप्त नहीं है और दोषियों पर गाज गिरना तय है। इस मामले में अब केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का रुख भी कड़ा है। जैसा कि पूछा जा रहा है, क्या वाकई केवल दो लोग इस गलती के लिए जिम्मेदार हैं? क्या केवल दो लोगों को कठघरे में खड़ा कर देने से एनसीईआरटी की जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? एनसीईआरटी को यह सुनिश्चित करना होगा कि पाठ्य-पुस्तक लेखन में बहुत सुलझे हुए विचारवान लोगों के लिए जगह बने। साथ ही, लेखन से भी ज्यादा जरूरी है, लिखे हुए पाठ को व्यापक दृष्टिकोण से परखना। समाज में नाना प्रकार के सत्य हैं, किंतु हर सत्य स्कूलों में पढ़ाया या सिखाया जाए, तो इसके नुकसान ज्यादा और फायदे कम हैं। सही पाठ्य-पुस्तकें बच्चों में उत्साह और आशा बढ़ाने का काम करती हैं। देश के प्रति प्रेम-भाव पैदा करती हैं, व्यवस्था के प्रति सम्मान भाव लाती हैं, ताकि बच्चे जब बड़े हों, तब जागरूक नागरिक साबित हों। यदि उन्हें कोई यह पढ़ाना चाहता है कि हमारी व्यवस्था का फलां अंग खराब हो चुका है, तो वास्तव में यह देश की शिक्षा और मानसिकता को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। इसे अपराध की श्रेणी में रखकर आगे बढ़ा जाए, तो बेहतर है।

बहरहाल, देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत गहन जांच चाहते हैं। यह पता लगाना चाहते हैं कि कौन-कौन जिम्मेदार हैं? दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और यह मामला अभी बंद नहीं होगा। शुरू में एनसीईआरटी की ओर से यह कोशिश हुई थी कि माफी मांगकर मामला रफा-दफा हो जाए, पर इसी वजह से न्यायालय की नाराजगी ज्यादा बढ़ी है। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सचेत रहना होगा और न्यायपालिका का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए जो भी संभव हो, करना होगा। ध्यान रहे, व्यवस्था में परस्पर अविश्वास बढ़ने से केवल नुकसान ही होगा। न्यायपालिका की यह वाजिब नाराजगी जितनी जल्दी दूर हो जाए, उतना अच्छा है। अब केंद्र सरकार ऐसे पुख्ता कदम उठाए कि एनसीईआरटी के लिए हमेशा के लिए नजीर बन जाए।

इजरायल से और गहरी हुई दोस्ती

हर्ष वी पंत | प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज लंदन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा ऐतिहासिक है। मोदी ने इजरायली संसद को संबोधित किया और वहां लगे हाथ फलस्तीन पर भारत के पुराने रुख को दोहराया है।

तेजी से बदलती वैश्विक भू-राजनीति के इस दौर में भारत और इजरायल का रिश्ता कितना परिपक्व हुआ है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेल अवीव दौर से पता चलता है। अमेरिका-ईरान में बढ़ते तनाव और गाजा संघर्ष की छाया में 25-26 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी इजरायल में थे। वहां न सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनके निजी रिश्ते की झलक मिली, बल्कि रणनीतिक नजरिये से द्विपक्षीय रिश्ते की अहमियत भी अधिक पुष्ट हुई।

गुरुवार को जारी साझा बयान में इजरायल से रक्षा, एआई, कृषि सहित कई क्षेत्रों में समझौते की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल के साथ 'विशेष रणनीतिक रिश्ते' की बात भी कही। वास्तव में, 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के बाद से दोनों देशों ने सुरक्षा हितों और आर्थिक तालमेल बढ़ाने पर खूब काम किया है। इससे मध्य-पूर्व में व्यापक संतुलन साधने में नई दिल्ली की मुश्किलें कुछ हद तक दूर हुई हैं। देखा जाए, तो दोनों देशों का यह रिश्ता सिर्फ द्विपक्षीय नहीं रहा, बल्कि पूरे मध्य-पूर्व को प्रभावित करता है। भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा और भारत-इजरायल-यूएई-अमेरिका (आई2यू2) को देखते हुए यह समझ में भी आता है।

साल 2017 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह दूसरी इजरायल यात्रा थी। अस्थिर क्षेत्रीय परिवेश के बीच आपसी रिश्तों को मजबूत करना इस यात्रा का बड़ा मकसद था। बेन गुरियन हवाई अड्डे पर भारतीय प्रधानमंत्री को लेने खुद नेतन्याहू पहुंचे, जो रणनीतिक रिश्ते में निहित निजी संबंध का संकेत था। ऐसी दोस्ती का बड़ा फायदा यह होता है कि इससे गठबंधन सिर्फ रणनीतिक नहीं रह जाता, बल्कि मानवीय बनता है। नेतन्याहू ने मोदी को 'बड़ा भाई' भी बताया।

येरुशलम के किंग डेविड होटल में दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई, जिसमें मुख्य जोर सुरक्षा और आर्थिक रिश्तों को बेहतर बनाने पर रहा। मुक्त व्यापार समझौते के लिए लंबित कामों को पूरा करने पर भी सहमति बनी। इसमें यह सब यूं ही नहीं हुआ है। इतिहास बताता है कि इजरायल ने हमेशा खुद को भारत का एक विश्वसनीय भागीदार साबित किया है। उसने जरूरत के समय महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकी की हमें आपूर्ति की है, जैसे 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान।

इस दौरे की एक ऐतिहासिक घटना रही, भारतीय प्रधानमंत्री का इजरायली संसद को संबोधित करना। इस मौके पर उन्हें 'स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल' से भी सम्मानित किया गया, जो इस सदन का सर्वोच्च सम्मान है। यहां मोदी का हमास हमलों के संदर्भ में यह कहना कि 'इजरायल के साथ भारत खड़ा है', उल्लेखनीय था, क्योंकि यह सीमा पार आतंकवाद, खासतौर से पाकिस्तानी जमीन पर पलने वाले संगठनों से भारत को होने वाले नुकसान से समानता रखता है। हालांकि, इसमें प्रधानमंत्री ने फलस्तीन मसले के संदर्भ में गाजा शांति योजना का भी समर्थन किया, जिससे भारतीय कूटनीति की गहराई सामने आती है। यह रुख अरब देशों का भरोसा बनाए रखने के साथ-साथ इजरायल के साथ हमारे रिश्ते को और गहरा बनाएगा।

राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग के साथ मुलाकात और याद वाशेम स्मारक के दौरे सहित अन्य बैठकों में मौजूदा खतरों के खिलाफ समन्वय बढ़ाने की वकालत की गई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, जल संसाधन और कृषि में इजरायल ने खासी तरक्की की है, जिसको प्रदर्शित करने वाली नवाचार प्रदर्शनी ने संभावित सहयोग के रास्ते दिखाए। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायली कंपनियों से भारत में निवेश करने को कहा और कई समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर भी हुए। इनमें इजरायली आयरन डोम को भारत की सुदर्शन चक्र वायु रक्षा प्रणाली से जोड़ने को लेकर किया गया एमओयू उल्लेखनीय है। इन सबसे यह संकेत मिलता है कि अब गोपनीय रक्षा समझौतों तक ही दोनों देशों की रिश्ता सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि यह अब बहुआयामी हो चुका है, जिसे इजरायली तकनीकी दक्षता और भारत के विशाल बाजार से नई ऊर्जा मिल रही है।

इस साझेदारी के मूल में कई कारक हैं, जिनमें पहला है- रक्षा और सुरक्षा सहयोग। यह 1992 से ही द्विपक्षीय संबंध की बुनियाद रहा है। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से इजरायल भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है और रक्षा खरीद 66.2 करोड़ डॉलर से अधिक की हो चुकी है। सुदर्शन चक्र-आयरन डोम जैसी संयुक्त परियोजनाएं पाकिस्तान व चीन के बरअक्स भारत को नई ताकत देंगी।

भारत और इजरायल, दोनों को अपने पड़ोसी देशों के 'नॉन स्टेट एक्टर्स' से जूझना पड़ता है। इसीलिए, खुफिया जानकारियां साझा करने और आतंकवाद-विरोधी समन्वय बढ़ाने की जरूरत भी समझी गई। हालांकि, इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। मसलन, ईरानी तेल पर भारत की निर्भरता और चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए नई दिल्ली को इस कदर संतुलन साधना पड़ेगा कि तेहरान भी नाराज न हो और येरुशलम से संबंध भी आगे बढ़े।

प्रौद्योगिकी और नवाचार दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां इजरायल की 'स्टार्ट-अप राष्ट्र' की छवि भारत की डिजिटल महत्वाकांक्षा को नया रूप दे सकती है। एआई, साइबर सुरक्षा और क्वांटम कंप्यूटिंग में सहयोग दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ पहुंचाएगा। 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार (रक्षा को छोड़कर) 10.77 अरब डॉलर था, जो मूलतः हीरा, रसायन और मशीनरी के कारोबार पर टिका था। इस आंकड़े को दोगुना करने का लक्ष्य है। फिलहाल, निवेश दोनों तरफ से होता है। इतना ही नहीं, इजरायल की ड्रिप सिंचाई और विलवणीकरण में विशेषज्ञता भारत की खाद्य सुरक्षा चुनौतियों से पार पाने में सहायक साबित हो रही हैं। भारत की बढ़ती उत्पादकता इसका सुबूत है।

क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर समान सोच इस साझेदारी को आगे बढ़ा रही है। भारत को जहां पाकिस्तान और चीन से तनाव झेलना पड़ता है, वहीं इजरायल को ईरान व उसके सहयोगी देशों से। हालांकि, भारत का रुख संतुलित है। फलस्तीनियों के प्रति सहानुभूति रखते हुए इजरायल के प्रति व्यावहारिक नजरिया अपनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा रक्षा, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद-विरोधी क्षेत्रों में साथ-साथ आगे बढ़ते हुए मध्य-पूर्व की प्रतिद्वंद्विता जैसी चुनौतियों से निपटने में सहायक साबित होगी। इससे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता मजबूत हुई है। तेजी से बहुध्रुवीय हो रहे विश्व में, दोनों देशों के लिए ऐसी साझेदारियां अनिवार्य हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

भारत को प्रवासन संबंधी एक स्पष्ट नीति चाहिए

राज ऋषि सिंघल | वरिष्ठ पत्रकार

लंबी जद्दोजहद के बाद देश की सबसे अमीर नगरपालिका बृहन्मुंबई नगरपालिका परिषद (बीएमसी) को रितु तावड़े के रूप में अपना मेयर मिल गया। मुंबइकरों ने नई मेयर से काफी उम्मीदें पाल रखी हैं, इसलिए जब उन्होंने अपने पहले बयान में बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा किए गए कब्जे को हटाने को पहली प्राथमिकता बताई, तो लोग कुछ हैरान रह गए। खस्ताहाल सड़क, अवैध निर्माण, बढ़ता प्रदूषण, जर्जर सार्वजनिक परिवहन, फुटपाथ की कमी, कचरा निपटान और फ्लाईओवर को गिरने से रोकने के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ऐसा लगता है, उन्होंने पार्टी नेतृत्व को खुश करने के इरादे से यह बयान दिया या फिर वह अनजाने ही उस बात को दोहरा बैठीं, जो अब एक मौसमी जुमला बन चुकी है।

ब्रिटिश अरबपति कारोबारी और फुटबॉल क्लब 'मैनचेस्टर यूनाइटेड' के एक मालिक जिम रैटक्लिफ ने हाल ही में यह दावा किया कि उनके देश पर 'प्रवासियों का कब्जा' हो गया है, जो देश के संसाधनों को चूस रहे हैं। जाहिर है, उनकी टिप्पणी नस्लीय घृणा से प्रेरित थी और इतनी गलत थी कि प्रधानमंत्री केर स्टार्मर ने उन्हें फटकार लगाई। हालांकि, यह कहते वक्त रैटक्लिफ भूल गए कि इंग्लैंड में कर से बचने के लिए वह खुद मोनाको में रहते हैं।

रैटक्लिफ बयार देखकर पीठ मोड़ने वाले इंसान हैं और उनका ताजा बड़बोलापन भी शायद इंग्लैंड में 2025 के निकाय चुनावों व उप-चुनावों में दक्षिणपंथी दल 'रिफॉर्म यूके' को मिली अप्रत्याशित बढ़त से प्रभावित हो सकता है। रिफॉर्म यूके पार्टी की पहचान प्रवासी-विरोधी रही है। यूरोप में ऐसी पार्टियां तेजी से उभर रही हैं। प्रवासियों के विरोध की यह प्रवृत्ति पश्चिम बंगाल और असम में भी दिख रही है, जहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा ने इन दोनों राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुद्दा बना रखा है और इससे वे आर्थिक व सामाजिक मुद्दे दरकिनार हो गए हैं, जिन पर चर्चा और नीति-निर्माण की जरूरत है।

संयुक्त राष्ट्र की संस्था 'इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन' प्रवासन को 'अपने निवास से दूर किसी नए स्थान पर बसने, अंतरराष्ट्रीय सीमा के बाहर जाने या किसी राज्य के अंदर ही प्रवास के तौर पर परिभाषित करती है। फरवरी 2025 में *फॉरेन अफेयर्स* पत्रिका में प्रकाशित एक लेख में इस संस्था की महानिदेशक एमी पोप ने लिखा, 'प्रवासी-विरोधी नेता और कार्यकर्ता अफवाह फैलाते हैं कि उनके देश में अवैध प्रवासियों की विशाल लहर आ रही है।... ऐसी घटनाएं इतनी वैश्विक प्रवृत्ति वाली हो चुकी हैं कि ये उन कार्रवाइयों की भी समस्या की ओर संकेत करती हैं, जिनका मकसद खास सरहदों या देशों के विरुद्ध सख्ती बरतना होता है। आज जिस पैमाने पर प्रवासन हो रहा है, उससे यह तो साफ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी पुरानी, जर्जर प्रवासन व्यवस्था आज की इंसानी जरूरतों, लोगों की प्रवृत्ति या श्रम बाजार की मांगों को पूरा नहीं कर पा रही।

आज जिस पैमाने पर मजदूरों की आवाजाही या प्रवासन हो रहा है, उससे पता चलता है कि वर्तमान व्यवस्था खरी नहीं उतर रही है।

भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात तो करती है, मगर बिहार और उत्तर प्रदेश से होने वाले अंतरराज्यीय प्रवासन पर ध्यान नहीं देती, जहां की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। इसका दूसरा पहलू भी है। एक ओर जहां, मेजबान राज्य की आर्थिक प्रगति में प्रवासी मजदूरों की मेहनत का बड़ा योगदान होता है, वहीं भेजे गए धन से मजदूरों के गृह राज्य की आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 45.6 करोड़ प्रवासी थे, जो आबादी का 38 प्रतिशत थे, जबकि 2001 में 31.5 करोड़ या आबादी का 31 प्रतिशत थे। ये आंकड़े बताते हैं कि कुल प्रवासन में विदेशों से आने वाले प्रवासियों का हिस्सा सिर्फ एक प्रतिशत था।

केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने समय-समय पर होने वाले श्रम बल सर्वेक्षण के आधार पर साल 2020-21 में प्रवास संबंधी प्रवृत्ति का अध्ययन कराया है। हालांकि, इस दौरान बार-बार लगे लॉकडाउन के कारण आंकड़े बहुत सटीक शायद नहीं हों। इसलिए भारत को एक 'राष्ट्रीय श्रमिक प्रवासन नीति' बनाने की सख्त जरूरत है, जो प्रवासियों के आर्थिक योगदान पर आधारित आधिकारिक दस्तावेज हो। बयानबाजी से चुनाव तो जीता जा सकता है, लेकिन इससे अच्छी नीति नहीं बन सकती।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

सबको जोड़ते चलिए

सही प्यार का क्या स्वरूप है? वैष्णव दर्शन में बताया गया है, जब प्रेम बढ़ता है, समाज में, जाति, परिवार में, तो उसमें लेने का भाव घटता है। मन-हृदय में देने-देने का ही भाव रह जाता है। इसे वैष्णव दर्शन में *तत्सुख सुखोत्तम* कहते हैं। प्रिया को सुख मिले, यह प्रियतम की भावना होती है। यदि वह सुखी है, तो हम सुखी हैं और प्रिया सोचती है कि हमें अपने सुख की कोई परवाह नहीं, जो होगा देखा जाएगा, बस हमारा प्रेमी या प्रियतम खुश रहे।

श्याम मनोहर कृष्ण तो एक ही थे, उनकी हजारों गोपियां और पत्नियां थीं, किंतु किसी का हार्ट फेल नहीं हुआ। किसी ने कृष्ण के विरुद्ध याचिका दायर नहीं की। गोपियां यदि मिलकर हंगामा करतीं, तो भागवत की कथा ही नहीं हो पाती। गोपियों ने अपना रोम-रोम श्यामसुन्दर को दे दिया। भक्ति के आचार्य के रूप में गोपियों को देखा जाता है। उनसे ज्यादा प्रयोग और ज्ञान किसी को भक्ति का नहीं है। आचार्य कौन है? जिसने सर्वस्व को समझा और जिसने सम्पूर्ण जीवन का सार समझा और जीवन में उतारा, उसी को आचार्य कहते हैं।

आज तो आचार्य बनाने वालों को ही आचार्य शब्द के अर्थ का ज्ञान नहीं है। भ्रष्टाचार और आतंकवाद के विरुद्ध आंदोलन करने वाले को भ्रष्टाचार का ज्ञान नहीं है। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई घर आता है, तो कोई पानी भी नहीं पूछता। आचार्य भी आते हैं, तो कोई बैठने को नहीं कहता है। यदि आचार्य ही भ्रष्ट होंगे, तो उनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। मैं कह देता हूं कि वरिष्ठता का हनन करके लोकतंत्र में यदि किसी जूनियर को आगे ले आया जा रहा है, तो यह भ्रष्टाचार है या नहीं? ऐसे धार्मिक-सामाजिक-मानसिक भ्रष्टाचार के सामने धन का भ्रष्टाचार भी छोटा लगता है। सास आए और बहू बैठने को भी न कहे, तो कैसे चलेगा?

आज लोगों को भ्रष्टाचार का वास्तविक स्वरूप ही समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में, रामजी का जो जीवन अभियान है, हमें उसे जरूर देखना चाहिए। रामजी ने साधन का संग्रह नहीं किया, किसी पार्टी या किसी जाति या किसी अमुक की कभी उपेक्षा नहीं की, जो मिलता गया, उसे जोड़ लिया। सुग्रीव मिले, तो उन्हें जोड़ा, जामवंत मिले, तो उन्हें जोड़ा। निषादराज मिले, तो उन्हें और अनेक लोगों को जोड़ा। अपने समय के महान चिंतकों, मनिषियों, ऋषियों के पास आश्रमों में जा-जाकर रामजी दंडवत करते हैं।

रामराज्य की स्थापना के कुछ सूत्रों को अपनाना पड़ेगा। जो सात्विक जीवन के लोग हैं, उनसे सहयोग लें, प्रेरणा पाएं, उनसे आपका आधार बन जाएगा। यही आपके लिए औषधि बन जाएगी।

रामराज्य की स्थापना के कुछ सूत्र हैं, उनको अपनाना पड़ेगा। जो सात्विक जीवन के लोग हैं, उनसे आप सहयोग लें, प्रेरणा प्राप्त करें, उनसे आपका आधार बन जाएगा। यही आपके लिए औषधि बन जाएगी। हर व्यक्ति श्रेष्ठ जन के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखे, तभी वह अपने जीवन का श्रेष्ठतम उपयोग कर पाएगा।

रामानंदाचार्य स्वामी श्रीरामनरेशाचार्य

योगी आदित्यनाथ | मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

भारतीय जहां कहीं भी दुनिया के अंदर हैं, अपने क्षेत्र में उन्होंने प्रगति की है, कुछ नया करके दिखाया है... हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, यही हमारा धर्म है। हर भारतीय अपने इस धर्म का पालन जहां भी रहता है, करता है।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले | 27 फरवरी, 1951

उत्तर प्रदेश का बजट

उत्तर प्रदेश के अर्थ मंत्री श्री सम्पूर्णानन्द ने राज्य का सन् 1951-52 का बजट विधानसभा के सामने पेश करते हुए जो भाषण दिया, वह शासन के लोक हितकारी प्रयासों का एक उज्ज्वल चित्र हमारे सामने पेश करता है। उन्होंने बताया है कि शासकीय दृष्टि से समाप्त हो रहा वर्ष उसके पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में कई दिशाओं में ज्यादा अच्छा रहा। राज्य में हिंसात्मक अपराधों की संख्या घट गयी। पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को सफलतापूर्वक बसाया गया। राज्य की श्रमिक स्थिति अच्छी रही और चीनी मिलों के मजदूरों की निष्फल हड़ताल के अलावा कोई उल्लेखनीय गड़बड़ नहीं हुई। विलीन राज्यों के शासन को समान स्तर पर लाने का काम भी ठीक प्रकार से हुआ और ग्राम-पंचायतों का अब तक का कार्य-कलाप राज्य में ग्राम प्रजातंत्र के उज्ज्वल भविष्य की आशा दिलाता है। आर्थिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश के माननीय अर्थ मंत्री ने संतोष प्रकट नहीं किया है। वह ऐसा संतोष प्रकट भी कैसे कर सकते थे, जबकि महंगाई अधिकाधिक बढ़ती जा रही है और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने मुद्रास्फीति को खुला मैदान दे दिया है। उन्होंने कृषि और उद्योगों का उत्पादन बढ़ाकर बीजों के दाम की बाढ़ को रोकने की आवश्यकता प्रतिपादित की है। किंतु इस दिशा में कितनी सफलता मिलेगी, यह संदिग्ध है।

सन् 1951-52 के लिये राज्य की आय 61 करोड़ 26 लाख और व्यय 61 करोड़ 51 लाख अनुमान किया गया है। इस अनुमान के अनुसार 25 लाख का घाटा रहेगा। अर्थ मंत्री का कहना है कि जिस राज्य की 60 करोड़ जितनी मोटी आय हो, उसके लिए 25 लाख का घाटा मामूली बात है। हमारे विचार से आमदनी छोटी हो अथवा बड़ी, अर्थशास्त्र का यह ठोस सिद्धांत उपेक्षणीय नहीं समझा जाना चाहिये कि व्यय हमेशा आय की सीमा के भीतर रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार को चालू वर्ष में 1 करोड़ 36 लाख का घाटा रहने का अनुमान किया जा रहा है और उसकी पूर्ति संचित कोष से करनी पड़ेगी। राज्य के अर्थ मंत्री ने राज्य की आय बढ़ाने के लिये मौजूदा करों में कुछ वृद्धि किये जाने की ओर संकेत किया है। यदि करों में वृद्धि की गयी तो अर्थ मंत्री ने आश्वासन दिया है कि यह अतिरिक्त बोझ उन्हीं वर्गों पर डाला जायेगा, जिन्होंने चीजों की महंगाई से फायदा उठाया है।

भ्रष्टाचार एक व्यापक सामाजिक समस्या

किसी भी लोकतांत्रिक समाज में भ्रष्टाचार का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील और दूरगामी परिणाम वाला विषय होता है। अभी भारत में यह बहस तेज है कि क्या स्कूली बच्चों को न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं, जैसे- भ्रष्टाचार, मुकदमों की लंबित संख्या और न्यायाधीशों की कमी के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए? बेशक यह बहस उचित है कि बच्चों को किस उम्र में किस प्रकार की नागरिक शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार जैसे विषय को केवल पाठ्य-पुस्तकों से हटाकर सार्वजनिक चर्चा से समाप्त नहीं किया जा सकता। हमें यह समझना होगा कि कार्यपालिका और विधायिका जहां राजनीतिक वातावरण में कार्य करती हैं और चुनावी जवाबदेही के अधीन रहती हैं, तो वहीं न्यायपालिका की वैधता उसकी निष्पक्षता, स्वतंत्रता और नैतिक गरिमा पर टिकी होती है। यही कारण है कि यदि न्यायपालिका के किसी भी सदस्य पर अनैतिक आचरण का आरोप लगता है, तो उसका प्रभाव व्यापक और गहरा होता है।

भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने की व्यवस्था महाभियोग के माध्यम से की गई है। यह प्रक्रिया संसद द्वारा पूरी की जाती है और इतिहास में यही देखा गया है कि महाभियोग की कार्यवाही बहुत कम मामलों में शुरू की गई। फिर भी, यह तथ्य गलत नहीं है कि भारत में भ्रष्टाचार एक व्यापक सामाजिक और प्रशासनिक समस्या के रूप में कायम है, जो शासन के सभी अंगों को प्रभावित करती है। यहां यह सवाल भी गलत नहीं कि क्या बच्चों को संस्थागत कमजोरियों से परिचित नहीं कराया जाना चाहिए या उन्हें केवल आदर्श सिद्धांतों तक सीमित रखना चाहिए? यदि बच्चों को संतुलित जानकारी दी जाएगी, जिसमें समस्याओं के साथ सुधार की प्रक्रिया और ईमानदार उदाहरणों का भी उल्लेख हो, तो ऐसी शिक्षा उनमें जागरूकता ही बढ़ाएगी।

लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि वह अपनी कमजोरियों को स्वीकार करे और उनको सुधारने का साहस दिखाए। यदि शैक्षिक सामग्रियों से समस्याओं का उल्लेख हटा भी दिया जाए, तो उससे वास्तविकता नहीं बदल जाएगी, बल्कि जागरूक नागरिक ही भविष्य में सुधार की राह प्रशस्त कर सकते हैं। नागरिक शिक्षा का उद्देश्य प्रचार नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण समझ विकसित करना होना चाहिए। ऐसा किया जाना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि इससे संस्थाओं पर जनता का विश्वास बढ़ता है। लोकतंत्र अपनी कमियों को स्वीकार करने से नहीं, बल्कि तब कमजोर होता है, जब वह अपनी खामियों को छिपाने के प्रयास करता है।

नृपेंद्र अभिषेक नृप, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

भ्रष्टाचार

विवादित विषय बच्चों को क्यों पढ़ाया जाए

स्कूली किताबों में विवादित विषय नहीं होने चाहिए। स्कूल हों या कॉलेज, ये शिक्षा के मंदिर होते हैं, जहां पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ बच्चों को नैतिक ज्ञान दिया जाता है। यहां ज्ञानवर्धक और उच्च आदर्शवादी शिक्षा ही बच्चों को मिलनी चाहिए, ताकि वे एक बेहतर नागरिक बन सकें और अपने जीवन में सही मुकाम हासिल कर सकें। उनसे यह भी अपेक्षा होती है कि वे परिवार, समाज और देश में उच्च आदर्श स्थापित कर सकेंगे। ऐसे में, उनको भ्रष्टाचार जैसा विषय पढ़ाने का भला क्या मतलब है? इससे जीवन की शुरुआत में ही उनमें नकारात्मक भाव पनपने लगेंगे, जिसका गलत असर उनकी मानसिकता पर पड़ेगा। इससे हमारे देश के बहुमूल्य मानव संसाधन को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए, बच्चों की किताबों में कभी विवादास्पद या अनैतिक पाठ शामिल नहीं किए जाने चाहिए। ऐसा करना तब और गलत है, जब हम अगले कुछ वर्षों में खुद को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। स्कूली किताबों में विवादित विषयों को शामिल करने से हम इस बड़े लक्ष्य से भटक सकते हैं। साफ है, विवादित विषयों से बच्चों की दूरी ही समाज के हित में है। कानून को ऐसे मामले में सख्त होना चाहिए, ताकि शिक्षा सदैव आदर्श विद्यार्थियों का निर्माण कर सके।

शकुंतला महेश नेनावा, टिप्पणीकार

एनसीईआरटी की किताब में भ्रष्टाचार से जुड़े एक अध्याय को लेकर उचित कहा गया है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात करके निश्चय ही हम तानाशाही की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं। संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया की प्रतिष्ठा देश में आस्था बढ़ाती है। धीरे-धीरे इनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का सिलसिला शुरू हुआ, जो असल में लंबे समय से चला आ रहा है। आलम यह है कि आज बेईमानी की बात कह-कहकर संसद को महत्वहीन बना दिया गया है। कार्यपालिका और सांविधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने के नाम पर महत्वहीन बना दिया गया है। मीडिया और प्रेस पर कथित दबाव की बात कही जा रही है। सिर्फ न्यायपालिका बची है। वह भी रोज हमले झेलती है। वह भी तब, जब उसे संविधान से संरक्षण मिला हुआ है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात करना न्यायाधीशों के इरादों को संदिग्ध बनाता है। यह उनकी अवमानना है। निस्संदेह, पहले से ही जजों के चयन की प्रक्रिया को सोशल मीडिया के जरिये संदिग्ध दिखाने की कोशिश होती रही है। ऐसे में, न्यायपालिका को भ्रष्ट बताकर या उसे संदिग्ध दिखाकर हम अपने बच्चों की नजर में संविधान को कमजोर दिखा रहे हैं। यह घातक है।

गिरिजेश वशिष्ठ, टिप्पणीकार

इंजेक्शन से मोटापे का कैसा इलाज?

एक दशक पहले तक मोटापा घटाने का मतलब था, कड़ी मेहनत और डाइटिंग। दवाओं के बाद अब विज्ञान ने एक और अहम हथियार दे दिया है– मोटापा घटाने का इंजेक्शन। भारत सहित दुनियाभर में लॉन्च हो रहे मोटापा रोधी इंजेक्शन ने वजन घटाने की जंग को नया मोड़ दे दिया है। मोटापा कम करने के लिए दवा और इंजेक्शन चुनने से पहले किन बातों को जानना जरूरी है, बता रही हैं अवंतिका सिंह

30

बीएमआई से अधिक होने पर या ऐसे लोग, जिनका बीएमआई 27 से अधिक है और उनमें मधुमेह, बीपी, लिवर आदि गंभीर रोगों के होने का खतरा हो, उन्हें मोटापा घटाने वाली दवाएं और इंजेक्शन लेने की सलाह दी जाती है।

बीते दस वर्षों में मोटापे को लेकर दो बातें दुनिया ने स्वीकार कर लीं। पहली- यह कि मोटापा अब महामारी बन चुका है और दूसरी- यह केवल आलस का कड़वा फल नहीं, किसी रोग का नतीजा भी हो सकता है। यहीं से निकला इसके इलाज का विचार और सामने आई दवाएं।

कसरत और डायटिंग को अलग रख दें, तो बेरिएट्रिक सर्जरी, लिपोसेक्शन, नॉन-सर्जिकल कूल-स्कल्प्टिंग और एंडोस्कोपिक प्रोसीजर जैसे तरीके भी आजमाए जाते हैं, मगर मोटापे को कम करने वाले इंजेक्शन फिलहाल किसी क्रांति से कम नहीं नजर आ रहे। कोई मेहनत नहीं, बस पैसे पकड़ाओ और फिगर ले जाओ।

कैसे काम करतीं ये दवाएं

सामान्य तौर पर जब आप खाना खाते हैं, तो पेट से दिमाग तक सिग्नल जाने में 20 मिनट लगते हैं। ये इंजेक्शन उस सिग्नल को 'बूस्ट' कर देते हैं। ये दवाएं पेट के खाली होने की प्रक्रिया को धीमा कर देती हैं, जिससे खाना देर तक पेट में रहता है। इसके अलावा ये दवाएं दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर को शांत करती हैं, जिससे आपको खाने में वह खुशी नहीं मिलती, जो पहले मिलती थी, जिससे आप कम खाते हैं। लिपोकट या वीवाईफैट जैसी दवाएं भोजन से फैट को सोखने की शरीर की क्षमता को कम कर देती है। यानी आप जो घी-तेल खाते हैं, वह जमा होने के बजाय बाहर निकल जाता है।

दवा और इंजेक्शन दोनों के विकल्प

मोटापे से लड़ने के लिए कुछ दवाएं भारत में पहले से उपलब्ध हैं। हाल ही में भारत में उन दवाओं को बेचने की भी मंजूरी दे दी गई है, जो दुनिया में काफी लोकप्रिय हो चुकी हैं। ये इंजेक्शन के रूप में हैं। ये इंजेक्शन 'प्री-फिल्ड पेन' के रूप में आते हैं, जिन्हें मरीज खुद लगा सकता है। इनकी कीमत नौ हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक है।

1. **वेगोवी :** इस इंजेक्शन को विशेष रूप से गंभीर मोटापे की स्थिति में दिए जाने के लिए मंजूरी दी गई है। इस दवा को भारत में आधिकारिक लॉन्च के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। यह उन लोगों के लिए है, जिनका बीएमआई 30 से अधिक है या 27 से अधिक है और उन्हें बीपी, डायबिटीज, लिवर आदि गंभीर समस्याओं का खतरा भी है। इसे हफ्ते में एक बार लिया जाता है।
2. **मौनजारो :** अमेरिकी कंपनी एली लिली के इस इंजेक्शन को भारत में डायबिटीज के साथ-साथ मोटापे के इलाज के लिए भी मंजूरी मिल गई है। यह दो हार्मोन (जीएलपी-1 और जीआईपी) पर काम करती है। इसे बिना डॉक्टरी पर्चे के नहीं लिया जा सकता। सप्ताह में एक बार लिया जाता है।
3. **रिबेल्सस :** यह दुनिया की पहली सेमाग्लूटाइड टैबलेट है। इसे भारत में पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन हाल ही में इसके ज्यादा क्षमता वाली टैबलेट को वजन घटाने के प्रभावी विकल्प के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। यह गोली हर रोज एक दिन ली जाती है।

इन सभी को शेड्यूल-एच ड्रग्स की श्रेणी में रखा गया है, यानी इन्हें बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं खरीदा जा सकता।

सर्जरी और आधुनिक प्रक्रियाएं

बेरिएट्रिक सर्जरी : हाल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के सर्जरी विभाग के अडिशनल प्रोफेसर डॉ. मंजूनाथ ने मेटाबॉलिक सर्जरी की सफलता के बारे में बताया। रिपोर्ट के मुताबिक, जिन लोगों की शुगर दवाओं से भी काबू नहीं हो रही थीं, ऐसे 35 लोगों की सर्जरी की गई। नतीजे बेहद उत्साहजनक रहे। लोगों का शुगर लेवल जल्दी ही काबू में आ गया। मेटाबॉलिक या बेरिएट्रिक सर्जरी में इंसान के बीएमआई और शारीरिक बनावट को ध्यान में रखते हुए पेट का आकार छोटा कर दिया जाता है। मोटापा कम करने के लिए यह सर्जरी की जाती है।

गैस्ट्रिक बैलून और कूल-स्कल्प्टिंग : ये तकनीक भी मोटापे से लड़ने में मदद करती हैं। गैस्ट्रिक बैलून में बिना चीरे के एंडोस्कोपी के जरिये पेट में एक सिलिकॉन बैलून डाल दिया जाता है, जो पेट की जगह घेर लेता है और आप कम खाते हैं। छह महीने बाद इसे निकाल दिया जाता है। यदि आप पूरी तरह फिट हैं, पर केवल पेट या जांघों की जिद्दी चर्बी हटाना चाहते हैं, तो कूल-स्कल्प्टिंग तकनीक अपनाई जाती है। यह फ्रीजिंग तकनीक बिना सर्जरी के उस वसा खत्म कर देती है।

इनके अलावा लिपोसक्शन काफी पुरानी तकनीक है, जो आज भी कुछ मामलों में इस्तेमाल की जाती है।

सेहत से जुड़े खतरे भी समझें

पोषण में कमी: ये दवाएं शरीर में भूख कम करने वाले हार्मोन की नकल करती हैं, जिससे व्यक्ति का खान-पान अचानक 40% तक कम हो जाता है। भोजन की मात्रा में इस भारी कमी के कारण शरीर को जरूरी विटामिन, खनिज और प्रोटीन नहीं मिल पाते।

मांसपेशियों और हड्डियों पर वार : लंबे समय तक इन दवाओं के सेवन से वसा ही कम नहीं होती, बल्कि मांसपेशियों और हड्डियों की कमजोरी भी बढ़ सकती है।

कमजोर इम्यूनिटी और एनीमिया : डाइट में आयरन और विटामिन की कमी से शरीर में खून की कमी और रोगों से लड़ने की क्षमता (इम्यूनिटी) घटने लगती है।

चौंकाने वाले आंकड़े: एक बड़े अध्ययन के अनुसार, इन दवाओं का सेवन करने वाले 22% लोगों में एक साल के भीतर किसी न किसी पोषक तत्व की गंभीर कमी पाई गई। इतना ही नहीं विभिन्न अध्ययन में यह भी पाया गया कि ऐसे लोगों के आहार में फाइबर, आयरन, कैल्शियम और विटामिन ए, सी, डी, ई की मात्रा निर्धारित मानकों से बहुत नीचे थी।

वजन घटाने के खतरनाक रास्ते

वजन घटाने के लिए कई ऐसे उत्पाद भी बाजार में हैं, जिनको बेचने या इस्तेमाल करने की मंजूरी सरकार ने नहीं दी है। ज्यादातर इनका इस्तेमाल जिम जाने वाले युवा कर रहे हैं। ब्लैक मार्केट में स्टेरॉइड के ऐसे इंजेक्शन उपलब्ध हैं, जो शरीर के भीतरी कोनों में छिपे फैट को जला देते हैं। ये इतना तेज होता है कि एक सेकेंड के भीतर आमतौर पर खांसी जैसा अहसास होता है। ये सभी दवां चोरी-छिपे बेचीं और खरीदी जाती हैं। ये दवाएं बेहद खतरनाक होती हैं।

अपनी जरूरत को समझना जरूरी

मोटापा कम करने के लिए कई सप्लीमेंट लंबे अर्से से बाजार में हैं। यह टेबलेट, कैप्सूल और शेक की शक्ल में उपलब्ध हैं। कुछ कंपनियां पूरा एक कोर्स उपलब्ध कराती हैं। इसमें आपको वही प्रोडक्ट खाना होता है, जो आपको दिया जाता है। आमतौर पर इस तरह के पैकेट में मल्टीविटामिन, शेक बनाने का पहले से तैयार पाउडर, पेट साफ करने का पाउडर व प्रोटीन पाउडर वगैरह दिया जाता है। इनके अलावा एल कार्निटाइन और सीएलए जैसे प्रोडक्ट को भी फैट बर्नर के तौर पर प्रचारित किया जाता। इन्हें विशेषज्ञों की देखरेख और अपनी जरूरत समझे बिना लेना नुकसान पहुंचा सकता है।

इंजेक्शन लें या नहीं

जब आप कसरत या सही खानपान के जरिये कुदरती तरीके से वजन कम करते हैं, तो शरीर में अलग ही मजबूती आती है। कसरत से फैट कम होता है और मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। अगर आप अच्छा खाते हैं, तो मांसपेशियां बढ़ती हैं और वसा कम होती है। इस तरह एक मजबूत और आकर्षक काया पा सकते हैं। दवाओं की मदद से जब फैट कम होता है और शरीर में कसावट की कमी उभर सकती है। कई बार कमजोरी भी महसूस होने लगती है।

आपको इंजेक्शन लेना चाहिए या नहीं, इस सवाल का जवाब आप एआई से न पूछें। अगर आपका वजन एक बीमारी की शक्ल ले चुका है, तो इस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन फैसला डॉक्टर के परामर्श के बाद ही लें। कई बार इंजेक्शन लेने पर भी आराम नहीं होता, ऐसे में मोटापे से जुड़े जेनेटिक कारणों को समझना भी जरूरी है।

विशेषज्ञ की राय

दवा प्रभावी, पर सावधानी जरूरी

भारतीयों में जेनेटिक रूप से ज्यादा विसरल फैट होने से ये दवाएं बेहतर मेटाबॉलिक सुधार दिखा सकती हैं। दवा या इंजेक्शन के इस्तेमाल से पहले कुछ जांचें जरूरी होती हैं, जिससे पता चलता है कि क्या शरीर इन दवाओं के लिए तैयार है। शरीर और दवा का तालमेल जरूरी है। इस तरह की दवा बिना सलाह न लें।

प्रो. ज्ञानेश्वर चौबे, जीन प्रोफेसर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी

किसी होड़ में फैसला न लें

नियमित व्यायाम, सही आहार और दिनचर्या पर भरोसा रखें। मोटापे की महामारी से बचाव का तरीका सतर्कता है। मोटापा कम करने की दवा, सर्जरी या इंजेक्शन से फौरी राहत तो मिल जाती है, लेकिन कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ध्यान न देने पर समस्या दोबारा भी हो सकती है।

डॉ. आशुतोष दुबे, फिजिशियन, सिविल हॉस्पिटल, लखनऊ

सवाल-जवाब

गठिया में घरेलू नुस्खों पर निर्भर न रहें

डॉ. पी. डी. रथ
वरिष्ठ कंसल्टेंट-रूमेटोलॉजी (आर्थराइटिस-रुमेटिज्म एंड पेन क्लीनिक)

■ **सवाल : क्या गठिया सिर्फ बुजुर्गों का रोग है?**

जवाब: नहीं। गठिया एक व्यापक शब्द है, जिसमें जोड़ों के दर्द और सूजन से जुड़ी समस्याएं शामिल होती हैं। गठिया की दो श्रेणी है-

सामान्य गठिया : जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, यह ज्यादातर घुटनों को प्रभावित करता है। बड़ी उम्र में यह समस्या अधिक होती है। इससे घुटनों में दर्द व उनके गति करने में परेशानी होती है। आमतौर पर इसका असर जोड़ों तक सीमित होता है।

गंभीर गठिया : जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस (आरए), स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, ल्यूपस, गाउट आदि। यह गठिया किसी उम्र में हो सकता है। शरीर के छोटे-बड़े कई जोड़ एक साथ प्रभावित हो सकते हैं। गंभीर मामलों में फेफड़े, किडनी, आंखें और दिमाग पर भी असर हो सकता है।

■ **सवाल : रूमेटॉइड आर्थराइटिस (आरए) के बारे में बताएं? क्या हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाना सही है?**

जवाब : आरए एक ऑटोइम्यून डिजीज है। 30 से 40 वर्ष की महिलाओं को यह अधिक होता है। इसमें हाथ व पैर के छोटे जोड़ ज्यादा प्रभावित होते हैं। समय पर ध्यान न देने पर दर्द दूसरे जोड़ तक बढ़ने लगता है। सुबह उठते ही दर्द और अकड़न अधिक होती है। धीरे-धीरे, मूवमेंट बढ़ने पर दर्द कम हो जाता है। आरए का उपचार हड्डी रोग विशेषज्ञ से नहीं, रूमेटोलॉजिस्ट से कराना चाहिए। इसकी पहचान के लिए मरीज की पारिवारिक जानकारी, लक्षण व कुछ विशेष खून की जांच करते हैं। हर मरीज में लक्षण अलग हो सकते हैं।

■ **सवाल : गठिया का कोई कारगर इलाज नहीं है?**

जवाब: इन दिनों गठिया का इलाज आधुनिक विशिष्ट दवाओं से किया जाता है। समय पर सही उपचार से मरीज की जिंदगी बदल सकती है। एक बार अगर अंगों में विकृति आ जाए, तो उसे ठीक करना मुश्किल होता है। कुछ लोग खुद से दर्द की गोली लेते रहते हैं या घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहते हैं। ऐसा न करें। दर्द निवारक दवाएं बीमारी जड़ से ठीक नहीं करतीं।

■ **सवाल: दवाओं के साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्या आराम आने के बाद खुद से दवा बंद कर दी जाए?**

जवाब : डॉक्टर की निगरानी में ली गई दवाएं सुरक्षित होती हैं। विशेषज्ञ दवाओं के असर को ध्यान में रखकर ही उनकी मात्रा और अवधि तय करते हैं। बिना सलाह दवाएं न बंद करें, न ही उससे अधिक अवधि तक स्वयं लेते रहें।

■ **सवाल : क्या गठिया केवल डाइट से ठीक किया जा सकता है।**

जवाब : गठिया केवल खानपान बदलकर ठीक नहीं किया जा सकता। यह सही है कि स्वस्थ जीवनशैली, संतुलित आहार और व्यायाम उपचार का जरूरी हिस्सा हैं। ताजे फल, सब्जियां व ओमेगा-3 युक्त फैटी एसिड वाली चीजें जैसे मछली व अलसी आदि लाभ पहुंचाते हैं। इसी तरह साइकिल चलाना, तैराकी, पैदल चलना आदि लाभकारी आसन हैं, पर इसके साथ दवा भी जरूरी है।

■ **वैकल्पिक चिकित्सा से कितना आराम मिलता है?**

जवाब : जहां तक वैकल्पिक चिकित्सा की बात है, उनसे गठिया में बहुत राहत नहीं मिलती। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर या ताईची जैसे व्यायाम से दर्द में कुछ राहत मिल सकती है। पर आधुनिक उपचार की सुविधाओं में ज्यादा बेहतर उपचार मौजूद हैं।

भेजें अपने सवाल

सेहत से जुड़े सवाल **tanmanhindustan@gmail.com** पर मेल करें। आप इस पते पर भी सवाल भेज सकते हैं–

तन-मन, हिन्दुस्तान, 11वां तल, द आइकॉन टॉवर, एफ सी-24 सी, फिल्म सिटी, सेक्टर-16ए, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301

खसरे के खतरे से बच्चों को बचाएं

बदलते मौसम में खसरे के मामले बढ़ने लगते हैं। खसरा तेजी से फैलता है और अनदेखी करने पर पेट और दिमाग पर बुरा असर डाल सकता है। कैसे बच्चों को बचाएं, जानें पूजा प्रसाद से

कुछ और जरूरी तथ्य...

- खसरा किसी भी उम्र में हो सकता है, यह 3 महीने के शिशु को भी हो सकता है।
- गर्भवती महिलाओं को भी खसरा हो सकता है। ऐसे में मां से गर्भस्थ बच्चे को होने की भी आशंका हो सकती है।

खसरा एक ऐसा रोग है, जो कोविड-19, फ्लू, पोलियो व इबोला जैसी संक्रामक बीमारियों से भी अधिक तेजी से फैलता है। सरकार देश भर में सालों से नियमित टीकाकरण अभियान चला रही है, बावजूद कई बार इसके मामले सामने आ जाते हैं।

टीकाकरण ही खसरे की रोकथाम करता है, लेकिन कोविड के दौरान यह अभियान धीमा पड़ा और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले बच्चों में खसरे के मामले बढ़े। हालांकि, 2023 की तुलना में इसके मामले कम हैं। कई लोग गलत धारणाओं की वजह से वैक्सीन नहीं लेते।

बदलता मौसम भी एक वजह

बदलते मौसम में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम और संक्रमणों के फैलने की गति अधिक होती है। यह एक संक्रामक रोग है, खांसी या छींक के दौरान निकलने वाले कण (ड्रॉपलेट) से हवा के जरिये या सीधे प्रभावित व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है।

कैसे करें बच्चों का बचाव

- समय से संपूर्ण टीकाकरण सबसे पहला और मजबूत उपाय है। सरकार के टीकाकरण अभियान के तहत एमआर (मीजल्स और रुबेला) की वैकसीन की पहली खुराक 9 से 12 महीने और दूसरी खुराक 16 से 24 माह की आयु में बच्चे को दी जाती है। यदि पहले टीका नहीं लगा है, तो अब इसे लगवा लें। प्राइवेट हॉस्पिटल एमआर की जगह एमएमआर (मीजल्स, रुबेला और मम्प्स) की डोज देते हैं। यह गलत धारणा है कि खसरे के टीके से ऑटिज्म होता है।
- बच्चों को भीड़ वाली जगहों में सावधानी बरतने के लिए कहें। पीड़ित बच्चे को कम से कम बाहर निकलने दें। खांसी-जुकाम के लक्षण होने पर मास्क लगाएं।
- विटामिन-ए की कमी न होने दें। इसके लिए लाल व पीले रंग के फल-सब्जियां खिलाएं।

अनदेखी न करें लक्षणों की

खसरा खांसी-जुकाम से फैलता है, मगर पीड़ित को पहले बुखार आता है। कान के पीछे या मुंह पर लाल दाने हो जाते हैं, जो बाद में अन्य हिस्सों में फैलने लगते हैं। इसके अलावा खूब नाक बहना, जीभ पर सफेद दाने, इसके मुख्य लक्षण हैं। अनदेखी करने पर इसका असर दिमागी बुखार, निमोनिया, पेट खराब के तौर पर भी दिख सकता है। कई बार ठीक होने के बाद भी इसके दाने निशान नहीं छोड़ते।

उपचार पर ध्यान दें

- यह वायरस से फैलने वाला रोग है, इसलिए लक्षणों को काबू करने की दवा दी जाती है।
- बच्चों में ऊर्जा बनाए रखने के लिए उन्हें संतुलित भोजन दें। मसालेदार चीजें व तली-भुनी चीजों के सेवन से बचाएं।
- विटामिन ए की पूर्ति जरूरी है। डॉक्टर से पूछ कर इसके सप्लीमेंट्स बच्चों को दें।
- अपनी व अपने आसपास की साफ-सफाई की आदतों का ध्यान रखें।
- घरेलू इलाज के भरोसे न रहें। डॉक्टर को जरूर दिखाएं।

हमारे विशेषज्ञ : डॉ. निखिल चतुर्वेदी, बाल रोग विशेषज्ञ।
डॉ. संजय वजीर, प्रमुख, नियोनेटोलॉजी और पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, मदरहुड हॉस्पिटल

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : मन अशांत रहेगा। संयत रहें। बेकार के क्रोध से बचें। बातचीत में भी संतुलित रहें। कारोबार में वृद्धि होगी। कारोबार के लिए यात्रा लाभप्रद रहेगी।

वृष : वाणी में मधुरता रहेगी। धैर्यशीलता भी बनाए रखें। परिवार का साथ मिलेगा। नौकरी के लिए साक्षात्कारादि कार्यों में सफलता मिलेगी।

मिथुन : मन प्रसन्न रहेगा। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय में भी वृद्धि होगी।

कर्क : मन परेशान हो सकता है। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें। कारोबार में बदलाव हो सकता है।

सिंह : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन में उतार-चढ़ाव भी हो सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। आय में वृद्धि होगी।

कन्या : मन परेशान हो सकता है। कारोबार में बदलाव के योग बन रहे हैं। परिवार का साथ मिलेगा। भागदौड़ अधिक रहेगी। खर्चों की अधिकता भी रहेगी।

तुला : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में वृद्धि हो सकती है। लाभ के अवसर मिलेंगे। यात्रा लाभप्रद रहेगी।

वृश्चिक : परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। परिवार में सुख-शांति रहेगी। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में वृद्धि हो सकती है। भागदौड़ अधिक रहेगी।

धनु : मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास बना रहेगा। पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। लेखनादि बौद्धिक कार्यों से मान-सम्मान बढ़ेगा। परिवार में सुख-शांति रहेगी।

मकर : मन अशांत रहेगा। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव के साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है। खर्चों में वृद्धि होगी।

कुंभ : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। परिवार में सुख-शांति रहेगी।

मीन : मन परेशान हो सकता है। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। पिता का साथ मिलेगा। कारोबार में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं। किसी दूसरे स्थान पर जाने का योग है।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋषिकांत गोस्वामी

27 फरवरी, शुक्रवार, **शक संवत्** : 08 फाल्गुन (सौर) 1947, **पंजाब पंचांग** : 16 फाल्गुन मास प्रविष्टे 2082, **इस्लाम** : 09 रमजान, 1447, **विक्रमी संवत्** : फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि रात्रि 10.33 बजे तक, वणिज करण चंद्रमा मिथुन राशि में रात्रि 03.53 बजे तक उपरांत कर्क राशि में। **सूर्य उत्तरायण।** सूर्य दक्षिण गोल। सूर्य दक्षिण गोल। शिशिर ऋतु। प्रात: 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। भद्रा प्रात: 11.34 बजे से रात्रि 10.33 बजे तक। आमलकी एकादशी व्रत। रंगभरी एकादशी।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

कृपया यह बताएं कि हम कैसे पता करें कि हमारा उत्तर पश्चिम में वास्तु दोष है।
निर्दोष दोषी, नोएडा

- यदि मां से संबंध खराब हो रहे हों, तो यह इस दिशा में दोष की निशानी है।
- यदि व्यक्ति खुद को फंसा महसूस कर रहा हो, ये समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करे।
- यदि व्यक्ति अपने पुराने दिनों को बार-बार याद करता रहता है।
- यदि महिला को मासिक धर्म में अनियमितता होती है, तो इस दिशा में दोष की स्थिति है।
- यदि समय पूर्व बाल सफेद हो रहे हैं, तो इसका एक कारण इस दिशा का दोष हो सकता है।
- यदि बायीं आंख या बाएं अंग में कोई समस्या या दर्द है, तो यह भी एक कारण हो सकता है।

वर्ग पहेली : 8253

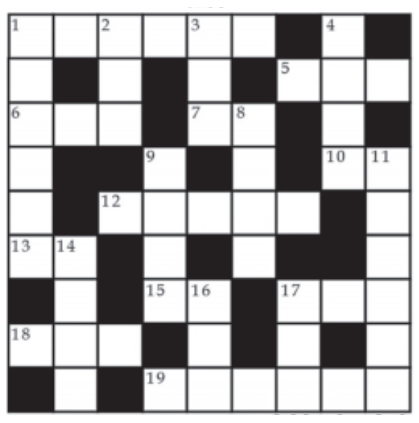

बाएं से दाएं
1. अप्रचलित; अरूढ़िगत; नया; नवीन; (6)
5. दिलेर; भयहीन; निर्भीक; साहसिक (3)
6. चरने के लिए ले जाना; घुमाना; फिराना; धोखा देना; छलना; बहकाना (3)
7. शब्द; ध्वनि; आवाज; उच्चारण (2)
10. नाक में डालने वाली औषधि; सुंघनी (2)
12. किसी के नाम से उसका माल बिकना; किसी के नाम से उसकी इज्जत होना (2,3)
13. कोना; चैक; मुहाना; सूई का छिद्र (2)
15. पोली लंबी गोल वस्तु; कमल की डंडी; धातु की नली; पानी की टोंटी (2)
17. आचरण; झक; झोंक; दीवानगी (3)
18. रोब; दाबने का कार्य; बोझ (3)
19. गला रुंध जाना; भावुक हो जाना (2,2,2)

ऊपर से नीचे
1. विस्मित होना; हैरान होना; चकित होना (2,4)
2. रंग चढ़ाना; रंग लगाना; रंग में डुबाना; प्रेम में फंसाना; आसक्त होना (3)
3. छनकर निकलना; छिद्र से धीरे-धीरे टपकना (3)
4. चित्त खुश करना; बहकाना; भुलावा देना (4)
8. चमकना; चमचमाना (4)
9. जन सामान्य; आम आदमी (2,2)
11. आदर करना; इज्जत करना; मान देना (3,3)
14. कामकाज; व्यापार; पेशा (4)
16. जिसमें लचक हो; लचकदार (3)
17. झोंका; बयार; बहती हवा; वायु; पवन (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8252

सुडोकू : 8235 *कठिन

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3×3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8234

4	7	2	5	9	1	3	6	8
8	9	5	7	3	6	2	4	1
6	3	1	2	4	8	5	9	7
5	4	3	8	2	9	7	1	6
2	8	9	6	1	7	4	3	5
1	6	7	4	5	3	8	2	9
7	1	6	3	8	4	9	5	2
3	2	8	9	6	5	1	7	4
9	5	4	1	7	2	6	8	3

संपादकीय जागरण

शुक्रवार, 27 फरवरी, 2026: फाल्गुन शुक्ल - 11 वि. 2082

गलती दोहराने का यही अर्थ है कि अतीत से कुछ सीखा नहीं

कनाडा की भूल सुधार

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के पहले वहां की सरकार ने जिस तरह यह कहा कि उनके देश में होने वाले अपराधों का भारत से कोई संबंध नहीं, वह केवल भूल सुधार ही नहीं, बल्कि इसका प्रमाण है कि जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली पिछली सरकार किस तरह अपने संकीर्ण राजनीतिक कारणों से भारत विरोधी एजेंडे पर चल रही थी। जस्टिन ने भारत से भागे और अवैध तरीके से कनाडा में प्रवेश करने वाले खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराते हुए ऐसे बेतुके बयान दिए थे कि इस हत्याकांड में भारत का हाथ होने के पुख्ता आरोप सामने आए हैं। प्रमाण के बजाय आरोप की हास्यास्पद बात करके उन्होंने अपनी जगहंसाई तो कराई ही थी, यह भी सिद्ध किया था कि वे खालिस्तान समर्थक नेता जगमीत सिंह के इशारे पर भारत से संबंध खराब करने पर तुल गए थे। यह ठीक है कि उनकी अल्पमत सरकार जगमीत की पार्टी के समर्थन की मोहताज थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे उसके दबाव-प्रभाव में भारत से संबंध बिगाड़ने की हद तक चले जाते। आम तौर पर अल्पमत सरकारें घरेलू मामलों में समर्थक दलों के दबाव में आती हैं, लेकिन ट्रूडो सरकार तो विदेश नीति पर जगमीत की पार्टी के समक्ष नतमस्तक हो गई।

समस्या केवल इतनी ही नहीं थी कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान समर्थक नेताओं के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे, बल्कि यह भी थी कि वे भारत विरोधी तत्वों की पीठ पर हाथ रखे हुए थे। इसका दुष्परिणाम यह था कि कनाडा में सक्रिय खालिस्तान समर्थक अतिवादी आए दिन भारत के खिलाफ उग्र-हिंसक प्रदर्शन करते थे। वे भारत के साथ-साथ भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को भी धमकाते थे, पर जस्टिन मौन साधे रहते थे। इस कारण भारत को भी उनके खिलाफ कठोर रवैया अपनाना पड़ा। यह अच्छा हुआ कि उनकी जगह प्रधानमंत्री बने मार्क कार्नी पहले दिन से भारत से संबंध सुधार के प्रयास कर रहे हैं, पर भारतीय नेतृत्व केवल इतने से संतुष्ट नहीं हो सकता कि नई सरकार पिछली सरकार की गलतियां ठीक कर रही है। भारत को यह देखना होगा कि कनाडा में भारत के खिलाफ सुनियोजित दुष्प्रचार करते रहने वाले खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ कोई ठोस कानूनी कार्रवाई होती है या नहीं? भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक चरमपंथी अभी भी भारतीय हितों के लिए खतरा बने हुए हैं। भारत यह भी नहीं भूल सकता कि तीन सौ से अधिक यात्रियों की जान लेने वाले एअर इंडिया के विमान को विस्फोट से उड़ाने वाले खालिस्तान समर्थक आतंकियों को कोई कठोर सजा नहीं दी जा सकी है और वहां जब-तब उनका महिमामंडन भी होता रहता है। संबंधों में वास्तविक सुधार के लिए यह सब बंद होना चाहिए।

चिंता की बात

दक्षिणी दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कालोनी के एक घर में ईडी अधिकारी बनकर छापेमारी के नाम पर लूटपाट करने के मामले में पुलिस ने घरेलू सहायिका समेत दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। घर के मालिक ने घरेलू सहायिका का पुलिस सत्यापन नहीं करवाया था। गनीमत रही कि पुलिस सीसीटीवी जांच करते हुए आरोपितों तक पहुंच गई, अन्यथा मामले का पर्दाफाश होना भी आसान नहीं था। आरोपित दोनों महिलाओं ने तीन अन्य के साथ मिलकर विगत 13 फरवरी को इस वारदात को अंजाम दिया था।

पुलिस सत्यापन को लेकर मकान मालिकों की उदासीनता चिंताजनक है, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए

दिल्ली में घरेलू सहायकों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्यरत सहायकों व किरायेदारों का पुलिस सत्यापन न कराया जाना किस हद तक नुकसानदायक है, ये घटना इसका उदाहरण है। यह गनीमत थी कि आरोपितों के पास हथियार नहीं थे, अन्यथा वृद्ध दंपती की जान को भी खतरा हो सकता था। पुलिस सत्यापन कराने के बाद घरेलू सहायकों में इस बात का डर होता है कि उनका विवरण पुलिस के पास है और घर में कोई भी अपराध करने पर उन्हें फौरन पकड़ लिया जाएगा। ऐसे में उनके द्वारा अपराध होने की आशंका कम हो जाती है। इसके बावजूद पुलिस सत्यापन को लेकर मकान मालिकों की उदासीनता चिंताजनक है।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या एनसीईआरटी की पुस्तक में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' विषय से जुड़े अध्याय पर सुप्रीम कोर्ट का विरोध उचित है?

आज का सवाल

क्या प्रधानमंत्री की इजरायल यात्रा पर कांग्रेस की आपत्ति उचित है?

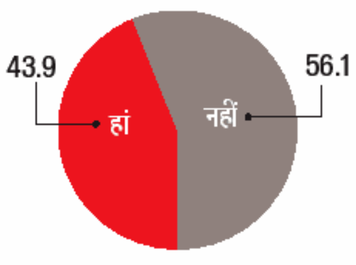

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

गठबंधन को लेकर बेपरवाह कांग्रेस

राज कुमार सिंह

चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, पर गठबंधन के तौर पर आइएनडीआइए में सक्रियता तो दूर, कोई सुगबुगाहट भी नहीं

शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र 'सामना' के संपादकीय, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर की टिप्पणियों से विपक्षी दलों के मोर्चे आइएनडीआइए की दरारें उजागर हुई ही थीं कि एआइ सम्मेलन में युवा कांग्रेस के अर्धनग्न प्रदर्शन से कांग्रेस की दिशाहीनता भी बेनकाब हो गई। लगता नहीं कि कांग्रेस को देश या विपक्षी एकता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का कोई अहसास है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की लगातार तीसरी निराशाजनक हार के बावजूद अन्य विपक्षी दलों ने राहुल को नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्वीकार कर उदारता ही दिखाई, लेकिन कांग्रेस ने कभी अन्य दलों को संसद के अंदर या बाहर साथ लेकर चलने की परिपक्वता नहीं दिखाई। राहुल गांधी अपेक्षा करते हैं कि वे जो भी रणनीति तय कर लें, संसद के अंदर-बाहर अन्य दलों को उनका श्रद्धापूर्वक अनुसरण करना चाहिए।

भाजपा को हराने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से लगभग एक साल पहले दो दर्जन विपक्षी दलों को जोड़कर आइएनडीआइए बनाया गया था। दो बार पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद भाजपा का 240 सीटों पर ठहरने को इस मोर्चे की एक सफलता के रूप में देखा गया, लेकिन लोकसभा चुनाव बाद गठबंधन के पक्ष में कुछ खास घटित होता नहीं दिख रहा। उनके बीच लगातार उजागर दरारें बताती हैं कि दलों में दोस्ती के बावजूद दिलों में दूरियां बरकरार हैं।

सफलताओं की बात करें तो झारखंड और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जीत तो हासिल हुई, लेकिन वहां कांग्रेस हाशिए पर ही है। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार में उसके हिस्से हार ही आई। इसमें महाराष्ट्र और बिहार की हार को शर्मनाक कहना कहीं अधिक उचित होगा। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में तो गठबंधन की गांठें पूरी तरह बिखरती दिखीं।

इस साल चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, पर गठबंधन के तौर पर आइएनडीआइए में सक्रियता तो दूर, कहीं कोई सुगबुगाहट भी नहीं। एसआइआर पर तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ही चुनाव आयोग से दो-दो हाथ करती नजर आती हैं। तमिलनाडु में भी चुनाव आयोग से लेकर भाजपा तक के विरुद्ध मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनकी पार्टी द्रमुक ही मोर्चा खोले है। बंगाल में ममता एकला चलो की राह पर हैं। पिछली बार वाम मोर्चा के साथ गठबंधन करने वाली कांग्रेस इस बार अकेले चुनावी जोर आजमाइश के मूड में है। केरल में तो मुख्य चुनावी

अवधेश राजपूत

मुकाबला सत्तारूढ़ वाम मोर्चा और कांग्रेसनीत यूडीएफ के बीच ही होता है। इसलिए राज्य की राजनीति में तो परस्पर समन्वय की गुंजाइश नहीं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक ही गठबंधन के सदस्य होने के नाते तमाम राजनीतिक मुद्दों पर तो आइएनडीआइए को एक सुर में बोलना चाहिए। तमिलनाडु में द्रमुक और कांग्रेस के बीच पुराना गठबंधन है, लेकिन वहां भी दरारें इस हद तक हैं कि मणिक्कम टैगोर और प्रवीण चक्रवर्ती सरीखे कांग्रेस के दूसरी पंक्ति के नेता द्रमुक पर निशाना साध रहे। नतीजतन द्रमुक को उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग करनी पड़ी। तमाम अटकलों के बाद अब द्रमुक-कांग्रेस में सीट बंटवारे पर बातचीत जारी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो 2027 में होने हैं, लेकिन वहां जारी एसआइआर को लेकर कांग्रेस की अनुपस्थिति उसके समाजवादी पार्टी से रिश्तों में खिंचाव का भी संकेत है।

'सामना' के संपादकीय 'अंदर की आवाजों का कन्फ्यूजन' में कांग्रेस से सवाल पूछा गया है-ममता, स्टालिन या कोई और? संपादकीय में गठबंधन को जागने और कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बातचीत करने की नसीहत देते हुए मणिशंकर अय्यर, संजय बारू और भूपेन बोरा आदि की टिप्पणियों को अंदर की आवाजों का कन्फ्यूजन करार दिया गया है। बारू ने आइएनडीआइए का नेतृत्व ममता बनर्जी को देने का सुझाव दिया है तो अरसे तक नेहरू-गांधी परिवार के करीबी समझे गए अय्यर की टिप्पणियां राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल के रूप में देखी जा रही हैं। जिस एकमात्र राज्य केरल में कांग्रेस की जीत की संभावना है, वहां भी अय्यर ने लगातार तीसरी बार वाम मोर्चा की ही जीत की भविष्यवाणी करते हुए मुख्यमंत्री विजयन की प्रशंसा की है। आइएनडीआइए के नेतृत्व के लिए वे स्टालिन को बेहतर मानते हैं। पार्टी से कोई संबंध न होने के आधार पर उनकी टिप्पणी को निजी राय बताकर कांग्रेस ने अय्यर से पल्ला झाड़ना चाहा है, पर राजनीतिक गलियारों से लेकर केरल-तमिलनाडु तक चर्चा थमी नहीं है। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद भले ही शशि थरूर के स्वर बदल गए हों, पर उससे पहले की तल्खियां सबने देखी हैं। असम के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा तो राहुल गांधी से बातचीत के बाद भी इस्तीफा वापस लेने के फैसले से पलट गए और हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा घोषित तारीख पर भाजपा में शामिल भी हो गए। लगभग एक दशक पहले हिमंत ने भी राहुल गांधी की कार्यशैली से खफा होकर कांग्रेस छोड़ी थी। पूर्वोत्तर में भाजपा के विस्तार में अहम भूमिका निभाने के बाद अब वे असम के मुख्यमंत्री और भाजपा आलाकमान के लाड़ले हैं।

दलबदल के बाद अक्सर अवसरवाद, दबाव और प्रलोभन की बातें सुनाई पड़ती हैं। इन्हें पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, पर दलबदल कहीं-न-कहीं नेतृत्व की क्षमता और दल की राजनीतिक संभावनाओं पर अविश्वास का परिणाम भी होते हैं। राहुल गांधी को कम-से-कम अपनी टीम का सदस्य बताए गए युवा नेताओं के कांग्रेस से पलायन पर तो आत्मविश्लेषण करना ही चाहिए और अगर वे पर्याप्त समय नहीं दे सकते तो फिर आइएनडीआइए का नेतृत्व ममता बनर्जी या स्टालिन जैसे किसी पूर्णकालिक क्षेत्रीय नेता को सौंपने की पहल करें। हाल के एआइ इंपैक्ट सम्मेलन में युवा कांग्रेस के अर्धनग्न प्रदर्शन से आइएनडीआइए के अन्य घटक दलों की मुखर असहमति भी कांग्रेस के लिए अपनी दशा और दिशा पर गंभीर पुनर्विचार का संदेश है, लेकिन शायद वह किसी संदेश को सुनने को तैयार नहीं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

लाभकारी बनाएं व्यापार समझौते

जयंतीलाल भंडारी

व्यापार समझौतों का पूरा लाभ तभी मिलेगा, जब देश नई पीढ़ी के सुधारों और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को आगे बढ़ाएगा

निर्यात को गति देंगे नए व्यापार समझौते ● फाइल

पिछले कुछ सालों में भारत मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के जरिये कई देशों से मुक्त व्यापार की राह पर आगे बढ़ा है। इससे भारतीय वस्तुओं के लिए दुनिया के बाजारों में निर्यात पहुंच बढ़ी है। गत दिवस पीएम मोदी ने कहा कि इजरायल के साथ भी भारत का एफटीए जल्दी ही आकार लेते हुए दिखाई देगा और भारत जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अवैध ठहराए जाने के बाद 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए भारत समेत सभी देशों पर 15 प्रतिशत अस्थायी ग्लोबल टैरिफ लागू हो गया है। इस अवधि के बाद अमेरिकी संसद तय करेगी कि इसे आगे बनाए रखना है या नहीं? अभी अमेरिकी प्रशासन के पास टैरिफ लगाने की कई शक्तियां बची हुई हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी संसद से टैरिफ पर प्रस्ताव मंजूर होने के बाद भारत के साथ किया गया व्यापार समझौता अपने पूर्व निर्धारित रूप में ही लागू होगा। ऐसे में जहां आगामी 150 दिन टैरिफ की अस्थायी कमी निर्यात बढ़ाने के लिए हितकर है, वहीं इसके बाद दोनों देशों के बीच अंतरिम व्यापार समझौता अमेरिका को निर्यात बढ़ाने के लिए लाभप्रद होगा।

भारत के लिए अमेरिका एक बड़ा बाजार है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और अमेरिका के बीच 131.84 अरब डालर मूल्य का व्यापार हुआ। इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल से दिसंबर के बीच भारत ने अमेरिका को 65.88 अरब डालर मूल्य का निर्यात किया है। ऐसे में अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौता भारतीय निर्यात बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। अमेरिका द्वारा शुरू किए गए टैरिफ और व्यापार व्यवधानों ने भारत को वैकल्पिक बाजार खोजने और नए व्यापार गठबंधन बनाने की राह पर आगे बढ़ाया है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत ने पिछले वर्ष कई व्यापार समझौते किए हैं और इस वर्ष भी कई नए व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन की तैयारी है। इनमें अत्यधिक महत्वपूर्ण यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ मुक्त व्यापार समझौता भी शामिल है। हाल में एआइ समिट के दौरान ईयू के कई राष्ट्राध्यक्षों ने 27 जनवरी को भारत-ईयू के दौरान किए गए एफटीए को शीघ्र कार्यान्वित किए जाने के लिए समर्थन दिया। यह एफटीए दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का बेजोड़ उदाहरण है। इस समझौते को सभी व्यापार समझौतों की जननी कहा गया है। इस एफटीए से दो अरब लोगों का एक साझा बाजार तैयार होगा, जिसका संयुक्त बाजार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग एक चौथाई हिस्से के बराबर होगा। अनुमान है कि यह एफटीए आगामी छह महीने में कार्यान्वित होते हुए दिखाई देगा।

पिछले वर्ष भारत द्वारा ब्रिटेन, ओमान के साथ किए गए एफटीए इसी अप्रैल से और न्यूजीलैंड के साथ किया गया एफटीए सितंबर से कार्यान्वित होते हुए दिखाई देगा। इन सबके साथ-साथ मारीशस, संयुक्त अरब अमीरात, आस्ट्रेलिया और चार यूरोपीय देशों के समूह यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (एफ्टा) के साथ हुए एफटीए से भी इस वर्ष निर्यात बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस वर्ष पेरू, चिली, आसियान, मेक्सिको, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इजरायल, भारत गल्फ कंट्रीज काउंसिल सहित अन्य प्रमुख देशों के साथ भी नए एफटीए हो सकते हैं। यह निर्यात बढ़ने की संभावनाओं का एक अनुकूल परिदृश्य है, लेकिन ट्रंप प्रशासन के लगातार बदलते रवैये को देखते हुए भारत के लिए उचित यही होगा कि वह अन्य देशों से व्यापार समझौते संबंधी वार्ताओं को गति दे।

वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत से निर्यात बढ़ाना कोई सरल काम नहीं है। भारत को निर्यात की नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। एक फरवरी को वित्त मंत्री की ओर से प्रस्तुत केंद्रीय बजट में विनिर्माण, वस्त्र, चमड़ा और समुद्री भोजन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए निर्यात बढ़ाने के लिए जो कई रणनीतिक उपाय किए गए हैं, उन पर नए वित्तीय वर्ष में शुरुआत से ही ध्यान देना होगा। निर्यात बढ़ाने के लिए हमें उत्पादों की गुणवत्ता और नए सुधारों पर भी ध्यान देना होगा। व्यापार समझौते अभी ऐतिहासिक कागजी दस्तावेज हैं। इनका पूरा लाभ तभी मिलेगा, जब भारत नई पीढ़ी के सुधारों और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को आगे बढ़ाएगा। नए व्यापार समझौतों से भारत दुनिया की बड़ी-बड़ी मंडियों में प्रवेश पाने में सफल तो होगा, लेकिन देश को व्यापारिक महाशक्ति बनाने के लिए आकर्षक दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाला माल तैयार करना होगा। सिस्टमैटिक्स ग्रुप की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत द्वारा व्यापार समझौतों का अधिकतम लाभ लेने के लिए सबसे पहले किफायती लागत पर गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, लाजिस्टिक्स और कस्टम प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे सुधारों पर तेजी से आगे बढ़ना होगा। निर्यातकों की दिक्कतें केवल शुल्क वृद्धि तक सीमित नहीं हैं। वे एंटी-डंपिंग शुल्क से भी संबंधित हैं। घरेलू कच्चे माल की ऊंची लागत और ईंधन की उच्च कीमतों के कारण भी भारत की ओर से निर्यात किए जाने वाले उत्पाद वैश्विक स्तर से करीब 20 प्रतिशत की अधिक लागत पर दिखाई देते हैं। व्यापार समझौतों से देश को आर्थिक शक्ति बनाने के लिए अधिकारियों को नए दौर की जरूरत के मुताबिक शिक्षित-प्रशिक्षित करने के साथ सरकारी और निजी क्षेत्रों में शोध, विकास एवं नवाचार बढ़ाना होगा।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

दीर्घायु होने का मंत्र

भारतीय संस्कृति शतायु अर्थात सौ वर्ष की आयु की संकल्पना को पोषित करती आई है। इसका आशय है कि सक्षम एवं सक्रिय इंद्रियों के साथ हम सौ वर्षों तक जीवित रहें। शतायु होने का कोई एक जादुई उपाय नहीं है। यह संतुलित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि, तनाव मुक्त जीवन, पर्याप्त नींद और व्यसनों से दूरी पर निर्भर है। प्रकृति में जब भी कोई चीज रुक जाती है तो वह सड़ने लगती है। जीवन में भी जिसे हम अक्सर आराम, विराम या विश्राम आदि कहते हैं, वह वास्तव में ठहराव है। हम जितना अधिक स्थिर रहेंगे, जीने की इच्छा उतनी ही कम होगी। जितना अधिक हम बैठे रहेंगे, उतनी ही जल्दी बूढ़े होंगे। हमें लगता है कि हम आराम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम अपने शरीर को जहर दे रहे हैं। हमारा खून धीमा पड़ जाता है, दिल पंप करना भूल जाता है। वजन बढ़ने लगता है, सिर्फ देह पर ही नहीं, बल्कि आत्मा पर भी।

जब हम स्वयं को एक चहारदीवारी में बंद रखते हैं तो हमारा शरीर खुद को ही खाने लगता है। मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं, हड्डियां भंगुर हो जाती हैं और दिमाग सुस्त पड़ जाता है। इस तरह हम निराशा और अवसाद को आमंत्रण दे बैठते हैं। मनोविज्ञान इसे 'मानसिक जुगाली' अर्थात 'छाया में सड़ना' कहता है। तब एक छोटी सी सैर भी हमे पहाड़ जैसी लगने लगती है। इसलिए नहीं कि हम आलसी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम 'जंग' खा चुके हैं।

वस्तुतः, ऊर्जा अनुभूति का भी विषय है और प्रायः इस अनुभूति के लिए अपने दायरे से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। यह वैज्ञानिक रूप से पुष्ट भी है कि ताजी हवा फेफड़ों को साफ करती है। धूप नींद को ठीक करती है। चलना दिल को दुरुस्त करता है। हमें यह मंत्र याद रखना होगा कि गति ही जीवन है, इसलिए स्वस्थ शरीर के लिए पैरों को और मन के लिए विचारों को चलायमान रखिए। यही दीर्घायु होने का मंत्र है।

डा. निर्मल जैन

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

भरोसा बढ़ाने वाला हस्तक्षेप

'लोकतंत्र में भरोसा बढ़ाने वाला निर्णय' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में हरबंश दीक्षित ने मतदाता सूची में शुद्धता की महत्ता को उचित रूप से रेखांकित किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंगाल में मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का निर्देश लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मतदाता सूची की शुद्धता ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला है। यदि सूची में त्रुटियां हों तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। न्यायालय का यह हस्तक्षेप किसी प्रशासनिक कार्य में दखल नहीं, बल्कि संविधानप्रदत्त अधिकारों और नागरिकों के मताधिकार की रक्षा का प्रयास है। इससे यह संदेश जाता है कि लोकतंत्र में संस्थाएं सजग हैं और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह निर्णय नागरिकों के विश्वास को सुदृढ़ करता है तथा लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत बनाता है। ऐसे कदम लोकतंत्र की जड़ों को गहरा करते हैं और संविधान के प्रति आस्था को पुनर्स्थापित करते हैं।

हिमांशु शेखर, केसपा (गया जी)

जलवायु परिवर्तन अब हकीकत

फरवरी का महीना कभी सर्द हवाओं, हल्की धूप और पहाड़ों पर जमी बर्फ के लिए जाना जाता था, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग है। उत्तर से लेकर मध्य भारत तक तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर चल रहा है। कश्मीर घाटी, जिसे बर्फ और ठंड की धरती माना जाता है, वहां अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह फरवरी में असामान्य माना जा रहा है। 24 फरवरी 2016 को 20.6 डिग्री तापमान दर्ज हुआ था, लेकिन इस वर्ष उससे भी अधिक गर्मी ने रिकार्ड तोड़ दिया। श्रीनगर के मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डा. मुख्तार अहमद के अनुसार, इस बार कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं हुआ, जिससे सामान्य शीतकालीन वर्षा और बर्फबारी नहीं हो सकी। यह केवल एक मौसमी उतार-चढ़ाव नहीं, बल्कि वायुमंडलीय असंतुलन का संकेत है। गुलमर्ग और सोनमर्ग में हाल में हुई बर्फबारी लगभग पिघल चुकी है। बर्फ की कमी का असर पर्यटन और खेल गतिविधियों पर साफ दिखाई दे रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को पर्याप्त बर्फ नहीं मिल पा रही। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कृत्रिम बर्फ बनाने की व्यवस्था पर जोर दिया है। यह स्थिति दर्शाती है कि जलवायु परिवर्तन अब केवल वैज्ञानिक रिपोर्टों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जमीनी हकीकत बन चुका है। लेह और आसपास के क्षेत्रों में जनवरी और फरवरी में लगभग बर्फ नहीं गिरी। 17,582 फीट ऊंचे खारदुंग ला और चांग में सामान्य से 70 से 80 प्रतिशत कम बर्फबारी दर्ज की गई। हालांकि 14 हजार फीट पर स्थित पैंगोंग झील जमी हुई है और वहां न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश व राजस्थान में भी तापमान सामान्य से तीन से पांच डिग्री अधिक रहा। श्रीगंगानगर में फरवरी के अंतिम सप्ताह में अधिकतम तापमान 32 डिग्री न्यूनतम तापमान भी 14 डिग्री के आसपास रहा।

कांतिलाल मांडोत, नई दिल्ली

अवैध कब्जे का निस्तारण

संपादकीय आलेख 'अवैध कब्जे का निस्तारण' पढ़ा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर दशकों से जमे कब्जों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने एक बड़े मानवीय और कानूनी विवाद को केंद्र में ला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का कोई निहित कानूनी अधिकार नहीं है और रेलवे विकास परियोजनाओं के विस्तार के लिए यह जमीन खाली करना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, यह एक संवेदनशील मामला है जिसमें लगभग चार से पांच हजार परिवार 50 हजार से अधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं, जो एक बड़ा वोट बैंक है। सालों तक इन कब्जों को अनदेखा करना या उन्हें सरकारी सुविधाएं (बिजली, पानी, आधार) प्रदान करना राजनीतिक संरक्षण को दर्शाता है। अब चूंकि मामला कोर्ट के कड़े निर्देश (अतिक्रमण हटाने का) में है, इसलिए अब कार्रवाई की जा रही है। कानूनी विशेषज्ञों और जनसामान्य का मानना है कि यदि अतिक्रमण शुरुआती दिनों में ही रोक दिया जाता, तो आज 50 हजार लोगों के विस्थापन का "मानवीय संकट" उत्पन्न नहीं होता। कोर्ट ने कहा है कि कब्जाधारी अपनी शर्त पर जमीन पर नहीं बने रह सकते, लेकिन उनके पुनर्वास का इंतजाम राज्य को करना होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि विकास (रेलवे लाइन विस्तार) के लिए जमीन खाली की जाएगी। कोर्ट ने इन विस्थापित परिवारों को मार्च 2026 के अंत तक व्यावहारिक समाधान खोजने को कहा है।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

पोस्ट

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में हमास का उल्लेख किया। बहुत बढ़िया। आतंकवादियों, उनके संगठनों और संचालकों के नाम होते ही हैं और उन्हें बेनकाब करने एवं शर्मसार करने में कोई संकोच नहीं किया जाना चाहिए।

सुनंदा वशिष्ठ@sunandavashisht

दिल्ली के एक जज साहब के यहां से जले नोट बरामद हुए, मगर जज साहब पर केस तक दर्ज नहीं हो पाया। किसी आम व्यक्ति के यहां से उतने ही जले नोट मिले होते तो अंदाजा लगाइए क्या हो गया होता। अब भी लार्ड ने उस किताब को ही बैन कर दिया, जहां इन जैसों के भ्रष्टाचार की बात हो रही थी।

अनुरंजन झा@anuranjanj

पाठ्यपुस्तकों के लेखन से जुड़े लोगों को सामाजिक समूहों, राजनीतिक दलों, नेताओं, न्यायपालिका और डिजिटल मीडिया आदि के माध्यम से निरंतर दबाव में नहीं रखा जा सकता। किसी भी प्रकार की सामग्री को हटाने मात्र से देश की सच्चाई नहीं बदल जाती। बच्चे तो किसी न किसी माध्यम से बातें जान ही लेते हैं।

वसुधा वेणुगोपाल@Vasudha156

जनपथ

नेतनयाहू को मिला 'मोदी हग' का गिफ्ट,
दो देशों की दोस्ती हुई और भी लिफ्ट।
हुई और भी लिफ्ट दोऊ सुख-दुख के साथी,
हम दोनों को देख जले दुश्मन की छाती!
हो जाएंगे साफ सभी मारीच-सुबाहु,
यदि भारत के साथ रहेंगे नेतनयाहू!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन.नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा -201309 से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित
संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 224

अब कहीं से भी कभी भी, चुटकियों में लें रेलवे क्लेम

- रात-दिन कभी भी घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से क्लेम पाने का किया जा सकेगा दावा
- ई-फाइलिंग, डिजिटल रिकार्ड व आटोमेटिक नोटिस सिस्टम से मामलों का तेज होगा निपटारा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : रेल यात्रियों को मुआवजा पाना पहले से ज्यादा आसान होने जा रहा है। रेल हादसे, चोट, मौत या सामान के नुकसान की स्थिति में मुआवजा लेने के लिए रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल (आरसीटी) की बेंच में बार-बार जाने की जरूरत नहीं होगी। ई-आरसीटी सिस्टम के तहत देशभर की सभी 23 आरसीटी बेंच को आनलाइन प्लेटफार्म से जोड़ा जाएगा। यात्री या उनके स्वजन रात-दिन कभी भी घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से क्लेम पाने का दावा कर सकेंगे। जरूरी दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने 52 हफ्ते-52 सुधार अभियान के तहत दो बड़े बदलावों की घोषणा की। पहला आरसीटी की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा। दूसरा रेल टेक पालिसी के जरिये स्टार्टअप और नवाचार करने वालों को सीधे रेलवे से जोड़ा जाएगा।

अब तक लोगों को दिक्कत होती थी क्योंकि घटना किसी एक राज्य में होती थी और यात्री दूसरे राज्य का होता था। ऐसे में यह तय करना मुश्किल हो जाता था कि केस कहां दायर करें। सुनवाई की तारीख जानने, दस्तावेज जमा करने और आदेश की प्रति लेने में समय और पैसा दोनों खर्च होते थे।

रेल भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते अश्विनी वैष्णव ● प्रेट्र

नई डिजिटल व्यवस्था में केस की पूरी जानकारी आनलाइन रहेगी। जरूरत पड़ने पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल होने की सुविधा भी मिलेगी। रेल मंत्री का कहना है कि ई-फाइलिंग, डिजिटल रिकार्ड और आटोमेटिक नोटिस सिस्टम से मामलों का निपटारा तेज होगा। पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। आदेश और फैसले भी आनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे।

शोध संस्थान अपना समाधान कर सकते हैं प्रस्तावित : दूसरा बड़ा सुधार 'रेल टेक पालिसी' है। इसके तहत कोई भी स्टार्टअप, शोध संस्थान या उद्योग रेलवे से जुड़े किसी मुद्दे पर अपना समाधान प्रस्तावित कर सकता है। पहले की नीति में रेलवे स्वयं समस्या तय करता था और उसी पर समाधान मांगे जाते थे। नई नीति के तहत एआइ आधारित पहचान प्रणाली, कोच में आग का तुरंत पता लगाने वाली तकनीक, ड्रोन से टूटी पटरी की जांच और रेल ट्रैक पर तनाव की निगरानी जैसे समाधान प्रोत्साहित किए जाएंगे। प्रेट्र के अनुसार, रेल मंत्रालय ने बताया कि यात्रियों को व्यापक सेवाएं प्रदान करने वाले रेलवन एप ने लांच होने के करीब आठ माह में दो करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया है।

मूल कंटेंट बनाने वालों को उचित कीमत दें इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म्स : अश्विनी वैष्णव

- स्वैच्छिक रूप से नहीं किया तो निकालना होगा कानूनी हल
- व्यक्ति की सहमति से बनना चाहिए उसका सिंथेटिक वीडियो

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: इलेक्ट्रानिक्स एवं आइटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म्स से कहा है कि वे मूल कंटेंट बनाने वालों के साथ अपना राजस्व उचित रूप में साझा करे और उन्हें उसकी सही कीमत मिलनी चाहिए। इन प्लेटफार्म्स को जागरूक बनना चाहिए और समाज ने जो एक संस्थागत मूल्य का निर्माण किया है, उसके महत्व को भी समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इंटरनेट मीडिया स्वैच्छिक रूप से राजस्व साझेदारी में इस फार्मूले को नहीं अपनाता तो इसका कानूनी हल निकालना होगा। कई देशों ने ऐसा किया भी है। गुरुवार को एक कार्यक्रम में वैष्णव ने यह भी कहा कि डीपफेक या सिंथेटिक वीडियो बनाने से पहले उस व्यक्ति की सहमति लेनी चाहिए। इस दिशा में भी इंटरनेट मीडिया को काम करना चाहिए। इंटरनेट मीडिया के इस युग में दूरदराज इलाके में भी कंटेंट निर्माता हैं। उनके बनाए हुए कंटेंट को इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म्स पर विभिन्न रूपों में चलाकर राजस्व प्राप्त किया जाता है, लेकिन असली कंटेंट निर्माता को इसका उचित लाभ नहीं मिलता। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म्स पर भारत में सबसे अधिक रील व वीडियो देखे जा रहे हैं। इंस्टाग्राम प्लेटफार्म पर भारत के 40 करोड़ लोग हैं और इनमें 95% लोग रील देखते हैं। वैसे ही फेसबुक और एक्स प्लेटफार्म पर भी 60% से अधिक लोग रील देखते हैं।

वैष्णव ने यह भी कहा कि प्लेटफार्म पर चलने वाले सभी कंटेंट की जिम्मेदारी उसी प्लेटफार्म की होगी। आनलाइन प्लेटफार्म पर बच्चों की सुरक्षा या अन्य व्यक्ति की भी आनलाइन सुरक्षा की जिम्मेदारी प्लेटफार्म की है। वैसे ही किसी की आवाज, चेहरा या उसके व्यक्तित्व का इस्तेमाल करके अगर डीप फेक या सिंथेटिक वीडियो बनाया जाता है तो उस व्यक्ति से इजाजत लेनी चाहिए।

मोदी सरकार में शांतिपूर्ण विरोध भी अपराध: राहुल गांधी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में शांतिपूर्ण विरोध को भी अपराध की तरह देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में असहमति को दबाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और संवैधानिक तरीके से आवाज उठाने वालों को दमन का सामना करना पड़ रहा है।

एक्स पर पोस्ट में राहुल ने जोर देकर कहा कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र की आत्मा है। इसे दबाने से लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई नागरिक सरकार की नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करता है तो उसके हिस्से में लाठीचार्ज, मुकदमे और गिरफ्तारी आ जाती है।

एक नजर में

'द केरल स्टोरी 2-गोज बियांड' की रिलीज पर रोक

कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म "द केरल स्टोरी 2-गोज बियांड" की रिलीज पर 15 दिनों के लिए अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को प्रमाणित करते समय सोच-समझकर काम नहीं किया। फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होने वाली थी। (प्रेट्र)

सर्वसम्मति से राकांपा की अध्यक्ष बनीं सुनेत्रा पवार

मुंबई: महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए राकांपा ने गुरुवार को उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति से अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया। अध्यक्ष चुने जाते ही सुनेत्रा ने अपने पति अजीत पवार के सपनों के अनुसार पार्टी को पुनः राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलवाने का संकल्प दोहराया। (राब्यू)

भगवान की मूर्ति तोड़ने के आरोप में रोहिंग्या गिरफ्तार

हैदराबाद: हैदराबाद शहर के चंद्रायणगुट्टा थाना क्षेत्र में स्थित एक मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने और तांबे का बर्तन चोरी करने के आरोप में तीन रोहिंग्या नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार 24 फरवरी को बरकास इलाके के हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ और चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। (प्रेट्र)

एएसआइ की रिपोर्ट : भोजशाला में मंदिर और मूर्तियां तोड़कर बनाई गई थी मस्जिद

परिसर में बनी अब्दुल्ला शाह चंगाल के मकबरे के गेट पर लगा शिलालेख दे रहा गवाही

प्रेमविजय पाटिल ● नईदुनिया

- फारसी में मुद्रित बातों का पक्षकारों की सुविधा के लिए अंग्रेजी व हिंदी में अनुवाद
- रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 260 पर लिखा है सच, खिलजी के शिलालेख का उल्लेख

धार: मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में मंदिर और मठ था। इन्हें ध्वस्त करके वहां स्थापित मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया था। इसकी गवाही परिसर में बनाई गई अब्दुल्ला शाह चंगाल के मकबरे के गेट पर लगा एक शिलालेख दे रहा है। यह शिलालेख वर्ष 1436 से 1469 तक मालवा के सुल्तान रहे महमूद खिलजी का है। इस शिलालेख का उल्लेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में खंड चार के पृष्ठ संख्या 260 पर किया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस शिलालेख की 17वीं और 18वीं पक्तियों में लिखा है कि यहां पहले एक प्राचीन धार्मिक मंदिर और शैक्षणिक केंद्र (मठ) मौजूद था। उस स्थल पर देवताओं की मूर्तियां थीं, जिन्हें नष्ट कर दिया गया और इस स्थान को मस्जिद व मजार में परिवर्तित कर दिया गया।

भोजशाला के सरस्वती (वाग्देवी) मंदिर बनाम मौला कमाल दरगाह मस्जिद विवाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में विचाराधीन है। वर्ष 2024 में एएसआइ द्वारा 98 दिन तक किए गए भोजशाला परिसर के वैज्ञानिक सर्वे की 2189 पृष्ठों की रिपोर्ट पर हाई कोर्ट ने मंदिर और मस्जिद पक्ष से आपत्तियां मांगी हैं। मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को है।

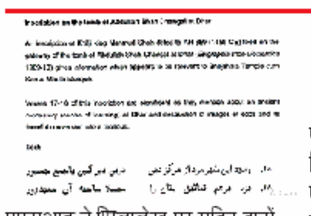
एएसआइ ने शिलालेख पर मुद्रित बातों का अंग्रेजी व फारसी में लिखा है ●

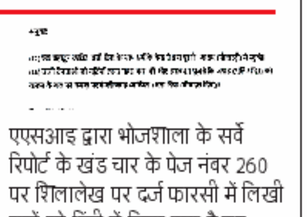
एएसआइ द्वारा भोजशाला के सर्वे रिपोर्ट के खंड चार के पेज नंबर 260 पर शिलालेख पर दर्ज फारसी में लिखी बातों को हिंदी में किया गया है यह अनुवाद ● सौ. एएसआइ की सर्वे रिपोर्ट

शिलालेख पर यह लिखा: एएसआइ ने सर्वे रिपोर्ट में शिलालेख पर फारसी में मुद्रित बातों का पक्षकारों की सुविधा के लिए अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद किया है। उसके अनुसार, खिलजी शासक महमूद शाह के शिलालेख की आयत 17-18, जो हिजरी वर्ष 859 (1455 ईस्वी) का है इसमें लिखा है- 'एक बहादुर व्यक्ति बड़ी सेना के साथ धर्म के केंद्र से इस पुराने आश्रम (मठ) में पहुंचा। उसने देवताओं की मूर्तियां तहस-नहस कर दीं और पूजने की जगह (मूर्तियों-मंदिर) को ताकत के बल पर नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद बना दिया।'

सर्वे रिपोर्ट में मंदिर के प्रमाण : सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, शिलालेख की लिखावट, परिसर में मिलीं मूर्तियों और वास्तुकला के अवशेष बताते हैं कि पत्थर की मूल संरचना को बाद में बदलकर मस्जिद बनाया गया। खिड़की के फ्रेम पर देवी-देवताओं की मूर्तियां अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में हैं। एक खंभे पर देवताओं की कटी-फटी आकृतियां हैं।

> भोजशाला का सच यही है कि इसके रूप को बदला गया। मंदिर को मस्जिद में बदलने के लिए इमारत को नुकसान पहुंचाया गया। -**डीके रिछारिया,** सेवानिवृत अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, धार

मंदिर पक्ष : शिलालेख इस बात की गवाही देता है कि यहां प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर मूर्तियों को नष्ट किया गया और बाद में मस्जिद में परिवर्तित किया गया। सर्वे का यह तथ्य भोजशाला को सरस्वती (वाग्देवी) मंदिर सिद्ध करने के पक्ष में महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं।
- **आशीष गोयल,** याचिकाकर्ता, मंदिर पक्ष

मस्जिद पक्ष : वर्ष 1903 और 1904 में एएसआइ के ही सर्वे में यह स्पष्ट रूप से तय किया गया था कि यह स्थान मस्जिद है और उसकी संरचना भी मस्जिद जैसी ही है। अब नए सर्वे रिपोर्ट में तथ्य बदले नजर आ रहे हैं।
- **अब्दुल समद,** सदर, कमाल मौलाना वेलफेयर कमेटी, धार

विस में उठा धार की वाग्देवी की प्रतिमा वापस लाने का मुद्दा

इस बीच, लंदन के म्यूजियम में रखी वाग्देवी (सरस्वती) की मूर्ति को भारत वापस लाने के मुद्दा गुरुवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में उठा। विधायक प्रताप ग्रेवाल द्वारा लिखित सवाल में पूछा गया कि प्रतिमा को वापस लाने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए। इस पर प्रदेश के संस्कृति विभाग के राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने लिखित जवाब में बताया कि इस संबंध में लगातार पत्राचार जारी है। गौरतलब है कि वाग्देवी की प्रतिमा 1930 में अंग्रेज अपने साथ ले गए थे और यह प्रतिमा फिलहाल लंदन के म्यूजियम में रखी है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने झारखंड व ओडिशा से मांगे 100-100 जज

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता: बंगाल में मतदाता सूची के एसआइआर के कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने कमर कस ली है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों का पालन करते हुए हाई कोर्ट ने पड़ोसी राज्यों-झारखंड और ओडिशा-से 100-100 न्यायिक अधिकारियों (जजों) की मांग की है। सूत्रों के अनुसार, गुरुवार को दोनों राज्यों के उच्च न्यायालयों को इस संबंध में औपचारिक पत्र भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डाटा संबंधी त्रुटियों के निपटारे की जिम्मेदारी कलकत्ता हाई कोर्ट को सौंपी थी। अब तक 532 जजों को इस काम में लगाया गया है। काम को देखते हुए और अधिक न्यायिक अधिकारियों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। 21 फरवरी की मध्यरात्रि तक डाटा संबंधी विसंगतियों के जो आंकड़े दिए गए थे, उन्हें ही अंतिम माना जाएगा।

बंगाल में नामांकन से ही निगरानी के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों का दल मौजूद रहेगा। सूत्रों के अनुसार, प्रत्येक विधानसभा की निगरानी के लिए कम से कम एक पर्यवेक्षक तैनात रहेगा। चुनाव आयोग ने पिछले चुनावों के अनुभव के आधार पर देखा है कि नामांकन से ही राज्य के कई स्थानों से अशांति की शिकायतें आने लगी थीं। राज्य में सबसे अधिक सुरक्षा घेरा उत्तर 24 परगना जिले में होगा, कुल 30 कंपनियां तैनात की जा रही हैं।

'सीमांचल से जल्द शुरू होगा घुसपैठिया मुक्त भारत अभियान'

- सीमांचल से तय किया बंगाल का एजेंडा, घुसपैठियों को बाहर निकालने का किया वादा
- भारत-नेपाल संबंधी मुद्दों पर सात सीमावर्ती जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठकें

बिहार में अररिया जिले के लेटी में एसएसबी जवानों को संबोधित करते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ● जागरण

जागरण संवाददाता, अररिया : घुसपैठ और सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध निर्माण के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीमांचल से घुसपैठिया मुक्त भारत अभियान जल्द शुरू होगा। सीमा के 10 किमी दायरे में बने अवैध निर्माणों को चिह्नित कर तत्काल ध्वस्त किया जाएगा। घुसपैठ रोकने के लिए व्यापक कार्ययोजना लागू की जाएगी। चुन-चुनकर घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाएगा। मोदी सरकार घुसपैठ का स्थायी समाधान करेगी। इसके साथ ही सीमांचल की धरती से बंगाल चुनाव का एजेंडा भी तय कर दिया। उन्होंने यह बातें सीमांचल के तीन दिवसीय दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को अररिया जिले के लेटी सीमा सशस्त्र बल (एसएसबी) कैंप में 170 करोड़ की योजनाओं के लोकार्पण व भूमिपूजन के मौके पर कही।

गृह मंत्री ने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव व घुसपैठ के मामले में बंगाल की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। भाजपा बिहार के तर्ज पर इन्हीं मुद्दों पर आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव में उतरेगी और जीतेगी। बंगाल में सरकार बनते ही घुसपैठ सरकार के पहले एजेंडे में होगा और सरकार गठन के साथ ही एक्शन शुरू होगा। केवल मतदाता सूची से नाम हटाने से घुसपैठ की समस्या का समाधान संभव नहीं है। घुसपैठिये न केवल हमारे चुनाव को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे हक के राशन और रोजगार पर भी डाका डालते हैं। लेटी एसएसबी कैंप से शाह सीधे अररिया पहुंचे और यहां कलेक्ट्रेट सभागार में भारत-नेपाल संबंधी मुद्दों पर सात सीमावर्ती जिलों के डीएम व एसपी, एसएसबी, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की।

अनिल अंबानी से नौ घंटे पूछताछ

पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय जाते अनिल अंबानी (दाएं) ● प्रेट्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : ईडी ने गुरुवार को रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी से उनके समूह की कंपनी आरकाम से जुड़े एक मनी लांड्रिंग मामले में नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। 66 वर्षीय उद्योगपति सुबह लगभग साढ़े दस बजे ईडी कार्यालय पहुंचे और रात लगभग सवा आठ बजे वहां से निकले। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें शुक्रवार को एक अलग मामले में जोकि यस बैंक के कथित ऋण धोखाधड़ी से संबंधित है, फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

जांच एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि अनिल अंबानी का बयान पीएमएलए के प्रविधानों के तहत दर्ज किया गया। यह जांच उनकी समूह की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकाम) द्वारा किए गए 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले से संबंधित है। अनिल अंबानी और उनके समूह की कई कंपनियों पर ऋण धोखाधड़ी के आरोप हैं। ईडी ने हाल ही में इन सभी मामलों की जांच के लिए एसआइटी का गठन किया है। ईडी ने बुधवार को मनी पीएमएलए के तहत अनिल अंबानी के मुंबई स्थित आवास 'एबोड' को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया था।

सीबीआइ ने की छापेमारी : सीबीआइ ने अनिल अंबानी और आरकाम के खिलाफ 2013-17 के दौरान बैंक आफ बड़ौदा को धोखा देने के आरोप में नया केस दर्ज किया है। यह मामला मंगलवार को बैंक से प्राप्त शिकायत के आधार पर शुरू हुआ। सीबीआइ ने अनिल के निवास और रिलायंस कम्युनिकेशंस के कार्यालयों पर छापे मारे व ऋण लेनदेन से संबंधित दस्तावेज बरामद किए। आरोप है कि आरकाम द्वारा लिए गए ऋणों के कारण बैंक को 2,220 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।

रंगों के उल्लास में झूमा नंदगांव...

ढोल-नगाड़ों की गूंज, रसिया गायन और पारंपरिक गाली गायन के मधुर परिहास के बीच हुरियारे और हुरियारिन रंगों में भींगकर झूम उठे। लठामार होली के उल्लास में एक ओर हुरियारिनों के हाथों से प्रेम पगे लठ बरसते रहे तो दूसरी ओर बरसाना से आए हुरियारे ढाल थामे उत्साह के साथ उनका सामना करते रहे। फाल्गुन शुक्ल दशमी पर गुरुवार को बरसाना के हुरियारे दोपहर ढाई बजे नंदगांव पहुंचे। वहां यशोदा कुंड पर उनका पारंपरिक स्वागत कर भांग के साथ स्वल्पाहार कराया गया। इसके बाद वह होली खेलने की अनुमति लेने दोपहर 3.30 बजे नंद भवन पहुंचे। जहां दोनों गांवों के गोस्वामी समाज के बीच पारंपरिक रसिया गायन हुआ। हुरियारिनों ने लठ बरसाने शुरू कर दिए और पांच बजे लठामार होली अपने चरम पर पहुंच गईं ● जागरण

पुलिस को सौंपी बच्चों के मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट, आज हाई कोर्ट में सुनवाई

जागरण संवाददाता, प्रयागराज: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद समेत अन्य के खिलाफ दर्ज मुकदमे की विवेचना को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने पीड़ित बच्चों का टीबी सप्रू अस्पताल में मेडिकल टेस्ट करवाया। गुरुवार को डाक्टरों की ओर से पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट बंद लिफाफे में दी गई। शुक्रवार को हाई कोर्ट में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मामले में सुनवाई होनी है। प्रकरण से जुड़े सभी तथ्यों व साक्ष्यों की प्रमाणिकता के आधार पर पुलिस कार्रवाई किए जाने की बात कह रही है।

कोर्ट के आदेश और आशुतोष ब्रह्मचारी की तहरीर पर झूंसी पुलिस ने अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य व तीन अज्ञात के खिलाफ कुकर्म, धमकी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने दो दिन में दोनों पीड़ित बच्चों का बयान दर्ज किया और फिर कोर्ट में बयान करवाया। बुधवार को पुलिस पीड़ितों को सीएचसी बनी सरायइनायत लेकर गई, जहां से डाक्टरों ने नाबालिग होने के कारण टीबी सप्रू अस्पताल भेजा। टीबी सप्रू अस्पताल में डाक्टरों ने मेडिकल टेस्ट किया। गुरुवार को मेडिकल रिपोर्ट पुलिस के पास बंद लिफाफे में भेजी गई। अब उस रिपोर्ट को विवेचना अधिकारी केस डायरी में शामिल करेंगे और कोर्ट में पेश करेंगे। डीसीपी सिटी मनीष शांडिल्य का कहना है कि पीड़ित बच्चों का मेडिकल और बयान दर्ज कराया जा चुका है। आगे की विवेचना चल रही है।

'यूपी पुलिस ने आशुतोष ब्रह्मचारी को प्रवक्ता बना लिया है'

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठाया है कि क्या यूपी पुलिस ने आशुतोष ब्रह्मचारी को अपना प्रवक्ता बना लिया है। उनके ऊपर शोषण मामले में जो

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद

गोपनीय रिपोर्ट है, वह पत्रकारवार्ता कर किस हैसियत से उसे सार्वजनिक कर रहे हैं। उन्हें पुलिस की ओर से कराई गई जांच कैसे मिली। इससे यह संदेश जाता है कि यूपी पुलिस के जांच अधिकारी शिकायतकर्ता से मिले हुए हैं। ऐसे में जांच की निष्पक्षता संदेह के घेरे में है। गुरुवार को श्रीविद्या मठ में पत्रकारों साथ अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने स्विमिंग पूल और पांच मंजिला भवन होने के आरोप का खंडन किया। कहा कि 1995 में ज्योतिष द्वारका शारदा पीठाधीश्वर मेरे गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने इस मठ का निर्माण अपने गुरु की इच्छा को पूरा करने के लिए कराया।

सड़क सुरक्षा में जोड़े जाएंगे सांसद, अधिकारी

- अधिक सड़क हादसों वाले सौ जिलों के मंत्रियों, सांसदों के साथ बैठक करेगी सरकार
- जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को सड़क सुरक्षा के उपाय के साथ जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: सड़क हादसों को कम करने के तमाम प्रयासों की विफलता के बीच सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अब नई योजना पर काम कर रहा है। मंत्रालय ने देशभर से ऐसे सौ जिले चिन्हित किए हैं, जहां सड़क हादसे अधिक होते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तय किया है कि एक माह के भीतर दिल्ली में इन सौ जिलों के कलेक्टरों का सम्मेलन बुलाया जाएगा। संबंधित सांसदों और मंत्रियों को भी बुलाकर उन्हें न सिर्फ सड़क सुरक्षा के उपाय सुझाए जाएंगे, जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कन्फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआइआइ) के सड़क सुरक्षा सम्मेलन में सड़क हादसों के लिए खराब रोड इंजीनियरिंग के साथ ही कमजोर एनफोर्समेंट को जिम्मेदार ठहराया। मंत्रालय की ओर से किए जा रहे तमाम प्रयासों का उल्लेख करने के साथ ही केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि उनके संसदीय क्षेत्र नागपुर में एक पुलिस अधीक्षक ने सड़क हादसों को लेकर संवेदनशीलता दिखाई। खुद प्रयास कर ब्लैक स्पाट चिन्हित कर विशेषज्ञों के द्वारा उनके समाधान के तरीके तलाशे। इस प्रयास के कारण उस क्षेत्र में सड़क हादसों में 50% की कमी आई है।

सीआइआइ के सड़क सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते नितिन गडकरी ● प्रेट्र

'ग्रेड' आधारित ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली लाने की तैयारी

प्रेट्र के अनुसार, सरकार सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जिम्मेदारी से वाहन चलाने को बढ़ावा देने के लिए 'ग्रेड' आधारित ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली लागू करने की योजना बना रही है। इसके तहत यातायात नियमों के उल्लंघन पर अंक काटे जाएंगे और गंभीर या बार-बार उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकेगा। गडकरी ने कहा कि देश में हर वर्ष करीब 1.8 लाख लोगों की मौत मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए वाहन चलाने, तेज रफ्तार, गलत दिशा में जाने या नशे में गाड़ी चलाने जैसे कारणों से होती है।

विमानन नियामक संस्था डीजीसीए 38 सलाहकारों की नियुक्ति करेगी

नई दिल्ली, प्रेट्र : विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कर्मचारियों की भारी कमी से निपटने के लिए 38 सलाहकारों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। यह निर्णय नियामक की कार्यक्षमता बढ़ाने और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। डीजीसीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, उड़ान योग्यता निदेशालय में 24 पद, विमान सुरक्षा निदेशालय में छह, अंतरराष्ट्रीय संबंध और कानूनी मामले के लिए सात पद (पांच वरिष्ठ सलाहकार और दो सलाहकार), और फ्लाइंग ट्रेनिंग निदेशालय में एक पद भरे जाएंगे। यह भर्ती अभियान विमानन क्षेत्र की सुरक्षा और निगरानी को सुदृढ़ करने की दिशा में एक तात्कालिक कदम है। ये सभी नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर होंगी।

भोर में उठना सफलता की गारंटी नहीं, सबका शरीर अलग

- जीन तय करते हैं कि आप भोर में उठने वाले होंगे या देर से
- जैविक घड़ी से मेल खाने वाली दिनचर्या दिलाएगी बेहतर नतीजे

लंदन, द कन्वर्सेशन: लंबे समय से यह माना जाता है कि भोर में उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है और जीवन में बड़ी सफलता हासिल करता है। इंटरनेट मीडिया पर भी ऐसे संदेशों की भरमार है, जो बताते हैं कि सूर्योदय से पहले दिन की शुरुआत करने का मतलब है कि आपने आधी जंग पहले ही जीत ली है। एपल के सीईओ टिम कुक, सफल उद्यमी रिचर्ड ब्रैनसन और हालीवुड एक्टर जेनिफर एनिस्टन जैसे बड़े नाम भी गिनाए जाते हैं, जो दिन की शुरुआत जल्दी करते हैं। संदेश साफ है। भोर में उठने का मतलब है कि आपकी सफलता तय है लेकिन विज्ञान ऐसा नहीं मानता। शोध बताते हैं लोग आमतौर पर बेहतर प्रदर्शन तब करते हैं, जब उनकी दिनचर्या उनके शरीर की प्राकृतिक घड़ी से मेल खाती है। बहुत से लोगों का शरीर ऐसा हो सकता है, जो सुबह पांच बजे उठना स्वीकार न करे। ऐसा करने से उनकी सेहत और उत्पादकता दोनों पर बुरा असर पड़ सकता है। काफी कुछ व्यक्ति विशेष की जैविक रिदम या क्रोनोटाइप पर निर्भर करता है।

मार्निंग टाइप वालों का बेहतर होता है प्रदर्शन

अध्ययनों में क्रोनोटाइप के बीच अंतर भी सामने आया है। मार्निंग टाइप वाले व्यक्तियों का अकादमिक प्रदर्शन आम तौर पर अच्छा रहता है। ऐसे लोग स्मोकिंग, शराब और मादक द्रव्यों के सेवन से भी दूर रहते हैं और नियमित व्यायाम भी करते हैं।

इवनिंग टाइप वालों का शारीरिक स्वास्थ्य हो सकता है खराब

इवनिंग टाइप के लोगों के साथ इस बात की संभावना अधिक रहती है कि वह काम से बुरी तरह से ऊब जाएं। उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। इवनिंग टाइप वालों की कामकाजी जिंदगी भी कम व्यवस्थित होती है। इससे उनको नींद न पूरी होने, थकान और तनाव का सामना करना पड़ सकता है।

अनुवांशिकी तय करती है आपका टाइप: क्रोनोटाइप दो तरह का होता है। एक है मार्निंग टाइप और दूसरा है इवनिंग टाइप। मार्निंग टाइप वाले लोग भोर में उठ जाते हैं व अलर्ट महसूस करते हैं। वहीं, इवनिंग टाइप वाले व्यक्ति दोपहर बाद ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं।

आम धारणा है कि सुबह जल्दी उठने की दिनचर्या अपनाने से आपको वही फायदे मिल सकते हैं जो मार्निंग टाइप के लोगों को मिलते हैं। क्रोनोटाइप आसानी से नहीं बदलता है। इसे आपकी अनुवांशिकी और सर्केडियन रिदम यानी शरीर की प्राकृतिक घड़ी आकार देती है। बहुत से इवनिंग टाइप वाले लोग अगर अपनी प्राकृतिक रिदम के विपरीत जाकर सुबह जल्दी उठते हैं तो उनको समय के साथ नींद पूरी न होने, एकाग्रता में कमी और खराब मूड जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

संपादकीय जागरण

शुक्रवार, 27 फरवरी, 2026: फाल्गुन शुक्ल - 11 वि. 2082

गलती दोहराने का यही अर्थ है कि अतीत से कुछ सीखा नहीं

कनाडा की भूल सुधार

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के पहले वहां की सरकार ने जिस तरह यह कहा कि उनके देश में होने वाले अपराधों का भारत से कोई संबंध नहीं, वह केवल भूल सुधार ही नहीं, बल्कि इसका प्रमाण है कि जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली पिछली सरकार किस तरह अपने संकीर्ण राजनीतिक कारणों से भारत विरोधी एजेंडे पर चल रही थी। जस्टिन ने भारत से भागे और अवैध तरीके से कनाडा में प्रवेश करने वाले खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराते हुए ऐसे बेतुके बयान दिए थे कि इस हत्याकांड में भारत का हाथ होने के पुख्ता आरोप सामने आए हैं। प्रमाण के बजाय आरोप की हास्यास्पद बात करके उन्होंने अपनी जगहंसाई तो कराई ही थी, यह भी सिद्ध किया था कि वे खालिस्तान समर्थक नेता जगमीत सिंह के इशारे पर भारत से संबंध खराब करने पर तुल गए थे। यह ठीक है कि उनकी अल्पमत सरकार जगमीत की पार्टी के समर्थन की मोहताज थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे उसके दबाव-प्रभाव में भारत से संबंध बिगाड़ने की हद तक चले जाते। आम तौर पर अल्पमत सरकारें घरेलू मामलों में समर्थक दलों के दबाव में आती हैं, लेकिन ट्रूडो सरकार तो विदेश नीति पर जगमीत की पार्टी के समक्ष नतमस्तक हो गई।

समस्या केवल इतनी ही नहीं थी कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान समर्थक नेताओं के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे, बल्कि यह भी थी कि वे भारत विरोधी तत्वों की पीठ पर हाथ रखे हुए थे। इसका दुष्परिणाम यह था कि कनाडा में सक्रिय खालिस्तान समर्थक अतिवादी आए दिन भारत के खिलाफ उग्र-हिंसक प्रदर्शन करते थे। वे भारत के साथ-साथ भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को भी धमकाते थे, पर जस्टिन मौन साधे रहते थे। इस कारण भारत को भी उनके खिलाफ कठोर रवैया अपनाना पड़ा। यह अच्छा हुआ कि उनकी जगह प्रधानमंत्री बने मार्क कार्नी पहले दिन से भारत से संबंध सुधार के प्रयास कर रहे हैं, पर भारतीय नेतृत्व केवल इतने से संतुष्ट नहीं हो सकता कि नई सरकार पिछली सरकार की गलतियां ठीक कर रही है। भारत को यह देखना होगा कि कनाडा में भारत के खिलाफ सुनियोजित दुष्प्रचार करते रहने वाले खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ कोई ठोस कानूनी कार्रवाई होती है या नहीं? भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक चरमपंथी अभी भी भारतीय हितों के लिए खतरा बने हुए हैं। भारत यह भी नहीं भूल सकता कि तीन सौ से अधिक यात्रियों की जान लेने वाले एअर इंडिया के विमान को विस्फोट से उड़ाने वाले खालिस्तान समर्थक आतंकियों को कोई कठोर सजा नहीं दी जा सकी है और वहां जब-तब उनका महिमामंडन भी होता रहता है। संबंधों में वास्तविक सुधार के लिए यह सब बंद होना चाहिए।

चिंता की बात

दक्षिणी दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कालोनी के एक घर में ईडी अधिकारी बनकर छापेमारी के नाम पर लूटपाट करने के मामले में पुलिस ने घरेलू सहायिका समेत दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। घर के मालिक ने घरेलू सहायिका का पुलिस सत्यापन नहीं करवाया था। गनीमत रही कि पुलिस सीसीटीवी जांच करते हुए आरोपितों तक पहुंच गई, अन्यथा मामले का पर्दाफाश होना भी आसान नहीं था। आरोपित दोनों महिलाओं ने तीन अन्य के साथ मिलकर विगत 13 फरवरी को इस वारदात को अंजाम दिया था।

पुलिस सत्यापन को लेकर मकान मालिकों की उदासीनता चिंताजनक है, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए

दिल्ली में घरेलू सहायकों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्यरत सहायकों व किरायेदारों का पुलिस सत्यापन न कराया जाना किस हद तक नुकसानदायक है, ये घटना इसका उदाहरण है। यह गनीमत थी कि आरोपितों के पास हथियार नहीं थे, अन्यथा वृद्ध दंपती की जान को भी खतरा हो सकता था। पुलिस सत्यापन कराने के बाद घरेलू सहायकों में इस बात का डर होता है कि उनका विवरण पुलिस के पास है और घर में कोई भी अपराध करने पर उन्हें फौरन पकड़ लिया जाएगा। ऐसे में उनके द्वारा अपराध होने की आशंका कम हो जाती है। इसके बावजूद पुलिस सत्यापन को लेकर मकान मालिकों की उदासीनता चिंताजनक है।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या एनसीईआरटी की पुस्तक में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' विषय से जुड़े अध्याय पर सुप्रीम कोर्ट का विरोध उचित है?

आज का सवाल

क्या प्रधानमंत्री की इजरायल यात्रा पर कांग्रेस की आपत्ति उचित है?

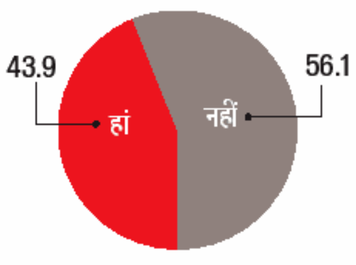

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

गठबंधन को लेकर बेपरवाह कांग्रेस

राज कुमार सिंह

चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, पर गठबंधन के तौर पर आइएनडीआइए में सक्रियता तो दूर, कोई सुगबुगाहट भी नहीं

शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र 'सामना' के संपादकीय, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर की टिप्पणियों से विपक्षी दलों के मोर्चे आइएनडीआइए की दरारें उजागर हुई ही थीं कि एआइ सम्मेलन में युवा कांग्रेस के अर्धनग्न प्रदर्शन से कांग्रेस की दिशाहीनता भी बेनकाब हो गई। लगता नहीं कि कांग्रेस को देश या विपक्षी एकता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का कोई अहसास है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की लगातार तीसरी निराशाजनक हार के बावजूद अन्य विपक्षी दलों ने राहुल को नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्वीकार कर उदारता ही दिखाई, लेकिन कांग्रेस ने कभी अन्य दलों को संसद के अंदर या बाहर साथ लेकर चलने की परिपक्वता नहीं दिखाई। राहुल गांधी अपेक्षा करते हैं कि वे जो भी रणनीति तय कर लें, संसद के अंदर-बाहर अन्य दलों को उनका श्रद्धापूर्वक अनुसरण करना चाहिए।

भाजपा को हराने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से लगभग एक साल पहले दो दर्जन विपक्षी दलों को जोड़कर आइएनडीआइए बनाया गया था। दो बार पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद भाजपा का 240 सीटों पर ठहरने को इस मोर्चे की एक सफलता के रूप में देखा गया, लेकिन लोकसभा चुनाव बाद गठबंधन के पक्ष में कुछ खास घटित होता नहीं दिख रहा। उनके बीच लगातार उजागर दरारें बताती हैं कि दलों में दोस्ती के बावजूद दिलों में दूरियां बरकरार हैं।

सफलताओं की बात करें तो झारखंड और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जीत तो हासिल हुई, लेकिन वहां कांग्रेस हाशिए पर ही है। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार में उसके हिस्से हार ही आई। इसमें महाराष्ट्र और बिहार की हार को शर्मनाक कहना कहीं अधिक उचित होगा। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में तो गठबंधन की गांठें पूरी तरह बिखरती दिखीं।

इस साल चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, पर गठबंधन के तौर पर आइएनडीआइए में सक्रियता तो दूर, कहीं कोई सुगबुगाहट भी नहीं। एसआइआर पर तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ही चुनाव आयोग से दो-दो हाथ करती नजर आती हैं। तमिलनाडु में भी चुनाव आयोग से लेकर भाजपा तक के विरुद्ध मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनकी पार्टी द्रमुक ही मोर्चा खोले है। बंगाल में ममता एकला चलो की राह पर हैं। पिछली बार वाम मोर्चा के साथ गठबंधन करने वाली कांग्रेस इस बार अकेले चुनावी जोर आजमाइश के मूड में है। केरल में तो मुख्य चुनावी

अवधेश राजपूत

मुकाबला सत्तारूढ़ वाम मोर्चा और कांग्रेसनीत यूडीएफ के बीच ही होता है। इसलिए राज्य की राजनीति में तो परस्पर समन्वय की गुंजाइश नहीं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक ही गठबंधन के सदस्य होने के नाते तमाम राजनीतिक मुद्दों पर तो आइएनडीआइए को एक सुर में बोलना चाहिए। तमिलनाडु में द्रमुक और कांग्रेस के बीच पुराना गठबंधन है, लेकिन वहां भी दरारें इस हद तक हैं कि मणिक्कम टैगोर और प्रवीण चक्रवर्ती सरीखे कांग्रेस के दूसरी पंक्ति के नेता द्रमुक पर निशाना साध रहे। नतीजतन द्रमुक को उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग करनी पड़ी। तमाम अटकलों के बाद अब द्रमुक-कांग्रेस में सीट बंटवारे पर बातचीत जारी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो 2027 में होने हैं, लेकिन वहां जारी एसआइआर को लेकर कांग्रेस की अनुपस्थिति उसके समाजवादी पार्टी से रिश्तों में खिंचाव का भी संकेत है।

'सामना' के संपादकीय 'अंदर की आवाजों का कन्फ्यूजन' में कांग्रेस से सवाल पूछा गया है-ममता, स्टालिन या कोई और? संपादकीय में गठबंधन को जागने और कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बातचीत करने की नसीहत देते हुए मणिशंकर अय्यर, संजय बारू और भूपेन बोरा आदि की टिप्पणियों को अंदर की आवाजों का कन्फ्यूजन करार दिया गया है। बारू ने आइएनडीआइए का नेतृत्व ममता बनर्जी को देने का सुझाव दिया है तो अरसे तक नेहरू-गांधी परिवार के करीबी समझे गए अय्यर की टिप्पणियां राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल के रूप में देखी जा रही हैं। जिस एकमात्र राज्य केरल में कांग्रेस की जीत की संभावना है, वहां भी अय्यर ने लगातार तीसरी बार वाम मोर्चा की ही जीत की भविष्यवाणी करते हुए मुख्यमंत्री विजयन की प्रशंसा की है। आइएनडीआइए के नेतृत्व के लिए वे स्टालिन को बेहतर मानते हैं। पार्टी से कोई संबंध न होने के आधार पर उनकी टिप्पणी को निजी राय बताकर कांग्रेस ने अय्यर से पल्ला झाड़ना चाहा है, पर राजनीतिक गलियारों से लेकर केरल-तमिलनाडु तक चर्चा थमी नहीं है। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद भले ही शशि थरूर के स्वर बदल गए हों, पर उससे पहले की तल्खियां सबने देखी हैं। असम के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा तो राहुल गांधी से बातचीत के बाद भी इस्तीफा वापस लेने के फैसले से पलट गए और हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा घोषित तारीख पर भाजपा में शामिल भी हो गए। लगभग एक दशक पहले हिमंत ने भी राहुल गांधी की कार्यशैली से खफा होकर कांग्रेस छोड़ी थी। पूर्वोत्तर में भाजपा के विस्तार में अहम भूमिका निभाने के बाद अब वे असम के मुख्यमंत्री और भाजपा आलाकमान के लाड़ले हैं।

दलबदल के बाद अक्सर अवसरवाद, दबाव और प्रलोभन की बातें सुनाई पड़ती हैं। इन्हें पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, पर दलबदल कहीं-न-कहीं नेतृत्व की क्षमता और दल की राजनीतिक संभावनाओं पर अविश्वास का परिणाम भी होते हैं। राहुल गांधी को कम-से-कम अपनी टीम का सदस्य बताए गए युवा नेताओं के कांग्रेस से पलायन पर तो आत्मविश्लेषण करना ही चाहिए और अगर वे पर्याप्त समय नहीं दे सकते तो फिर आइएनडीआइए का नेतृत्व ममता बनर्जी या स्टालिन जैसे किसी पूर्णकालिक क्षेत्रीय नेता को सौंपने की पहल करें। हाल के एआइ इंपैक्ट सम्मेलन में युवा कांग्रेस के अर्धनग्न प्रदर्शन से आइएनडीआइए के अन्य घटक दलों की मुखर असहमति भी कांग्रेस के लिए अपनी दशा और दिशा पर गंभीर पुनर्विचार का संदेश है, लेकिन शायद वह किसी संदेश को सुनने को तैयार नहीं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

लाभकारी बनाएं व्यापार समझौते

जयंतीलाल भंडारी

व्यापार समझौतों का पूरा लाभ तभी मिलेगा, जब देश नई पीढ़ी के सुधारों और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को आगे बढ़ाएगा

निर्यात को गति देंगे नए व्यापार समझौते ● फाइल

पिछले कुछ सालों में भारत मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के जरिये कई देशों से मुक्त व्यापार की राह पर आगे बढ़ा है। इससे भारतीय वस्तुओं के लिए दुनिया के बाजारों में निर्यात पहुंच बढ़ी है। गत दिवस पीएम मोदी ने कहा कि इजरायल के साथ भी भारत का एफटीए जल्दी ही आकार लेते हुए दिखाई देगा और भारत जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अवैध ठहराए जाने के बाद 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए भारत समेत सभी देशों पर 15 प्रतिशत अस्थायी ग्लोबल टैरिफ लागू हो गया है। इस अवधि के बाद अमेरिकी संसद तय करेगी कि इसे आगे बनाए रखना है या नहीं? अभी अमेरिकी प्रशासन के पास टैरिफ लगाने की कई शक्तियां बची हुई हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी संसद से टैरिफ पर प्रस्ताव मंजूर होने के बाद भारत के साथ किया गया व्यापार समझौता अपने पूर्व निर्धारित रूप में ही लागू होगा। ऐसे में जहां आगामी 150 दिन टैरिफ की अस्थायी कमी निर्यात बढ़ाने के लिए हितकर है, वहीं इसके बाद दोनों देशों के बीच अंतरिम व्यापार समझौता अमेरिका को निर्यात बढ़ाने के लिए लाभप्रद होगा।

भारत के लिए अमेरिका एक बड़ा बाजार है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और अमेरिका के बीच 131.84 अरब डालर मूल्य का व्यापार हुआ। इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल से दिसंबर के बीच भारत ने अमेरिका को 65.88 अरब डालर मूल्य का निर्यात किया है। ऐसे में अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौता भारतीय निर्यात बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। अमेरिका द्वारा शुरू किए गए टैरिफ और व्यापार व्यवधानों ने भारत को वैकल्पिक बाजार खोजने और नए व्यापार गठबंधन बनाने की राह पर आगे बढ़ाया है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत ने पिछले वर्ष कई व्यापार समझौते किए हैं और इस वर्ष भी कई नए व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन की तैयारी है। इनमें अत्यधिक महत्वपूर्ण यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ मुक्त व्यापार समझौता भी शामिल है। हाल में एआइ समिट के दौरान ईयू के कई राष्ट्राध्यक्षों ने 27 जनवरी को भारत-ईयू के दौरान किए गए एफटीए को शीघ्र कार्यान्वित किए जाने के लिए समर्थन दिया। यह एफटीए दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का बेजोड़ उदाहरण है। इस समझौते को सभी व्यापार समझौतों की जननी कहा गया है। इस एफटीए से दो अरब लोगों का एक साझा बाजार तैयार होगा, जिसका संयुक्त बाजार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग एक चौथाई हिस्से के बराबर होगा। अनुमान है कि यह एफटीए आगामी छह महीने में कार्यान्वित होते हुए दिखाई देगा।

पिछले वर्ष भारत द्वारा ब्रिटेन, ओमान के साथ किए गए एफटीए इसी अप्रैल से और न्यूजीलैंड के साथ किया गया एफटीए सितंबर से कार्यान्वित होते हुए दिखाई देगा। इन सबके साथ-साथ मारीशस, संयुक्त अरब अमीरात, आस्ट्रेलिया और चार यूरोपीय देशों के समूह यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (एफ्टा) के साथ हुए एफटीए से भी इस वर्ष निर्यात बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस वर्ष पेरू, चिली, आसियान, मेक्सिको, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इजरायल, भारत गल्फ कंट्रीज काउंसिल सहित अन्य प्रमुख देशों के साथ भी नए एफटीए हो सकते हैं। यह निर्यात बढ़ने की संभावनाओं का एक अनुकूल परिदृश्य है, लेकिन ट्रंप प्रशासन के लगातार बदलते रवैये को देखते हुए भारत के लिए उचित यही होगा कि वह अन्य देशों से व्यापार समझौते संबंधी वार्ताओं को गति दे।

वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत से निर्यात बढ़ाना कोई सरल काम नहीं है। भारत को निर्यात की नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। एक फरवरी को वित्त मंत्री की ओर से प्रस्तुत केंद्रीय बजट में विनिर्माण, वस्त्र, चमड़ा और समुद्री भोजन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए निर्यात बढ़ाने के लिए जो कई रणनीतिक उपाय किए गए हैं, उन पर नए वित्तीय वर्ष में शुरुआत से ही ध्यान देना होगा। निर्यात बढ़ाने के लिए हमें उत्पादों की गुणवत्ता और नए सुधारों पर भी ध्यान देना होगा। व्यापार समझौते अभी ऐतिहासिक कागजी दस्तावेज हैं। इनका पूरा लाभ तभी मिलेगा, जब भारत नई पीढ़ी के सुधारों और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को आगे बढ़ाएगा। नए व्यापार समझौतों से भारत दुनिया की बड़ी-बड़ी मंडियों में प्रवेश पाने में सफल तो होगा, लेकिन देश को व्यापारिक महाशक्ति बनाने के लिए आकर्षक दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाला माल तैयार करना होगा। सिस्टमैटिक्स ग्रुप की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत द्वारा व्यापार समझौतों का अधिकतम लाभ लेने के लिए सबसे पहले किफायती लागत पर गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, लाजिस्टिक्स और कस्टम प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे सुधारों पर तेजी से आगे बढ़ना होगा। निर्यातकों की दिक्कतें केवल शुल्क वृद्धि तक सीमित नहीं हैं। वे एंटी-डंपिंग शुल्क से भी संबंधित हैं। घरेलू कच्चे माल की ऊंची लागत और ईंधन की उच्च कीमतों के कारण भी भारत की ओर से निर्यात किए जाने वाले उत्पाद वैश्विक स्तर से करीब 20 प्रतिशत की अधिक लागत पर दिखाई देते हैं। व्यापार समझौतों से देश को आर्थिक शक्ति बनाने के लिए अधिकारियों को नए दौर की जरूरत के मुताबिक शिक्षित-प्रशिक्षित करने के साथ सरकारी और निजी क्षेत्रों में शोध, विकास एवं नवाचार बढ़ाना होगा।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

दीर्घायु होने का मंत्र

भारतीय संस्कृति शतायु अर्थात सौ वर्ष की आयु की संकल्पना को पोषित करती आई है। इसका आशय है कि सक्षम एवं सक्रिय इंद्रियों के साथ हम सौ वर्षों तक जीवित रहें। शतायु होने का कोई एक जादुई उपाय नहीं है। यह संतुलित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि, तनाव मुक्त जीवन, पर्याप्त नींद और व्यसनों से दूरी पर निर्भर है। प्रकृति में जब भी कोई चीज रुक जाती है तो वह सड़ने लगती है। जीवन में भी जिसे हम अक्सर आराम, विराम या विश्राम आदि कहते हैं, वह वास्तव में ठहराव है। हम जितना अधिक स्थिर रहेंगे, जीने की इच्छा उतनी ही कम होगी। जितना अधिक हम बैठे रहेंगे, उतनी ही जल्दी बूढ़े होंगे। हमें लगता है कि हम आराम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम अपने शरीर को जहर दे रहे हैं। हमारा खून धीमा पड़ जाता है, दिल पंप करना भूल जाता है। वजन बढ़ने लगता है, सिर्फ देह पर ही नहीं, बल्कि आत्मा पर भी।

जब हम स्वयं को एक चहारदीवारी में बंद रखते हैं तो हमारा शरीर खुद को ही खाने लगता है। मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं, हड्डियां भंगुर हो जाती हैं और दिमाग सुस्त पड़ जाता है। इस तरह हम निराशा और अवसाद को आमंत्रण दे बैठते हैं। मनोविज्ञान इसे 'मानसिक जुगाली' अर्थात 'छाया में सड़ना' कहता है। तब एक छोटी सी सैर भी हमे पहाड़ जैसी लगने लगती है। इसलिए नहीं कि हम आलसी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम 'जंग' खा चुके हैं।

वस्तुतः, ऊर्जा अनुभूति का भी विषय है और प्रायः इस अनुभूति के लिए अपने दायरे से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। यह वैज्ञानिक रूप से पुष्ट भी है कि ताजी हवा फेफड़ों को साफ करती है। धूप नींद को ठीक करती है। चलना दिल को दुरुस्त करता है। हमें यह मंत्र याद रखना होगा कि गति ही जीवन है, इसलिए स्वस्थ शरीर के लिए पैरों को और मन के लिए विचारों को चलायमान रखिए। यही दीर्घायु होने का मंत्र है।

डा. निर्मल जैन

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

भरोसा बढ़ाने वाला हस्तक्षेप

'लोकतंत्र में भरोसा बढ़ाने वाला निर्णय' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में हरबंश दीक्षित ने मतदाता सूची में शुद्धता की महत्ता को उचित रूप से रेखांकित किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंगाल में मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का निर्देश लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मतदाता सूची की शुद्धता ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला है। यदि सूची में त्रुटियां हों तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। न्यायालय का यह हस्तक्षेप किसी प्रशासनिक कार्य में दखल नहीं, बल्कि संविधानप्रदत्त अधिकारों और नागरिकों के मताधिकार की रक्षा का प्रयास है। इससे यह संदेश जाता है कि लोकतंत्र में संस्थाएं सजग हैं और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह निर्णय नागरिकों के विश्वास को सुदृढ़ करता है तथा लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत बनाता है। ऐसे कदम लोकतंत्र की जड़ों को गहरा करते हैं और संविधान के प्रति आस्था को पुनर्स्थापित करते हैं।

हिमांशु शेखर, केसपा (गया जी)

जलवायु परिवर्तन अब हकीकत

फरवरी का महीना कभी सर्द हवाओं, हल्की धूप और पहाड़ों पर जमी बर्फ के लिए जाना जाता था, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग है। उत्तर से लेकर मध्य भारत तक तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर चल रहा है। कश्मीर घाटी, जिसे बर्फ और ठंड की धरती माना जाता है, वहां अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह फरवरी में असामान्य माना जा रहा है। 24 फरवरी 2016 को 20.6 डिग्री तापमान दर्ज हुआ था, लेकिन इस वर्ष उससे भी अधिक गर्मी ने रिकार्ड तोड़ दिया। श्रीनगर के मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डा. मुख्तार अहमद के अनुसार, इस बार कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं हुआ, जिससे सामान्य शीतकालीन वर्षा और बर्फबारी नहीं हो सकी। यह केवल एक मौसमी उतार-चढ़ाव नहीं, बल्कि वायुमंडलीय असंतुलन का संकेत है। गुलमर्ग और सोनमर्ग में हाल में हुई बर्फबारी लगभग पिघल चुकी है। बर्फ की कमी का असर पर्यटन और खेल गतिविधियों पर साफ दिखाई दे रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को पर्याप्त बर्फ नहीं मिल पा रही। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कृत्रिम बर्फ बनाने की व्यवस्था पर जोर दिया है। यह स्थिति दर्शाती है कि जलवायु परिवर्तन अब केवल वैज्ञानिक रिपोर्टों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जमीनी हकीकत बन चुका है। लेह और आसपास के क्षेत्रों में जनवरी और फरवरी में लगभग बर्फ नहीं गिरी। 17,582 फीट ऊंचे खारदुंग ला और चांग में सामान्य से 70 से 80 प्रतिशत कम बर्फबारी दर्ज की गई। हालांकि 14 हजार फीट पर स्थित पैंगोंग झील जमी हुई है और वहां न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश व राजस्थान में भी तापमान सामान्य से तीन से पांच डिग्री अधिक रहा। श्रीगंगानगर में फरवरी के अंतिम सप्ताह में अधिकतम तापमान 32 डिग्री न्यूनतम तापमान भी 14 डिग्री के आसपास रहा।

कांतिलाल मांडोत, नई दिल्ली

अवैध कब्जे का निस्तारण

संपादकीय आलेख 'अवैध कब्जे का निस्तारण' पढ़ा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर दशकों से जमे कब्जों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने एक बड़े मानवीय और कानूनी विवाद को केंद्र में ला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का कोई निहित कानूनी अधिकार नहीं है और रेलवे विकास परियोजनाओं के विस्तार के लिए यह जमीन खाली करना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, यह एक संवेदनशील मामला है जिसमें लगभग चार से पांच हजार परिवार 50 हजार से अधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं, जो एक बड़ा वोट बैंक है। सालों तक इन कब्जों को अनदेखा करना या उन्हें सरकारी सुविधाएं (बिजली, पानी, आधार) प्रदान करना राजनीतिक संरक्षण को दर्शाता है। अब चूंकि मामला कोर्ट के कड़े निर्देश (अतिक्रमण हटाने का) में है, इसलिए अब कार्रवाई की जा रही है। कानूनी विशेषज्ञों और जनसामान्य का मानना है कि यदि अतिक्रमण शुरुआती दिनों में ही रोक दिया जाता, तो आज 50 हजार लोगों के विस्थापन का "मानवीय संकट" उत्पन्न नहीं होता। कोर्ट ने कहा है कि कब्जाधारी अपनी शर्त पर जमीन पर नहीं बने रह सकते, लेकिन उनके पुनर्वास का इंतजाम राज्य को करना होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि विकास (रेलवे लाइन विस्तार) के लिए जमीन खाली की जाएगी। कोर्ट ने इन विस्थापित परिवारों को मार्च 2026 के अंत तक व्यावहारिक समाधान खोजने को कहा है।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

पोस्ट

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में हमास का उल्लेख किया। बहुत बढ़िया। आतंकवादियों, उनके संगठनों और संचालकों के नाम होते ही हैं और उन्हें बेनकाब करने एवं शर्मसार करने में कोई संकोच नहीं किया जाना चाहिए।

सुनंदा वशिष्ठ@sunandavashisht

दिल्ली के एक जज साहब के यहां से जले नोट बरामद हुए, मगर जज साहब पर केस तक दर्ज नहीं हो पाया। किसी आम व्यक्ति के यहां से उतने ही जले नोट मिले होते तो अंदाजा लगाइए क्या हो गया होता। अब भी लार्ड ने उस किताब को ही बैन कर दिया, जहां इन जैसों के भ्रष्टाचार की बात हो रही थी।

अनुरंजन झा@anuranjanj

पाठ्यपुस्तकों के लेखन से जुड़े लोगों को सामाजिक समूहों, राजनीतिक दलों, नेताओं, न्यायपालिका और डिजिटल मीडिया आदि के माध्यम से निरंतर दबाव में नहीं रखा जा सकता। किसी भी प्रकार की सामग्री को हटाने मात्र से देश की सच्चाई नहीं बदल जाती। बच्चे तो किसी न किसी माध्यम से बातें जान ही लेते हैं।

वसुधा वेणुगोपाल@Vasudha156

जनपथ

नेतनयाहू को मिला 'मोदी हग' का गिफ्ट,
दो देशों की दोस्ती हुई और भी लिफ्ट।
हुई और भी लिफ्ट दोऊ सुख-दुख के साथी,
हम दोनों को देख जले दुश्मन की छाती!
हो जाएंगे साफ सभी मारीच-सुबाहु,
यदि भारत के साथ रहेंगे नेतनयाहू!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन.नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा -201309 से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित
संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 224

अब कहीं से भी कभी भी, चुटकियों में लें रेलवे क्लेम

- रात-दिन कभी भी घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से क्लेम पाने का किया जा सकेगा दावा
- ई-फाइलिंग, डिजिटल रिकार्ड व आटोमेटिक नोटिस सिस्टम से मामलों का तेज होगा निपटारा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : रेल यात्रियों को मुआवजा पाना पहले से ज्यादा आसान होने जा रहा है। रेल हादसे, चोट, मौत या सामान के नुकसान की स्थिति में मुआवजा लेने के लिए रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल (आरसीटी) की बेंच में बार-बार जाने की जरूरत नहीं होगी। ई-आरसीटी सिस्टम के तहत देशभर की सभी 23 आरसीटी बेंच को आनलाइन प्लेटफार्म से जोड़ा जाएगा। यात्री या उनके स्वजन रात-दिन कभी भी घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से क्लेम पाने का दावा कर सकेंगे। जरूरी दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने 52 हफ्ते-52 सुधार अभियान के तहत दो बड़े बदलावों की घोषणा की। पहला आरसीटी की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा। दूसरा रेल टेक पालिसी के जरिये स्टार्टअप और नवाचार करने वालों को सीधे रेलवे से जोड़ा जाएगा।

अब तक लोगों को दिक्कत होती थी क्योंकि घटना किसी एक राज्य में होती थी और यात्री दूसरे राज्य का होता था। ऐसे में यह तय करना मुश्किल हो जाता था कि केस कहां दायर करें। सुनवाई की तारीख जानने, दस्तावेज जमा करने और आदेश की प्रति लेने में समय और पैसा दोनों खर्च होते थे।

रेल भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते अश्विनी वैष्णव ● प्रेट्र

नई डिजिटल व्यवस्था में केस की पूरी जानकारी आनलाइन रहेगी। जरूरत पड़ने पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल होने की सुविधा भी मिलेगी। रेल मंत्री का कहना है कि ई-फाइलिंग, डिजिटल रिकार्ड और आटोमेटिक नोटिस सिस्टम से मामलों का निपटारा तेज होगा। पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। आदेश और फैसले भी आनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे।

शोध संस्थान अपना समाधान कर सकते हैं प्रस्तावित : दूसरा बड़ा सुधार 'रेल टेक पालिसी' है। इसके तहत कोई भी स्टार्टअप, शोध संस्थान या उद्योग रेलवे से जुड़े किसी मुद्दे पर अपना समाधान प्रस्तावित कर सकता है। पहले की नीति में रेलवे स्वयं समस्या तय करता था और उसी पर समाधान मांगे जाते थे। नई नीति के तहत एआइ आधारित पहचान प्रणाली, कोच में आग का तुरंत पता लगाने वाली तकनीक, ड्रोन से टूटी पटरी की जांच और रेल ट्रैक पर तनाव की निगरानी जैसे समाधान प्रोत्साहित किए जाएंगे। प्रेट्र के अनुसार, रेल मंत्रालय ने बताया कि यात्रियों को व्यापक सेवाएं प्रदान करने वाले रेलवन एप ने लांच होने के करीब आठ माह में दो करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया है।

मूल कंटेंट बनाने वालों को उचित कीमत दें इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म्स : अश्विनी वैष्णव

- स्वैच्छिक रूप से नहीं किया तो निकालना होगा कानूनी हल
- व्यक्ति की सहमति से बनना चाहिए उसका सिंथेटिक वीडियो

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: इलेक्ट्रानिक्स एवं आइटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म्स से कहा है कि वे मूल कंटेंट बनाने वालों के साथ अपना राजस्व उचित रूप में साझा करे और उन्हें उसकी सही कीमत मिलनी चाहिए। इन प्लेटफार्म्स को जागरूक बनना चाहिए और समाज ने जो एक संस्थागत मूल्य का निर्माण किया है, उसके महत्व को भी समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इंटरनेट मीडिया स्वैच्छिक रूप से राजस्व साझेदारी में इस फार्मूले को नहीं अपनाता तो इसका कानूनी हल निकालना होगा। कई देशों ने ऐसा किया भी है। गुरुवार को एक कार्यक्रम में वैष्णव ने यह भी कहा कि डीपफेक या सिंथेटिक वीडियो बनाने से पहले उस व्यक्ति की सहमति लेनी चाहिए। इस दिशा में भी इंटरनेट मीडिया को काम करना चाहिए। इंटरनेट मीडिया के इस युग में दूरदराज इलाके में भी कंटेंट निर्माता हैं। उनके बनाए हुए कंटेंट को इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म्स पर विभिन्न रूपों में चलाकर राजस्व प्राप्त किया जाता है, लेकिन असली कंटेंट निर्माता को इसका उचित लाभ नहीं मिलता। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म्स पर भारत में सबसे अधिक रील व वीडियो देखे जा रहे हैं। इंस्टाग्राम प्लेटफार्म पर भारत के 40 करोड़ लोग हैं और इनमें 95% लोग रील देखते हैं। वैसे ही फेसबुक और एक्स प्लेटफार्म पर भी 60% से अधिक लोग रील देखते हैं।

वैष्णव ने यह भी कहा कि प्लेटफार्म पर चलने वाले सभी कंटेंट की जिम्मेदारी उसी प्लेटफार्म की होगी। आनलाइन प्लेटफार्म पर बच्चों की सुरक्षा या अन्य व्यक्ति की भी आनलाइन सुरक्षा की जिम्मेदारी प्लेटफार्म की है। वैसे ही किसी की आवाज, चेहरा या उसके व्यक्तित्व का इस्तेमाल करके अगर डीप फेक या सिंथेटिक वीडियो बनाया जाता है तो उस व्यक्ति से इजाजत लेनी चाहिए।

मोदी सरकार में शांतिपूर्ण विरोध भी अपराध: राहुल गांधी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में शांतिपूर्ण विरोध को भी अपराध की तरह देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में असहमति को दबाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और संवैधानिक तरीके से आवाज उठाने वालों को दमन का सामना करना पड़ रहा है।

एक्स पर पोस्ट में राहुल ने जोर देकर कहा कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र की आत्मा है। इसे दबाने से लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई नागरिक सरकार की नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करता है तो उसके हिस्से में लाठीचार्ज, मुकदमे और गिरफ्तारी आ जाती है।

एक नजर में

'द केरल स्टोरी 2-गोज बियांड' की रिलीज पर रोक

कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म "द केरल स्टोरी 2-गोज बियांड" की रिलीज पर 15 दिनों के लिए अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को प्रमाणित करते समय सोच-समझकर काम नहीं किया। फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होने वाली थी। (प्रेट्र)

सर्वसम्मति से राकांपा की अध्यक्ष बनीं सुनेत्रा पवार

मुंबई: महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए राकांपा ने गुरुवार को उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति से अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया। अध्यक्ष चुने जाते ही सुनेत्रा ने अपने पति अजीत पवार के सपनों के अनुसार पार्टी को पुनः राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलवाने का संकल्प दोहराया। (राब्यू)

भगवान की मूर्ति तोड़ने के आरोप में रोहिंग्या गिरफ्तार

हैदराबाद: हैदराबाद शहर के चंद्रायणगुट्टा थाना क्षेत्र में स्थित एक मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने और तांबे का बर्तन चोरी करने के आरोप में तीन रोहिंग्या नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार 24 फरवरी को बरकास इलाके के हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ और चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। (प्रेट्र)

एएसआइ की रिपोर्ट : भोजशाला में मंदिर और मूर्तियां तोड़कर बनाई गई थी मस्जिद

परिसर में बनी अब्दुल्ला शाह चंगाल के मकबरे के गेट पर लगा शिलालेख दे रहा गवाही

प्रेमविजय पाटिल ● नईदुनिया

- फारसी में मुद्रित बातों का पक्षकारों की सुविधा के लिए अंग्रेजी व हिंदी में अनुवाद
- रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 260 पर लिखा है सच, खिलजी के शिलालेख का उल्लेख

धार: मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में मंदिर और मठ था। इन्हें ध्वस्त करके वहां स्थापित मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया था। इसकी गवाही परिसर में बनाई गई अब्दुल्ला शाह चंगाल के मकबरे के गेट पर लगा एक शिलालेख दे रहा है। यह शिलालेख वर्ष 1436 से 1469 तक मालवा के सुल्तान रहे महमूद खिलजी का है। इस शिलालेख का उल्लेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में खंड चार के पृष्ठ संख्या 260 पर किया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस शिलालेख की 17वीं और 18वीं पक्तियों में लिखा है कि यहां पहले एक प्राचीन धार्मिक मंदिर और शैक्षणिक केंद्र (मठ) मौजूद था। उस स्थल पर देवताओं की मूर्तियां थीं, जिन्हें नष्ट कर दिया गया और इस स्थान को मस्जिद व मजार में परिवर्तित कर दिया गया।

भोजशाला के सरस्वती (वाग्देवी) मंदिर बनाम मौला कमाल दरगाह मस्जिद विवाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में विचाराधीन है। वर्ष 2024 में एएसआइ द्वारा 98 दिन तक किए गए भोजशाला परिसर के वैज्ञानिक सर्वे की 2189 पृष्ठों की रिपोर्ट पर हाई कोर्ट ने मंदिर और मस्जिद पक्ष से आपत्तियां मांगी हैं। मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को है।

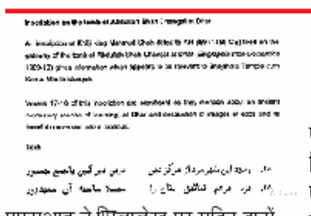
एएसआइ ने शिलालेख पर मुद्रित बातों का अंग्रेजी व फारसी में लिखा है ●

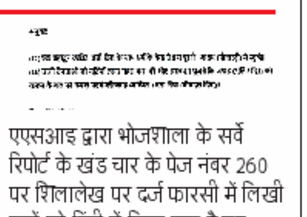
एएसआइ द्वारा भोजशाला के सर्वे रिपोर्ट के खंड चार के पेज नंबर 260 पर शिलालेख पर दर्ज फारसी में लिखी बातों को हिंदी में किया गया है यह अनुवाद ● सौ. एएसआइ की सर्वे रिपोर्ट

शिलालेख पर यह लिखा: एएसआइ ने सर्वे रिपोर्ट में शिलालेख पर फारसी में मुद्रित बातों का पक्षकारों की सुविधा के लिए अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद किया है। उसके अनुसार, खिलजी शासक महमूद शाह के शिलालेख की आयत 17-18, जो हिजरी वर्ष 859 (1455 ईस्वी) का है इसमें लिखा है- 'एक बहादुर व्यक्ति बड़ी सेना के साथ धर्म के केंद्र से इस पुराने आश्रम (मठ) में पहुंचा। उसने देवताओं की मूर्तियां तहस-नहस कर दीं और पूजने की जगह (मूर्तियों-मंदिर) को ताकत के बल पर नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद बना दिया।'

सर्वे रिपोर्ट में मंदिर के प्रमाण : सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, शिलालेख की लिखावट, परिसर में मिलीं मूर्तियों और वास्तुकला के अवशेष बताते हैं कि पत्थर की मूल संरचना को बाद में बदलकर मस्जिद बनाया गया। खिड़की के फ्रेम पर देवी-देवताओं की मूर्तियां अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में हैं। एक खंभे पर देवताओं की कटी-फटी आकृतियां हैं।

> भोजशाला का सच यही है कि इसके रूप को बदला गया। मंदिर को मस्जिद में बदलने के लिए इमारत को नुकसान पहुंचाया गया। -**डीके रिछारिया,** सेवानिवृत अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, धार

मंदिर पक्ष : शिलालेख इस बात की गवाही देता है कि यहां प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर मूर्तियों को नष्ट किया गया और बाद में मस्जिद में परिवर्तित किया गया। सर्वे का यह तथ्य भोजशाला को सरस्वती (वाग्देवी) मंदिर सिद्ध करने के पक्ष में महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं।
- **आशीष गोयल,** याचिकाकर्ता, मंदिर पक्ष

मस्जिद पक्ष : वर्ष 1903 और 1904 में एएसआइ के ही सर्वे में यह स्पष्ट रूप से तय किया गया था कि यह स्थान मस्जिद है और उसकी संरचना भी मस्जिद जैसी ही है। अब नए सर्वे रिपोर्ट में तथ्य बदले नजर आ रहे हैं।
- **अब्दुल समद,** सदर, कमाल मौलाना वेलफेयर कमेटी, धार

विस में उठा धार की वाग्देवी की प्रतिमा वापस लाने का मुद्दा

इस बीच, लंदन के म्यूजियम में रखी वाग्देवी (सरस्वती) की मूर्ति को भारत वापस लाने के मुद्दा गुरुवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में उठा। विधायक प्रताप ग्रेवाल द्वारा लिखित सवाल में पूछा गया कि प्रतिमा को वापस लाने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए। इस पर प्रदेश के संस्कृति विभाग के राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने लिखित जवाब में बताया कि इस संबंध में लगातार पत्राचार जारी है। गौरतलब है कि वाग्देवी की प्रतिमा 1930 में अंग्रेज अपने साथ ले गए थे और यह प्रतिमा फिलहाल लंदन के म्यूजियम में रखी है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने झारखंड व ओडिशा से मांगे 100-100 जज

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता: बंगाल में मतदाता सूची के एसआइआर के कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने कमर कस ली है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों का पालन करते हुए हाई कोर्ट ने पड़ोसी राज्यों-झारखंड और ओडिशा-से 100-100 न्यायिक अधिकारियों (जजों) की मांग की है। सूत्रों के अनुसार, गुरुवार को दोनों राज्यों के उच्च न्यायालयों को इस संबंध में औपचारिक पत्र भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डाटा संबंधी त्रुटियों के निपटारे की जिम्मेदारी कलकत्ता हाई कोर्ट को सौंपी थी। अब तक 532 जजों को इस काम में लगाया गया है। काम को देखते हुए और अधिक न्यायिक अधिकारियों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। 21 फरवरी की मध्यरात्रि तक डाटा संबंधी विसंगतियों के जो आंकड़े दिए गए थे, उन्हें ही अंतिम माना जाएगा।

बंगाल में नामांकन से ही निगरानी के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों का दल मौजूद रहेगा। सूत्रों के अनुसार, प्रत्येक विधानसभा की निगरानी के लिए कम से कम एक पर्यवेक्षक तैनात रहेगा। चुनाव आयोग ने पिछले चुनावों के अनुभव के आधार पर देखा है कि नामांकन से ही राज्य के कई स्थानों से अशांति की शिकायतें आने लगी थीं। राज्य में सबसे अधिक सुरक्षा घेरा उत्तर 24 परगना जिले में होगा, कुल 30 कंपनियां तैनात की जा रही हैं।

'सीमांचल से जल्द शुरू होगा घुसपैठिया मुक्त भारत अभियान'

- सीमांचल से तय किया बंगाल का एजेंडा, घुसपैठियों को बाहर निकालने का किया वादा
- भारत-नेपाल संबंधी मुद्दों पर सात सीमावर्ती जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठकें

बिहार में अररिया जिले के लेटी में एसएसबी जवानों को संबोधित करते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ● जागरण

जागरण संवाददाता, अररिया : घुसपैठ और सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध निर्माण के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीमांचल से घुसपैठिया मुक्त भारत अभियान जल्द शुरू होगा। सीमा के 10 किमी दायरे में बने अवैध निर्माणों को चिह्नित कर तत्काल ध्वस्त किया जाएगा। घुसपैठ रोकने के लिए व्यापक कार्ययोजना लागू की जाएगी। चुन-चुनकर घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाएगा। मोदी सरकार घुसपैठ का स्थायी समाधान करेगी। इसके साथ ही सीमांचल की धरती से बंगाल चुनाव का एजेंडा भी तय कर दिया। उन्होंने यह बातें सीमांचल के तीन दिवसीय दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को अररिया जिले के लेटी सीमा सशस्त्र बल (एसएसबी) कैंप में 170 करोड़ की योजनाओं के लोकार्पण व भूमिपूजन के मौके पर कही।

गृह मंत्री ने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव व घुसपैठ के मामले में बंगाल की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। भाजपा बिहार के तर्ज पर इन्हीं मुद्दों पर आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव में उतरेगी और जीतेगी। बंगाल में सरकार बनते ही घुसपैठ सरकार के पहले एजेंडे में होगा और सरकार गठन के साथ ही एक्शन शुरू होगा। केवल मतदाता सूची से नाम हटाने से घुसपैठ की समस्या का समाधान संभव नहीं है। घुसपैठिये न केवल हमारे चुनाव को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे हक के राशन और रोजगार पर भी डाका डालते हैं। लेटी एसएसबी कैंप से शाह सीधे अररिया पहुंचे और यहां कलेक्ट्रेट सभागार में भारत-नेपाल संबंधी मुद्दों पर सात सीमावर्ती जिलों के डीएम व एसपी, एसएसबी, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की।

अनिल अंबानी से नौ घंटे पूछताछ

पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय जाते अनिल अंबानी (दाएं) ● प्रेट्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : ईडी ने गुरुवार को रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी से उनके समूह की कंपनी आरकाम से जुड़े एक मनी लांड्रिंग मामले में नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। 66 वर्षीय उद्योगपति सुबह लगभग साढ़े दस बजे ईडी कार्यालय पहुंचे और रात लगभग सवा आठ बजे वहां से निकले। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें शुक्रवार को एक अलग मामले में जोकि यस बैंक के कथित ऋण धोखाधड़ी से संबंधित है, फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

जांच एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि अनिल अंबानी का बयान पीएमएलए के प्रविधानों के तहत दर्ज किया गया। यह जांच उनकी समूह की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकाम) द्वारा किए गए 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले से संबंधित है। अनिल अंबानी और उनके समूह की कई कंपनियों पर ऋण धोखाधड़ी के आरोप हैं। ईडी ने हाल ही में इन सभी मामलों की जांच के लिए एसआइटी का गठन किया है। ईडी ने बुधवार को मनी पीएमएलए के तहत अनिल अंबानी के मुंबई स्थित आवास 'एबोड' को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया था।

सीबीआइ ने की छापेमारी : सीबीआइ ने अनिल अंबानी और आरकाम के खिलाफ 2013-17 के दौरान बैंक आफ बड़ौदा को धोखा देने के आरोप में नया केस दर्ज किया है। यह मामला मंगलवार को बैंक से प्राप्त शिकायत के आधार पर शुरू हुआ। सीबीआइ ने अनिल के निवास और रिलायंस कम्युनिकेशंस के कार्यालयों पर छापे मारे व ऋण लेनदेन से संबंधित दस्तावेज बरामद किए। आरोप है कि आरकाम द्वारा लिए गए ऋणों के कारण बैंक को 2,220 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।

रंगों के उल्लास में झूमा नंदगांव...

ढोल-नगाड़ों की गूंज, रसिया गायन और पारंपरिक गाली गायन के मधुर परिहास के बीच हुरियारे और हुरियारिन रंगों में भींगकर झूम उठे। लठामार होली के उल्लास में एक ओर हुरियारिनों के हाथों से प्रेम पगे लठ बरसते रहे तो दूसरी ओर बरसाना से आए हुरियारे ढाल थामे उत्साह के साथ उनका सामना करते रहे। फाल्गुन शुक्ल दशमी पर गुरुवार को बरसाना के हुरियारे दोपहर ढाई बजे नंदगांव पहुंचे। वहां यशोदा कुंड पर उनका पारंपरिक स्वागत कर भांग के साथ स्वल्पाहार कराया गया। इसके बाद वह होली खेलने की अनुमति लेने दोपहर 3.30 बजे नंद भवन पहुंचे। जहां दोनों गांवों के गोस्वामी समाज के बीच पारंपरिक रसिया गायन हुआ। हुरियारिनों ने लठ बरसाने शुरू कर दिए और पांच बजे लठामार होली अपने चरम पर पहुंच गईं ● जागरण

पुलिस को सौंपी बच्चों के मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट, आज हाई कोर्ट में सुनवाई

जागरण संवाददाता, प्रयागराज: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद समेत अन्य के खिलाफ दर्ज मुकदमे की विवेचना को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने पीड़ित बच्चों का टीबी सप्रू अस्पताल में मेडिकल टेस्ट करवाया। गुरुवार को डाक्टरों की ओर से पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट बंद लिफाफे में दी गई। शुक्रवार को हाई कोर्ट में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मामले में सुनवाई होनी है। प्रकरण से जुड़े सभी तथ्यों व साक्ष्यों की प्रमाणिकता के आधार पर पुलिस कार्रवाई किए जाने की बात कह रही है।

कोर्ट के आदेश और आशुतोष ब्रह्मचारी की तहरीर पर झूंसी पुलिस ने अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य व तीन अज्ञात के खिलाफ कुकर्म, धमकी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने दो दिन में दोनों पीड़ित बच्चों का बयान दर्ज किया और फिर कोर्ट में बयान करवाया। बुधवार को पुलिस पीड़ितों को सीएचसी बनी सरायइनायत लेकर गई, जहां से डाक्टरों ने नाबालिग होने के कारण टीबी सप्रू अस्पताल भेजा। टीबी सप्रू अस्पताल में डाक्टरों ने मेडिकल टेस्ट किया। गुरुवार को मेडिकल रिपोर्ट पुलिस के पास बंद लिफाफे में भेजी गई। अब उस रिपोर्ट को विवेचना अधिकारी केस डायरी में शामिल करेंगे और कोर्ट में पेश करेंगे। डीसीपी सिटी मनीष शांडिल्य का कहना है कि पीड़ित बच्चों का मेडिकल और बयान दर्ज कराया जा चुका है। आगे की विवेचना चल रही है।

'यूपी पुलिस ने आशुतोष ब्रह्मचारी को प्रवक्ता बना लिया है'

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठाया है कि क्या यूपी पुलिस ने आशुतोष ब्रह्मचारी को अपना प्रवक्ता बना लिया है। उनके ऊपर शोषण मामले में जो

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद

गोपनीय रिपोर्ट है, वह पत्रकारवार्ता कर किस हैसियत से उसे सार्वजनिक कर रहे हैं। उन्हें पुलिस की ओर से कराई गई जांच कैसे मिली। इससे यह संदेश जाता है कि यूपी पुलिस के जांच अधिकारी शिकायतकर्ता से मिले हुए हैं। ऐसे में जांच की निष्पक्षता संदेह के घेरे में है। गुरुवार को श्रीविद्या मठ में पत्रकारों साथ अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने स्विमिंग पूल और पांच मंजिला भवन होने के आरोप का खंडन किया। कहा कि 1995 में ज्योतिष द्वारका शारदा पीठाधीश्वर मेरे गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने इस मठ का निर्माण अपने गुरु की इच्छा को पूरा करने के लिए कराया।

सड़क सुरक्षा में जोड़े जाएंगे सांसद, अधिकारी

- अधिक सड़क हादसों वाले सौ जिलों के मंत्रियों, सांसदों के साथ बैठक करेगी सरकार
- जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को सड़क सुरक्षा के उपाय के साथ जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: सड़क हादसों को कम करने के तमाम प्रयासों की विफलता के बीच सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अब नई योजना पर काम कर रहा है। मंत्रालय ने देशभर से ऐसे सौ जिले चिन्हित किए हैं, जहां सड़क हादसे अधिक होते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तय किया है कि एक माह के भीतर दिल्ली में इन सौ जिलों के कलेक्टरों का सम्मेलन बुलाया जाएगा। संबंधित सांसदों और मंत्रियों को भी बुलाकर उन्हें न सिर्फ सड़क सुरक्षा के उपाय सुझाए जाएंगे, जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कन्फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआइआइ) के सड़क सुरक्षा सम्मेलन में सड़क हादसों के लिए खराब रोड इंजीनियरिंग के साथ ही कमजोर एनफोर्समेंट को जिम्मेदार ठहराया। मंत्रालय की ओर से किए जा रहे तमाम प्रयासों का उल्लेख करने के साथ ही केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि उनके संसदीय क्षेत्र नागपुर में एक पुलिस अधीक्षक ने सड़क हादसों को लेकर संवेदनशीलता दिखाई। खुद प्रयास कर ब्लैक स्पाट चिन्हित कर विशेषज्ञों के द्वारा उनके समाधान के तरीके तलाशे। इस प्रयास के कारण उस क्षेत्र में सड़क हादसों में 50% की कमी आई है।

सीआइआइ के सड़क सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते नितिन गडकरी ● प्रेट्र

'ग्रेड' आधारित ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली लाने की तैयारी

प्रेट्र के अनुसार, सरकार सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जिम्मेदारी से वाहन चलाने को बढ़ावा देने के लिए 'ग्रेड' आधारित ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली लागू करने की योजना बना रही है। इसके तहत यातायात नियमों के उल्लंघन पर अंक काटे जाएंगे और गंभीर या बार-बार उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकेगा। गडकरी ने कहा कि देश में हर वर्ष करीब 1.8 लाख लोगों की मौत मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए वाहन चलाने, तेज रफ्तार, गलत दिशा में जाने या नशे में गाड़ी चलाने जैसे कारणों से होती है।

विमानन नियामक संस्था डीजीसीए 38 सलाहकारों की नियुक्ति करेगी

नई दिल्ली, प्रेट्र : विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कर्मचारियों की भारी कमी से निपटने के लिए 38 सलाहकारों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। यह निर्णय नियामक की कार्यक्षमता बढ़ाने और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। डीजीसीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, उड़ान योग्यता निदेशालय में 24 पद, विमान सुरक्षा निदेशालय में छह, अंतरराष्ट्रीय संबंध और कानूनी मामले के लिए सात पद (पांच वरिष्ठ सलाहकार और दो सलाहकार), और फ्लाइंग ट्रेनिंग निदेशालय में एक पद भरे जाएंगे। यह भर्ती अभियान विमानन क्षेत्र की सुरक्षा और निगरानी को सुदृढ़ करने की दिशा में एक तात्कालिक कदम है। ये सभी नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर होंगी।

भोर में उठना सफलता की गारंटी नहीं, सबका शरीर अलग

- जीन तय करते हैं कि आप भोर में उठने वाले होंगे या देर से
- जैविक घड़ी से मेल खाने वाली दिनचर्या दिलाएगी बेहतर नतीजे

लंदन, द कन्वर्सेशन: लंबे समय से यह माना जाता है कि भोर में उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है और जीवन में बड़ी सफलता हासिल करता है। इंटरनेट मीडिया पर भी ऐसे संदेशों की भरमार है, जो बताते हैं कि सूर्योदय से पहले दिन की शुरुआत करने का मतलब है कि आपने आधी जंग पहले ही जीत ली है। एपल के सीईओ टिम कुक, सफल उद्यमी रिचर्ड ब्रैनसन और हालीवुड एक्टर जेनिफर एनिस्टन जैसे बड़े नाम भी गिनाए जाते हैं, जो दिन की शुरुआत जल्दी करते हैं। संदेश साफ है। भोर में उठने का मतलब है कि आपकी सफलता तय है लेकिन विज्ञान ऐसा नहीं मानता। शोध बताते हैं लोग आमतौर पर बेहतर प्रदर्शन तब करते हैं, जब उनकी दिनचर्या उनके शरीर की प्राकृतिक घड़ी से मेल खाती है। बहुत से लोगों का शरीर ऐसा हो सकता है, जो सुबह पांच बजे उठना स्वीकार न करे। ऐसा करने से उनकी सेहत और उत्पादकता दोनों पर बुरा असर पड़ सकता है। काफी कुछ व्यक्ति विशेष की जैविक रिदम या क्रोनोटाइप पर निर्भर करता है।

मार्निंग टाइप वालों का बेहतर होता है प्रदर्शन

अध्ययनों में क्रोनोटाइप के बीच अंतर भी सामने आया है। मार्निंग टाइप वाले व्यक्तियों का अकादमिक प्रदर्शन आम तौर पर अच्छा रहता है। ऐसे लोग स्मोकिंग, शराब और मादक द्रव्यों के सेवन से भी दूर रहते हैं और नियमित व्यायाम भी करते हैं।

इवनिंग टाइप वालों का शारीरिक स्वास्थ्य हो सकता है खराब

इवनिंग टाइप के लोगों के साथ इस बात की संभावना अधिक रहती है कि वह काम से बुरी तरह से ऊब जाएं। उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। इवनिंग टाइप वालों की कामकाजी जिंदगी भी कम व्यवस्थित होती है। इससे उनको नींद न पूरी होने, थकान और तनाव का सामना करना पड़ सकता है।

अनुवांशिकी तय करती है आपका टाइप: क्रोनोटाइप दो तरह का होता है। एक है मार्निंग टाइप और दूसरा है इवनिंग टाइप। मार्निंग टाइप वाले लोग भोर में उठ जाते हैं व अलर्ट महसूस करते हैं। वहीं, इवनिंग टाइप वाले व्यक्ति दोपहर बाद ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं।

आम धारणा है कि सुबह जल्दी उठने की दिनचर्या अपनाने से आपको वही फायदे मिल सकते हैं जो मार्निंग टाइप के लोगों को मिलते हैं। क्रोनोटाइप आसानी से नहीं बदलता है। इसे आपकी अनुवांशिकी और सर्केडियन रिदम यानी शरीर की प्राकृतिक घड़ी आकार देती है। बहुत से इवनिंग टाइप वाले लोग अगर अपनी प्राकृतिक रिदम के विपरीत जाकर सुबह जल्दी उठते हैं तो उनको समय के साथ नींद पूरी न होने, एकाग्रता में कमी और खराब मूड जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

चिंतन

रचनात्मक स्वतंत्रता व सामाजिक संवेदनशीलता के बीच हो संतुलन

केरल उच्च न्यायालय ने फिल्म 'केरला स्टोरी 2' की रिलीज पर रोक लगा दी और सेंसर बोर्ड को कहा है कि वह इसे दिए गए प्रमाणपत्र की पुनः समीक्षा करे। असल में फिल्मों के नाम व कथानक को लेकर भारत में विवाद कोई नया नहीं है। हाल ही में एक फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल पर भी तीखा विवाद हुआ था और निर्माता द्वारा नाम बदलने के बाद ही यह मामला शांत हुआ। शायद ही कोई कला माध्यम सिनेमा जितनी तीव्र सार्वजनिक बहस को जन्म देता हो। फिल्में केवल मनोरंजन नहीं करतीं, वे इतिहास की व्याख्या करती हैं, संस्कृति को आकार देती हैं और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं भी उत्पन्न करती हैं। इसी कारण फिल्मों को लेकर विवाद इस माध्यम की प्रकृति का हिस्सा हैं। राजनीतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय व जातीय विषयों वाली फिल्में अक्सर व्यापक सामाजिक तनावों का केंद्र बन जाती हैं। ताजा विवाद भी कुछ इसी तरह का है। मामले में याचिकाकर्ता का तर्क था कि फिल्म विभिन्न राज्यों की महिलाओं के बारे में है, जिन्हें कथित रूप से फुसलाकर धार्मिक परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन फिल्म का शीर्षक केरला स्टोरी 2 है, जिससे कथित तौर पर जबरन धर्मांतरण के विषय को केरल राज्य से जोड़कर प्रस्तुत किया गया है। यह भी आरोप लगाया गया कि यह फिल्म कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा कर सकती है। यह फिल्म एक भ्रामक क्षेत्रीय संबंध स्थापित करती है और केरल के लोगों की गरिमा एवं प्रतिष्ठा को कमजोर करती है। देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहस का विषय रही है। इसे लेकर अनेक बार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैरोकारों के बीच विरोधाभास भी देखने को मिला है। दरअसल, लोग अपनी सुविधा के हिसाब से इस स्वतंत्रता का पक्ष लेते रहे हैं। सिनेमा के क्षेत्र में ऐसा होना कोई अपवाद नहीं है। अधिकांश फिल्म विवादों के मूल में एक केंद्रीय मुद्दा होता है व्याख्या। एक फिल्मकार की दृष्टि अक्सर जनता की धारणा से टकरा जाती है। जब दर्शकों को लगता है कि किसी फिल्म में उनकी पहचान, इतिहास या मूल्यों का गलत चित्रण किया गया है तो विरोध स्वाभाविक हो जाता है। उदाहरण के तौर पर ऐतिहासिक विषय पर बनी फिल्म पद्मावत को रिलीज से पहले ही भारी विरोध का सामना करना पड़ा। यह विरोध फिल्म की वास्तविक सामग्री से अधिक सांस्कृतिक विकृति की आशंका पर आधारित था। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि आजकल विवाद अक्सर फिल्म देखने से पहले ही राजनीतिक और सामाजिक आशंकाओं के कारण खड़े हो जाते हैं। राजनीतिक विषयों पर आधारित फिल्में भी तीखी प्रतिक्रियाओं को जन्म देती हैं। द कश्मीर फाइल्स इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसने भारत में गहन राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया। समर्थकों ने इसे ऐतिहासिक पीड़ा का सशक्त चित्रण बताया, जबकि आलोचकों ने इसके कथानक और राजनीतिक दृष्टिकोण पर प्रश्न उठाए। इससे स्पष्ट होता है कि सिनेमा अब केवल कला का माध्यम नहीं, बल्कि वैचारिक विमर्श का मंच भी बन गया है। सोशल मीडिया ने इन विवादों को और अधिक तेज और व्यापक बना दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जैसी संस्थाओं का दायित्व रचनात्मक स्वतंत्रता और सामाजिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाना है, लेकिन उनके निर्णयों की अक्सर दोनों पक्षों से आलोचना होती है। कभी अधिक सख्ती के लिए तो कभी ढील देने के लिए। यह द्वंद्व हमारे समाज की जटिलता को दर्शाता है। हालांकि, कई बार ऐसे विवाद समाज में आवश्यक संवाद को जन्म देते हैं।

विश्लेषण

ऋतुपर्ण दवे

क्या ट्रंप सबसे विवादित राष्ट्रपति कहलाएंगे

न्याय तो न्याय होता है फिर वो अपनों के लिए हो या गैरों के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह भी नागवार गुजरा, जब वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कानून की हद और जद में वो फैसला सुनाया, जो उनके खिलाफ था। दरअसल अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट में अदालतों की नियुक्ति वहां के राष्ट्रपति करते हैं जो कि आजीवन या जब तक जज सक्षम, स्वस्थ और सक्रिय रहें, तब तक के लिए होती है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के पहले कार्यकाल के नियुक्त तीन जज थे। इनसे ट्रंप पूरे भरोसे में थे, इतने कि उन्हें अपनी जागीर समझ बैठे। फैसला उनके खिलाफ भला कैसे जाएगा? लेकिन वो ये भूल गए कि जजों ने न्याय करने की शपथ ली थी न कि ट्रंप के हितों की रक्षा की। फैसला आते ही उन्होंने जिन शब्दों में सुप्रीम कोर्ट और खिलाफ फैसला देने वाले जजों पर आरोप लगाए तो निश्चित रूप से अमेरिका की पूरी न्याय प्रणाली पर कटाक्ष था, जो बेहद निंदनीय है। इसी तरह हालिया भारत-पाक युद्ध को रोकने को लेकर अनगिनत बार एकतरफा बोलने वाले ट्रंप इस बार तो इतना कह गए कि यदि वो दोनों का परमाणु युद्ध नहीं रुकवाते तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती।

वाकई ट्रंप, ट्रंप ही हैं और वो अमेरिका के राष्ट्रपति कम, कई बार राष्ट्रविद्रोही की भूमिका में ज्यादा नजर आने लगते हैं। दुनिया भर में इस फैसले की चर्चा इसलिए भी हो रही है कि वहां के सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से इसे असंवैधानिक करार दिया। इसमें ट्रंप के नियुक्त जजों ने भी अहम भूमिका निभाई। 6-3 के बहुमत से ट्रंप टैरिफ को असंवैधानिक करार देते हुए 1977 के आईईईपीए कानून यानी 'अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम' (इंटरनेशनल इमरजेंसी इकॉनामिक पॉवर ऐक्ट) का हवाला दिया। यह वो अमेरिकी कानून है जो राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विदेशी खतरों से निपटने के लिए आर्थिक लेनदेन, आयात-निर्यात और संपत्ति को विनियमित करने का अधिकार देता है। जबकि अमेरिका में ऐसी स्थिति नहीं है। बिना कांग्रेस की सहमति लिए जिद्दी ट्रंप ने दुनिया भर में मनमाने टैरिफ ठोंक दिए। इससे भारत भी अछूता नहीं रहा। फैसला आते ही कुछ देर में ट्रंप ने प्रेस कांफ्रेंस की, जिसमें फैसले की न केवल आलोचना की बल्कि विरोध में फैसला देने वाले खुद के नियुक्त जजों को जमकर कोसा, लताड़ा भी। कोर्ट पर मनमाने आरोप भी लगाए और कहा कि अदालत विदेशी हितों और ऐसे राजनीतिक आंदोलनों से प्रभावित है, जो लोगों की सोच से छोटे हैं। फैसले को अपने चुनाव परिणाम से जोड़ते हुए कहा कि मैं लाखों वोटों से जीता फिर भी धोखाधड़ी हुई, नहीं तो अंतर और बढ़ता बावजूद इसके भारी मतों से जीता। उन्होंने यहां तक कहा कि जो लोग बुरे, अनजान और शोर मचाने वाले हैं, वो चिल्लाकर बोलते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ जज इससे डर गए और सही काम नहीं करना चाहते। जस्टिस गोरसच और जस्टिस बैरेट जो ट्रंप के द्वारा नियुक्त थे, ने भी खिलाफ में फैसला दिया, जबकि ब्रेट कैवनॉघ ट्रंप द्वारा नियुक्त वो जज थे, जिन्होंने पक्ष में फैसला सुनाया। मुख्य न्यायधीश जॉन रॉबर्ट्स द्वारा लिखे गए फैसले के कुछ घंटे बाद ट्रंप ने बौखलाहट भरी प्रतिक्रियाएं दीं कि टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद निराशाजनक है। कोर्ट के कुछ सदस्यों पर शर्म आ रही

है, जो देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं कर पाए। निश्चित रूप इससे ट्रंप की साख गिरी है, न कि अमेरिकी सुप्रीम अदालत की। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स के साथ बहुमत में न्यायाधीश नील गोरसच और एमी कोनी बैरेट भी शामिल थे। इनकी नियुक्ति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में की थी। सहमति जताने वालों में न्यायाधीश क्लेरेंस थामस, सैमुअल एलिटो और ब्रेट कैवना थे जिनमें कैवना को ट्रंप ने नियुक्त किया था। इन्होंने असहमति मत में लिखा कि वास्तव में टैरिफ आयात को नियंत्रित करने का पारंपरिक और सामान्य उपकरण है तथा आईईईपीए का पाठ, इतिहास तथा पूर्व की तमाम मिसालें प्रशासन के पक्ष का समर्थन करती हैं। जज कैवना ने चेतावनी दी कि इस निर्णय से चीन, ब्रिटेन और जापान जैसे देशों के साथ हुए व्यापार समझौतों पर अनिश्चितता पैदा हो सकती है। हालांकि फैसले में यह साफ नहीं है कि कंपनियों को उन अरबों डॉलर का रिफंड मिलेगा या नहीं, जो दिसंबर 2025 तक ही अमेरिकी खजाने में करीब 133 अरब डॉलर से अधिक जमा हो चुके हैं। इनमें कुछ कंपनियां पहले ही निचली अदालतों में रिफंड का दावा पेश कर चुकी हैं। निश्चित रूप से ट्रंप की स्थिति बहुत मजाक वाली हो गई है। कहीं न कहीं वो हाशिए पर भी हैं। ट्रंप की खिसियाहट इसी से समझ आती है कि एक तो उन्होंने अदालत को भला-बुरा कह कर दुनिया को चौंकाया और यहां तक कि उनके द्वारा नियुक्त विरोध में फैसले देने वाले न्यायाधीशों को देश द्रोही और परिवार में कैसे मुंह दिखाएंगे, तक कह दिया। लगता है कि ट्रंप को न्याय में विश्वास नहीं है और देर-सबेर अमेरिका में यह मांग भी उठेगी कि भारत सहित तमाम देशों की न्याय पालिका के समान वाली साफ और निष्पक्ष व्यवस्था अमेरिका में भी हो, जिससे नियुक्त न्यायाधीश बिना किसी के दबाव में न्याय हित में काम कर सकें। हां, ट्रंप का एक और सुन्दर सपना टूट जरूर गया है लेकिन ट्रंप और विवादों का चोली-दामन का रिश्ता कब और क्या, कुछ नया कर दे, कोई नहीं जानता। फिलाहाल ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ लगाकर, जब चाहें तब बदलकर अपने ही देश की सर्वोच्च अदालत को एक तरह से चुनौती दे डाली। इससे पहले शांति का नोबल पुरस्कार न मिलने पर उनकी हरकतों को दुनिया ने देखा। यह सब उनके पद और गरिमा को देखकर अनुकूल नहीं था। लगता है वो अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति जरूर बनने की ओर हैं जो सबसे विवादित, सनकी, नासमझ और तानाशाह कहलाएंगे। बता दें कि, व्हाइट हाउस में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ एक संयुक्त प्रेस कार्यक्रम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एक महिला पत्रकार से सवाल पूछने के लिए कहा। जब पत्रकार ने चीन की लैटिन अमेरिका में बढ़ती उपस्थिति को लेकर अमेरिका की भूमिका पर एक सवाल किया, तो ट्रंप ने जवाब देने के बजाय उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस की ओर मुड़कर कहा, 'मुझे बस उनकी बातें सुनना अच्छा लगता है।' इसके बाद दोनों को हंसते हुए देखा गया, और फिर ट्रंप ने वापस पत्रकार की ओर मुड़कर कहा, 'बशाबाश...शाबाश...शुक्रिया, डार्लिंग।' यह वीडियो ऑनलाइन तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने ट्रंप को आड़े हाथों लिया।

इससे पहले, ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को दिए गए एक अटपटे कॉम्प्लीमेंट को लेकर भी सुर्खियां बटोरी थीं। शर्म अल-शेख में एक गाजा शांति शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक नेताओं को धन्यवाद देते समय ट्रंप ने मेलोनी की ख़ूबसूरतीऱ पर जोर दिया और पूछा कि क्या वह इस तारीफ से नाराज तो नहीं हैं। बहरहाल, ऐसे खिसियाए ट्रंप को देखकर लोग यही कह रहे हैं 'जिन्हें हम हार समझे थे गले अपने लगाने को, वही काले नाग बन बैठे हमें ही काट खाने को।'

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

शहीदी दिवस

सुनील कुमार महला

चंद्रशेखर आज़ाद : क्रांति, साहस व आत्मसम्मान की अमर गाथा

महान क्रांतिकारी, अदम्य साहस, अटूट देशभक्ति और आत्मसम्मान के प्रतीक चंद्रशेखर आज़ाद का आज 27 फरवरी को शहीद दिवस है। वर्ष 1931 में इसी दिन उन्होंने इलाहाबाद (अब प्रयागराज) के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क (तत्कालीन अल्फ्रेड पार्क) में अंग्रेजों से घिर जाने पर वीरगति प्राप्त की। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में हुआ तथा उनका बचपन झाबुआ जिले के भाबरा गांव में बीता, जहां उनके अधिकांश मित्र भील जनजाति के बालक थे। उनके साथ रहते हुए उन्होंने बचपन में ही धनुष-बाण चलाने में दक्षता हासिल कर ली, जो आगे चलकर उनकी अचूक निशानेबाजी का आधार बनी। इनका वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी था और 'आज़ाद' नाम उन्होंने स्वयं अदालत में घोषित किया था। दिसंबर 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने अपना नाम 'आज़ाद', पिता का नाम 'स्वतंत्रता' और पता 'जेलखाना' बताया। सजा के रूप में उन्हें 15 कोड़े लगाए गए, जिसके बाद से वे 'आज़ाद' के नाम से प्रसिद्ध हो गए।

उनकी माता जगरानी देवी चाहती थीं कि वे संस्कृत के विद्वान बनें, इसलिए उन्हें पढ़ाई के लिए वाराणसी के काशी विद्यापीठ भेजा गया, किंतु जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनकी सोच बदल दी और वे क्रांतिकारी मार्ग पर चल पड़े। उनकी जुबां पर अक्सर एक शेर रहता था-'दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे।' आज़ाद ने शपथ ली थी कि वे कभी अंग्रेजों के हाथ जीवित नहीं पकड़े जाएंगे और उन्होंने अंत तक अपने इस वचन को निभाया भी। वे भेष बदलने की कला में अत्यंत निपुण थे तथा कई बार पुलिस के सामने से निकल गए और उन्हें पता भी नहीं चला। पुलिस से बचने के लिए वे साधु/संन्यासी बनकर भी रहे और बच्चों को पढ़ाया। झांसी के पास ओरछा के जंगलों में उन्होंने 'पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी' नाम से संन्यासी रूप में निवास किया तथा साथियों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी दिया। उनकी फुर्ती और तेज दिमाग के कारण साथी उन्हें 'क्विक सिल्वर' (पारा) कहते थे। वे क्रांतिकारी संगठन के वरिष्ठ नेता थे और युवाओं को प्रशिक्षण देते थे, जिनमें भगत सिंह भी शामिल थे। भगत सिंह उन्हें सम्मान से 'पंडित जी' कहते थे। दोनों की जोड़ी को 'आग और हवा' की तरह माना जाता था, जहां भगत सिंह वैचारिक रूप से गहरे थे, वहीं आज़ाद संगठन संचालन और क्रांतिकारी कार्रवाई में निपुण थे। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित किए जाने के बाद वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (एचआरए) से जुड़े। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने हेतु 1925 में काकोरी ट्रेन कार्रवाई की गई। बाद में संगठन का पुनर्गठन कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (एचएसआरए) बनाया गया, जिसकी स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर और जोगेश चंद्र चटर्जी सहित अन्य साथियों ने की। उल्लेखनीय है कि आज़ाद 1929 में लॉर्ड इरविन की ट्रेन पर बम फेंकने की योजना में भी शामिल थे। 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने अपने साथी सुखदेव राज को सुरक्षित निकल जाने का अवसर दिया और स्वयं लगभग 40 मिनट तक अकेले पुलिस से लोहा लेते रहे। उस समय उनके पास केवल एक छोटी कोल्ट पिस्तौल थी। जब अंतिम गोली बची तो अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए उन्होंने स्वयं को गोली मार ली और वीरगति प्राप्त की। जानकारी मिलती है कि उनकी मृत्यु के बाद भी ब्रिटिश पुलिस उनके पास जाने से डर रही थी। पुष्टि करने के लिए दूर से उनके शरीर पर गोलियां चलाई गईं, तब जाकर वे पास पहुंचे। आज़ाद अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि कई बार संगठन के लिए धन बचाने हेतु स्वयं भूखे रह जाते थे, लेकिन अपने साथियों की जरूरतें वे पहले पूरी करते थे। उनकी शहादत के बाद काफी समय तक उनकी माता को पूरी जानकारी नहीं दी गई थी, ताकि उन्हें गहरा सदमा न पहुंचे। निष्कर्षतः चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना सम्पूर्ण जीवन राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने युवाओं को यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता, स्वाभिमान और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि दृढ़ संकल्प, त्याग और साहस से असंभव प्रतीत होने वाले लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं।

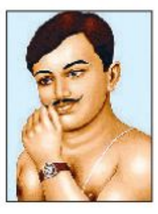

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

साधना से ही मिलता है वास्तविक सुख

संकलित

दर्शन

अधिकांश व्यक्ति आज भौतिक मूल्यों के उपासक बन गए हैं। इस कारण जीवन के धर्म एवं मर्म को भुला बैठे हैं। उनकी इस उपासना ने दुनिया के बाह्य जगत को बड़ा सुहावना, लुभावना और आकर्षक बना दिया है। जबकि वास्तविक सुख आंतरिक सौंदर्य, अंतर्जगत की जागृति एवं अंतर्यात्रा से ही संभव है। भौतिक आकर्षण के पीछे मनुष्य दौड़ रहा है। यदि वह क्षण भर रुककर गंभीरता से सोचे तो उसे पता चलेगा कि यह सब भ्रम जाल है। जीवन वह नहीं, जिसे वह जी रहा है। संत एकनाथ ने कहा है कि धन जोड़कर भक्ति का दिखावा करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि ऐसा करने से मन में वासना और भी बढ़ जाएगी और जिनका चित्त वासना में फंसा हुआ है, उन्हें अंतरात्मा के दर्शन कैसे हो सकते हैं। वास्तविक सुख पाने के लिए व्यक्ति भक्ति यानी साधना की ओर प्रवृत्त होता है। स्थायी सुख की प्राप्ति भक्ति पर ही निर्भर है। भक्ति से मन को वश में करना है और मन को वश में करने का सरल उपाय है उसे परमात्मा के हेतु निरंतर भले कार्यों में लगाए रखना। महात्मा गांधी ने प्रेमा बहन के नाम लिखे पत्र में लिखा है-जो लोग कृष्ण-कृष्ण कहते हैं वे उसके पुजारी नहीं हैं। जो उनका काम करते हैं, वे ही पुजारी हैं। रोटी-रोटी कहने से पेट नहीं भरता, अपितु रोटी खाने से ही भरता है। मन को वश में लाने का अभ्यास अनेक प्रकार का होता है। इन अभ्यासों को ही भक्ति यानी साधना कहा गया है। जिस व्यक्ति ने स्वयं को शांति-अशांति, मान-अपमान और सुख-दुख से निर्लिप्त बना लिया है, वही निर्विघ्न शांति में स्थित रह सकता है।

गरीब विद्वान व राजा भोज, बने भाई-भाई

संकलित

प्रेरणा

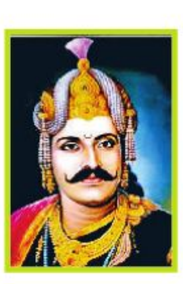

कई वर्ष पहले धार में राजा भोज का शासन था। उस राज्य में एक गरीब विद्वान रहता था। आर्थिक तंगी से घबराकर एक दिन विद्वान की पत्नी ने उससे कहा-आप राजा भोज के पास क्यों नहीं जाते? वह विद्वानों का बड़ा आदर करते हैं। हो सकता है आपकी विद्वता से प्रभावित होकर वह आपको ढेर सारा धन दे दें। विद्वान राजा के दरबार में पहुंचा। पहरेदार ने पूछाः आप कौन हैं? कहां जाना है? विद्वान ने कहाः जाओ राजा से कहो कि उनका भाई आया है। पहरेदार ने जब भोज को यह बात बताई तो.. वह सोचने लगेः मेरा तो कोई भाई है नहीं है फिर कौन हो सकता है। कहीं कोई धूर्त तो नहीं। उनकी उत्सुकता जागी। उन्होंने विद्वान को बुलवा लिया। 'कैसे हुए भाई-भाई' भोज ने विद्वान से पूछाः क्या तुम मेरे भाई हो? किस नाते से? विद्वान ने कहाः मैं आपका मौसेरा भाई हूं। आपकी मौसी का लड़का। भोज ने पूछाः कैसे? मेरी तो कोई मौसी नहीं है। विद्वान बोलाः महाराज। आप संपत्ति माता के पुत्र हैं और मैं विपत्ति माता का पुत्र। संपत्ति और विपत्ति बहनें हैं। इस नाते मैं आपका मौसेरा भाई हुआ न। यह सुनकर भोज बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं विद्वान को दीं। फिर भोज ने पूछाः मेरी मौसी तो कुशल हैं न? इस पर विद्वान ने जवाब दियाः राजन्, जब तक आपकी मौसी जीवित थीं, आपके दर्शन नहीं हुए थे। अब आपके दर्शन हुए तो आपकी मौसी स्वर्ग सिधार गईं। इस उत्तर से भोज को और भी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विद्वान को गले से लगा लिया।

समय से पहले खिले फूल

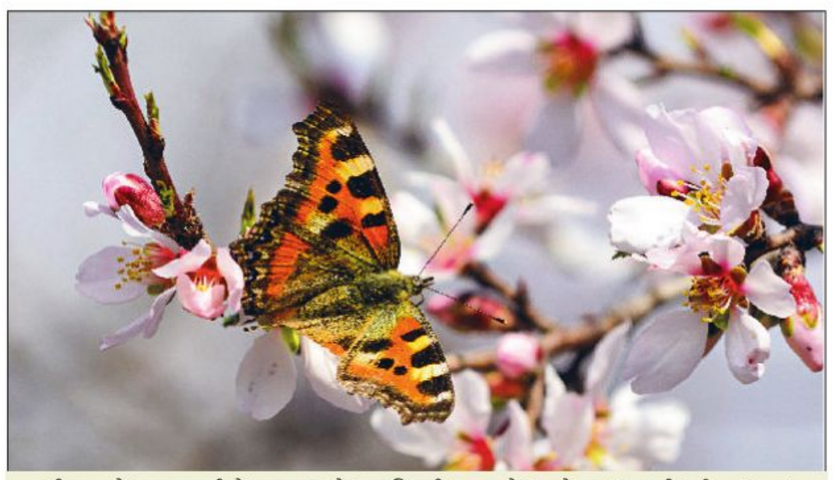

श्रीनगर के बादामवारी में गुरुवार को एक तितली बादाम के फूलों पर मंडराती हुई, इस साल पेड़ों पर असामान्य रूप से फूल जल्दी खिले हैं, जो मौसम के बदलते पैटर्न का संकेत है।

आज की पाती

विधायकों के भत्ते या फिजूलखर्ची

लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली सुविधाएं हमेशा चर्चा और बहस का विषय रही हैं। वेतन और भत्तों का मूल उद्देश्य यह माना जाता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि आर्थिक चिंता से मुक्त होकर जनता की सेवा कर सकें। लेकिन जब इन सुविधाओं का आकार बढ़ता है और उनके उपयोग में पारदर्शिता कम दिखाई देती है, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठते हैं। हाल ही में बिहार विधानसभा द्वारा विधायकों और विधान पार्षदों के लिए मासिक टेलीफोन भत्ता बढ़ाकर 8300 रुपए करने का निर्णय सामने आया है। इस फैसले की सबसे खास बात यह है कि यह राशि बिना किसी बिल या वाउचर के दी जाएगी। यानी खर्च का प्रमाण देना अनिवार्य नहीं होगा। यही कारण है कि यह विषय अचानक सार्वजनिक चर्चा का केंद्र बन गया है। - ललित बंझोर, रायपुर

ट्रेंड

मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स

हमारी सरकार ने गोंदिया-जबलपुर, पुनारख-किऊल और गम्हरिया-चांडिल के बीच तीन मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में आर्थिक विकास तेज होने के साथ-साथ रोजगार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

आतंकवाद स्वीकार नहीं

भारत और इजरायल पूरी तरह से स्पष्ट है कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में, आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता।हम कंधे-से-कंधा मिलाकर आतंकवाद और उनके समर्थकों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।

-पियुष गोयल, केंद्रीय उद्योग मंत्री

गोवा में मिला अवसर

गोवा ने हमें एक छोटा सा अवसर दिया है, हम पूरी ईमानदारी और क्षमता से काम कर रहे हैं। हमें पूरे राज्य की सेवा करने का मौका दीजिए, और हम शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सड़कें, बिजली और पानी जैसी व्यवस्थाओं में पंजाब की तर्ज पर बदलाव लाएंगे।

-अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम, नई दिल्ली

ट्रंप की धमकी

आप सब जानते हैं, रूस हमारा पुराना दोस्त, हमको तेल बेचता था, ईरान हमको तेल बेचता था, हम सस्ते में वहां से लेते थे, लेकिन ट्रंप ने धमकी दी और ये बोले- यस सर। ट्रंप जो कहते हैं उसको- यस सर।

-मल्लिकार्जुन खरगे, अध्यक्ष, कांग्रेस

करंट अफेयर

ब्रिटेन में हिंदू मंदिर के बंद होने का खतरा

पूर्वी ब्रिटेन के पीटरबरो शहर में एक परिसर में मौजूद 40 साल पुराने हिंदू मंदिर और कम्युनिटी सेंटर के बंद होने का डर है, क्योंकि स्थानीय प्राधिकारियों ने इस भवन को बेचने के फैसले को सही ठहराया है जो मंदिर के लिए किराये पर दिया गया है। भारत हिंदू समाज मंदिर की स्थापना 1986 में शहर के न्यू इंग्लैंड कॉम्प्लेक्स में हुई थी और कैमब्रिजशायर, नॉरफॉक तथा लिंकनशायर के बड़े इलाके के 13,000 से अधिक हिंदू यहां दर्शन करने आते हैं। मंदिर प्रशासन पीटरबरो सिटी काउंसिल से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करते हुए अभियान चला रहा है। इस महीने की शुरुआत में काउंसिल कैबिनेट की बैठक में यह कहा गया कि संपत्ति की बिक्री से करदाताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल्य दिलाने की उसकी कानूनी जिम्मेदारी/" है। वहीं, मंदिर ने एक बयान में कहा, हम भारत हिंदू समाज से जुड़े भवन की बिक्री की कड़ी निंदा करते हैं। समुदाय द्वारा बनाई गई संस्था को बंद दरवाजों के पीछे बिना पारदर्शिता या सहमति के नहीं बेचा जाना चाहिए। इसमें कहा गया, ' 'यह सिर्फ संपत्ति के बारे में नहीं है, बल्कि विरासत, भरोसे और जवाबदेही के बारे में है। समुदाय जवाब पाने का हक रखता है, गोपनीयता का नहीं। इस फैसले पर सवाल उठाए जाने चाहिए और इसका विरोध किया जाना चाहिए।' '

ऑफ बीट

मानसिक समस्या जितनी गंभीर, सहानुभूति उतनी कम

समाज में चिंता (एंग्जायटी), अवसाद (डिप्रेशन) और एडीएचडी जैसी कुछ मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों को पहले की तुलना में अब अधिक स्वीकार्यता मिली है। लोग अब कार्यस्थल, घर और सोशल मीडिया पर इनके बारे में खुलकर बात कर पाते हैं और अक्सर उन्हें सलाह भी मिलती है। यह बदलाव महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे मदद मांगना आसान हुआ है और संस्थानों के लिए मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को आधार बना कर कड़े कदम उठाना कठिन हो गया। लेकिन सार्वजनिक सहानुभूति समान रूप से नहीं मिलती है। कुछ स्थितियां व्यापक रूप से समझी जाती हैं, जबकि अन्य को अब भी संदेह और कठोर निर्णय का सामना करना पड़ता है। जैसे-जैसे लोग कुछ बीमारियों से परिचित होते जाते हैं, वे बीमारियां मानसिक रोग की /"स्वीकार्य/" छवि तय करने लगती हैं। जो लक्षण इस छवि में फिट नहीं बैठते, उन्हें अलग नजर से देखा जाता है। यहां बात 'अस्वीकार्यता' से संबंधित है। शोध से पता चलता है कि अवसाद और चिंता के प्रति सामाजिक नजरिया नर्म है, जबकि शिज़ोफ्रेनिया और व्यक्तित्व विकारों (जैसे बॉर्डरलाइन या नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर) के प्रति समाज में अधिक दूरी और भय वाली सोच है। नौ अलग-अलग निदानों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि लोगों द्वारा दूरी बनाए रखने की इच्छा शिज़ोफ्रेनिया और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के मामलों में सबसे अधिक थी।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से aapkepatra.haribhoomi@gmail.com पर भेज सकते हैं।

नेहरू के शासनकाल की विदेश नीति, सीमा सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय निर्णयों की समीक्षा हो: पात्रा

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

नेहरू युग में लिए गए निर्णयों के नकारात्मक प्रभाव आज भी दे रहे दिखाई: भाजपा

भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को कहा कि नेहरू युग में भारत की विदेश नीति, सीमा सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लिए गए निर्णयों के नकारात्मक प्रभाव आज भी दिखाई देते हैं, आज इन ऐतिहासिक घटनाओं की समीक्षा जरूरी है। भाजपा के लोकसभा सांसद एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ संबित पात्रा ने गुरुवार को दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते विश्व एआई समिट में कांग्रेस की एक सोची समझी साजिश के तहत भारत को बदनाम करने की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस और विशेष रूप से नेहरू युग की कॉम्प्रोमाइज्ड नीतियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान प्लेकार्ड के माध्यम से कांग्रेस से सात सवाल भी पूछे गए।

डॉ. पात्रा ने कहा कि आज जो घटनाक्रम सामने आया, उसके पीछे एक सोचा-समझा प्लान और अरेंजमेंट था। सोशल मीडिया पर कई रील्स और ट्वीट्स के माध्यम से यह दावा किया गया जा रहा है कि उन्हें कांग्रेस कार्यालय और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से मेसेज आए थे, जिनमें वर्ल्ड एआई समिट के खिलाफ ट्वीट या रील बनाने पर

25,000 रुपए, 50,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक देने की बात कही गई। ऐसे कई उदाहरण सोशल मीडिया पर साझा किए गए हैं, जिनमें कथित संदेशों के स्क्रीनशॉट भी दिखाए गए, और कुछ मीडिया चैनलों ने भी इन्हें प्रसारित किया। यह सब भारत की छवि को अंतरराष्ट्रीय मंच पर नीचा दिखाने की राहुल गांधी की एक पूर्व-नियोजित तैयारी का हिस्सा था, और वो जिस तरह से 'कंप्रोमाइज्ड' शब्द का उपयोग कर रहे हैं, वास्तव में 'कंप्रोमाइज्ड' कौन है, आज देश को यह जानना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस पूरे सिलसिले में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, किस प्रकार कंप्रोमाइज्ड नेहरू ने देश को भी कंप्रोमाइज्ड किया। जिन्हें कभी 'चाचा नेहरू' कहा जाता था, वे दरअसल 'चाचा कॉम्प्रोमाइज्ड' थे और अब उन्हें इसी नाम से पुकारा जाना चाहिए। जब चाचा ही कंप्रोमाइज्ड थे तो देश की स्थिति क्या होगी, यह सहज समझा जा सकता है। चाचा कॉम्प्रोमाइज्ड की जो गलतियां थीं, वो केवल अनजाने में हुई नीतिगत गलतियां नहीं थीं, बल्कि सोच-समझकर और जान-बूझकर लिए गए फैसले थे, जिससे देश कंप्रोमाइज्ड हो।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि चाचा कॉम्प्रोमाइज्ड नेहरू के सचिवालय में सीआईए का इतना प्रभाव था कि उनके विशेष सहायक एम. ओ. मथाई को अमेरिकी एजेंट कहा जाता था। 1960 के दशक में रूस की एजेंसी केजीबी के एजेंट भी चाचा कॉम्प्रोमाइज्ड के कार्यालय में मौजूद थे। चाहे एमओ मथाई हों या केजीबी के एजेंट, उस समय सीआईए और केजीबी दोनों का ही नेहरू के कार्यालय पर दबदबा था। 60 और 70 के दशक में यह कहा जाता था कि नेहरू शासनकाल में विदेशी ताकतों को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होती थी, वे अमेरिका और रूस को आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। चाचा कॉम्प्रोमाइज्ड का देश की सुरक्षा के साथ किया गया यह गंभीर कॉम्प्रोमाइज था। आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा इतनी खोखली क्यों बनाई गई कि देश के गुप्त दस्तावेज विदेशी हाथों में पहुंच जाते थे?

डॉ. पात्रा ने कहा कि दूसरा विषय क्षेत्रीय समर्पण का है। चाचा कॉम्प्रोमाइज्ड ने जब मन किया, भारत के नक्शे पर मानो स्केच पेन से रेखा खींचकर हिस्से बांट दिए कि कौन स हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाए और कौन सा चीन को। तिब्बत और अक्साई चीन की कहानी पूरा देश जानता है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि नेहरू ने पश्चिम बंगाल सरकार को बिना सूचित किए और बिना किसी कैबिनेट कंसल्टेशन के, राज्य को अंधेरे में रखते हुए बेरूबारी के हिस्से को पाकिस्तान को देने का निर्णय लिया, जिसे नेहरू-नून समझौता कहा जाता है। इस समझौते के तहत बेरूबारी पाकिस्तान को सौंप दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और स्पष्ट कहा कि इस प्रकार राज्य से परामर्श किए बिना देश के हिस्से को नहीं सौंपा जा सकता, लेकिन इसके बावजूद संविधान में नवें संशोधन के माध्यम से नेहरू ने बेरूबारी को पाकिस्तान को देने का कार्य किया।

लोक सभा सांसद ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए प्रयासरत है, जबकि 1950 में अमेरिका और 1955 में सोवियत संघ ने भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन नेहरू ने अपनी बहन विजयलक्ष्मी पंडित को पत्र लिखकर कहा कि इससे चीन नाराज हो सकता है, इसलिए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना चाहिए। नेहरू ने अमेरिका और रूस के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसमें भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाने की बात कही गई थी, क्योंकि उनका प्रिय मित्र चीन नाराज हो सकता था।

खबर संक्षेप

5 महिलाओं को पिकअप ने रौंदा, 3 की मौत

महोबा। जिले में कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एक पैलेस में बुधवार देर रात आयोजित वैवाहिक

कार्यक्रम में खाना बनाकर लौट रहीं 5महिलाओं को पीछे से आ रही पिकअप ने कुचल दिया। 3महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गईं। सभी घायलों को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया।

असम में 35 औद्योगिक इकाइयों को मंजूरी

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कहा कि औद्योगिक विकास को

बढ़ावा देने से राज्य विकास की ओर बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग और बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश किया जा रहा है। एक्स पर सीएम सरमा ने बताया कि 5,067 करोड़ रुपए की 35 औद्योगिक इकाइयों को मंजूरी दी गई है। 26 क्षेत्रों को स्वीकृत किया है।

8 घंटे काम पर अड़े मजदूरों ने किया पथराव

पानीपत। पानीपत रिफाइनरी में श्रमिकों की तरफ से पुलिस पर पथराव किया गया जिसके बाद

पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। श्रमिक 12 घंटे की बजाय 8 घंटे काम की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं।कुछ दिन पहले भी श्रमिकों और सीआईएसएफ जवानों के बीच झड़प हुई। बताया गया कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हवाई फायरिंग भी हुई।

कंपनी में कर्मचारियों ने तोड़फोड़ की, आग लगाई

हजीरा। गुजरात के हजीरा में आर्सेनल मित्तल एंड निपोन स्टील कंपनी में गुरुवार को इसलिए हंगामा और तोड़फोड़ हुई क्योंकि हरियाणा के पानीपत में एक कामगार की मौत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इससे कामगार भड़क गए। कर्मियों ने गुस्से में कंपनी में भारी तोड़फोड़ की और आग लगा दी।

सीमांचल से गृहमंत्री शाह ने किया घुसपैठ मुक्त भारत का शंखनाद

वोट बैंक नहीं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक-एक घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा

सीमांचल की राजनीति को एक नए अंदाज में साधने के लिए गृह मंत्री शाह ने बिगुल फूंक दिया। सीमांचल पूरी भाजपा के लिए केवल चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा मिशन का केंद्र बिंदु बन गया है।

एजेंसी ⏭ पटना

बिहार में सीमांचल की राजनीति को एक नए अंदाज में साधने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को बिगुल फूंक दिया। सीमांचल पूरी भाजपा के लिए केवल चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा मिशन का केंद्र बिंदु बन गया है। भाजपा की राजनीति की इस सोच में सीमांचल की बदलती डेमोग्राफी और अवैध तरीके से घुसपैठ के विरुद्ध मुक्ति का अभियान है। इसे आज के परिप्रेक्ष्य में गृह मंत्री शाह के उदबोधन से भी समझा जा सकता है। शाह ने सीमा सुरक्षा बल को संबोधित करते कहा है कि हम पूरे सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। यह घुसपैठिए की ओर से हमारे देश के गरीबों के अनाज की हकमारी ही नहीं बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी भी है। जब तक इनको देश से बाहर नहीं किया जाएगा तब तक ये देश की सुरक्षा को भेदते रहेंगे। इतना भर ही नहीं बल्कि एक्शन प्लान के प्रथम स्टेज में सीमा से 10 किमी अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं उसे हटाने के निर्देश भी दिया है।

यहां की राजनीति को नए अंदाज में साधने के लिए अभियान शुरू किया

यह देशभर की सुरक्षा मिशन का केंद्र बिंदु बना

सीमा से 10 किमी अंदर तक अतिक्रमण हटेंगे

गृहमंत्री अमित शाह

सरकार डेमोग्राफी परिवर्तन को लेकर संकल्पित

शाह ने दूसरा संकल्प लेते कहा कि यह सरकार डेमोग्राफी परिवर्तन को लेकर भी संकल्पित है। इस संदर्भ में एक उच्च स्तरीय समिति सिर्फ सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे देश की बदली डेमोग्राफी का गहराई से अध्ययन कर रिपोर्ट करेगी। इसके बाद घुसपैठिये को देश से बाहर निकालने की कवायद को अंजाम दिया जाएगा।

प्लान राजद की जड़ में मट्ठा डालने के समान

सीमांचल पर शाह का फोकस सिर्फ इसलिए नहीं है कि वे चुनावी जीत का इसे आधार बनाना चाहते हैं। बल्कि वे सीमांचल में राजद की राजनीति का सफाया करना चाहते हैं। शाह का यह प्लान राजद की जड़ में मट्ठा डालने के समान है। शाह इसके जरिए सीमांचल में 24 विधानसभा सीटों पर स्थाई जीत की नींव रखना चाहते हैं। दरअसल शाह पीएम मोदी के उस की गारंटी को पूरा करना चाहते हैं जिसे उन्होंने बिहार की भूमि पर ली थी। वह संकल्प था घुसपैठिया को बाहर जाना ही होगा ।

अतिक्रमण विरोधी अभियान चलेगा

गृह मंत्री ने कहा कि सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूद अवैध अतिक्रमणों को हटाने का अभियान चलाया जाएगा और घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार हैं।

घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई को दृढ़ संकल्पित

केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि देश को घुसपैठियों से मुक्त कराना कोई चुनावी वादा नहीं, बल्कि केंद्र की मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प है। उन्होंने कहा कि एक-एक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें भारत की भूमि से बाहर किया जाएगा। घुसपैठिए चुनाव को प्रभावित नहीं करते, गरीबों के राशन, युवाओं के रोजगार औरसुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

अररिया में कार्यक्रम और सीमा सुदृढ़ीकरण

शाह ने अररिया में बॉर्डर आउट पोस्ट 'लेटी' और 'इंदरवा' के उद्घाटन तथा सशस्त्र सीमा बल के विभिन्न कार्यों के ई-लोकार्पण और ई-शिलान्यास को संबोधित किया। भारत-नेपाल सीमा सड़क योजना के तहत 556 किलोमीटर लंबी बॉर्डर रोड को स्वीकृति दी गई है, जिसमें 18 में से 14 खंडों का कार्य पूरा हो चुका है।

सीमा सुरक्षा और निगरानी पर जोर

शाह ने कहा कि सड़क परियोजना पूरी होने से सीमा पर निगरानी क्षमता बढ़ेगी और सुविधाएं भी बेहतर होंगी। विकास योजनाओं को अंतिम सीमा तक पहुंचाने में भी इससे मदद मिलेगी। शाह ने बल की सराहना करते हुए कहा कि मित्र देश के साथ लगी सीमा की सुरक्षा के साथ-साथ संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना आवश्यक है। बल के जवानों और अधिकारियों से सीमांत गांवों के साथ बेहतर संवाद और संपर्क बनाए रखने पर जोर दिया।

मोगा में 14 को करेंगे रैली, 'अकाली' के साथ गठबंधन भी संभव

नई दिल्ली। शाह की प्रस्तावित रैली 14 मार्च को मोगा में होगी। गृह मंत्रालय ने पंजाब भाजपा को इसकी जानकारी दे दी है। पहले यह रैली 22 फरवरी को प्रस्तावित थी।सभी राजनीतिक दलों की नजर शाह की रैली पर टिकी हुई हैं। मुख्य कारण शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन की संभावना है।

राहुल का ट्रेड डील पर सरकार पर हमला

किसानों की सुरक्षा और सम्मान से ही भारत सफल-सुदृढ़ होगा

कन्नूर में किसान सम्मेलन को राहुल ने किया संबोधित

एजेंसी ⏭ कन्नूर

केरल दौरे पर पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। कन्नूर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि भारत तभी सफल हो सकता है जब हमारे किसानों का सम्मान और सुरक्षा हो। राहुल ने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एपस्टीन फाइलों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री को धमकाने के लिए किया ताकि वे एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करें जिससे भारतीय किसानों की 'बलि' चढ़ जाएगी।राहुल कन्नूर जिले के पेरावूर में किसानों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार इस सरल तथ्य को नहीं समझती कि किसान भारत की नींव हैं। आईटी और अन्य क्षेत्रों के बारे में लंबे-लंबे व्याख्यान दिए जाते हैं, लेकिन नींव को मजबूत नहीं बनाया जाता। यदि आप नींव का सम्मान नहीं करते, तो कुछ भी नहीं बन सकता। नींव बनाने वाले को सम्मान या सुरक्षा नहीं मिलती। हम हर दिन भोजन करते हैं,

भारत में मशीनीकरण का स्तर कम

उन्होंने कहा कि भारतीय किसान छोटे किसान हैं और उनमें मशीनीकरण का स्तर कम है। अमेरिकी किसानों के पास विशाल खेत हैं और उनमें मशीनीकरण का स्तर उच्च है। अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजारों तक पहुंच प्रदान करना एक आपराधिक कृत्य है। पहले के किसी भी प्रधानमंत्री ने अमेरिकी किसानों को भारत में सोयाबीन, सब्जियां और फल जैसे उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि ससे भारतीय कृषि की नींव नष्ट हो जाएगी। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति किसानों के लिए ही हुई थी। राहुल ने कहा कि कृषि संबंधी मतभेदों के कारण भारत-अमेरिका समझौता चार महीने से रुका हुआ था। सरकार अमेरिकी कंपनियों के लिए कृषि क्षेत्र खोलना नहीं चाहती थी। कुछ भी प्रगति नहीं हो रही थी और अमेरिकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे थे। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रपति के संबोधन के बाद उन्हें संसद में बोलने की अनुमति नहीं दी गई।

वायनाड लैंडस्लाइड पीड़ितों से मिले

कहा- आप मेरा परिवार, घरों का शिलान्यास किया

राहुल गांधी ने मुंडक्कई-चूरलमाला लैंडस्लाइड पीड़ितों के लिए कांग्रेस द्वारा बनाए गए घरों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह कोई एक दिन की घटना नहीं है। क्योंकि आप हमारा परिवार हैं और हम आपके साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि जब भी आपको हमारी जरूरत होगी, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। परमिशन को लेकर मुश्किलें थीं, जमीन को लेकर मुश्किलें थीं, और भी मुश्किलें थीं। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। मेरे लिए, वायनाड वापस आना हमेशा खुशी की बात होती है।

चुंगथांग-लाचेन एक्सिस और ताराम चू ब्रिज का उद्घाटन

रक्षा राज्य मंत्री संजय ने कहा

सेठ ने सीमा सुरक्षा संगठन के कमाल को 'राहतभरी' महान उपलब्धि बताया

एजेंसी ⏭ गंगटोक

रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उत्तरी सिक्किम में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा पुनर्निर्मित चुंगथांग-लाचेन मार्ग और 400 फीट लंबे बेली सस्पेंशन ताराम चू पुल का उद्घाटन किया। यह मई-जून 2025 में विनाशकारी बादल विस्फोट, जून 2024 में चक्रवात रेमल और अक्टूबर 2023 में हिमनदी झील विस्फोट बाढ़ के बाद संगठन द्वारा किए जा रहे आपदा राहत प्रयासों में अहम उपलब्धि है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सीमा सुरक्षा संगठन ने संचार व्यवस्था को बहाल करने के लिए स्वास्तिक परियोजना के तहत 96 भूस्खलनों को साफ किया, 4 प्रमुख पुलों का निर्माण किया और 2अन्य पुलों की मरम्मत की। सीमा सुरक्षा संगठन की इंजीनियरिंग टीम ने 8 किलोमीटर की नई भू-सफाई पूरी की और विभिन्न वैकल्पिक मार्ग बनाए।

क्षेत्र में संपर्क और मजबूत होगा

ये प्रयास अक्टूबर 2025 में 7.5 किलोमीटर लंबे नागा-टूंग मार्ग के खुलने के बाद किए गए हैं, इससे संपर्क और मजबूत हुआ है। 28 किमी लंबी चुंगथांग-लाचेन सड़क और ताराम चू पुल के पूरा होने से स्थानीय निवासियों, सुरक्षा एजेंसियों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

आयकर विभाग की छापेमारी में अब तक 10 करोड़ कैश मिला

बसपा विधायक, करीबियों पर छापा

एजेंसी ⏭ लखनऊ

उत्तर प्रदेश के एकमात्र बसपा विधायक उमाशंकर सिंह और उनके करीबियों के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई। यह गुरुवार को भी जारी रही। खबर है कि उमाशंकर सिंह और उनके करीबियों के घर से 10 करोड़ कैश बरामद हुए हैं। वहीं कई स्थानों पर अभी भी कार्रवाई जारी है। लखनऊ के विपुलखंड स्थित सिंह के आवास पर छापेमारी खत्म हो चुकी है। आयकर विभाग ने

30 ठिकानों पर छापे

लखनऊ, बलिया, सोनभद्र, कौशांबी, मिर्जापुर और प्रयागराज में 30 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। 50 से अधिक अधिकारियों की टीम ठिकानों पर पहुंची थी आयकर विभाग की यह कार्रवाई खत्म नहीं हुई है।

सैमटेक्स फैशंस लिमिटेड
पंजी. कार्यालय : खसरा नं. 62 डी1/3, इंडस्ट्रियल एरिया, राजारामपुर
सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर, यूपी-203205 भारत
CIN: L17112UP1993PLC022479, Email: samtex.compliance@gmail.com,
Website: www.samtexfashions.com, Ph. No.: 011-49025972

शेयरधारकों को सूचना
(फिजिकल शेयरों के हस्तांतरण आग्रहों के पुनः प्रस्तुतीकरण हेतु स्पेशल विंडो)

सेबी सरकुलर नं. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी 2026 के अनुसरण में, कम्पनी ने फिजिकल सिक्योरिटीज जो 01 अप्रैल 2019 से पूर्व बेचे अथवा खरीदे गये थे और ऐसे हस्तांतरण आग्रह पूर्व में जमा करवाए गए थे तथा **दस्तावेजों / प्रक्रिया में कमी / अथवा अन्यथा की वजह से निरस्त कर दिये गये / वापस लौटा दिये गये / ध्यान नहीं दिया गया,** के हस्तांतरण/डिमैटीरियलाइजेशन ("डिमैट") हेतु 05 फरवरी 2026 से 04 फरवरी 2027 तक एक वर्ष की अवधि के लिए स्पेशल विंडो पुनः खोली है।

इस अवधि के दौरान, सिक्योरिटीज जो हस्तांतरण के लिए पुनः दावर की गई हैं, केवल डिमैट मोड में जारी की जाएंगी और हस्तांतरण के पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष की लॉक-इन अवधि के तहत होंगी। ऐसी सिक्योरिटीज उक्त लॉक-इन अवधि के दौरान हस्तांतरित / ग्रहणाधिकार-मार्कर्ड/गिरवीकृत नहीं की जाएंगी। हस्तांतरिती को उपरोक्त सेबी सरकुलर के तहत निर्धारित अनुसार सभी दस्तावेज अनिवार्य रूप से जमा करवाने आवश्यक होंगे।

हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरिती के बीच विवादों के मामले ; निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को हस्तांतरित की गई सिक्योरिटीज के बारे में प्रोसैसिंग के लिए इस विंडो के तहत विचार नहीं किया जाएगा।

शेयरधारक अपेक्षित दस्तावेजों सहित अपने आग्रह निर्धारित अवधि के अंदर कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) बीटल फाइनैंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड, बीटल हाउस, तृतीय तल, 99 मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, नई दिल्ली-110062 के पास जमा करवा सकते हैं ई-मेल करें beetalrta@gmail.com

कृते सैमटेक्स फैशंस लिमिटेड
हस्ता/-
अतुल मित्तल
प्रबंध निदेशक

दिनांक : 26 फरवरी 2026
स्थान : दिल्ली

भाजपा ने झारखंड में वित्तीय अनियमितता को लेकर हेमंत सरकार पर साधा निशाना

डीएमएफटी फंड में घोटाले, विभिन्न विभागों में संदिग्ध लेनदेन के साथ- साथ संगठित अपराध से राज्य बेहाल,10,000 करोड़ का हिसाब नहीं: तुहिन सिन्हा

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

भाजपाके राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने गुरुवार को झारखंड में लगभग 10,000 करोड़ की वित्तीय अनियमितताओं, डीएमएफटी फंड में घोटाले, विभिन्न विभागों में संदिग्ध लेनदेन और डीजीपी नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर हेमंत सोरेन सरकार की जमकर आलोचना की। नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए सिन्हा ने कहा कि संगठित अपराध, फिरौती और अपहरण का जो नेक्सस पहले बिहार में हुआ करता था, आज झारखंड में चल रहा है और हेमंत सोरेन अपने चहेते पुलिस अधिकारियों द्वारा इसे आगे बढ़ा रहे हैं।

सिन्हा ने कहा कि बीते दिनों झारखंड में भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष बाबू लाल मरांडी के संज्ञान में एक खत आया, जिसके मुताबिक लगभग 10,000 करोड़ का कोई स्पष्ट हिसाब राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से जुड़ी अखबार यह खबर दिखाते हुए कहा कि यह लगभग 22 वर्षों से चल रहा स्कैम है, लेकिन सबसे बड़े घोटाले 2019 के बाद रचे गए। लिकर स्कैम हो, लैंड स्कैम हो या अन्य माध्यमों से की गई वित्तीय अनियमितताएं हों, करीब 10,000 करोड़ का कोई स्पष्ट हिसाब राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। यह जानकारी इंडी अलायंस सरकार के ही तत्कालीन वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर सोरेन ने 2024 में दी थी। उन्होंने झारखंड के कैबिनेट सेक्रेटरी को पत्र लिखकर 10,000 करोड़ रुपए के लेखे-जोखे पर प्रश्न उठाए और जांच की आवश्यकता बताई थी। 6 महीने के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया गया, यह लूट हेमंत की निगरानी में हो रही थी। सिन्हा ने कहा कि संभव है कि तत्कालीन वित्त मंत्री को भी पूरी जानकारी न हो, या फिर हेमंत के ही निर्देश पर कैबिनेट सेक्रेटरी ने उनके सवालों का जवाब न दिया हो। इतना बड़ा स्कैम, कोई हिसाब नहीं है? सिन्हा ने कहा कि यह सामने आ रहा है कि अत्यंत शातिर तरीके से अनेक विभागों को छोटे-छोटे वित्तीय लक्ष्य दिए गए थे। ऊर्जा विभाग ने लगभग 108 करोड़ की राशि फिक्स्ड डिपॉजिट में रखी थी, जो ब्याज सहित परिपक्वता के दिन 108 करोड़ रुपए होनी थी, लेकिन मैच्योरिटी के दिन पूरी राशि गायब पाई गई। इस विषय को सबसे पहले सरयू राय ने उठाया था, जो वर्तमान में जेडीयू में हैं। विभिन्न विभागों को 200 करोड़, 500 करोड़ जैसे अलग-अलग लक्ष्य दिए गए और छोटे-छोटे स्तर पर की गई इन वित्तीय अनियमितताओं को जोड़ने पर कुल राशि लगभग 10,000 करोड़ तक पहुंचती है। लगभग 4 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट स्कैम, का मुद्दा उठाया गया था। 2016 में एक नियम के तहत देश के सभी माइनिंग जिलों के कल्याण के लिए एक फंड बनाया गया था, जिसमें माइनिंग लीज होल्डर्स को रॉयल्टी आय का 10-30 प्रतिशत इस फंड में जमा करना होता था। यह राशि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास और वेलफेयर कार्यों पर खर्च की जानी थी। केवलबोकारो जिले में, जो धनबाद सहित कोल बेल्ट क्षेत्र का हिस्सा है और जहां बड़े पैमाने पर खनन होता है, डीएमएफटी के तहत लगभग 500 करोड़ की अनियमितताएं सामने आई हैं। सीबीआई जांच की मांग की गई, लेकिन राज्य सरकार ने उत्तर नहीं दिया।

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा
धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त नाम **राम किशोर मुखिया पुत्रः** श्याम सुंदर मुखिया **पताः** सी–265/10 नाला के पास, राधे राधे गली चिराग दिल्ली, ने **FIR No. 403/24 U/s 25/54/59ARMS ACT थानाः सनलाइट कॉलोनी दिल्ली,** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **राम किशोर मुखिया** मिल नही रहा हैं और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **राम किशोर मुखिया** फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **FIR No. 403/24 U/s 25/54/59ARMS ACT थानाः सनलाइट कॉलोनी दिल्ली,** के उक्त अभियुक्त **राम किशोर मुखिया** से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **28.03.2026** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
श्री अदिति राव
जेएमएफसी–07, कमरा नंबर 508
साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली

DP/2506/SE/2026
(Court Matter)

Last Day To Join Private channel

I GIVE YOU MY GUARANTEE, THIS PURCHASE WILL BE WORTH IT.

📚Indian Newspapers:

1) Times of India
2) Hindustan Times
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times
6) The Hindu
7) Live Mint
8) Financial Express
9) Business standard
+All Editorial PDFs

Uploding starts from 5AM

🎈Access to all this In Just 19 Rupees [lifetime Validity]

Click below to

Join

📚International Newspapers Channel

📚 Magazine Channel (National & International)